राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या: 08

मंगलवार,

14 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री सभापति: प्रश्न काल। श्री बाबुलाल।

झाड़ोल में लूटपाट की घटनाएं

135. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विगत चार वर्षों में लूटपाट की कितनी घटनाएं हुई हैं? थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विगत चार वर्षों (2019, 2020, 2021 एवं 2022) में लूटपाट के कुल 58 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनका थानेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदयजी ने जो मुझे चार्ट उपलब्ध कराया है, इसमें विभिन्न थानों में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें झाड़ोल में 30, फलासिया में 2, ओगणा में 8, बाघपुरा में 3, कोटड़ा में 7, माण्डवा में 6 और पानरवा में 2 बताई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि 58 प्रकरण दर्ज हुए, उनमें से कितने लोग आपने गिरफ्तार किये और कितने लोग अब भी फरार हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि झाड़ोल थाने में बड़ी संख्या में, 30 घटनाएं हुई हैं, उनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? यह बतायें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
मालूम है कि आपकी विधान सभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 7 थाने हैं और उनमें 58 प्रकरण दर्ज हुए हैं। आपने पूछा कि 58 थानों में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये तो 147 आदमी गिरफ्तार किये गये। उन 58 में से 43 प्रकरणों में चालान पेश कर दिया गया है, बाकी 13 बचे हैं। उनमें से 8 में तो अदम पता मुलजिम एफ आर पेश की गयी, बाकी 5 रह गये। वे 5 केस असत्य थे। 2 प्रकरण 2022 के हैं। जो अभी तफ्तीश में हैं।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, झाड़ोल थाना संवेदनशील थाना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है।

श्री सभापति: प्रश्न क्या है आपका?

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। वहां पर गिरोह बनाकर लोग व्हाट्सएप पर जीरो जीरो सेवन, आर.बी.आर. के नाम से ग्रुप बना कर मोबाइल से सूचना करके अपराध करते हैं, घटनाएं करते हैं। उनके लिए सरकार कोई योजना बनाकर ऐसे गिरोहों को पकड़कर उनकी रोकथाम का प्रयास करेगी क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): झाड़ोल का जहां तक सवाल है, सोशल मीडिया अकेले झाड़ोल में नहीं है, पूरे देश में है, पूरे संसार में है। सवाल यही आता है कि 2019, 2020, 2021, 2022 के प्रकरण हैं। 2021 तक तो 7 प्रकरण थे और 2022 आते-आते वह 16 हो गये। बढ़े तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी रोकथाम के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहां के पुलिस को आई जी ने बुलाकर मीटिंग ली है और उनको टाइट किया है। मैं यह समझता हूं कि इन प्रकरणें में आइन्दा गिरावट ही आयेगी।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अब क्या बाकी रह गया?

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): आप कहो तो बैठ जाऊं? मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि हम रोकथाम नहीं करेंगे तो वह बहुत बड़े गैंग के रूप में होगा। थोड़ा-सा आप सक्रिय होकर इसको रोकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको आगे पुलिस की पूरी सक्रियता मिलेगी। अगले विधान सभा सत्र में जब आप पधारेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गिरावट नजर आयेगी।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

मांडलगढ़ के विद्यालयों में कक्षा-कक्ष

136. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माडंलगढ़ के क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ व कक्षा-कक्षों की उपलब्धता नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में स्टाफ व संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आदिनांक तक उक्त क्षेत्र में कुल 04 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षा-कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी (गैप्स) तथा कार्यरत, स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आदिनांक तक 17 रा.मा.वि. को रा.उ.मा.वि. में, 03 रा.उ.प्रा.वि. को सीधे ही रा.उ.मा.वि. में तथा 01 राप्रावि को राउमावि में (महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित) क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षा-कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी (गैप्स) तथा कार्यरत, स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग में क्रमश: 48,000 तृतीय श्रेणी (लेवल-1 व लेवल-2) तथा 32,845 (6,000 स्कूल प्राध्यापक, 9,760 वरिष्ठ अध्यापक, 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, 5,546 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 461 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 460 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय, 461 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय व 295 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक) रोजगार दिये जाने के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी है। उक्त भर्तियों से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा

(शिक्षा मंत्री)

विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र कार्मिक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय विद्यालय के लिए कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रतिवर्ष जारी की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने जवाब में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की, कुर्सी, मेज, पीने का जल, शौचालय, बिजली आदि की कमी आपने स्वीकार की है। मंत्री महोदय जी, इन सब संसाधनों को आप कब तक पूरा करवा देंगे?

मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार शिक्षकों की कमी होना आपने स्वीकार किया है, माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्रीजी मेरे क्षेत्र में शिक्षकों को नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो खोल दिये, वहां पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल होगी, परन्तु वहां पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं तो अंग्रेजी की स्कूलें खोलने से क्या मतलब है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कब तक मेरे इस क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा-कक्षों और सभी सुविधाएं एवं बच्चों के अनुपात में जितनी आवश्यकता है, वहां पर आप शिक्षकों की भर्ती कब तक करेंगे और मेरे क्षेत्र में कब तक लगायेंगे? यह बताने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक तो इन्होंने यह कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ। विगत तीन वर्षों में मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 14 करोड़ 55 लाख 28 हजार के कार्य स्वीकृत कराये गये हैं और 43 कार्यों में से 10 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो स्कूलें क्रमोन्नत की गयी हैं, उनमें भी इनके यहां

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

7 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें खटवाड़ा में दो काम, एक 75 हजार का, दूसरा 11 लाख 22 हजार, बरलियास में 3 लाख 72 हजार का, हाजीवास में 10 लाख, कलकला में 40 लाख 12 हजार, नन्दराय में 66.96 लाख का और कोटड़ी में 01 करोड़ 98 लाख 07 हजार का, कुल मिलाकर 1 करोड़ 98 लाख और 7 हजार के सारे कार्य हैं। अभी-अभी आपकी स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं और आप भी जानते हैं कि एक दिन में तो हाथ में सरसों उगेगी नहीं। अभी स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, हम पी ए बी में भेजेंगे, वहां से स्वीकृति मिलेगी तो हम अपना अंशदान मिलाकर के आगामी वर्षों में इनके कक्षा कमरों की तथा अन्य कमियों को पूरा करेंगे।

जहां तक इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कही है, मेरे को तो आज तक माननीय विधायक महोदय ने चिट्ठी नहीं लिखी कि हमारे यहां अध्यापकों की कोई कमी है। मैं पता कर लूंगा और जो-जो कमियां हैं उनको जल्दी ही पूरा करूंगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके पास कितनी बार लैटर भेजे? आप स्वीकार कर रहे हैं कि 2-3 स्कूलों में आपने कुछ पैसा पास किया है, उससे क्या होता है? हर पंचायत में, हर गांव में स्कूल है। बच्चे आसमान के तले पढ़ रहे हैं, खुले में पढ़ रहे हैं और कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। स्कूलों में लाइट तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप कब तक पूरा करेंगे? यह जवाब दीजिये आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जहां-जहां पानी की कमी है, आप लिखकर भेज दें, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। मैंने आपको बताया कि अभी जो स्कूलें नई क्रमोन्नत हुई हैं उनमें 7 कार्य मंजूर कर दिये हैं। बाकी जो स्कूलें हुई हैं, कुल मिलाकर के इनके 25 स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं। आप देखिये, उन स्कूलों की स्कीमों में कम से कम एक चौथाई स्कूलों को तो हमने ले लिया। बाकी स्कूलों को भी, जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होगा, वैसे हम करेंगे।

जहां तक मास्टरों का सवाल है, इनके यहां कुछ मास्टर एक्सेस भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से कोटड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुरिया, इसमें 5 पद स्वीकृत हैं और 9 कार्यरत हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं। वहां समानीकरण करके करेंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): बहुत-सी जगह दो ही हैं। आपने मुझे यह जवाब दे रखा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जहां अध्यापकों के पद रिक्त हैं, मैंने आपको बताया 48 हजार पदों के लिए 25 फरवरी को रीट का एग्जाम हो रहा है, जैसे ही टीचर्स उपलब्ध होंगे, जहां-जहां कमियां हैं वहां-वहां उपलब्ध करा देंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): कहीं ज्यादा है तो बराबर करके आप लगाइये उनको।

श्री सभापति: विराजिये। हो गया आपका प्रश्न। विराजिये।

प्रश्न संख्या 137

श्रीमती गायत्री देवी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में वन भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

138. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कई ऐसे गांव हैं जो वन भूमि पर बसे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव कब से बसे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन भूमि को आबादी भूमि में किस प्रावधान के तहत परिवर्तित किया जा सकता है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्रीमती कल्पना देवी)

माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूं and I am very sorry to say, पर यह जवाब गलत है।

मैं आपके सामने तथ्य के साथ यह बता रही हूं कि प्रश्न के खण्ड1 के उत्तर में आपने जो कहा है, नहीं है, जी नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कोटा के लाडपुरा तहसील की खाता संख्या 6 खसरा नंबर 1 जिसका रकबा 7.6500 हैक्टेयर है, को आपने गैर मुमकिन जंगल दर्ज किया है। इसी खाता संख्या के खसरा नंबर 17, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 37, 40, 41 इसमें भी गैर मुमकिन जंगल दर्ज है।

यहां 10 हजार से ज्यादा संख्या, यह मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं, मेरे लाडपुरा क्षेत्र के केवल नगर में जहां 10 हजार की संख्या में लोग बसे हैं, जहां वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत नहीं हो रही है क्योंकि कह रहे हैं कि वन भूमि में है। आपने कैसे कहा कि, जी नहीं?

दूसरा, आपने खण्ड-2 के उत्तर में यह कहा है कि वन भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, क्या यह सही है कि वन भूमि के मुकाबले दूसरी भूमि को एक्सचेंज करके, इस केवल नगर की जो बात मैं कर रही हूं, इस भूमि को निकाला जा सकता है? ऐसे मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकती हूं जहां आपने ऐसी वन भूमि की लैंड को एक्सचेंज किया है, ताकि केवल नगर के जो 10 हजार लोग हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्य हम वहां करा सकते हैं। विधायक कोष से अगर मैं हैंडपम्प भी स्वीकृत कराती हूं तो वह निरस्त किया जाता है कि वन भूमि की जमीन है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने प्रश्न में गांव बसने की बात कही थी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): हां।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): वहां कोई गांव नहीं बसे हुए हैं लेकिन जो गांव बसे हुए हैं, उनके पास में जो वन भूमि है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उप वन संरक्षक, कोटा में हाका केसरा फूटा, उसमें बस्ती का नाम है केवल नगर, उसमें 50 हैक्टेयर में अतिक्रमण कर रखा है। वहां निवास कर रहे परिवारों की संख्या 1500 है। इसी तरह हाका केसरा फूटा,

(श्री हेमाराम चौधरी)

बोर कुई इसमें 10 हैक्टेयर में अतिक्रमण कर रखा है, इसमें 60 परिवार रह रहे हैं। देवली राड़ी, बस्ती का नाम राजनगर, इसमें 15 हैक्टेयर में 300 परिवार निवास कर रहे हैं। खेड़ा जगपुरा, बस्ती का नाम जगपुरा, इसमें 7 हैक्टेयर में 30 परिवार निवास कर रहे हैं। ढाढ देवी वनखण्ड में बस्ती का नाम उम्मेदगंज, उसमें 10 हैक्टेयर में 300 परिवार और लाखावा 'ए' जिसमें 50 हैक्टेयर में 400 परिवार और कहार बस्ती में 17.23 हैक्टेयर में 35 परिवार निवास कर रहे हैं।

आप खुद मान रहे हैं कि यह जंगलात की भूमि है। जंगलात की भूमि पर इनका अतिक्रमण है। अतिक्रमण को आप डायवर्जन की बात कर रहे हैं, तो उसमें Forest (Conservation) Act (FCA), की गाइडलाइंस 11.09 के तहत रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, "the Central Government will not entertain any proposal for diversion of forest land for construction of residential or dwelling house". इसमें साफ लिखा है कि वन विभाग की भूमि है, उसको हम नहीं दे सकते हैं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह जिस केवल नगर की बात कर रहे हैं, यह आजादी के पहले वहां बसे हुए लोग हैं। आप इसको अतिक्रमण कैसे मान रहे हैं? वहां फैक्ट्री लगी हुई हैं। फैक्ट्रीज चल रही हैं एक नहीं अनेक।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जो भी बसे हुए हैं, जमीन जंगलात के नाम से है, फोरेस्ट के नाम से है, जब हमारे नाम से जमीन है तो हम अतिक्रमी ही मानेंगे उनको।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक साल पहले तक वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाये जा रहे थे लेकिन लगभग एक साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। आप पहले कैसे दे रहे थे? अगर आप उसको मान नहीं रहे थे और वह वन क्षेत्र में था तो पहले कैसे आपने स्वीकृत कराये प्रधानमंत्री आवास योजना के घर?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने यह कहा है कि वन भूमि में डायवर्जन नहीं होगा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सर, एक साल पहले तक तो वह स्वीकृत थे।

श्री सभापति: रिहायशी कालोनियों का डायवर्जन वन भूमि में नहीं होगा, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया। वह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या बतायें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): एक साल से स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। पहले कैसे दे रहे थे और अब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिंपल चीज है। उसी जगह पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के घर स्वीकृत कर रहे थे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि वन भूमि में रिहायशी के परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): गांव पहले बसा हुआ था। वन विभाग बाद में आया है। एक साल पहले आप दे रहे थे।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

राजलदेसर (चूरू) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

139. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए क्या नियम व मानदण्ड निर्धारित है?

(2) क्या सरकार जिला चूरू की उप तहसील राजलदेसर को तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) प्रदेश में नवीन उप तहसील/तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित नियम व मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र 2023-24 के दौरान दिनांक 10.02.2023 को जिला चूरू की उप तहसील राजलदेसर को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। उक्त की अनुपालना में विभाग द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आपने जो मांग रखी थी, उससे पहले ही सरकार ने मान लिया। वहां की जनता की भावनाओं को देखते हुए तहसील खोल दी गयी। मांग पूरी हो गयी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मंत्री

(श्री अभिनेश महर्षि)

महोदय ने कहा कि प्रश्न पूछने से पहले ही खोल दी थी, तो यह गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे प्रश्न पूछने के बाद में तहसील की घोषणा की है। नंबर एक बात।

दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्व मंडल के द्वारा आपने जो मुझे नियम भेजे हैं इसमें जो तहसील की सीमाओं के सीमांकन करने की बात कही गई है, क्या यह सीमांकन पूरा कर लिया गया है? क्या अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो आपने परिशिष्ट-अ में मुझे भेजा है?

आपके उप निबंधक, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को एक पत्र 19.04.2007 को भेजा गया है जिसमें तहसील के गठन हेतु 30 पटवार मंडल और 6 से 8 पटवार मंडलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, क्या ये मापदंड पूरे कर लिए गये हैं? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि तहसील कब तक शुरू हो जाएगी? तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कब हो जाएगी या ये सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्व मंडल के सर्कुलर की जहां तक बात की है, दिनांक 19.04.2007 के सर्कुलर में तहसील, उप तहसील बनाने के मानदंड के बारे में बताया गया है। इसमें तहसील हेतु 30 पटवार मंडल, 8 पटवार मंडलों पर 1 गिरदावर सर्कल, भू-अभिलेख निरीक्षक होता है। उप तहसील 15 पटवार मंडल के आधार पर खोली जाती है। अगर इन नियमों में शिथिलता देनी होती है तो वो मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर होती है। आपकी तहसील में नियमों में शिथिलता देकर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है तो इनके नियम मानदंडों से ऊपर बढ़कर उस एरिया के लोगों को फायदा देने का काम किया है। इसमें आपको तो खुशी होनी चाहिए।

माननीय सदस्य, जहां तक आपकी खोलने का और लागू होने की बात है, बजट में कोई घोषणा होती है तो वह अप्रैल के बाद ही पूरे तरीके से सीमांकन होगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। बाकी इसमें शिथिलता देने की बात है, कम पटवार मंडल है, आप और चाहो कि इसको आगे-पीछे करना है तो आप लिखकर देना, उसके आधार पर हम कर देंगे।

दूसरी बात है कि जो उप तहसील, तहसील, ए सी एम आफिस, एस

(श्री रामलाल जाट)

डी एम आफिस खोले हैं, वे आज दिन तक की सरकारों, जब से राजस्थान का निर्माण हुआ होगा, तब बनी या इन चार सालों में बनी है। आप चाहो तो मैं आपको आंकड़े बता दूं। इससे पहले पिछले साल के बजट में खोली हैं, वे सब लागू हो चुकी हैं, रजिस्ट्रियां होने का ऐलान कर दिया गया, उप तहसीलों की बिल्डिंग्स बन गईं, तहसीलों की बिल्डिंग्स बन गईं, कुछ निर्माणाधीन हैं, ऐसा नहीं है कि बजट में केवल घोषणाएं ही हैं। आपकी जो-जो घोषणाएं हुई हैं अब तक, सारी की सारी पूरी की हैं। हमने इस कार्यकाल में ए सी एम आफिस एक खोला, ए डी एम आफिस 11 खोले, एस डी ओ आफिस 30 खोले, तहसील कार्यालय 73 खोले, सब-तहसील आफिस 91 खोले, आई एल आर आफिस 32 खोले, पटवार मंडल अभी मुख्य मंत्रीजी ने और खोलने की घोषणाएं की हैं। ये सारे अप्रैल के बाद लागू होंगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के मन में यदि कोई शंका है तो पिछले कार्यकाल को देखते हुए कोई शंका रहनी ही नहीं चाहिए। अब तो इनको वापस कांग्रेस में आकर चुनाव लड़कर, जीतकर आना चाहिए। इतना काम किया है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): इस बात की चिंता आप मत करो मंत्री महोदय, कि मुझे कहां रहना है, कहां नहीं रहना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभिनेष महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अभी मैं बजट पर बोलूंगा। देखिए, जब माननीय मंत्री महोदय ने छेड़ा है तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस में आऊंगा या बीजेपी में रहूंगा या कांग्रेस वालों के छक्के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, विराजिए आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिए आप। (व्यवधान) आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि मापदंड क्या हैं, होगा या नहीं होगा, तो मंत्री ने स्पष्ट (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। (व्यवधान) श्री धर्मनारायण जोशी। (व्यवधान) विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए, एक मिनट। आपका स्पेसिफिक प्रश्न है, मापदंड क्या हैं, राजलदेसर में बनेगी या नहीं बनेगी? (व्यवधान) मंत्री महोदय ने आपको जवाब दे दिया कि यह मापदंड है और वहां पर घोषणा कर दी गई है। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: नो, नॉट अलाउड।

श्री धर्मनारायण जोशी।

जोगणिया माता व विजवा माता मन्दिर का विकास

140. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2021-22 में उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा व आकर्षण हेतु फतहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी रोड, मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार) गोगुन्दा के जीर्णोद्धार पर उन्नीस करोड़ रुपये व्यय करने व पर्यटन विकास कोष में पांच सौ करोड़ रुपयों का प्रावधान करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त की क्रियान्वित में कब-कब, कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बजट 2021-22 में जोगणिया माता (बेगूं), चित्तौड़गढ़ व विजवा माता मन्दिर (मोदपुर), आसपुर में विकास कार्य करने की घोषणा की क्रियान्विति में क्या-क्या कार्य कराये गये? उक्त पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी हां। उदयपुर में फतहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी रोड एवं मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार) गोगुन्दा के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण हेतु स्वीकृत विकास कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2021-22 के बजट में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई थी, जिसे वर्ष 2022-23 के बजट में बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास कोष में से स्वीकृत कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) राज्य बजट 2021-22 की घोषणा की क्रियान्विति में जोगणिया

(पर्यटन मंत्री)

माता (बेगूं), चित्तौड़गढ़ व विजवा माता मन्दिर (मोदपुर), आसपुर, डूंगरपुर में स्वीकृत विकास कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि परिशिष्ट-अ पर महाराणा प्रताप के शस्त्रागार सहित 3 कामों पर 24 करोड़ 87 लाख रुपयों में से मात्र 98 लाख 2 हजार रुपये व्यय दिखाया गया है। वहीं परिशिष्ट-ब पर वर्ष 2021-22 में 163 करोड़ 4 लाख में से मात्र 14 करोड़ 79 लाख रुपये और वर्ष 2022-23 में 347 करोड़ 28 लाख में से मात्र 7 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय हुए हैं। क्या यह विभाग की अकर्मण्यता प्रदर्शित नहीं करता है? मंत्री महोदय, आपको इस बारे में क्या कहना है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, महाराणा प्रताप के प्रति सबकी बहुत गम्भीर श्रद्धा है। इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आधा काम यू डी एच का है और आधा काम पी डब्ल्यू डी कर रही है। चूंकि यह वन क्षेत्र है, इसमें रोड भी निकालनी पड़ेगी, रोड निकल रही है, इसमें टाइम लगता है, पहाड़ों के थ्रू रोड निकलेगी, रोड के बाद बाउण्ड्री वाल होगी और उसके बाद वृक्षारोपण और सौन्दर्यीकरण का काम शुरू होगा। आप जानते हैं कि बिना दीवार बने जो भी पौधे वहां लगाए जाएंगे, जानवरों द्वारा उनको खा लिया जाएगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि परिशिष्ट-ब पर वर्ष 2022-23 के 28 कामों में से मात्र 5 काम प्रारम्भ हुए हैं, 5 काम। वहीं प्रश्न के उत्तर में 28 में से 18 कामों पर व्यय राशि के स्थान पर 'क्रियान्वयन प्रारम्भिक स्तर पर', यह जवाब मुझे दिया है। क्या यह उत्तर भ्रामक व सदन को गुमराह करने वाला नहीं है? मैं आसन से निवेदन करूंगा कि ऐसा उत्तर देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कराई जाए। क्या मंत्री महोदय ऐसा करेंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, गुमराह कौन किसको कर रहा है? यह तो आप एम एल ए साहब किसी दिन घर पधारो, एक कप चाय पीओ, बैठकर बात करते हैं। डिनर पर पधारना चाहो तो

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

डिनर पर पधारो, भोजन पर पधारें। आप बता देना, कोई अधिकारी दोषी निकलेगा तो आपके सामने सज़ा दूंगा उसको। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय। मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप पैसे ही खर्च नहीं कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): मैं तो डिनर भी ऑफर कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): और राठौड़ साहब वाला डिनर, खाना नहीं, डिनर, जो राठौड़ साहब ने कहा था।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जब इतनी राशि की स्वीकृति हुई तो इसमें इतनी ही राशि क्यों खर्च हुई इसका कारण क्या है? स्वीकृति कब जारी हुई और काम क्यों नहीं हो रहा, इसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जवाब दिया, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है, दो साल तो कोविड में गए, बाकी जो उन्होंने पूछा उसका जवाब मैंने दे दिया। इसमें आधा काम तो यू डी एच के पास है और आधा काम पी डब्ल्यू डी के पास है, दोनों विभाग मेरे पास नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से सरकार चलती है, यह काम यू डी एच के पास है या किसी और के पास है, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं डिनर दूंगा, मैं लंच दूंगा, आप सीधा उत्तर दिलाइए।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आपको क्या उत्तर चाहिए मुझसे, वो ही उत्तर दे दूंगा। आप बता दो, वो ही दे दूंगा उत्तर। (व्यवधान) आप बता दो न।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

अग्निकांड की घटनाओं पर रोकथाम के उपाय

141. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माह जनवरी, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 की अवधि

(श्री सतीश पूनियां)

में अग्निकांड की घटनाएं कहां-कहां घटित हुईं तथा उक्त में कितनी जान माल की हानि हुई? वर्षवार, घटनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किन प्रमुख घटनाओं की तथा उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अग्निकांड की घटनाओं में प्रभावितों को किस-किस प्रकार की क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई? सरकार भविष्य में उक्त प्रकार की घटनाओं में समय पर त्वरित कार्यवाही एवं रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) प्रदेश मे आगजनी से माह जनवरी, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 की अवधि में घटित घटनाओं में 42 मानव, 1003 पशु एवं 346 आवासीय क्षति हुई है। वर्षवार/ घटनावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यह विभाग प्राकृतिक आपदा/अज्ञात कारणों से हुई आगजनी पर पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान करता है। पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एस डी आर एफ नोर्म्स अनुसार आगजनी की घटनाओं में सहायता राशि रुपये 288.85 लाख का भुगतान किया गया है।

(3) भारत सरकार दवारा निर्धारित एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार आगजनी की घटनाओं में सहायता राशि 288.85 लाख का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

अग्निशमन स्टेशनों पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। आगजनी की घटना घटित होने पर अग्निशमन वाहन भिजवाकर आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं कि एस डी आर एफ के नोर्म्स क्या हैं और कितने मामले अभी तक लम्बित हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): भारत सरकार

(श्री गोविंद राम)

द्वारा 12 प्राकृतिक आपदाओं को राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत सहायता हेतु अधिसूचित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आकाशीय बिजली तथा अन्धड़-तूफान को राज्य प्राकृतिक आपदा अधिसूचित किया हुआ है। आगजनी में प्राकृतिक/अज्ञात कारणों से क्षति होने पर एस डी आर एफ मापदण्डानुसार सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जो 12 प्राकृतिक आपदाएं हैं वे हैं- चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, सुनामी, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण, पाला एवं शीतलहर और स्टेट की ओर से अन्धड़ और तूफान, आकाशीय बिजली।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, मैंने एस डी आर एफ के मापदण्ड पूछे हैं ताकि सदन को भी जानकारी हो जाये। पीड़ितों को भी जानकारी कम होती है। साथ ही, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने मामले लम्बित हैं?

श्री सभापति: मंत्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है, मापदण्ड क्या हैं इसके?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): यही पूछा है न, नोर्म्स के अनुसार विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि, यही तो बताना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपदा होने पर कितनी राशि दी जायेगी? मकान पक्का टूटने पर, कच्चा टूटने पर, ये सब।

श्री सभापति: विराजिये, ये बता रहे हैं।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): मैं वही बता रहा हूं। मानव क्षति पर 4 लाख रुपये। मानव अंग की क्षति जो 40 से 60 परसेंट होती है, उसमें पहले थे 59 हजार रुपये, दिनांक 10.10.2022 से केन्द्र सरकार के जो नये नियम आये हैं, उनमें 74 हजार रुपये। मानव घायल, उसके अन्दर 5,400 रुपये। मानव पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 2,500 रुपये। जीविका गम्भीर रूप से होने पर अनुग्रह सहायता राशि प्रति दो व्यक्ति या मनरेगा की वास्तविक दरों की राशि औसतन, पर जो भी कम हो। पशु क्षति, पहले 30 हजार रुपये थी, अब 37 हजार रुपये है। पशु क्षति (दुधारू), पहले 25 हजार रुपये थी, अब 32 हजार रुपये है। मुर्गी पालन, पहले 50 था, अब 100 मुर्गी पालन पर दिया जाता है। झोंपड़ी, पहले 4,100 रुपये थे, अब 8 हजार रुपये हैं। शैड, पहले 2,100 रुपये थे, अब 3,000 रुपये हैं। यही है, सर।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, मापदण्ड और लम्बित मामले पूछे थे, लेकिन मैं अगले सवाल पर आ जाता हूं। यह जो मुआवजा सरकार अग्नि पीड़ितों को देती है, वह बहुत कम होता है, आज के मानकों के हिसाब से बहुत न्यून है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एस डी आर एफ के नोर्म्स हैं, क्या सरकार उन्हें रिवाइज करने की मंशा रखती है, ताकि आज के मानकों के हिसाब से अग्नि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कहीं भी आगजनी, जो अज्ञात कारणों से होती है, उसमें हम मदद करते हैं और मैंने अभी डिफरेंस भी बताया कि पहले हमारे यहां जो झोंपड़ी में 4 हजार थे, अब 8 हजार हैं। मानव की जो क्षति होती थी, पहले 95 हजार थी, अब 1 लाख 20 हजार है। अभी 10.10.2022 को केन्द्र सरकार के द्वारा ही जो संशोधन करके भेजे गये हैं, उन्हीं के अनुसार मैंने ये बताये हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से जो मैंने पूछा, वह बहुत सिम्पल्सा था, आपकी भी जानकारी में आ गया होगा।

श्री सभापति: इनका पूछना यह है कि एस डी आर एफ में अभी वर्तमान में जो स्थिति है, क्या आपकी उसमें परिवर्तन करके बढ़ोतरी करने की मंशा है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): यह केन्द्र सरकार पर निर्भर है। पूनियां जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर ये केन्द्र सरकार से चैंज करवा देते हैं तो हम तो इनसे यही मांग करेंगे कि आप भी सहयोग करें।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय...

श्री सभापति: आपने पूछा कि क्या वे मापदण्ड चैंज करने का विचार रखते हैं और उन्होंने कह दिया कि यह भारत सरकार का मामला है, तो इसमें फिर यहां अब स्टेट में क्या बाकी रह गया?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, इससे जुड़ा हुआ सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए।

श्री सभापति: नहीं, मैंने अब दूसरा नाम पुकार लिया है। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर जीरा मण्डी समिति द्वारा भूखण्डों का आबंटन

142. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जीरा मण्डी समिति द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को जीरा मण्डी प्रारम्भ करने हेतु भूखण्डों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी में भूखण्ड आबंटन की पत्रावलियां कितने समय से लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर द्वारा जीरा मण्डी प्रांगण में रिक्त भूखण्डों के आबंटन हेतु दिनांक 21.07.2017 को आबंटन समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर की आबंटन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 21.07.2017 के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के स्तर पर जांच करवाई गयी तथा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय, कृषि विपणन द्वारा पत्र दिनांक 08.05.2018 के द्वारा कार्यवाही विवरण का आंशिक अनुमोदन किया गया।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा आबंटन हेतु प्रस्तावित 77 भूखण्डों में से महिला कृषक वर्ग हेतु प्रस्तावित 15 भूखण्ड एवं कृषि जिन्सों के निर्यातकों/मूल्य संवर्धन औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित 19 भूखण्डों का, इस प्रकार कुल 34 भूखण्डों के आबंटन का अनुमोदन किया गया है। शेष 43 अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं निःशक्तजन अनुज्ञापत्रधारी वर्ग को आबंटित भूखण्डों का अनुमोदन नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आबंटन समिति की बैठक दिनांक 21.07.2017 के तहत प्रस्तावित आबंटन में से अनुमोदन से शेष रहे 43 प्रस्तावित आबंटियों द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 39 के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 पेश किया गया था। निदेशक, कृषि विपणन द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र 10.10.2022 को निर्णीत किया जाकर, इस सम्बन्ध में प्राप्त मण्डी प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान में निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर में बहुत अधिक मात्रा में जीरा पैदा होता है और ऊंझा जाता है। इसके लिए 28.03.2016 को

(श्री मेवाराम जैन)

बजट में बाड़मेर जीरा मण्डी की घोषणा हुई। 2017 में कमेटी द्वारा दुकानें आबंटित हुई। आपने अपने जवाब में ही दिया है कि 08.05.2018 को कृषि विपणन निदेशालय ने उसका अनुमोदन कर दिया। फिर कहीं ए सी बी में शिकायत हुई, उसका भी निस्तारण हो चुका। हाई कोर्ट में भी निर्णय हो चुका। उसके बाद में अभी तक वह शुरू नहीं हुई। मंत्री महोदय, क्या आप इस जीरा मण्डी, बाड़मेर को शुरू करना चाहते हैं? यदि हां, तो कितने दिनों में? उन्होंने पैसे जमा करा दिये। राशि जमा हुए इतने साल हो गये। आखिर इस मण्डी को शुरू करेंगे अथवा नहीं? कृपया बताएं।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 21.07.2017 को मण्डी समिति द्वारा इन दुकानों का आबंटन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शिकायत ए सी बी को प्राप्त हो गयी थी। उसके बाद में विभाग ने भी इसकी जांच कमेटी बैठायी। इसका प्रकरण चलता रहा। 34 दुकानों का आबंटन उस टाइम कर दिया गया था। 43 दुकानें, जिनकी जांच में कुछ कमियां पायी गयी थीं, वे निरस्त कर दी गयी थीं। उसके बाद में जो आबंटी लोग थे, वे कोर्ट में चले गये।

अभी हाल ही में उन्होंने दुबारा दिनांक 2021 में रिव्यू लगाया। इससे पहले ए सी डी का फैसला भी उनके पक्ष में आ गया था। उन्होंने बोला था कि यदि आप हमें कंसीडर कर लेते हैं तो हम कोर्ट से हमारा केस वापस ले लेंगे। इस बात को लेकर 10.10.2022 को डायरेक्ट्रेट स्तर पर निर्णय हो गया था कि इन्हें ये दुकानें आबंटित कर दी जाएंगी। अभी चार-पांच महीने से यह फैसला पैंडिंग है। मण्डी स्तर पर इसका अनुमोदन हो गया, डायरेक्टर स्तर पर अनुमोदन हो गया। सरकारी स्तर पर यह पैंडिंग है। आने वाले एक महीने में हम आबंटियों को दुकानें आबंटित कर देंगे।

श्री सभापति: पैंडिंग रहने का क्या कारण है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्री महोदय, इतना समय हो चुका और उसके बाद भी इतने टाइम से फाइल पैंडिंग है। आप आज इस पर घोषणा करें कि इतने दिन में हम कर लेंगे।

श्री सभापति: यह पैंडिंग क्यों चल रहा है? आपने कुछ को कर दिया और कुछ पैंडिंग हैं, तो क्यों हैं पैंडिंग?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जैसे मैंने बताया कि कुछ दुकानों की कम्पलेंट ए सी डी में हो गई थी, जिसके कारण से उन दुकानों को

(श्री मुरारी लाल)

पैंडिंग कर दिया गया था। अब सारी जाचें कम्प्लीट हो चुकी हैं और अतिशीघ्र एक माह में इनका आबंटन कर देंगे और मण्डी को भी चालू कर देंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ए सी डी में भी पक्ष में निर्णय हो चुका है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मेरा इसमें स्पष्ट निवेदन यह है कि जो आपने पैंडिंग रखे हैं उनमें खासतौर से डिसेबल लोग हैं, इसलिए मेहरबानी करके इसको जल्दी करवायें। डिसेबल लोगों को हम यदि को-आपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): बिलकुल एक माह में कर देंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): थैंक यू।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी उप खण्ड में खेल स्टेडियम की स्थापना

143. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी एवं सैपऊ में कोई खेल स्टेडियम नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उप खण्ड बाड़ी में खेल स्टेडियम स्वीकृत कर उक्त को खेल अभ्यास हेतु विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): जी हां। वर्तमान में उप खण्ड बाडी में खेल स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सी एस आर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जायेगी।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

माननीय सभापति महोदय, यह जवाब इस बजट से पूर्व का है। मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि 2023-24 का जो बजट यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने 'बचत-राहत-बढ़त' की राह पर दिया और शानदार, दमदार, धुआंधार और जोरदार बजट दिया है, उसमें बिन्दु संख्या 46 पर आपके बाड़ी और सैपऊ दोनों स्टेडियम की घोषणा कर दी गयी है। जिस बजट से अद्भुत और ऐतिहासिक जनता का दिल प्रसन्न है, आपको भी प्रसन्न कर दिया गया है। दो स्टेडियम आपको दे दिये गये हैं।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह तो ठीक है कि बजट में इन्होंने घोषणा कर दी, धन्यवाद भी दूंगा, पर मैं मंत्री जी से एक चीज कह रहा हूं कि इनके काम कब से चालू हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो कि घोषणा होकर ही रह जाए।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक तो इनका समय पर काम चालू हो जाए, दूसरा बजट में आपके लिए और मुख्य मंत्री जी के लिए धन्यवाद कि उन्होंने घोषणा की।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभागीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है और तुरन्त प्रभाव से जल्द से जल्द इस काम को शुरू कराया जायेगा।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्रीविजयनगर (रायसिंहनगर) में महाविद्यालय की स्थापना

144. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजकीय महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के श्रीविजयनगर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी नहीं। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में रायसिंहनगर के डाबला पंचायत में बुड्ढा जोहड़

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुणों के आधार पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने इस वर्ष 2023-24 के बजट में रायसिंहनगर के डाबला पंचायत में बुड्ढा जोहड़ में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, उसके लिए क्या आपने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है? इसका भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और छात्रों का इस कालेज में कब तक प्रवेश शुरू हो जाएगा?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जल्दी ही नया जो सत्र आएगा उसमें यह महाविद्यालय कहीं पर भी, किराये पर या किसी धर्मशाला में शुरू कर दिया जाएगा और जमीन चिह्नित करने के आदेश दे दिये गये हैं। किराये पर भवन लेकर हमने सारे शुरू किये हैं। पहले भी 87 के 87 महाविद्यालय हमने शुरू कर दिये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसको कहते हैं सच बोलना। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): भवन तो घोषणा के बाद ही बनते हैं और आपकी सरकार के टाइम के महाविद्यालय हमने बनाकर दिये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान) श्री बलवीर सिंह लूथरा। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। प्लीज, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, डाबला में बुड्ढा जोहड़ में ऐसी कोई बड़ी धर्मशाला नहीं है जहां आप कालेज शुरू कर सको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल की अपनी एक गम्भीरता होती है। माननीय सदस्य कोई बात पूछना चाह रहे हैं, मंत्री बताना चाह रहे हैं तो फिर इतनी उत्तेजना किस बात की? थोड़ी गम्भीरता बरतें। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, नम्बर दो, आपने सभी उप खण्ड मुख्यालयों में कालेज खोलने की घोषणा की थी। श्रीविजयनगर उप खण्ड मुख्यालय है पर आपने वहां कालेज खोलने की घोषणा नहीं की है, तो क्या सरकार अपने वायदे से मुकर रही है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): ऐसा नहीं है। श्रीविजयनगर अभी पिछले दिनों ही उप खण्ड खुला है और इसका परीक्षण करके यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही करवायी जाएगी।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): श्रीविजयनगर उप खण्ड कार्यालय पिछले दिनों नहीं, बीस साल हो गये श्रीविजयनगर में उप खण्ड कार्यालय चलते हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): श्रीविजनगर उप खण्ड कार्यालय की ही बात कर रहे हैं कि तब नहीं खुले थे, पर जब भी खोलेंगे तो यहां भी खोलेंगे।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में श्रमिकों को देय अनुदान

145. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिक कार्ड योजना में श्रमिकों व उनके परिजनों को लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवायी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में विगत चार वर्षों में श्रमिक कार्ड योजना में कितने कार्ड बनाये गये व कितने श्रमिकों को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी सहायता व अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई तथा उक्त के कितने आवेदन लम्बित हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या सरकार श्रमिकों के उक्त लम्बित आवेदनों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को मण्डल द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है। मण्डल द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु लागू योजनाओं में देय सहायता राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में विगत 4 वर्षों में पंजीकृत श्रमिकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। विगत 4 वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में योजनावार एवं वर्षवार स्वीकृत आवेदन तथा स्वीकृत की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। लम्बित योजना आवेदनों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पात्र श्रमिकों का माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में सत्यापन कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है एवं चरणबद्ध भुगतान प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कितने आवेदन प्राप्त हुए और प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन क्यों निरस्त कर दिये गये? कारण बतायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): यह परिशिष्ट-2 में स्वीकृति का दे रखा है और उसके बाद में 4 वर्षों का परिशिष्ट-3 में दे रखा है। 2019 में 712 आवेदन स्वीकृत हुए 2020 में 1061, 2021 में 569 और 2022 में 254 स्वीकृत हुए। टोटल चार साल में 2596 स्वीकृत हुए हैं और टोटल सहायता 2.62 करोड़ की दी गई है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने यह पूछा था कि कितने निरस्त हुए? श्रेणीवार बतायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में 2019 से चार वर्षों में 7,210 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 5,226 स्वीकृत हुए हैं बाकी निरस्त हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये 2 हजार निरस्त क्यों हुए हैं और आवेदन प्राप्त होने पर कितने समय में उसका सत्यापन कर लेना चाहिए? यह भी बतायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): उनमें कमियां थीं, उसके कारण से निरस्त हुए हैं। कमियां हैं तभी तो निरस्त होंगे न? कमी होगी तभी निरस्त होंगे?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कारण क्या है? मैंने कारण पूछे हैं। वही तो पूछ रहा हूं कि आप कमी बता रहे हैं तो किन कमियों के कारण से निरस्त हुए हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): या तो फार्म सही भरा हुआ नहीं था, या काट-छांट थी, स्पष्ट दिखता नहीं था इसलिए उन्होंने ऑनलाइन वापस किया है। वापस उन्होंने जवाब नहीं भेजा तब जाकर निरस्त हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि कैंसिल क्यों हुए हैं? निश्चित रूप से यह गम्भीर मामला है, श्रमिकों के कल्याण के लिए यह है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): फार्म ऑनलाइन भरे जाते हैं।

श्री सभापति: ऐसे मामले जो लम्बित हैं, उनका त्वरित गति से निस्तारण करें और जो कोई कमियां हैं उनमें उन श्रमिकों को बुलाकर पूरा करें। जो भी कमियां हैं उन्हें आप पूरा करवायें। श्री अविनाश।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): पूरा कर लेंगे, साहब।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आवेदन का सत्यापन कितने दिन में कर लेना चाहिए क्योंकि चार-चार साल के भी पैंडिंग हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री अविनाश।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): कोई स्पष्ट तारीख नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि इस तारीख तक पास किये जाएंगे। जैसे ही कमियां पूरी होंगी, पास कर देंगे।

श्री सभापति: विराजिये, श्री अविनाश। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आपकी भावना से मैं सहमत हूं और आसन ने यह निर्देश दे दिये कि जो भी बाकी हैं उनका त्वरित गति से निस्तारण करें, जो कमियां हैं उन्हें पूरा करवायें। और क्या बाकी रह गया? प्लीज, श्री अविनाश। (व्यवधान)

जैतारण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरण

146. श्री अविनाश (जैतारण): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 से 2021 तक अनेकों राज्य कर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी मामलों में जांच हेतु विभागीय अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यूरो द्वारा उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 से 2021 तक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार 998 राज्य कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। जिनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के लिए मनाही की गई है, का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) ब्यूरो द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 03 अभियोग ट्रेप सम्बन्धी निम्न कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं-

1. श्री दिलीप कुमार धाकड़, तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, बर, जिला पाली।

2. श्री महेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जैतारण, जिला पाली।

3. श्री मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अमरपुरा, तहसील जैतारण, जिला पाली।

(3) उक्त में से श्री दिलीप कुमार धाकड़, तकनीकी सहायक एवं महेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। श्री मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अमरपुरा, तहसील जैतारण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाना शेष है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने परिशिष्ट 'क' में उत्तर दिया कि 2019-20 और 2021 में कुल 998 के करीब ए सी बी के मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से 811 में अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 59 प्रकरणों में मना कर दिया गया है और वर्तमान में 128 प्रकरण लम्बित हैं। 128 प्रकरण लम्बित रहने के क्या कारण हैं? इनके खिलाफ कब तक अभियोजन स्वीकृति मिल जायेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिए, 2019 से लेकर 2021 तक कुल मिलाकर 1015 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से 998 के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये हैं। उसमें से जैसा मैंने आपको बताया कि 811 मामलों में तो अभियोजन स्वीकृति दे दी गई और 59 में मना कर दिया गया और 128 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं, जो अभी भी लम्बित हैं। शेष 17 मामले ऐसे हैं, जिनमें 3 प्रकरण तो 2019 के हैं, 01 प्रकरण 2020 का है और 13 प्रकरण 2021 के हैं। इनमें अनुसंधान अभी जारी है। अनुसंधान जारी होने के दौरान मामला लम्बित ही रहेगा और कैसे रहेगा?

दूसरी बात, आपने मुकेश कुमार के लिए पूछा है, उसका चालान 17 फरवरी, 2023 को पेश कर दिया जायेगा।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, ये जो राज्य के कर्मचारी हैं, ए सी बी में ट्रैप होने के बाद 48 घंटे या उससे ज्यादा समय तक जेल में रहते हैं। राज्य सरकार का नियम बना हुआ है कि कोई राज्य का कार्मिक या प्रतिनिधि ए सी बी में ट्रैप होता है और 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या इन सभी कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था? वर्तमान में ये क्या किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने ये सवाल न तो पूछा, अब आप पूछ रहे हैं तो वह फिगर मेरे पास नहीं है। मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन जहां तक ट्रैप का सवाल है, ट्रैप वाला आदमी फौरन गिरफ्तार होता है। दो आदमी गिरफ्तार होते हैं, एक तो जिसके पास आय से अधिक सम्पत्ति हो और दूसरा ट्रैप हुआ हो। उनके खिलाफ एफ आई आर के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
होती है। वे सीधे गिरफ्तार हो जायेंगे। बाकी सब मामलों में 2018 के बाद में इस एक्ट में जो आपका संशोधन आया है, उसके तहत तो एफ आई आर दर्ज करने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी जाती है। ये लोग अब सस्पेंड हैं या नहीं हैं, इसकी सूचना तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो उत्तर दिया..

श्री सभापति: जो आपने पूछा उसका सारा जवाब दे दिया है। प्लीज, अब आप विराजिए। श्री सुरेश टाक। अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

किशनगढ़ में आर्ट गैलरी की स्थापना

147. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की बणी-ठणी चित्रकला शैली को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा विगत वर्ष यहां आर्ट गैलरी खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावानुसार आर्ट गैलरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जी हां। वर्तमान में किशनगढ में आर्ट गैलरी खोलने का कोई विचार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्णय गुणावगुण व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर लिया जाता है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि किशनगढ़ शैली की चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है। सरकार के पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में विश्व प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली की चित्रकारी दम तोड़ रही है। साथ ही, चित्रकारों की कला, कलम, रंग फीके पड़ रहे हैं। क्या सरकार दिये गये उत्तर पर पुनर्विचार कर इस विश्व प्रसिद्ध बणी-ठणी शैली को जीवन देने के लिए इस पर उचित निर्णय लेने और इन चित्रकारों व इनकी आने वाली पीढ़ी को इस कला से विमुख होने से बचाने का प्रयास करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, समय-समय पर अलग-अलग सम्भागों में ललित कला अकादमी द्वारा कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में जवाहर कला केन्द्र में कला मेला लगाया गया था। उसमें पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं, उन सब जगहों से ईवन गांवों से भी लोग आये थे, उन्होंने अपनी आर्ट का प्रदर्शन किया था। वहां से सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की कलाकृतियां खरीदी भी गयीं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पालिसी आयेगी तब तो विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई पालिसी नहीं है, जिसके अन्तर्गत किया जाए। कोटा में एक बार जरूर भुवनेशजी चतुर्वेदी ने 24.10.2001 को वहां पर एक आर्ट गैलरी बनाई थी। वह अपने सांसद कोटे से बनाई थी।

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक मिनट। दिनांक 24.10.2001 को सांसद कोटे से भुवनेशजी चतुर्वेदी ने बनाई थी और बनाने के बाद उसमें तीन कला दीर्घाएं, दो प्रशासनिक कक्ष, रसोई घर, स्टोर, मुख्तार-ए-खास, थियेटर ये सब उन्होंने बनाये थे। उसके बाद ललित कला अकादमी उसके रिकरिंग एक्सपेंडिचर 4 लाख 75 हजार और 52 हजार रुपये पानी और बिजली का खर्च करके उसका संचालन कर रही है। यदि आप स्वायत्त शासन से सम्बन्धित संस्थाओं से कोई भवन वगैरह का प्रस्ताव बनाकर देंगे तो हम उस पर आगे विचार कर लेंगे।

प्रश्न संख्या 148

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर एम आई ए की औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे पानी से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम

149. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि एम.आई.ए., अलवर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से तहसील रामगढ़ के ग्रामों में प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की रोकथाम करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): एम.आई.ए. अलवर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा निस्त्रावित उच्छिष्ट से तहसील रामगढ़ के गांवों में प्रदूषण फैलने की कोई अधिकृत सूचना सरकार को नहीं है। तहसील रामगढ़ में ग्राम अग्यारा के पास हनुमान मंदिर के समीप, ग्राम बगड मेव व ग्राम बगड राजपूत से भू-जल के नमूने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक 6 माह में एकत्रित किये जाते हैं। नवीनतम नमूने दिनांक 10.10.2022 को एकत्रित किये गये थे। उक्त तीनों भू-जल स्रोतों के नमूने टोटल कालीफार्म/फीकल कालीफार्म के मानकों को छोड़कर बी.आई.एस. के ड्रिंकिंग मानकों के अनुरूप हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। भू-जल में कालीफार्म की उपस्थिति सीवेज जनित प्रदूषण को दर्शाती है। यह औद्योगिक उच्छिष्ट से होने वाले भू-जल प्रदूषण का संकेतक नहीं है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर एम.आई.ए., अलवर में स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर प्रदूषण के सम्बन्ध में जांच की जाती है। उद्योगों से निष्कासित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नहीं पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जिसमें उद्योगों को बन्द कराना, विद्युत एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करना शामिल है।

विगत एक वर्ष में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पांच उद्योगों को उच्छिष्ट परिसर के बाहर निस्त्रावित करते हुए पाया गया। उनके विरुद्ध राज्य मण्डल द्वारा जल अधिनियम की धारा 33ए के अन्तर्गत उद्योग बन्द कराने तथा विद्युत व जल सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

(समय: 12.00 बजे)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, शुरू में यह कहा गया है कि सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अगर सूचना ही नहीं है तो आप हर छह महीने में सैम्पलिंग कर रहे हैं उसका पूरा एक डाटा आप रख रहे हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है?

दूसरा, समय-समय पर सालों से आन्दोलन हुए हैं, ज्ञापन दिये हैं एस डी एम को। जिले की मीटिंग में हमारे प्रभारी मंत्री हैं बी.डी. कल्ला जी, इनको भी ज्ञापन दिया गया है, उसका जवाब पॉल्यूशन अधिकारी ने दिया है तो यह कैसे हो सकता है कि सूचना नहीं है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सभापति महोदय, यह परिशिष्ट 'अ' में जो जांच की गयी है, नमूने दिये गये हैं और उसमें साफ बताया गया है कि उक्त सारणी के अनुसार केवल फीकल कालीफोर्म ही मानकों से अधिक है जो मुख्य रूप से घरेलू उच्छिष्ट के कारण होता है न कि औद्योगिक उच्छिष्ट के कारण होता है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, वहां क्लोरिन का लेवल इतना हाई है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, खास तौर से विन्टर्स में, और मंत्री जी कह रहे हैं कि नोर्म्स के खिलाफ कुछ है ही नहीं। प्लस, आपने जो रिपोर्ट दी है जिसमें क्रोमियम भी है, लैड भी है, कैडमियम भी है तो इनका क्राइटेरिया क्या है? कितने लेवल तक होना चाहिये? क्योंकि यह रिपोर्ट तो दर्शाती है कि प्रजेन्स तो है, लेकिन उसको कम्पेयर किससे करेंगे? थोड़ी-सी लैड की है, थोड़ी-सी भी मात्रा तो बहुत डेंजरस होती है और कालीफोर्म को तो आपने माना है तो कॉलीफोर्म से तो पेट की इतनी बीमारियां हो रही हैं तो इसका पैमाना क्या है सभापति महोदय? यह तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या। माननीय मंत्री महोदय, जल प्रदूषित होने का गम्भीर मामला है। विशेष रूप से आप इसमें कोई कार्यवाही करके और यह एंश्योर करें कि इस तरह के जल प्रदूषण नहीं हों।

प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से अक्का लॉजिस्टिक कम्पनी द्वारा थर्मल पावर प्लांट एवं सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा व कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़ में कोल हैंडलिंग एवं अन्य कार्यों में की जा रही अनियमितता व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नरेना नगरपालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में छह माह के कारावास में रहने के उपरान्त भी पद पर बने रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री सभापति)

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर के गांव मुंडासर निवासी विवाहित महिला की हत्या कर शव गायब करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर में 'प्रशासन-शहरों-के-संग' अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से बांटे गये गलत व जाली पट्टों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में विधायक कोष के कार्यों की स्वीकृति हेतु नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में घुमन्तू, घुमक्कड़ व विमुक्त परिवारों को राजकीय आदेशोपरान्त भी निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सहकारी समितियों के चुनावों में प्रशासन की मिलीभगत से हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की आबंटित राशि को कोटा जिले में स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों द्वारा 1200 वर्ग गज तक के पट्टे दिए जाने का नियम लागू करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम में अनुसूचित क्षेत्र की विज्ञापित कामर्शियल असिस्टेंट-II की भर्ती में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर विस्तार के मध्यनजर कोटा विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री सभापति)

(12) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में शराब की मॉडल शाप नीति के अन्तर्गत आबंटन के पश्चात् शर्तों में फेरबदल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में।

(14) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं का पुनर्निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 2017 में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र, सांगानेर में बरसाती एवं दूषित जल भराव की समुचित निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(18) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री अविनाश, श्री छगनसिंह, श्री जगसी राम, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री जोराराम कुमावत तथा श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से मारवाड़ संभाग में बेमौसम वर्षा से ईंटों का आवा-कजावा में हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री संदीप शर्मा, श्री संयम लोढ़ा, श्री अशोक लाहोटी एवं मूल प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र सिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री सभापति)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर के दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में वन भूमि पर वर्षों से बसे परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम धाकड़खेड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में लम्बे समय से पड़े बी.एच.सी. पाउडर का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुंडावर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में बीकानेर-रतनगढ़ रेलखण्ड मार्ग पर अण्डरब्रिजों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से नगर परिषद, पाली में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के पशु चिकित्सा उप केन्द्र बौंली में सूअरों के टीकाकरण की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत व्यापक उपयोग की औषधियों को योजना से बाहर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने एवं जल भराव से प्रभावितों का पुनर्वास करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में शहरी निकायों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के आवासीय एवं व्यावसायिक रूपान्तरण करने के अधिकार देने के सम्बन्ध में।

(श्री सभापति)

(10) श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सिंचाई विभाग के अधीन माही कडाना प्रोजेक्ट की भूमि गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित करने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से राणा पूंजा भील छात्रावास, उदयपुर के संचालन का अधिकार हस्तान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सेम से प्रभावित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की रामदेव कालोनी के निवासियों को नगर परिषद् द्वारा पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से नगर परिषद्, पाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नारायण बेनीवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नागौर के गांव मुंडासर निवासी विवाहित महिला की हत्या

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सदन का ध्यान नागौर विधान सभा क्षेत्र के मुंडासर निवासी विवाहित महिला की हत्या कर शव गायब करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आकर्षित करवाना चाहता हूं। आज से करीब 23-24 दिन पहले गुड्डी नाम की एक महिला जो पीहर जाने का कहकर गयी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं राजस्थान पत्रिका में छपी इस

(श्री नारायण बेनीवाल)

खबर की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराऊंगा क्योंकि बजट सेशन है और कानून-व्यवस्था पर भी लम्बी-चौड़ी बातें बजट में लिखी गई हैं। 'कुएं से खाली हाथ निकले जवान शव को लेकर सस्पेंस बरकरार।'

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊंगा कि वहां की पुलिस ने सारे प्रयास कर लिए। 24 दिन के बाद भी आरोपी हिरासत में है, लेकिन 24 दिन बाद भी उस आरोपी से पुलिस यह नहीं उगलवा पाई कि उसने उस विवाहिता का क्या किया। वह जिन्दा है या मर गई है। कहीं ऐसा हश्र न हो कि इस तरह से, इसकी कोई एक हड्डी जरूर मिली है और अखबारों में बहुत बड़ी खबर छपी है कि यह काण्ड जो नागौर का है यह दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा भी हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस मामले में नार्को टेस्ट जैसी नवीनतम जो भी विधियां हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सहारा लेकर इस मामले की तह तक जाकर अपराधियों को और जितने संलिप्त अपराधी हैं उन सब को पकड़कर इस परिवार को न्याय दिलवायें। धन्यवाद।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर हाउस इस तरह से चलेगा, उधर देखो संसदीय कार्य मंत्री को, आप इनको प्रताड़ित तो करो, डांटो तो सही आप ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, ऐसा है कि किसको क्या काम करना है, देना है, चीफ व्हिप यह तो आकर कह ही सकते हैं, यह इनकी ड्यूटी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल। (व्यवधान) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के अंतर्गत (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, क्या हो रहा है यह? माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज, फ्री फोर आल ऑवर नहीं है। सिर्फ चन्द्रकान्ता मेघवाल जी बोलेंगी, माननीय सदस्य।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य, सहयोग करें। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की आबंटित राशि का अन्यत्र हस्तांतरण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के अंतर्गत मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डी.एम.एफ.टी. रूल, 2016 के तहत प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें सभी जिलों में स्थित हमारे प्रधान खनिज से होने वाली रायल्टी राशि का फंड 30 प्रतिशत और अप्रधान का 10 प्रतिशत, सीधा-सीधा हम उस एरिया में, उस जिले में जमा करवाते हैं और उसका विकास होता है, यह हम सब जानते हैं। इस राशि का उपयोग नियम 4 के अनुसार हम देखें तो जिस जिले की राशि है, उसी में इसका पैसा खर्च किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ इस बात को यहां बोल रही हूं कि तीन बार राजस्थान विधान सभा में इस बात को उठाने के बावजूद अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहां तक कि मैं पिछले 4-5 साल से देख रही हूं, बूंदी जिले की डी.एम.एफ.टी. की राशि, जिसमें मैं कहूंगी कि कार्यालय खनिज अभियंता, कोटा के क्षेत्राधिकार में बूंदी जिले की इंद्रगढ़, केशोरायपाटन एवं नैनवा तहसील की ग्राम पंचायतें आतरदा, तलवास, करवर, मोडसास, खजूरी आदि भी इस कार्यालय के अंतर्गत आती हैं, बूंदी कलेक्टर महोदय द्वारा लगातार बार-बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक कोटा माइनिंग अधिकारियों का इस बात पर ध्यान तक नहीं गया कि हमारे केशोरायपाटन की राशि कहां जा रही है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब नियम बना रखा है, अगर जिले की सीमा किसी एरिया में पड़ती है, लीज में पड़ती है तो जिस एरिया में वह ज्यादा लीज है, उस जिले में जानी चाहिये। उदयपुर माइनिंग विभाग को भी हमारे कोटा वाले माइनिंग अधिकारियों ने लिखा और उन्होंने लिखा कि रेमिटर की जानकारी दी जाये। आपके बैंक अकाउंट में एक कालम होता है कि रेमिटर का नाम प्रदर्शित किया जाये, लेकिन यह कहकर गुमराह करना कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रेमिटर का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा, मेरे एरिया की राशि को अन्यत्र खर्च करना, निश्चित तौर पर यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता का हक मारा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए हमारे केशोरायपाटन, इंद्रगढ़ और करवर की हमारी पंचायतों की लीज राशि को उसी एरिया में खर्च किया जाये, क्योंकि डी.एम.एफ.टी. की राशि से जो मालियों की बाड़ी हमारी पुलिया बनी हुई थी, सड़कें बनी हुई थीं, वे टूट चुकी हैं, उनको भी रिपेयर करना है।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा पुन: निवेदन है कि उस राशि को हमसे प्रस्ताव लेकर बूंदी जिले में ही खर्च किया जाये और तुरंत प्रभाव से कोटा जिले से उस राशि को वहां पर ट्रांसफर किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जीरो ऑवर चल रहा है, आफिसर गैलेरी की तरफ आप निगाह उठाएं, एक अधिकारी नहीं। इस विधान सभा को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा। सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हो, जीरो ऑवर में माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। एक आदमी नहीं होना, कितनी बुरी बात है यह। कोई नोडल आफिसर नहीं।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज, प्लीज, सहयोग करें। ...(व्यवधान)

कोटा विकास प्राधिकरण का गठन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। कोटा शहर राजस्थान का सबसे आगे बढ़ता हुआ शहर है और आज कोटा शहर तीसरे नंबर का शहर बन गया है जो तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दो नगर निगम, जिनमें 150 वार्ड हैं। लगभग 12 लाख से भी अधिक आबादी वाली शैक्षणिक नगरी कोटा में पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा की अपार संभावनाएं हैं। कोटा शहर प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले अधिक समृद्ध शहर है। दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग तथा दिल्ली से मुम्बई को जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग कोटा से निकल रहा है। मां चम्बल नदी का आशीर्वाद, अकूत खनिज सम्पदा, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन कोटा शहर में प्रचुर मात्रा में हैं।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, कोटा में यू.आई.टी. का बजट लगभग 1300 करोड़ है, जो जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण से काफी अधिक है। पिछली बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोटा विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने 60 दिन की अपनी कार्ययोजना में कोटा यू.आई.टी. को के.डी.ए. बनाने के प्रोजेक्ट में भी शामिल किया था, परंतु पूरा साल खतम होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा की बढ़ती जनसंख्या व तेजी के साथ बढ़ता क्षेत्रफल शहर के समग्र, सर्वांगीण विकास हेतु कोटा यू.आई.टी. को के.डी.ए. में परिवर्तित करना निहायत और नितांत आवश्यक हो चुका है। वर्तमान में कोटा का क्षेत्रफल 86 हजार करोड़...

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं तो दो मिनट भी नहीं बोला हूं।

श्री सभापति: सरकार के संज्ञान में ला दिया, अब विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरी मुख्य बात तो कह लूं।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें आप। प्लीज, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, विराजिए। कुछ सीख लीजिए, अच्छा रहेगा, विराजिए आप। विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ अच्छी परम्पराएं सीख लेंगे तो...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, थोड़ा बहुत अनुशासित करें। जब दो मिनट बोलने का समय दिया गया है और बोल लिए और अब लगातार इंटरवीन कर रहे हैं ...(व्यवधान) प्लीज विराजिए। मैं अलाउ नहीं करता। विराजिए।

शराब की मॉडल शाप नीति के तहत आबंटन पश्चात् शर्तों में फेरबदल

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आबकारी नीति लाने के बाद कतिपय व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो संशोधन लाकर राजस्थान की जनता के, राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान किया गया, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो आबकारी नीति 2022-23 और 2023-24 लाई गई, उसमें नवीनीकरण की प्रक्रिया वार्षिक गारंटी राशि या वास्तविक उठाव की राशि पर निर्धारित की गई। माननीय सभापति महोदय, एक करोड़ की दुकान पर 12 परसेंट की वृद्धि, 1-2 करोड़ की दुकान पर 11 परसेंट की वृद्धि, 2-3 करोड़ की दुकान पर 10 परसेंट वृद्धि, 3-4 करोड़ की दुकान पर 9 परसेंट वृद्धि, 4-5 करोड़ की दुकान पर 8 परसेंट वृद्धि और 5 करोड़ या उससे ऊपर की दुकान पर 7 परसेंट वृद्धि के आधार पर आबकारी नीति में दुकान देना तय किया गया। माननीय सभापति महोदय, इसी आबकारी नीति में मॉडल शाप का भी प्रावधान किया गया और बहुत साफ उल्लेख किया गया कि मॉडल शाप कहां पर होगी। उसमें मॉडल शाप का एयरकंडीशन होना, शापिंग मॉल में होना या कामर्शियल कामप्लेक्स जो यू.आई.टी. या स्थानीय निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, उसमें वह मॉडल शाप लगाई जा सकती थी। माननीय सभापति महोदय, मजे की बात यह है कि इन दुकानों के लिए तो गारंटी राशि रखी गई और उन मॉडल शाप के लिए किसी तरह की कोई गारंटी राशि नहीं रखी गई, सिर्फ लाइसेंस फीस के आधार पर वह मॉडल शाप दी गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसी 44 दुकानें राजस्थान में प्रस्तावित की गईं। हर जिला मुख्यालय पर एक एवं बड़े शहरों के अन्दर जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन सब में इनकी संख्या ज्यादा रखी गयी। माननीय सभापति महोदय, यह आबकारी नीति आने के बाद मॉडल शाप के अन्दर एक्साइज कमिश्नर ने एक संशोधन निकाल दिया कि मॉडल शाप अप्रूव कामर्शियल कामप्लेक्स और शापिंग मॉल के अलावा जो कामर्शियल रोड हैं, उन पर भी मॉडल शाप खोली जा सकेगी। माननीय सभापति महोदय, उसका नतीजा क्या हुआ, आबकारी मंत्री खुद जब सिरोही जिले के दौरे पर आये, सारे शराब के दुकानदार उनसे आकर मिले, जिन्होंने गारन्टी के आधार दुकानें ली थीं। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, इनका समय हो गया है, यह क्या अन्याय है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 10 करोड़ रुपये की गारन्टी के आधार पर जिसने दुकान ली है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री अशोक लाहोटी ...(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, यह गलत बात है।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा का सदन कूप में प्रवेश)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप चेयर को गाइड नहीं कर सकते हैं। आप इनको समझाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। माननीय उप नेता महोदय, मुझे माननीय सदस्य का नाम लेना पड़ेगा। (व्यवधान) प्लीज, अपने स्थान पर जाइये। आप आसन को डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप अपने स्थान पर जाइये। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप सदन को छोड़कर चले जाइये। माननीय उप नेता महोदय, मैं अपेक्षा रखता हूं कि जो नये माननीय सदस्य आये हैं, उन्हें कहें कि सदन में गंभीरता बरतें। यह कौनसा तरीका है? शान्त रहें। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के अति विशेष नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप मुझे अपना पूरा करने दीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। एक मिनट विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इनको बिठाइये, इनका समय पूरा हो गया है।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये। आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गयी कि आप दो-दो मिनट में अपनी बात रखेंगे। आपने जो कुछ कहा है, वह सरकार के संज्ञान में भी आ गया और आसन के संज्ञान में भी आ गया।

(श्री सभापति)

कृपया अपनी बात को समाप्त करें। आपने समाप्त कर दिया। मैंने दूसरा नाम बुला लिया। प्लीज इंटरवीन नहीं करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि प्लीज सहयोग करें। प्लीज विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या बात हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इनको पहले बिठायें। इनको आपने विशेष अधिकार दे रखा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, सहयोग करें। विराजिये। सदन के काफी माननीय वक्ता बोलने वाले हैं। यदि आप यही समझ रहे हैं कि आपको नहीं बोलना है तो मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आपने जो लिस्ट दी हुई है, इससे आप वंचित रह जायेंगे। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बात में ही अपनी बात रखें। सदन का हर माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। नये-नये आये हैं, कुछ सीख लेंगे। (व्यवधान) प्लीज, आप विराजिये। पूरा राजस्थान आपको यू-ट्यूब पर देख रहा है और आपकी गंभीरता को भी महसूस कर रहा है। सदन को यदि आप गंभीरता से लेंगे तो आपके प्रति भी लोगों में एक गंभीर भाव बनेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, विधान सभा के अति विशेष नियम 50 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे बहुत अपेक्षा रखता हूं। आप बहुत वरिष्ठ हैं। आसन पर इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। इसे कार्यवाही से निकालें। आप आसन को अंगुली दिखाकर ऐसे करेंगे कि मैं गंभीरता बरतूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आप इनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: आप प्लीज, विराजिये। मैं बोलने नहीं देता? विराजिये। माननीय सदस्य, आप मुझे बाध्य मत कीजिये। प्लीज, विराजिये। माननीय उप नेता महोदय, मुझे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। प्लीज, आप विराजिये। आसन को उसके नियमों के बारे में पता है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मुझे तो अपना स्थगन रखने दें।

श्री सभापति: मिस्टर लाहोटी, एक मिनट। क्या यह सदन की गंभीरता है? माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में यह निर्णय हुआ कि जो-जो भी स्थगन प्रस्ताव हैं, उन पर निम्न माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जायेगा। माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात रख रहे हैं। सदन में बात रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपने जो कुछ भी कहा है, सरकार के संज्ञान में आ गया है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, वह सरकार के संज्ञान में है। आपने अपनी बात रख दी। बार-बार आसन को प्रेशराइज करना, डिक्टेट करना कि आपको इतना समय देना पड़ेगा, आसन आपसे असहमति व्यक्त करता है।

आप सभी से यह अपेक्षा रखता है कि सदन की गरिमा बनी रहेगी तो आप यकीन मानिये, जिन प्रयत्नों से और जिन कोशिशों के बाद, इस सदन में साढ़े सात करोड़ लोगों के बीच आप लोग मात्र दो सौ लोग हैं। राजस्थान आपसे यह अपेक्षा रखता है कि सदन में गंभीरता बरतें और आपकी यह गंभीरता आपके जीवन की एक आभूषण बनेगी। मैं भी सदन का एक बहुत पुराना सदस्य हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है, वह इस सदन से सीखा है। अपने आपको मानसिक रूप से इस बात के लिए बाध्य कीजिये कि सदन में जब आप प्रवेश करेंगे तो पूरी तरह से गरिमा का व्यवहार बनाकर रखेंगे। एक-दूसरे के प्रति शालीनता बरतेंगे और आसन के प्रति आपका जो डिस्कर्टियस बिहेवियर है, प्रताप सिंह जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम बहुत पुराने

(श्री सभापति)

साथी रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आसन की ओर अंगुली करके इस तरह की अभद्र टिप्पणी कतई शोभनीय नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भले ही मैं इसको बर्दाश्त करूं, लेकिन आसन की अपनी गरिमा है। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आसन की आज्ञा सर्वोपरि है। सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को यह तकलीफ थी कि वे बस अपनी बात को कन्क्लूड कर लेते। बस इतनी-सी बात थी। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य भी कन्क्लूड नहीं कर पाये। कोई बात नहीं, आपने आज्ञा दे दी। सभापति महोदय, आप गुस्से में बहुत ही हसीन लगते हैं।

श्री सभापति: दो-दो मिनट का समय दिया गया है। वक्ता के लिए यह जरूरी है कि वे दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैंने संदीप जी को भी दो मिनट से ज्यादा का समय दिया है। संयम जी को भी मैंने दो मिनट से ज्यादा का समय दिया है। यदि फ्री फोर आल कर दूंगा कि जितना मर्जी हो, उतना बोलें, मुझे कोई असुविधा नहीं है। आप यह तय कर लीजिये कि आज की कार्यवाही में सिर्फ स्थगन प्रस्तावों पर ही चर्चा होगी। सायंकाल 5 बजे तक का आपके लिए समय निर्धारित है। आप पांच बजे तक फ्री फोर आल डिबेट कीजिये। मेरे पास आपने जो स्थगन प्रस्ताव पर नाम दिये हैं, उन्हीं पर मैं आप सबका वक्तव्य करा देता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उप नेता महोदय, जो यहां पर मौजूद हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि एक बार ऐसा भी वाकया हो चुका है, जब निरंजन नाथ आचार्य डिप्टी स्पीकर के बतौर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने भैरोंसिंह जी से मना किया कि आप बोल चुके, अब आप नहीं बोलेंगे। भैरोंसिंह जी उस वक्त विपक्ष में थे। भैरोंसिंह जी ने गुस्से में आकर यह कह दिया Quit the Chair, छोड़कर चले जाओ। उस पर मोहन लाल सुखाड़िया जी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा। आप देखिये कि भैरोंसिंह जी की महानता थी कि उन्होंने फौरन उस बात के लिए सदन के सामने माफी मांग ली। चेयर के आदेश की अवहेलना करना, चेयर के आदेश को नहीं मानना, यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। आपका वाक्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यह तय करना चेयर का काम होता है। चेयर आपको दो मिनट के लिए अलाउ करता है। दो मिनट में आप अपनी पूरी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बात कह चुके हैं। कहने के बाद भी आप आगे बोलते जा रहे हैं तो चेयर के आदेश को मानना चाहिए।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, इनको जरा समझाइये। यह समझाइये कि चेयर को चेयर ही समझें। वहां का आदेश आखिरी आदेश होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आसन की आज्ञा की पालना और आसन की गरिमा की मैं और मेरे साथी कभी अवहेलना नहीं करेंगे। बस आप सहृदयता और थोड़ा-सा मुस्कुराते रहें।

श्री सभापति: यह सदन नियमों व परम्पराओं से चलता है। अकेला आसन नियम और परम्पराओं का पालन नहीं करवा सकता। सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि सदन गंभीरता से चले, अनुशासित रूप से चले। एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, पहली बार जो लोग आये हैं, कम हैं, जो आ रहे हैं, फिर कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप उनको सिखा देंगे, वह उनके जीवन की पूंजी होगी। आप तो मेरे बहुत पुराने साथी हैं। जैसा अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, उन्होंने शेखावत साहब का जिक्र किया, बाकी लोगों का जिक्र किया, मैं भी उनमें से एक हूं। मुझे भी उन्हीं लोगों के द्वारा सिखाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं था। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने उस वक्त मुझे यह सिखाया। उसी वक्त यह सिखाया गया। सदन के जो वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि जो लोग पहली बार आये हैं, उन्हें सदन के अंदर और सदन के बाहर गरिमापूर्ण व्यवहार करने की आप नसीहत दें। उनको सिखाएं कि सदन किस तरह से मर्यादित रहता है, किस तरह से आपको अपनी बात रखनी है। सदन का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, आसन का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आसन आप सभी से अपेक्षा रखता है। आसन यह भी अपेक्षा रखता है कि आसन की गरिमा बनी रहेगी तो आप सबकी भी गरिमा बनी रहेगी।

मिस्टर लाहोटी।

सांगानेर में बरसाती व दूषित जल भराव की समुचित निकासी

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): विधान सभा के अति विशेष नियम 50

(श्री अशोक लाहोटी)

के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के रामपुरा रोड क्षेत्र, मदरामपुरा डिग्गी रोड क्षेत्र, माल की ढाणी, तेजाजी का बाड़ा क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, के.सी.सी. नगर, कनक विहार, भांकरोटा क्षेत्र, कालाबड़ फाटक, टीबा टोल टैक्स क्षेत्र, इंडिया गेट, सीतापुरा क्षेत्र की कालोनियां, राजीव आवास योजना, कीरो की ढाणी क्षेत्र में बारिश नहीं होने के बावजूद भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है, लोग गाड़ियों से भी नहीं निकल पा रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से वार्ड नंबर 65, 66, 67, 71, 74, 83, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99 में, पृथ्वीराज नगर, पत्रकार कालोनी व आसपास की कालोनियां, नारायण विहार, असरपुरा, गणकपुरा, गोल्यावास, मान्यवास, कल्याणपुरा, दादू दयाल नगर, जोतड़ा वाला, शिकारपुरा, धानका बस्ती का क्षेत्र इत्यादि सैकड़ों कालोनियों में पानी की निकासी नहीं है। जे.डी.ए. व नगर निगम के अधिकारियों का कई बार वहां दौरा करवा दिया, मौका दिखा दिया, आमजन के साथ जाकर प्रदर्शन कर लिया, लेकिन वहां सीवरेज और नालियों की व्यवस्था नहीं करवाने के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

सभापति महोदय, मानसरोवर, प्रतापनगर, श्योपुर, पिंजरापोल गोशाला क्षेत्र, सांगानेर कस्बा व आसपास की कालोनियां, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा क्षेत्र व आसपास की कालोनियों में 30 वर्ष पहले सीवरेज लाइन डली थी। वह आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। लोग जयपुर शहर, राजधानी में रहने के बावजूद इस क्षेत्र की सैकड़ों कालोनियों में नारकीय जीवन जी रहे हैं। दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जे.डी.ए. को नियमन के नाम पर कालोनियों के लोगों ने जमा करवा दिए। इसके बावजूद भी न सड़कें बन रही हैं, न नालियां बन रही हैं, न सीवरेज डल रही है।

मेरा आपके माध्यम से यू.डी.एच. मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाकर आम लोगों को जीवन यापन करने का अधिकार दें। इस महत्वपूर्ण विषय पर यू.डी.एच. मंत्री महोदय, इस बजट में थोड़ी-बहुत घोषणा सांगानेर की भी करवा दें, यही आपसे निवेदन है। सारा बजट केवल जोधपुर मत ले जाइए, कोटा मत ले जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

मारवाड़ संभाग में बेमौसम वर्षा से ईंटों के आवा-कजावा में भारी नुकसान

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, आपने नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान पिछले महीने पाली, जालौर, सिरोही सहित पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान में कुम्हार जाति के लोग आदिकाल से अपनी आजीविका चलाने के लिए खुले आसमान के नीचे मिट्टी की ईटें, मिट्टी के खिलौने, मटके, मूर्तियां, दीपक इत्यादि बनाने का काम करते हैं। इसमें उनका पूरा परिवार लगता है। राजस्थान में लाखों लोग इस कार्य को करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। कई बार बेमौसम बरसात आ जाती है और उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं, ईटें हैं या जो सामग्री बनाते हैं, वह इस बरसात से गलकर नष्ट हो जाती है। ऐसा ही वाकया पिछले महीने पाली, जालौर, सिरोही और पूरे राजस्थान में हुआ। वह जो ईंटें बनाते थे मिट्टी की, वे पूरी की पूरी पानी के अंदर डूब गयीं और पूरे राजस्थान में लाखों परिवार इससे बर्बाद हो गये, लाखों रुपये का नुकसान हो गया।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मिट्टी की ईंटें बनाकर व मिट्टी को विभिन्न रूपों में आकार देकर इन आवा-कजावा व ईंट भट्टे वालों को सरकार सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: नियम 295, श्री मदन दिलावर।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

वन भूमि पर बसे परिवारों को मूलभूत सुविधाएं

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर के दक्षिण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 07, 08 व 29 में आंवली,

(श्री मदन दिलावर)

रोझडी, नयागांव, दौलतगंज, रथकांकरा सहित कुछ गांवों के लगभग 01 लाख जनसंख्या में से अधिकांश लोग वन क्षेत्र की भूमि में लगभग 30-40 वर्षों से बसे हुए हैं। इस कारण से इनको प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता अभियान, सड़क व पेयजल से वंचित होना पड़ रहा है। इसके कारण गरीब लोग अत्यन्त पीड़ा भोग रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त वन भूमि क्षेत्र को आबादी में आबंटित करने हेतु वन विभाग को उतनी ही जमीन अन्यत्र अन्य किस्म की आबंटित कर दी जाये, ताकि वन विभाग उपरोक्त बसावट क्षेत्र से अपना अधिकार छोड़ दे। इसके बाद इस क्षेत्र में लोगों को आवासीय भूखण्ड आबंटित किये जा सकते हैं। इस हेतु सम्बन्धित व सक्षम अधिकारियों को निर्देश दें कि वे अविलम्ब वन विभाग को अन्यत्र जमीन देने से सक्षम स्तर पर अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करें, ताकि वन विभाग बसावट क्षेत्र से अपना अधिकार छोड़ दे।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा के ग्राम धाकड़खेड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में रखे हुए बी.एच.सी. पाउडर का निस्तारण

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 1996 से पूर्व कच्ची बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारियों (मलेरिया) के बचाव हेतु बी.एच.सी. पाउडर का छिड़काव किया जाता था। वर्ष 1996 से सरकार द्वारा बी.एच.सी. पाउडर के छिड़काव को प्रतिबंधित किया गया। फलस्वरूप कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा कार्यालय के चम्बल गोदाम, नयापुरा पर 52.2 मैट्रिक टन बी.एच.सी. 50 प्रतिशत पाउडर रखा हुआ था, किन्तु गोदाम की भूमि कृषि विभाग को आबंटित होने के कारण गोदाम में रखे गये बी.एच.सी. पाउडर को दो सब-सेन्टर धाकड़खेड़ी भेजा गया, जिनमें से धाकड़खेड़ी में आज तक पाउडर पड़ा है। पाउडर के अवधिपार होने के बाद इसके निस्तारण के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा चिकित्सा निदेशालय, जयपुर को कई बार पत्र लिखकर पाउडर के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश चाहे गये थे, किन्तु निदेशालय, जयपुर एवं प्रभारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोटा से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होने से इसके

(श्रीमती कल्पना देवी)

निस्तारण की कार्यवाही लंबित है। धाकड़खेड़ी की जनता उप-स्वास्थ्य केन्द्र होने के बावजूद भी इतने वर्षों से स्वास्थ्य केन्द्र से वंचित है। प्रशासन की लापरवाही के कारण क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार हेतु दूसरे स्वास्थ्य केन्द्र जाना पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है कि ग्राम धाकड़खेड़ी के उप-स्वास्थ्य केन्द्र में रखे बी.एच.सी. पाउडर का निस्तारण शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए चिकित्सा निदेशालय, जयपुर एवं जिला प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा से पाउडर के निस्तारण हेतु तुरंत दिशा-निर्देश प्रदान करवाने की कृपा करें, जिससे धाकड़खेड़ी के लोगों को उप स्वास्थ्य केन्द्र का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल।

मुण्डावर के मुख्य मार्गों की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन डामरीकरण

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि गत वर्ष 2020 से 2021 तक नेशनल हाईवे 48 बंद होने की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में भारी एवं सभी वाहनों का आवागमन विधान सभा क्षेत्र की सड़कों से होता था, जिसकी वजह से सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. 200 फुट गिलोठ चौक से कुतीना कांकर होते हुए हरियाणा बोर्डर तक।
2. नेशनल हाईवे 48 से सक्तपुरा बावद मानका, रामसिंहपुरा होते हुए हरियाणा बोर्डर तक।
3. शाहजहांपुर, पलावा, बीरोद, गादली, दादीया होते हुए हरियाणा बोर्डर तक।
4. नेशनल हाईवे 48 से नीमराणा नाधोडी, दादीया होते हुए गिलोठ इण्डस्ट्रियल एरिया तक।
5. शाहजहांपुर दादीया सड़क से गादली की ढाणी होते हुए मानका तक।

उक्त सड़कों की हालत ऐसी है कि इन सड़कों पर वाहन तो चलना दूर व्यक्ति पैदल तक नहीं चल पाता है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और दुर्घटनाओं में लोग मृत्यु का शिकार भी हो रहे हैं। साथ ही धूल-मिट्टी उड़ने से स्थानीय लोग अस्थमा व अन्य बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी इन सड़कों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जनहित में इन सड़कों के पुनः निर्माण के लिए मुख्य मंत्री जी बजट में विशेष पैकेज की घोषणा कर आमजन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल महिया (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली नगर परिषद् में सफाई कर्मियों के रिक्त पद

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि नगर परिषद् पाली में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के काल में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी। वर्तमान सरकार के चार वर्ष हो गये। इस अंतराल में सैकड़ों सफाईकर्मी सेवानिवृत्त हो गये, परन्तु नई भर्ती नहीं की। वर्तमान में पद रिक्त हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। वाल्मीकि समाज के भाई-बहनों हेतु दूसरे विभागों में वर्षों पूर्व भर्तियां लेनी बंद कर दीं और वहां सारा काम ठेके पर किया जा रहा है। अब एक मात्र स्थानीय निकाय में ही इनके पद हैं। वहां भी पांच वर्षों में भर्ती की स्वीकृति नहीं देना वाल्मीकि समाज के प्रति अन्याय है। पहले स्वच्छकार पुनर्वास योजना अंतर्गत ऋण अनुदान दिया जाता था परन्तु पिछले वर्षों में यह भी नहीं दिया जा रहा। निजी क्षेत्रों में भी इन्हें रोजगार बमुश्किल मिलता है। सफाई कर्मियों की कमी के कारण यशस्वी प्रधान मंत्री का स्वच्छ भारत मिशन भी प्रभावित होता है। केन्द्र सफाई कार्य हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्रतिवर्ष भारी राशि देती है। प्रधान मंत्री जी ने तो इन्हें स्वच्छता सैनिक का नाम दिया, क्योंकि ये गंदगी को मिटाकर हमें स्वच्छ वातावरण में ज़ीने का सुअवसर देते हैं, नागरिकों को बीमारी से बचाते हैं। कोरोना काल में प्रदेश में जिस प्रकार इन स्वच्छता सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किये बिना हमें स्वच्छ वातावरण दिया, कोरोना से मृतकों के अंतिम संस्कार करने का कार्य किया, अस्पतालों में भी सफाई व्यवस्था सम्भाली। इनके बेमिसाल काम के लिए सम्पूर्ण समाज इनका ऋणी एवं आभारी है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के होने पर भी जिस प्रकार का स्वच्छ वातावरण दिया तो प्रधान मंत्री जी ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मियों का सम्मान किया। पुरस्कृत भी किया व उन्हें कुर्सी पर बिठाकर, खुद नीचे बैठ कर उनके पैर धोकर देशवासियों को संदेश दे दिया कि सफाई कार्य हल्का नहीं सबसे पवित्र एवं श्रेष्ठ कार्य है, समाज में इनका स्थान सबसे ऊपर है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की इनके प्रति उदासीनता एवं अनदेखी इनके साथ अन्याय है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अतः आपसे निवेदन है कि पाली में तत्काल रिक्त पदों पर भर्ती की जाये। अन्य विभाग, जहां ठेके पर सफाई करवाई जा रही है, वहां पद निर्धारित कर स्थाई भर्ती की जाये एवं सफाई कार्य हेतु वाल्मीकी समाज को ही अवसर दिया जावे।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

बौंली (बामनवास) के पशु चिकित्सा उप केन्द्र में सूअरों के टीकाकरण की समुचित व्यवस्था

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कस्बा बौंली में वाल्मीकि समाज के द्वारा बड़ी संख्या में सूअरों का पालन किया जाता है। पिछले कई दिनों से एक अज्ञात बीमारी के कारण यहां करीब 1500 से ज्यादा सूअर मर गये हैं और इनकी मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पशु उप केन्द्र पर भी सूअरों के टीकाकरण की सुविधा और उक्त अज्ञात बीमारी की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वाल्मीकि समाज सूअरों का पालन कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। इस अज्ञात बीमारी के कारण उनके सूअरों की मृत्यु हो जाने के कारण उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से बौंली क़स्बे में पशु डाक्टरों की एक टीम भेजी जाए तथा सूअरों में फैली इस अज्ञात बीमारी का पता लगाकर उनका इलाज किया जाए। बौंली उप पशु उप केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं तथा सूअरों की टीकाकरण की भी समुचित व्यवस्था की जाए।

अतः मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी से मांग करती हूं कि बौंली क़स्बे में शीघ्र डाक्टरों की एक टीम भेजें और सूअरों में फैली अज्ञात बीमारी का इलाज करें। वाल्मीकि समाज के गरीब लोग, जिनकी सूअरों की अज्ञात बीमारी से मौत हुई है, उनका जनहित में सर्वे कराया जाए तथा उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वाल्मीकि समाज के लोगों को राहत प्रदान की जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत औषधियों का योजना में पुन:सम्मिलन

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं:-

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध कई औषधियों को बंद करने से कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समक्ष उत्पन्न असाधारण स्थिति पर राज्य सरकार का ध्यानार्कषण हेतु।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) में लाभार्थियों को उपलब्ध औषधियों की सूची में से राज्य सरकार ने बिना किन्हीं सुसंगत कारणों के 30 से अधिक व्यापक उपयोग की औषधियों को हटा दिया है। हटाई गई औषधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, हड्डी रोग, खांसी एवं जुकाम, अनिद्रा, विटामिन की कमी एवं रक्त अल्पता जैसे रोगों के उपचार में सम्मिलित औषधियां हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी उक्त रोगों से ग्रस्त हैं।

योजना के प्रारम्भ से ही इन औषधियों को लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। अधिकारी कह रहे हैं कि उक्त औषधियां गलती से सूची में सम्मिलित कर दी गई थीं। स्वास्थ्य योजना में सामान्य प्रचलित रोगों की औषधियों को बाहर रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से योजना में सूची से हटाई गई सभी औषधियों को पुनः सम्मिलित करने के लिए अनुरोध कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

पीपल्दा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण एवं जल भराव प्रभावितों का पुनर्वास

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2020 से 2022 में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में हुई अतिवृष्टि के कारण चम्बल कालीसिंध, पार्वती, सूकरनी आदि नदियों एवं अन्य नालों-खालों वाले विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के करीब

(श्री रामनारायण मीना)
50 से अधिक ग्राम अधिकांशतया जलमग्न हो जाने से अनेक मकान क्षतिग्रस्त एवं नष्ट (धराशायी) हो गये हैं। गरीब व्यक्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। तहसील क्षेत्र पीपल्दा तथा उप तहसील क्षेत्र सुल्तानपुर में फ़सलों, मकानों, रास्तों आदि को भारी (सर्वाधिक) नुकसान हुआ है। जल भराव एवं जल प्रवाह के कारण सड़कें एवं पुलियाएं क्षतिग्रस्त होने से इस क्षेत्र का एक-दूसरे से तथा जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क कट गया था।

भारी वर्षा तथा नदियों में पानी के भारी उफान के कारण विगत 3 वर्षों से क्षेत्र के ग्रामों में ऐसी स्थिति बन रही है। आगामी वर्षों में भी ऐसी स्थिति के पुनः उत्पन्न होने की आशंका के चलते ऊंचे स्थानों पर आबादी के तत्काल पुनर्वास की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमान में भी काफी संख्या में लोग बेघर होकर तम्बुओं एवं झोपड़ियों में अस्थायी बसर कर रहे हैं। आबादी शिफ्टिंग हेतु पर्याप्त भूमि आबंटन तथा पुनर्वास एवं आवास के निर्माण के लिए आर्थिक संसाधन भी शीघ्र उपलब्ध करवाने अपेक्षित हैं। अभी तक वर्ष 2022 के अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया है। वर्ष 2021 के कुछ बाढ़ पीडितों को भी अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है।

जिन सड़क मार्गों पर निर्मित पुलियाएं क्षतिग्रस्त व ध्वस्त हुई हैं उनकी भी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण अविलम्ब करवाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक भी अनेक ग्रामों के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला मुख्यालय से सम्पर्क मार्ग भली-भांति बहाल नहीं हो पाये हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद-बीज एवं अन्य आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं का परिवहन कार्य नहीं हो पा रहा है।

अत: अनुरोध है कि 2020 से 2022 की अवधि में हुई क्षति का पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिलवाने, डूब क्षेत्र से बाहर पुनर्वास कार्यवाही करने तथा क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग-पुलियाओं के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य अवलिम्ब करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के आवासीय एवं व्यावसायिक रूपांतरण के अधिकार की प्रदायगी

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी काश्तकार या डवलपर कृषि खातेदारी की जमीन को आवासीय, व्यावसायिक रूपांतरण कराता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग कर प्लाट काटकर बेचता है। रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, लेकिन क्रेता के नाम पर नामान्तरण नहीं खुलता है, वह जमीन विक्रेता के नाम पर ही बोलती है। उससे कई भूमाफिया उस जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं फिर कई तरीकों के विवाद होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। इसमें जैसे शहरी क्षेत्र में होता है जमीन का भूमि रूपान्तरण होते ही वह जमीन उसका खातेदार का नाम हटाकर नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम के नाम दर्ज हो जाती है फिर ये शहरी निकाय उसके पट्टे जारी करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह का नियम बनाया जाना चाहिए, उससे कन्वर्ट जमीन ग्राम पंचायत के नाम समर्पित हो जाये और फिर ग्राम पंचायत उसके पट्टे जारी करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

वल्लभनगर में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में रविवार दिनांक 29.01.2023 को कई स्थानों पर भारी बारिश एवं ओलावृष्टि हुई, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में भारी ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहां आय का प्रमुख स्रोत कृषि एवं उससे संबंधित व्यवसाय है। क्षेत्र में बेर के आकार के ओले गिरे जिससे खेतों में सफेद चादर बिछ गई तथा बर्बादी का आलम देखकर किसान मायूस और हताश हो गये। भारी बारिश के बीच किसान खेतों में फावड़े से ओले समेटते रहे, परन्तु ओलावृष्टि एवं तेज बारिश के कारण फसल नहीं बचा सके।

क्षेत्र में सरसों, गेहूं, जौ, चना, मेथी सहित विभिन्न सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सरसों की तो पकी फसल ही ओले और बरसात के पानी में डूब गई, तथा अन्य खड़ी फसलें आड़ी पड़ गईं। हर तरफ किसान फसलों की बरबादी की पीड़ा सुना रहे हैं। क्षेत्र में इस प्रकार की अतिवृष्टि पहली बार देखी गई है। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

फिर गया, जिसके कारण इनमें काफी ज्यादा निराशा का माहौल है। किसानों के द्वारा लाखों रुपये लगाकर रबी की फसल की बुआई करने हेतु महंगे खाद एवं बीजों को क्रय कर खेतों में बुआई की गई थी। किसानों के घरों की छतें टूट गईं तथा घरों में पानी भर गया है।

विधान सभा क्षेत्र की समस्त 71 ग्राम पंचायतों में फसल नष्ट हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को जो टोल फ्री नम्बर दिया गया है, उसे कोई रिसीव नहीं करता है। साथ ही उनके द्वारा जो ऐप लान्च की गई है वह भी डाउनलोड नहीं होती है। इस गम्भीर लापरवाही के कारण भी किसानों में केन्द्र सरकार के विरुद्ध भारी रोष है।

अतः मेरा राज्य सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिये यह आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के गांवों में 90 प्रतिशत फसल खराबा होने के कारण अविलम्ब मुआवजा राशि स्वीकृत कर किसान भाइयों को राहत प्रदान की जाये।

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद डिण्डोर।

माही/कडाना प्रोजेक्ट की भूमि के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण की जांच

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत सागवाड़ा के राजस्व विभाग में फर्जी तरीके से भूमि हस्तांतरण होने पर निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज, आप अपने स्थान पर पधारें। आप अपने स्थान पर पधारें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): सागवाड़ा में राजस्व विभाग के अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से फर्जी आदेश निकालकर छुट्टी के दिन सागवाड़ा कस्बे की सिंचाई विभाग के अधीन माही कडाना प्रोजेक्ट की करोड़ों की भूमि का नामांतरण खोलकर रजिस्ट्री कर डाली। सरकारी जमीन पर नामांतरण खोलने की खोखली हकीकत में आखिर असली गुनाहगार कौन और किसे मिली सजा? इससे भी बड़ी बात यह कि ऐसे फर्जीवाड़े हुए हैं जो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया और इसी तरह से करोड़ों की जमीन की हेराफेरी का

(श्री रामप्रसाद)

कांड होता जा रहा है। यहां आदिवासियों की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री के बहुत से केस हैं जिसे सरकार ने कभी जांच करने की कोशिश नहीं की है। सागवाड़ा में कडाना की करीब 210 बीघा जमीन पर अतिक्रमण सालों से प्रभावशाली लोगों ने कर रखा है। इस जमीन की सरकारी दर ही 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की है जबकि बाजार का भाव इससे तीन से चार गुना ज्यादा है।

अत: मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि सागवाड़ा में कडाना की भूमि फर्जीवाड़ा और आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों के नाम जो हस्तांतरण हुई है उसकी उच्चस्तरीय जांच की जाए ताकि असली गुनाहगारों को सजा मिले और प्रभावशाली लोगों का सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा (अनुपस्थित)। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में सेमग्रस्त भूमि के सुधार हेतु आर्थिक पैकेज

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में काफी कृषि भूमि सेम से ग्रस्त दलदली हो गई थी। काफी कृषि भूमि पर 4-5 फुट पानी सन् 1980 से भरा रहा था परन्तु आज सेम नाले के निर्माण होने के कारण जल भराव खतम हो गया। कृषि भूमि लवणीय व बंजर हो गई। जो काश्तकार 50 साल से सेम के कारण बेघर हो गये व मजदूरी करने लग गये थे, उन काश्तकारों में सेमग्रस्त भूमि उपजाऊ करने में असमर्थता है तथा आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सेमग्रस्त भूमि को सुधार करने के लिए उन पीड़ित काश्तकारों को सरकार भूमि सुधार हेतु आर्थिक पैकेज (सहायता) दे, ताकि 40 वर्षों से सेमग्रस्त बंजर भूमि का सुधार हो सके व काश्तकार अपना जीवन सही ढंग से यापन कर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ की रामदेव कालोनी के निवासियों को पट्टे की प्रदायगी

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ के वार्ड नम्बर-1, रामदेव कालोनी के क्षेत्रवासियों द्वारा पट्टे दिये जाने को लेकर

(श्री सुरेश टाक)

नगर परिषद् के बाहर धरने पर बैठने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नम्बर-1, रामदेव कालोनी के वार्डवासियों को नगर परिषद् द्वारा पट्टे नहीं दिये जाने से दिनांक 07 फरवरी, 2023 से नगर परिषद्, किशनगढ़ के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज तो धरना प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने विरोध में मुंडन तक करवा लिया। यह खबरें सभी मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं, जिनकी परिषद् के जिम्मेदार लोगों द्वारा परवाह नहीं की जा रही है।

सरकार ने 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान इसीलिए चलाया था कि लोगों को अधिक से अधिक पट्टे मिलें, किन्तु नगर परिषद् द्वारा इन लोगों को पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। इसे लेकर पूर्व में भी क्षेत्रवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था जिस पर नगर परिषद् के सभापति द्वारा रामदेव कालोनी के निवासियों को आश्वस्त किया गया था कि दीपावली तक इन्हें पट्टे दे दिये जायेंगे, परन्तु क्षेत्रवासियों को अभी तक पट्टे नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों ने रोष जाहिर करते हुए वापस धरना प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया है। नगर परिषद् द्वारा क्षेत्रवासियों को पहले भी एक वर्ष तक लटकाये रखा गया और यही कहा गया कि जोनल प्लान बोर्ड बैठक में पास कर आपको जल्द पट्टे दे देंगे और परिषद् द्वारा बार-बार जोनल प्लान में जानबूझकर त्रुटियां छोड़कर लोगों को परेशान व भ्रष्टाचार करने की नीयत से इस प्लान को लम्बित रखा गया। काफी विरोध के बाद नगर परिषद्, किशनगढ़ के बोर्ड द्वारा इसे पारित कर दिनांक 14.12.2022 को स्वीकृति के लिए डी.एल.बी. भेजा गया है।

ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मंत्री महोदय, इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेकर डी.एल.बी. से नगर परिषद् को स्वीकृति दिलायें और परिषद् को निर्देश प्रदान करें कि जोनल प्लान के अभाव में रोके गये पट्टे तत्काल जारी करे और मुझे भी अवगत करवाने की कृपा करें ताकि नगर परिषद् के बाहर धरने पर बैठे लोगों को मैं सरकार के माध्यम से आश्वस्त कर सकूं कि इस समयावधि में जोनल प्लान स्वीकृत होकर आप सभी को पट्टे दे दिये जाएंगे।

अत: मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नगर परिषद्, किशनगढ़ से डी.एल.बी. को भिजवाये गये जोनल प्लान का परीक्षण करवाकर इसकी स्वीकृति नगर परिषद्, किशनगढ़ को प्रदान करवाकर धरने पर बैठे लोगों को पट्टे दिलवाकर लाभान्वित करें। धन्यवाद।

(समय: 13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

पाली नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, पाली नगर परिषद् द्वारा ठेकेदारों के चैक काटने के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन जबरन लेने से तंग आकर ठेकेदार हनुमान सिंह ने आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि नगर परिषद् द्वारा उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का करीब दो करोड़ रुपये का पेमेंट इसलिये नहीं किया जा रहा है कि उनके द्वारा भारी कमीशन देने में असमर्थता जताई गयी। राशि नहीं मिलने से उसके द्वारा अन्यों को पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उसको मांगने वालों से मुंह छिपाना पड़ रहा है।

अन्य ठेकेदार जो ज्यादा कमीशन देते हैं उनको तत्काल पेमेंट यहां तक कि फर्जी बिल बनाकर भी पेमेंट कर दिया जाता है। मृतक की छवि अच्छे ठेकेदार की रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी न तो दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कानूनी कार्यवाही की गई, न ही सरकार ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की। राजपुरोहित समाज के प्रतिनिधियों ने चार बार माननीय मुख्य मंत्री से मिलकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार की। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि निष्पक्ष जांच करा हनुमान सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी, परन्तु अभी तक न तो जांच हुई है न ही कोई कार्यवाही, जिसको लेकर सम्पूर्ण राजपुरोहित समाज में भारी आक्रोश है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि शीघ्र निष्पक्ष जांच कराएं एवं इनका बकाया पेमेंट मृतक के परिजनों को शीघ्र दिलाने का निर्देश देवें।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

डूंगरगढ़ में बीकानेर-रतनगढ़ रेलखण्ड मार्ग पर अण्डरब्रिज का निर्माण

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत बीकानेर-रतनगढ़ रेलखण्ड मार्ग पर श्रीडूंगरगढ़

(श्री गिरधारीलाल)

तहसील के अनेक गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर रेलवे अण्डरब्रिज का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

बीकानेर-रतनगढ़ रेलखण्ड मार्ग पर श्रीडूंगरगढ़ तहसील में अनेक गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर रेलवे अण्डरब्रिज का निर्माण करवाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। वर्तमान में इस रेलमार्ग पर विद्युतीकरण के कार्य व रेल लाइन के दोहरीकरण की संभावना को देखते हुए श्रीडूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के दुसारणां-श्रीडूंगरगढ़, दुलचासर-बासी महियान, दुलचासर-भोजास, श्रीडूंगरगढ़-पुंदलसर व बिग्गा-बीदासर मार्ग पर अण्डरब्रिज का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता है। अण्डरब्रिज नहीं होने से इन गांवों के ग्रामीणों, विद्यार्थियों व किसानों को जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक रास्तों से रेलवे लाइन के ऊपर से आवागमन करना पड़ता है और हर समय हादसा होने की संभावना रहती है। अब रेल विद्युतीकरण होने व रेल लाइन के दोहरीकरण को देखते हुए इन वैकल्पिक रास्तों को भी रेलवे द्वारा बंद किया जा रहा है जिससे गांवों का सम्पर्क एक-दूसरे से कट जाएगा और आमजन के सामने आवागमन की भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन की इस विकट समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और तहसील क्षेत्र के उक्त सम्पर्क मार्गों पर रेलवे अण्डरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी जाए।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उनके पास समय नहीं है। वे मस्त हैं बातचीत में। मेरे को दे दो। मैं रख देता हूं। आसन के निर्देशों की पालना नहीं करना संसदीय कार्य मंत्री के आचरण में आ गया, सभापति महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद आपको।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

1. अधिसूचना संख्या: प.1(13)नविवि/3/72पार्ट-II दिनांक 16.02.2022 जिसके द्वारा बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2023 का अनुमोदन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.10(18)नविवि/3/2011 दिनांक 18.02.2022 जिसके द्वारा बड़ी सादड़ी के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.11(3)नविवि/बानसूर/2022 दिनांक 21.02.2022 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, अलवर को बानसूर (जिला-अलवर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: प.10(18)नविवि/3/2011 दिनांक 22.02.2022 जिसके द्वारा बड़ी सादड़ी के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 के लिए जारी की गई अधिसूचना की दिनांक को 26.04.2021 के स्थान पर 20.07.2021 कर संशोधित किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.10(6)नविवि/3/81पार्ट-1 दिनांक 22.02.2022 जिसके द्वारा भीलवाड़ा मास्टर प्लान-2035 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/2021 दिनांक 24.02.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को परतापुर-गढ़ी(जिला-बांसवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: प.11(5)नविवि/लक्ष्मणगढ़/2022 दिनांक 24.02.2022 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, अलवर को लक्ष्मणगढ़ के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: प.11(3)नविवि/सरदारशहर(चूरू)/2016 दिनांक 15.03.2022 जिसके द्वारा सरदारशहर मास्टर प्लान-2036 का अनुमोदन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: प.11(7)नविवि/भीनमाल/2022 दिनांक 30.03.2022 जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को भीनमाल के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

10. अधिसूचना संख्या: प.11(6)नविवि/जावाल/2022 दिनांक 30.03.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को जावाल (जिला-सिरोही) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: प.11(9)नविवि/जालोर/2022 दिनांक 30.03.2022 जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को जालोर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय योजनाओं में "रिटायरमेन्ट होम्स" नाम से नए उपबन्ध जोड़े गए हैं;

13. अधिसूचना संख्या: प.2(17)नविवि/बीकानेर/2019 दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा बीकानेर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार राजस्व ग्राम शिवबाड़ी में गोपालक योजना विकसित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: प.11(12)नविवि/उच्चैन/2022 दिनांक 25.02.2022 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, भरतपुर को उच्चैन (भरतपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 28.04.2022 जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के तहत कार्य करने वाली पात्र अलाभकारी संस्थाओं को पूर्व में प्रदत्त छूटों के साथ ही उन्हें आबंटित भूमि पर लीज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/84 दिनांक 04.05.2022 जिसके द्वारा चूरू मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: प.11(14)नविवि/लालगढ़ जाटान/2022 दिनांक 05.05.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को लालगढ़ जाटान (जिला-श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्राम चक के सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

18. अधिसूचना संख्या: प.11(16)पीलीबंगा/2022 दिनांक 05.05.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को पीलीबंगा (जिला-हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्राम चक के सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: प.11(15)नविवि/मंडावरी/2022 दिनांक 05.05.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को मंडावरी (जिला -दौसा) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों के मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: प.11(17)नविवि/सूरतगढ़/2022 दिनांक 10.05.2022 जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्राम चक के सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/डेगाना/2017 दिनांक 10.05.2022 जिसके द्वारा डेगाना मास्टर प्लान-2041 में संशोधन किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: प.11(8)नविवि/भोपालगढ़/2022 दिनांक 10.05.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: प.17(22)नविवि/नियम/2020 दिनांक 10.05.2022 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति और आबंटन) (संशोधन) नियम, 2022 विरचित किये गये हैं;

24. अधिसूचना संख्या: प.10(56)नविवि/3/2011 दिनांक 01.06.2022 जिसके द्वारा धौलपुर मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: प.1(1)नविवि/3/77 दिनांक 01.06.2022 जिसके द्वारा पूर्व में जारी विभागीय अधिसूचना दिनांक 06.07.2011 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: प.11(18) नविवि/पावटा-प्रागपुरा/2022 दिनांक 03.06.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को पावटा-प्रागपुरा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(जिला-जयपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों के सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: प.11(22)नविवि/सुल्तानपुर/2022 दिनांक 03.06.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को सुल्तानपुर (जिला -कोटा) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों के सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: प.11(23)नविवि/अटरू/2022 दिनांक 14.06.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को अटरू(जिला-बारां) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों के सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: प.11(21)नविवि/बसेड़ी/2022 दिनांक 14.06.2022 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को बसेड़ी(जिला-धौलपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: प.11(20)नविवि/बामनवास/2022 दिनांक 14.06.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को बामनवास (जिला-सवाईमाधोपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: प.12(1)नविवि/बाड़मेर/2022 दिनांक 17.06.2022 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, बाड़मेर द्वारा मास्टर प्लान अनुसार राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी की भूमि पर "सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक एवं आवासीय योजना" तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: प.12(3)नविवि/सवाईमाधोपुर/2022 दिनांक 21.06.2022 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर की सीमा में अभीष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम कुतलपुरा जाटान की भूमि पर "आवासीय योजना" के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: प.11(3)नविवि/2021 दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा नसीराबाद क्षेत्र के लिए तैयार किये गये नसीराबाद मास्टर प्लान-2041 का अनुमोदन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

34. अधिसूचना संख्याः प.11(5)नविवि/2021 दिनांक 04.08.2022 जिसके द्वारा पूर्व में जारी विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.08.2021 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्याः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 18.08.2022 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है;

36. अधिसूचना संख्याः प.10(132)नविवि/3/2009/पार्ट दिनांक 23.08.2022 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स, 2017 में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्याः प.11(28)नविवि/कुशलगढ़/2022 दिनांक 25.08.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को कुशलगढ़ (जिला-बांसवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

38. अधिसूचना संख्याः प.11(29)नविवि/कपासन/2022 दिनांक 25.08.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को कपासन (जिला-चित्तौडगढ़) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

39. अधिसूचना संख्याः प.11(30)नविवि/सलूम्बर/2022 दिनांक 25.08.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को सलूम्बर (जिला-उदयपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

40. अधिसूचना संख्याः प.10(55)नविवि/3/2011 दिनांक 25.08.2022 जिसके द्वारा नागौर मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्याः प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014पार्ट दिनांक 07.09.2022 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्याः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 22.09.2022 जिसके द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के अन्तर्गत कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रीमियर की दरें निर्धारित की गई हैं;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

43. अधिसूचना संख्या: प.12(2)नविवि/सवाईमाधोपुर/2022 दिनांक 28.09.2022 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर की सीमा में अभीष्ठ नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम घुडासी की भूमि पर "फार्म हाउस योजना" के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है;

44. अधिसूचना संख्या: पीआर./1121/एमपी(ई)कोटा दिनांक 20.10.2022 जिसके द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है;

45. अधिसूचना संख्या: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 02.11.2022 जिसके द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों की प्रीमियर की दरें निर्धारित की गई हैं;

46. अधिसूचना संख्या: प.10(35)नविवि/3/2011 दिनांक 15.11.2022 जिसके द्वारा ब्यावर के अनुमोदित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत ब्यावर के नगरीय क्षेत्र में 04 नये राजस्व ग्राम जोड़े गये हैं;

47. अधिसूचना संख्या: टीपीआर./1121/एमपी(ई)/केटीजेड/सवाईमाधोपुर दिनांक 28.11.2022 जिसके द्वारा सवाईमाधोपुर मास्टर प्लान-2035 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है;

48. अधिसूचना संख्या: प.10(32)नविवि/3/98 दिनांक 30.11.2022 जिसके द्वारा डीग मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को वर्ष 2031 तक बढ़ाया गया है;

49. अधिसूचना संख्या: भूमि/प.7(ड)डीएलबी/2022 दिनांक 01.12.2022 जिसके द्वारा नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु धारा 90-क की कार्यवाही करने के अधिकार आयुक्त, नगरपालिका (प्राधिकृत अधिकारी) नाथद्वारा को 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' की अवधि तक के लिए प्रदान किये गये हैं;

50. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/2021 दिनांक 02.12.2022 जिसके द्वारा परतापुर-गढी (जिला-बांसवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र हेतु कतिपय राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है;

51. अधिसूचना संख्या: प.17(19)नविवि/नियम/2019 दिनांक 21.12.2022 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2022 की अवधि को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

52. अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/1981 दिनांक 22.12.2022 जिसके द्‌वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को सीकर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

53. अधिसूचना संख्या: प.11(19)नविवि/सरमथुरा/2022 दिनांक 23.12.2022 जिसके द्‌वारा उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को सरमथुरा (जिला-धौलपुर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

54. अधिसूचना संख्या: प.10(18)नविवि/3/2012 दिनांक 27.12.2022 जिसके द्‌वारा उदयपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

55. अधिसूचना संख्या: प.2(46)नविवि/कोटा/2021 दिनांक 09.01.2023 जिसके द्‌वारा ग्राम लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला-कोटा की नगर निगम क्षेत्र स्थित 9226 वर्गफीट व्यवसायिक भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास, कोटा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है;

56. अधिसूचना संख्या: प.10(132)नविवि/3/2018/पार्ट दिनांक 13.01.2023 जिसके द्‌वारा श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जयपुर में टैक्निकल मेम्बर नियुक्त किया गया है; एवं

57. अधिसूचना संख्या: प.17(22)नविवि/नियम/2020 दिनांक 18.01.2023 जिसके द्‌वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैन्ड) रूल्स, 1974 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: श्री अंजना उदयलाल।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री अंजना उदयलाल)

दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का आडिट प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र (वर्ष 2021-22)

1. दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का आडिट प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र वर्ष 2021-22;

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

2. राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

3. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22.

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री सभापति: श्री महेश जोशी।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रगति रिपोर्ट (वर्ष 2022)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2022 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

(वर्ष 2021-22)

1. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22; एवं

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट

(वर्ष 2021-22)

2. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22.

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2021-22)

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2021-22;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

2. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (वर्ष 2021-22)

3. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2021-22.

श्री सभापति: श्री बी.डी. कल्ला साहब।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस कार्यसूची में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे जिनका उल्लेख किया गया, हमें सूचना दी गयी है, उन्हीं को सदन की मेज पर रखा जाता है। आप बीच में खड़े होकर महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं। इसमें कहीं लिखा हुआ तो है नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): लिखा हुआ है इसमें, शकुन्तला रावतजी के बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कहां लिखा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): थर्ड नम्बर, पेज नम्बर 7 पर रमेश चन्द मीना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप रमेश मीना हो?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं। यह संयुक्त रेसपोंसिबिलिटी है। आपके वक्त में भी मंत्री अनुपस्थित रहते थे तो उनका आप ही रखते थे।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान। श्री जे.पी. चन्देलिया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने 10 फरवरी, 2023 को जो बजट इस सदन में पेश किया, वह इस प्रदेश के अन्तिम पंक्ति

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

में जो व्यक्ति अन्तिम में खड़ा है उसको सामने रखकर तैयार किया और प्रस्तुत किया, जिससे कि गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को खुशहाली मिले, उनका आर्थिक उन्नयन हो तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। यह 170 पेज का 270 पैराग्राफ्स या बिन्दुओं का एक शानदार डाक्युमेंट है जिसमें समाज के सभी लोगों को और सभी आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह वयस्क हो, चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो और किसी भी वर्ग का हो। सबकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, सबके आर्थिक उन्नयन के लिए और सबको खुशहाली देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह शानदार बजट 2023-24 प्रस्तुत किया है। उसमें समाविष्ट है कि जो व्यक्ति हमारे प्रदेश का है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वह भूखा नहीं सोयेगा।

प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, जो वाल्मीकि समाज है, उसके लिए उन्होंने 30 हजार नौकरियां प्राप्त करने के अवसर दिये और गत बजट में 20 करोड़ का वाल्मीकि कोष स्थापित किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि 20 करोड़ रुपये का वाल्मीकि कोष, इनकी जनसंख्या को देखते हुए और जगह-जगह जो यह फैले हुए हैं उनको देखते हुए 20 करोड़ रुपये कम रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मन भी था और मन को देखते हुए ही मैंने उन्हें लिखा था। मुझे इस बात की खुशी है और इस बात के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि 20 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 100 करोड़ रुपये का वाल्मीकि कोष उन्होंने स्थापित किया।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि यह 30 हजार रोजगार के अवसर जो मिल रहे हैं, चूंकि अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी उठायी है, कल भी उठायी थी कि सफाई कर्मचारियों की संख्या जो हमारी जनसंख्या है, उसके अनुपात में कम है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि जो 30 हजार के रोजगार के अवसर हैं, वे 2 वर्ष के बजाय अगर इसी साल दिये जाते हैं तो मेरे विचार से ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, कई संगठन, जो इस समाज से जुड़े हुए

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया है और उनकी यह भावना है कि वाल्मीकि समाज को इतना बड़ा उपकृत माननीय मुख्य मंत्री महोदय कर रहे हैं तो वाल्मीकि जयंती पर या महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर एक अवकाश भी, जब वह अपना जवाब दें, उसमें जरूर घोषित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि युवा विकास कल्याण कोष 500 करोड़ रुपये से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है। यह तो पहले भी लोगों को स्पष्टगोचर हो रहा था कि इस बार का बजट युवाओं के लिए आयेगा, महिलाओं के लिए आयेगा, बेरोजगारों के लिए आयेगा, जरूरतमंदों के लिए आयेगा, समाज के आम व्यक्ति के लिए आयेगा, लेकिन खाली यह युवा कोष कल्याण ही नहीं, उन्होंने अलग-अलग नाम से और भी कोष स्थापित किये हैं। जैसे कि ओ.बी.सी. के लिए, एम.बी.सी. के लिए, ई.डब्ल्यू.एस. के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 200-200 करोड़ रुपये का विकास कोष स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत शानदार शुरुआत है।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से कुछ घटनाएं, जो नकल के नाम से या अनफेयरमींस के नाम से जो उजागर हो रही थीं, वह एक चैलेंज था राज्य सरकार के सामने। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है और फेयरनैस के हिसाब से और अधिक ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम, 2022 लाया गया और उसी संदर्भ में इस बार स्पेशल टास्क फोर्स, एस.टी.एफ. के गठन की जो घोषणा की गयी, यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो बेरोजगारों के लिए शुरुआत की गयी है, यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है। बेरोजगार के लिए जो आवेदन की फीस है, उसकी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा उनके माता-पिता पर भार पड़ता है। कई बार माता-पिता के पास भी कोई साधन नहीं होता, इसलिये जो रजिस्ट्रेशन एक बार बेरोजगार युवक या युवती ने करा दिया, वह हमेशा उसके काम आयेगा। इस बात के लिए मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार युवक-युवतियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की जो व्यवस्था की गयी है, यह एक बहुत बड़ी बात है। आज का जमाना गलाकाट प्रतियोगिता का है। अगर लड़का या लड़की बहुत शानदार तरीके से अपनी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं करते हैं तो उनका फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आना, सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिये वह एक अच्छी इंस्टीट्यूट में कोचिंग प्राप्त करे, जिस इंस्टीट्यूट का नाम अच्छा हो, वह कोचिंग प्राप्त करे, यह बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक ब्लाक स्तर पर बनाना, एक बहुत शानदार शुरुआत है। कई बार पुस्तकों के अभाव में, न्यूजपेपर उपलब्ध नहीं होने के अभाव में, उसको अच्छी मैगजीन नहीं मिलने के कारण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ जाते हैं। इस लाइब्रेरी के माध्यम से वह बहुत बड़ा लाभ उठायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उद्यम प्रोत्साहन योजना है, स्टार्ट-अप है, चूंकि मेरा समय निश्चित है, इसलिए मैं थोड़ा-सा संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है। चिकित्सा सुविधाओं में 25 लाख रुपये तक का इलाज, 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस, यह बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां ओल्ड पेंशन स्कीम का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं। पिछली बार तो राज्य के जो कर्मचारी थे, केवल वही उसमें शामिल थे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय की एक बहुत बड़ी सोच है कि जो कर्मचारी वर्ग है, वह खाली राज्य सेवा में ही नहीं, बल्कि जो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, स्टेट के अंडरटेकिंग्स हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, उन सारे कर्मचारियों को इस ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करके बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा प्रमोशन में जो विसंगतियां थीं, उसमें भी 9, 18 और 27 का लाभ इन बोर्ड, कार्पोरेशंस के कर्मचारियों को देकर उन्होंने इनका मनोबल भी बढ़ाया है और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है। अन्य पेंशन योजनाओं में, स्किल्स में वृद्धि की है, उनका स्कोप बढ़ाया है। यह बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा का काम है।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा रसोई की संख्या एक हजार कर दी। इसी प्रकार से 500 करोड़ का जो कोष था एस.सी., एस.टी. के विकास का,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उसको एक हजार करोड़ कर दिया। यह सारे काम ऐसे हैं जो यह प्रमाणित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, उनका गरीबों के प्रति, जरूरतमंद लोगों के प्रति, समाज के उन लोगों के प्रति, जो अभी मैनस्ट्रीम में नहीं आ पाये हैं, उनके लिए उनकी बहुत अच्छी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के विकास में बहुत काम हुए। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत बड़े काम किये इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। चूंकि समय की सीमा है इसलिये मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिलानी में उप-तहसील बनायी। माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे पिलानी में जब उप-तहसील बनायी, मैंने निवेदन किया कि उप-तहसील से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पिलानी की दो नगरपालिकाओं के लोगों को और 24 पंचायतों के लोगों को दूसरे विधान सभा क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसलिये मुझे इस बात के लिए खुशी है और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय राजस्व मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिलानी की उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कर दिया। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा और दूसरे विधान सभा क्षेत्र में उनको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि माननीय राजस्व मंत्री अभी सदन में मौजूद हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तहसील है, यह आपने बनायी है पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए, इसलिये जब तक वहां एस.डी.एम. का पद नहीं आयेगा, पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पालिसी है कि जहां तहसीलदार है, वहां आपका एस.डी.एम. होता है तो पहला तो मेरा निवेदन यह है कि एस.डी.एम. का पद भी मेहरबानी करके पिलानी में क्रियेट किया जाये और एस.डी.एम. को वहां बिठाया जाये ताकि पूरा का पूरा लाभ पिलानी के लोगों को मिल जाये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 24 पंचायतें, 50 से ज्यादा गांव और 2 पूरी नगरपालिकाएं, पिलानी और विद्याविहार पिलानी, यह इतने लोग हैं, उन लोगों को एस.डी.एम. के काम के लिए किसी दूसरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं जाना पड़े, इसलिए एस.डी.एम., पिलानी का पद भी आप कृपा करके क्रियेट करें। जब तक यह पद सृजित नहीं हो जाये, तब

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

तक जो एस.डी.एम. है पिलानी विधान सभा क्षेत्र में, एस.डी.एम. चिड़ावा, उसके माध्यम से पिलानी तहसील है, उसका काम प्रशासनिक दृष्टि से उनके नियंत्रण में हो, वह एस.डी.एम. चिड़ावा के नियंत्रण में हो और उसके बाद जब एस.डी.एम. पिलानी बन जाये तो उसके नियंत्रण में हो।

माननीय सभापति महोदय, यहां मैं यह रेफर करना चाहता हूं कि एक उप-तहसील और है मंड्रेला, जिस दिन आप एस.डी.एम. पिलानी बनायेंगे तो वह मंड्रेला वाली उप-तहसील भी एस.डी.एम. के नीचे आयेगी, इसलिये पूरा काम एस.डी.एम. को मिलेगा, उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या गम्भीर पेयजल संकट है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल में पहले विधान सभा क्षेत्र पिलानी शामिल नहीं था। हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय जलदाय मंत्री महोदय की कृपा से डी पी आर को अमेंड करवाया। 8780 करोड़ रुपये की डी पी आर बनी। अभी कुछ दिनों पहले 8026.76 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी, डी पी आर बन चुकी है। अभी राज्य स्तर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, स्कीम सैंक्शन कमेटी है, उसकी मीटिंग आने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी फर्स्ट मीटिंग में यह जो डी पी आर है, इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए ताकि पिलानी विधान सभा क्षेत्र तो है ही, इसके साथ-साथ नीम का थाना भी है, सूरजगढ़ भी है, सिंघाना भी है, अन्य भी कई जगह हैं जहां पर इससे पानी मिलेगा। इसको एक्स्पेडाइट करने की जरूरत है, अदरवाइज अभी पीने के पानी की सर्दियों में भी गम्भीर समस्या है। गर्मियों में क्या हाल होगा, यह आप इमेजिन कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, पी एच ई डी मिनिस्टर को और जल संसाधन मंत्री को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के गहरे पेयजल संकट का निदान करने के लिए तुरंत कोई तात्कालिक उपाय करें। जब तक चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी नहीं आता है, तब तक हमारे सभी किसानों को खेतों में एक-एक कुंड दें तथा कंटिन्जेंसी प्लान बनाकर के सभी जगहों पर ऐसी योजना बनायें जिससे कि पानी उपलब्ध हो सके।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछली बार चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के लिए इसी सदन में माननीय

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मुख्य मंत्री महोदय ने किया था। अगर वह 500 करोड़ रुपये अन्यथा अभी तक कहीं काम नहीं आये हों, क्योंकि डी पी आर चेंज हुई है तो उन 500 करोड़ रुपयों को तात्कालिक योजना बनाने के लिए, कंटिन्जेंसी प्लान बनाने के लिए, पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए काम में लें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था, कई पत्र माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को लिखे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र लांबा गोठड़ा, इूलानिया, बेरी और बनगोठड़ी हैं, इनको आप पी एच सी में अपग्रेड करिये, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाइये। इस बजट में अभी तक वह नहीं आये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपना जवाब दें तो यह लांबा गोठड़ा, इूलानिया, बेरी और बनगोठड़ी, यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वे घोषणा करें। वहां के लोगों को जो अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, 10-10, 15-15, 20-20 पंचायतों के लोग हैं, ढाणियों के लोग हैं, जिनके पास समुचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, यह बन जायेगी तो सबको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

इसी प्रकार से मेरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिड़ावा है। चिड़ावा एक बहुत बड़ा नगर है। वहां जो सी एच सी इस समय है, उसमें बेड्स की संख्या मात्र 75 है, जबकि अन्य सारी सुविधा उसमें उपलब्ध है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 25 बेड्स इसमें बढ़ायें। 100 बेड्स तो कम से कम करें। इसका जो दर्जा है, वह उप जिला अस्पताल के रूप में इसको घोषित करें। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जवाब आयेगा, उसमें यह उम्मीद करूंगा और उत्सुकता से इंतजार करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी सी एच सी चिड़ावा को उप जिला हास्पिटल के रूप में मान्यता देवें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार पिछले बजटों में कृषि उपज मंडी समिति और पॉलिटेक्निक कालेज के लिए घोषणा हुई थी। पॉलिटेक्निक कालेज चल रहा है। चूंकि पिलानी में सरकारी जमीन की उपलब्धता लगभग नगण्य है, इसलिए जिला कलेक्टर को राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिये जाएं कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

वह इन दोनों संस्थाओं के लिए पिलानी में जमीन उपलब्ध कराये ताकि वहां भवन बन सके।

पशु चिकित्सा केन्द्र, सरदारपुरा और नूनियां गोठड़ा यह उप केन्द्र हैं। यह जो एरिया है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, वह हमारे पशुपालकों का मुख्य स्थान है। पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारपुरा और नूनियां गोठड़ा, इनको पशु चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत करके मुझे अनुग्रहित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैंने बराबर 295 भी लगाये हैं, 131 भी लगाया है, लेकिन अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय इस ओर गंभीरता से देखें। पिलानी विधान सभा क्षेत्र का जो सड़क नेटवर्क है, वह बहुत कमजोर है। इसके लिए मैंने इन दोनों ही महानुभावों को पत्र भी लिखा है। मैं निवेदन करता हूं कि मैंने 41 रोड की एक सूची भेजी है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वहां पर कोई रोड की सुविधा नहीं है। मात्र 35 करोड़ रुपये की उसमें आवश्यकता है। पी डब्ल्यू डी का जो एस ई, झुंझुनूं से लेटेस्ट असेसमेंट बनकर आया है, खाली 35 करोड़ रुपये चाहिए। इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त रोड्स हैं, नॉन पेचेबल रोड हैं, उनके लिए 16 करोड़ रुपये चाहिए। यह 35 और 16 करोड़ की बहुत छोटी सी राशि राज्य सरकार के बजट को देखते हुए है। मैं निवेदन करता हूं कि विशेष स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनूं को मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए दें, ताकि यहां का जो रोड नेटवर्क है, वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी 2 स्कूलें बड़ी पिक्युलियर सिचुएशन में हैं, एक चिड़ावा की अडुकिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक ब्लाक पिलानी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगीना है। वहां साइंस है, साइंस चल रही है, लेकिन हर विद्यार्थी साइंस में नहीं चल पाता है। अभिभावकों को भी लगता है कि बच्चा आर्ट्स में चल जायेगा। जब वहां आर्ट्स नहीं मिलती है तो बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है और वह घर बैठ जाते हैं। दूर जा नहीं सकते हैं। मेरा क्षेत्र किसानों और मजदूरों का क्षेत्र है, निर्धनों का क्षेत्र है, जरूरतमंदों का क्षेत्र है। यह छोटी सी बात है। ये दोनों स्कूलें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अडुकिया, चिड़ावा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगीना, ब्लाक पिलानी, इनमें कला संकाय भी जरूर करें। इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चे वाला काम भी नहीं है। इन दोनों स्कूलों में कला संकाय होने से जो बच्चे साइंस में नहीं चल सकते, उनको पढ़ने के आगे अवसर मिलेंगे। इनमें बच्चियां भी शामिल हैं।

अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी लिस्ट नहीं भेजी है, बल्कि सलेक्टेड जगह की लिस्ट भेजी है। मैंने भी भेजी है और जो हमारे 2 CBEO हैं, उन्होंने भी भेजी है। बिलकुल स्पेसिफिक उसमें कारण लिखे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन लिखी है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जैसे एक हजार स्कूल्स की घोषणा हुई है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल्स खुलेंगी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से जो प्रस्ताव अधिकारियों के मार्फत भी आये हैं, मैंने भी आपको भेजे हैं, एक बार नहीं अनेक बार भेजे हैं, कृपया उन पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक गौर करें।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। आप जो अग्रणी आदमी जा रहा है, उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सिल्वर मैडल अगर वह ले रहा है तो वह गोल्ड मैडल की तरफ जा रहा है। इसलिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल और यह 2 मैंने कला संकाय खोलने के लिए आपसे निवेदन किया है, वह आप जरूर खोलकर मुझे अनुग्रहित करें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार कृषि महाविद्यालय के रूप में मुझे बहुत बड़ी सौगात दी थी। मेरा तो क्षेत्र ही किसानों का है। कृषि महाविद्यालय मुझे स्वीकृत किया था। सदन को आपके मार्फत मैं जानकारी देता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के चिड़ावा नगर में कृषि महाविद्यालय चालू हो गया है। मैंने टेम्परेरी बिल्डिंग के अंदर व्यवस्था कर दी है। हमारे बच्चों के शत-प्रतिशत एडमिशन हो गये हैं। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां स्कूल की बिल्डिंग के लिए, लड़कियों के हॉस्टल के लिए, लड़कों के हॉस्टल के लिए हमें जगह चाहिए। साथ ही 300 बीघा का रिसर्च फार्म चाहिए। बिना रिसर्च के, बिना एक्सपेरिमेंट के एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने खाली इस सेशन के लिए हमारे यहां एक श्रीधर यूनिवर्सिटी है, वहां से प्रेक्टिकल करने की सुविधा बच्चों को

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

दिला दी है लेकिन यह कब तक चलेगा? यह चल नहीं सकता। वहां यह जमीन की व्यवस्था जिला कलेक्टर करे।

साथ ही एक और निवेदन करता हूं कि जमीन का एक प्रस्ताव यहां डी एल बी में आया हुआ है। माननीय यू डी एच मिनिस्टर साहब चले गये, लेकिन उनको आप कन्वे करेंगे कि डी एल बी में एक प्रस्ताव आया हुआ है कि चिड़ावा के बिलकुल नजदीक भगिनिया जोहड़े के नाम से एक जमीन है, वह नगरपालिका ने अभी अलाट नहीं की है। चूंकि वह बड़ा चंक था, यहां डी एल बी के पास आया हुआ है। आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को निवेदन करता हूं कि वह कृषि महाविद्यालय, चिड़ावा के लिए भगिनिया जोहड़ में जमीन अलाट करायें ताकि मैं वहां राज्य सरकार से बजट लेकर के कालेज बनवा सकूं, लड़कियों का हॉस्टल बनवा सकूं, लड़कों का हॉस्टल बनवा सकूं। 300 बीघा का जो रिसर्च फार्म है, वह भी डवलप करने के लिए जमीन दी जाए। मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि जब इस क्षेत्र में सेटलमेंट आया था तो उन्होंने सारी जमीन या तो जोहड़े में डाल दी या उसको चरागाह कर दिया जबकि मौके पर न चरागाह है और न जोहड़ है, पानी वाली बात है ही नहीं। हमारे यहां कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई सतही पानी का साधन नहीं है तो जोहड़ कहां से होगा? वहां जोहड़ नहीं है इसलिए राज्य सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, प्रस्ताव जिला कलेक्टर के यहां से आ गये होंगे या आ जाएंगे। जोहड़ को, बिलकुल खाली पड़ा है, किसी काम नहीं आ रहा है, उसमें अगर बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है तो मेरे विचार से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वास्तव में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे बच्चे बनने की राह पर चल पड़े हैं, वे बन जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र में 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। बहुत अच्छे थे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे सिस्टम में भी नहीं है, लेकिन नौजवानों के आंदोलन करने के बावजूद 10 साल तक धरने पर बैठने के बावजूद एक भी कालेज नहीं मिल पाई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपके मार्फत, सदन के मार्फत कि 4 कालेज दी, अभी 2 साल तो कोरोना खा गया,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मेरे इसी टेन्योर में 4 कालेज दीं, 01 गवर्नमेंट कालेज चिड़ावा, 01 कन्या महाविद्यालय, पिलानी, 01 पॉलिटेक्निक कालेज, पिलानी और 01 कृषि महाविद्यालय, चिड़ावा, ये 4 कालेज दीं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला कलेक्टर को लिखकर इनकी जमीन वगैरह की जो समस्या है वो निपटाई जानी चाहिए। आपके यहां से डायरेक्शन जाएगा तो मेरे विचार से यह मेरी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की समस्या जो नये कालेज बने हैं उनमें सभी जगह विद्यमान हैं। अगर सभी जगह नये अपोइंटमेंट नहीं कर सकें, ट्रांसफर परमानेंट नहीं कर सकें तो कार्य व्यवस्था के लिए वहां टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ इन कालेजों में लगाया जाए ताकि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां जो कालेज खुले हैं, उनमें लगभग सेंट-परसेंट एडमिशन हो गये हैं।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स ईएन, पी डब्ल्यू डी का एक दफ्तर मैंने मांगा है। कारण है उसका, दो सब-डिविजन तो हमारे हैं, एक सब-डिविजन बिलकुल पड़ोस में सूरतगढ़ का है, तीन सब-डिविजन पी डब्ल्यू डी के हैं, एक्स ईएन दफ्तर के लिए हमें 65 किलोमीटर जाना पड़ता है। 65 किलोमीटर जाना पड़ता है एक्स ईएन, डिविजन आफिस के लिए। चिड़ावा में बिल्डिंग बनी हुई है और सब कुछ है। श्रीमती इंदिरा गांधीजी जब सूचना और प्रसारण मंत्रीजी थीं, तब उसके आसपास उद्घाटन करने के लिए वो आई थीं। ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, इसलिए एक एक्स ईएन, पी.डब्ल्यू.डी का वहां पर बैठना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मंड्रेला मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक्स्ट्रीम कोना है जो चूरू से लगता है और उधर अन्य स्थानों से लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जो नोर्म्स तय कर रखे हैं, उन नोर्म्स से कहीं ज्यादा कनेक्शन उपभोक्ताओं के हैं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था और अब भी मैं निवेदन कर रहा हूं। अभी यहां सदन में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र के मंड्रेला में एक पद ए ईएन, अजमेर

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सृजित होना चाहिए। उनको बगड़ जाना पड़ता है। बगड़ झुंझनूं विधान सभा क्षेत्र का है, पिलानी विधान सभा क्षेत्र का है ही नहीं। दूसरे विधान सभा क्षेत्र में जाना बड़ा तकलीफदेह होता है और आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वहां कोई मिले, नहीं मिले तो माननीय सभापति महोदय, एक वह जरूर आपके माध्यम से चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी माननीय खेलकूद और युवा मामले मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र, बल्कि झुंझुनूं जिला, फिजिकली साउंड लोगों का क्षेत्र है। खेलकूद में जो बहुत आगे बढ़ते हैं, जो टेलेंटेड बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, उनके लिए जाना-माना क्षेत्र है, लेकिन सुविधाएं तो होनी चाहिए। बिना सुविधाओं के हमारे बच्चे किस प्रकार से अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु हनुमान व्यायाम शाला है, सार्वजनिक संस्था है, किसी प्राइवेट आदमी की नहीं है, हमारे सांसद शीशरामजी ओला साहब, उन्होंने उसको डवलप किया था, सांसद कोष से काफी पैसा लगाया। मैं जब एम एल ए बना तो मैंने भी पैसा लगाया। हमारे पास जमीन है, 1.26 हैक्टेयर, उसमें खेल स्टेडियम बनना चाहिए। अगर खेल स्टेडियम किसी अन्य योजना में नहीं बन रहा हो तो मैं मेरे विधायक कोष से 25 लाख रुपये की घोषणा कर रहा हूं। 25 लाख रुपये की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है। माननीय खेलकूद और युवा मामले मंत्रीजी इसको स्वीकृत करने की घोषणा इसी जवाब में कर दें। मेरा चैक सी ई ओ के पास पहुंच जाएगा ताकि कम से कम 50 लाख में तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम चिड़ावा में बने।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मंड्रेला में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, उसका खेल का मैदान है, किसी अन्य योजना के अंतर्गत वहां पर भी एक खेल का मैदान बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इन सब मांगों के बावजूद भी मैं कन्क्लूड करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का यह जरूरतमंद और बेसहारा, गरीबों का, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए बनाया गया बजट बहुत सराहनीय है, खुशहाली देने वाला है और मैं इसके पक्ष में अपना जोरदार समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्रजी ने काफी बातें बोलीं, वो पूरी रिपीट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस छोटी-सी उम्र में सदन के नेता ने एक नया ही इतिहास रचा है। प्रजातंत्र में पहली बार बजट में इस प्रकार की रीडिंग हुई है जिसमें फिगर्स पिछले साल के बजट के थे। उन्होंने कहा था कि गलती से पेज लग गया लेकिन बाकी बातें हैं वो उसमें साथ में रही हैं, गलती से तो नहीं हुआ। विधान सभा में पारित होने के लिए प्रस्तुत हो गया, आसन का आदेश हुआ, काम चालू हो गया लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष बजट भाषण में लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी। ये इतनी थोथी महसूस होंगी, ये मजबूरियां हैं वरना इस बजट में न तो कोई दिशा है और न ही कोई गति है। 2013-14 में भी इसी तरह की झड़ी लगाई थी। रिकार्ड है, प्रतिपक्ष में हम लोग बैठे थे। हम लोगों ने कहा भी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं माने और उसका रिजल्ट सामने आया। आर बी आई ने स्टडी करवाई, राज्य कर्ज बोझ से कराह रहे, कर्ज के जाल में राज्य फंसता जा रहा है। इसमें तीन स्टेट हैं, पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल और हमारा राजस्थान उसमें सम्मिलित है। 31.05.2024 तक अनुमानित था, 2021-22 में 3.96 जो कि वास्तव में चालू वित्तीय वर्ष में 4.33 तक हो गया है जबकि केन्द्र ने राज्यों को जी एस डी पी का राजकोषीय घाटा 3 परसेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कम्पनीज के लिए 0.5 का रिलेक्सेशन देते हुए किया। तब तक अनुमति दी है। माननीय सभापति महोदय, 4.33, इस पर तो आप सहमत होंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज तो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, ये तो रहेंगी ही, इसको कैसे आप सुधार पाएंगे, यह सम्भव लगता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने अपने 9 फरवरी को दिये गये भाषण में चेतावनी दी थी, कुछ स्टेट्स ने अर्थ नीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया, उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स को जाकर समझाने की बात कही। हमारे पड़ोसी देश चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, तात्कालिक लाभ के लिए, चाहे आने वाली पीढ़ी भुगतान करे, ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए, लेकिन इस पर आर्थिक सेहत के सम्बन्ध में डिसिप्लीन का रास्ता है वही अपनाने से पार पड़ेगी वरना अर्थ का अनर्थ होगा। राजकोषीय जवाबदेही और

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बजट प्रबंधन देश में राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए एफ आर बी एम कानून 2003 में लाया गया, जुलाई 2004 से इसको लागू किया गया। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था का आकार काफी छोटा था, विदेशी निवेश के लिए परिस्थितियों के लिए यह कानून अनुकूल नहीं था जितना आज है। पर कैपिटा इनकम अन्य देशों की तुलना यह कानून में बहुत कम थी, लेकिन आज की स्थिति काफी बदल गई है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनने की ओर हम अग्रसर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी दूसरी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से वृद्धि करने वाली बन चुकी है। 2008-09 में ग्लोबल वित्तीय संकट के बाद भी दुनिया भर में फिस्कल पालिसी में भारी परिवर्तन आए, इस कारण से एफ आर बी एम कानून में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। उसको देखते हुए एनके. सिंह, पूर्व वित्त सचिव और सीनियर इकोनॉमिस्ट के अधीन एक समिति बनाई। समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकारों के ऋण के लिए केन्द्र सरकार का कर्ज जी डी पी का 40 प्रतिशत और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज 20 प्रतिशत होगा। समिति ने अपनी सिफारिश कर दी। मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में आत्ममुग्ध होकर कहा कि हमने पिछले चार बजटों में कोई नया कर नहीं लगाया। चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्टों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर 32 प्रतिशत डिविजिबल पूल में था, जिसे बढ़ाकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने 42 प्रतिशत किया है। इससे विकास के लिए कर और कर के अलावा केन्द्र अनुदान, ये दोनों मिलाकर, 2018-19 में जाएं, यह राशि 61 हजार 889 करोड़ थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख 1 हजार 711 करोड़ रुपये हो गयी।

पिछले पांच वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र का हस्तान्तरण औसत 45 प्रतिशत है, लेकिन अधिकांश लोक-लुभावनी योजनाओं में जा रहा है। राज्य के विकास पर व्यय नहीं हो रहा। राजस्थान में नया कर नहीं लगाने के बाद भी राज्य के स्वयं की कर आय में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका श्रेय केन्द्र की मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि केन्द्रीय आर्थिक नीति के कारण यह सम्भव हुआ है। यह तो मुख्य मंत्री जी मानते होंगे कि कांग्रेस ने जी एस टी को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहा था। मजाक उड़ाया था। उसी जी एस टी ने राज्य की झोली भर दी। 2017 में जब जी एस टी लागू हुआ, उस वर्ष राजस्थान को जी एस टी 12 हजार 137 करोड़ रुपये

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मिला था, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 48 हजार 946 करोड़ रुपये होगा। यह 400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। प्रदेश में कर राजस्व में जी एस टी का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है, लेकिन राज्य के स्वयं का कर राजस्व पिछले पांच वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाया। 2019-20 में यह राशि 59 हजार 245 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1 लाख 14 हजार 169 करोड़ हो जायेगी। लगभग 93 प्रतिशत वृद्धि है। इसमें जी एस टी की राशि घटा दी जाये तो 2019-20 में कर राजस्व गैर कर जी एस टी 37 हजार 291 करोड़, जो आगामी वित्तीय वर्ष में 65 हजार 223 करोड़ रुपये होगी। गैर कर राजस्व में पिछले पांच वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019-20 के गैर कर राजस्व में आय 15 हजार 714 करोड़ थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 21 हजार 97 करोड़ होगी। इस गैर कर राजस्व में पिछले पांच वर्षों में 6 हजार 143 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में केन्द्रीय नीतियों की आलोचना की। वास्तव में आर्थिक नीति के कारण केन्द्रीय राजस्व व जी एस टी में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए केन्द्र सरकार की प्रशंसा न करके आलोचना करना मुख्य मंत्री जी की राजनीतिक ईमानदारी नहीं लगती। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उन्होंने सीएसएस के जितने भी दान हैं, जो केन्द्र से राशि मिलेगी, उसमें पहले राज्य का अपने हिस्से का जो पैसा खर्च करना पड़ता था और राशि मिल जाती थी, अब वह पूरी राशि खर्च करने के बाद में मिलती है।

(समय: 13.44 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

जल जीवन मिशन के 27 हजार करोड़ रुपये, जो केन्द्र सरकार से मिले, राज्य सरकार ने अपने अंश के सिर्फ साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं। उसके बाद वह राशि कहां जमा होती है? पी डी अकाउंट में जमा होती है। उसका रेवेन्यू सरप्लस दिखाकर आपने अपने बजट का आकार बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए आर बी आई और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रोन्ग फिगर्स के आधार पर अपनी आमदनी बढ़ाकर राज्य सरकारें दिखा रही हैं, यह वास्तव में सही फ्रेमवर्क नहीं है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में सोशल सिक्योरिटी को लेकर काफी चिन्ता जतायी। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सामाजिक सुरक्षा की प्रशंसा करते हुए पूर्व राष्ट्रपति

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बराक ओबामा को भी उद्धृत किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियां विभेदकारी थीं। इस सम्बन्ध में मैं नोबेल लॉरिएट स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियों की समीक्षा की थी, "Gunnar Myrdal was a lifelong foe of inequality, and supporter of wealth redistribution, he showed how economic policies implemented by President Franklin Delano Roosevelt, including the minimum wage law and restrictions on cotton production, hurt African-Americans.". विभेदकारी थीं, इसलिए नीतियों में परिवर्तन भी करना पड़ा। हम वेलफेयर स्टेट हैं। हमारी सरकारें जनता के कल्याण के लिए काम करती हैं, इसलिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की आड़ में चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी बांटने का विरोध होना चाहिए। फ्रीबीज के चक्कर में अनेक कल्याणकारी योजनाओं में धनाभाव के कारण कटौती करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी ने पुरानी पेंशन स्कीम तो लागू कर दी, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं तथा एन पी एस की आलोचना की है। हर स्कीम, योजना में रिस्क होता है। रिस्क का नाम ही लाभ है। यू पी ए शासनकाल में एल आई सी, एस बी आई आदि बैंकों ने कई नामी-गिरामी कम्पनियों में निवेश किया था, जो डूब गयीं। ओ पी एस में भी रिस्क है।

मुख्य मंत्री जी, आपको याद दिला दूं। 1999 में जब आपकी पार्टी ने सत्ता सम्भाली थी और आप मुख्य मंत्री बने थे तो आपकी जिद के कारण रिटायरमेंट एज 60 से घटाकर 58 की गयी। इसके कारण एक साथ रिटायर्ड लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ देना पड़ा। काफी लोगों का भुगतान रोकना पड़ा। बैनिफिट्स का भुगतान रोकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति डांवाडोल हो गयी। योजनाओं के आकार में भारी कटौती की गयी। आरबीआई से लगातार ओवरड्राफ्ट लिया गया। कर्मचारियों के वेतन देने के लिए धनराशि नहीं थी। बार-बार वित्त निगम से करोड़ों रुपये का उधार लेना पड़ा। ऐसी स्थिति से काम चलने वाला नहीं।

सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य के राजस्व, पूंजी व ऋण के आंकड़े बताना चाहूंगा। 2020-21 में 2 लाख 91 हजार 191 था, जब कर्ज का भार 1 लाख 1 हजार 363 करोड़, 35 प्रतिशत भार था। कर्ज का भुगतान था 56 हजार 128 करोड़, 2022-23 में कुल व्यय 3 लाख 46 हजार 182 करोड़, कर्ज का भार 1 लाख 22 हजार 819 करोड़, 35.47

(श्री नरपत सिंह राजवी)

परसेंट पर पहुंचा। कर्ज का भुगतान 72 हजार 714 करोड़, था। 2022-23 के संशोधित अनुमान। 3 लाख 82 हजार 246 करोड़, कर्ज का भार 1 लाख 50 हजार 685 करोड़, 39.42 परसेंट। कर्ज भुगतान 1 लाख 4 हजार 810 करोड़, था। 2023-24 के बी ई में 3 लाख 90 हजार 856 करोड़, कर्ज का भार 1 लाख 48 हजार 355 करोड़, 38 परसेंट। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप देखें तो कुल व्यय का 8.29 प्रतिशत हम व्यय कर रहे हैं। टोटल बजट एलोकेशन बढ़ाने के लिए आकार बढ़ाने पर ब्याज की देनदारी प्रतिशत के अनुपातिक आधार पर कम होनी चाहिए। तभी जाकर प्रगति दिखेगी। ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सदन के नेता ने कम्पेयर भी किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018-19 में 16 हजार 638 करोड़ था जो 2023-24 में 38 हजार 61 करोड़ हो गया। यह कम्पेयर तो किया है लेकिन खुद की गवर्नमेंट के दस्तावेज तो देख लेते। 2021-22 में 28 हजार 88 करोड़, का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान था जो घटकर 24 हजार 152 करोड़, रह गया। 2022-23 के बी.ई. में 34 हजार 809 करोड़, था जो घटकर 29 हजार 141 करोड़, रह गया, 8.42 परसेंट, 10 परसेंट से कम हुआ है। अब 9.74 परसेंट बता रहे हैं पर वास्तविकता में यह कहां जाकर पहुंचेगा यह ईश्वर ही जानता है। बजट भाषण के पैरा 5 में 2018-19 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, यह तो बता दिया। आपने वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान 28 हजार 88 करोड़, का प्रावधान किया था, वास्तव में खर्च 24 हजार 152 करोड़, हुआ और चालू वित्त वर्ष में 5 हजार 668 करोड़ की कमी करके संशोधित अनुमान 29 हजार 148 करोड़, किया है।

पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय एक-दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की उपेक्षा कर रही है। पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करते हैं और साथ ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। In other words, such investments support future growth in the output of economy. पूंजीगत व्यय से रोजगार का सृजन होता है विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। Capital expenditure increases the economy’s demand for products and services, and is essential for boosting private sector. केन्द्र सरकार ने अपने बजट 2023-24 में पूंजीगत खर्च के लिए 13.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो जी डी पी का 4.5 प्रतिशत है। केन्द्रीय बजट, decided to continue the 50-year interest free loan to state governments for one more year to spur investment in

(श्री नरपत सिंह राजवी)

infrastructure and to incentivise them for complementary policy actions, with a significantly enhanced outlay of Rs. 1.3 lakh crore. यह स्टेट्स को और दिया है और उसके बाद भी अगर नहीं कर पायें तो ईश्वर ही मालिक है।

सभापति महोदय, राजस्व प्राप्तियां, राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। आर ई और बी ई में तो भारी अन्तर आता ही है। 2023-24 में 1 लाख 14 हजार 169 करोड़ का कर राजस्व दिखाया है, गैर कर राजस्व 24 हजार 285 करोड़ दिखाया है। लेकिन इसमें केन्द्र का हस्तान्तरण कितना है वह 61 हजार 522 करोड़ बी ई में आया है और 33 हजार 982 करोड़ बी ई में अनुदान, कुल राजस्व यह हो गया 2 लाख 33 हजार 988 करोड़। The individual share of Rajasthan in taxes devolved by the centre out of 100. 14वें वित्त आयोग में 5.495 परसेंट था, 15वें वित्त आयोग में 5.979 था और वर्ष 2021-22 से 2025 तक 6.026 परसेंट का डिवॉल्यूशन है। इतना बड़ा डिवोल्यूशन होने के बाद फ्रीबीज के कारण से अगर डवलपमेंट नहीं हो तो ईश्वर ही मालिक है।

राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय हस्तान्तरण। 2017-18 में 60 हजार 968 करोड़ था और 2023-24 बी ई में 95 हजार 534 करोड़, जो कि 40 परसेंट है और औसत 5 वर्षों का 45 परसेंट डिवोल्यूशन है केन्द्रीय हस्तारण का। यह बहुत बड़ी राशि है।

सभापति महोदय, GST receipts as percentage of own tax revenue-2017-18 में 50 हजार 605 करोड़, 2022-23 में 98 हजार 294 करोड़, बी ई में, आर ई में 92 हजार 718 करोड़, था। 2023-24 की 1 लाख 14 हजार 169 करोड़, है जिसमें जी एस टी का कम्पोनेंट पहले 12 हजार 137 करोड़ 2017-18 में था, 2023-24 में 48 हजार 946 करोड़ का है पर परसेंटेज के हिसाब से 42.87 प्रतिशत है जो छोटा डिवोल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा डिवोल्यूशन है।

जी एस डी पी का अग्रिम अनुमान। पैरा 4.58, 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जी एस डी पी के पूर्व व अग्रिम अनुमान कई राज्य स्वयं की परिकल्पनाओं के आधार पर 2019-20 के सन्दर्भ में उपलब्ध कराते हैं लेकिन वे एन एस ओ द्वारा सत्यापित नहीं होते। राज्य सरकारें इन अनुमानों को आधार बनाकर अगले वित्तीय वर्ष के लिए आधार

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रूप में ले लेती हैं इसलिए जी एस डी पी के अनुमान सही नहीं हैं और वास्तव में हकीकत में यह होकर दिखेगा।

सभापति महोदय, इकोनोमिक ग्रोथ। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पैरा 260 में उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान की जी एस डी पी की वृद्धि दर भारत सरकार की जी एस डी पी की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी वर्ष अपने बजट भाषण में कहा है, as per the first advance estimates of National Income for 2022-23, the India's Real GDP and normal GDP are projected to grow by 7 per cent and 15.4 per cent, year-on-year basis in 2022-23.

ऋण एवं देनदारी, कितना घी पीया है। 2019 में 3 लाख 11 हजार 373 करोड़, जो बढ़कर बजट एस्टिमेट में हो गया 5 लाख 79 हजार 781 करोड़। आपके कार्यकाल के पांच बजटों में राज्य का कर्ज एवं देनदारियां जो 31 मार्च, 2019 में 3 लाख 11 हजार 373 करोड़, थी उससे बढ़कर 5 लाख 79 हजार करोड़ होना 86 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे आप अनुमान लगायें कि वास्तव में यह अच्छी है या गलत है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में आज प्रश्न आया तो मैंने इसको भी उठाना उपयुक्त समझा। आप तो स्वयं अधिकारी रहे हैं। मैंने पिछले बजट के समय भी कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जहां पर ट्रैप करता है और लाइव ट्रैप हो जाता है, रिकार्ड हो जाता है, उसके बाद उसको डिसमिस करने के अलावा कोई चारा नहीं है और वह 10 साल मुकदमा लड़ेगा पर कोई मतलब नहीं रहता था। आपको दण्डात्मक कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। मैंने भी एक प्रश्न पूछा था, नाम से पूछा था लेकिन संख्या के हिसाब से उत्तर दिया है। डिपार्टमेंट्स को गबन के या आय से अधिक सम्पत्ति के या ट्रैप के केसेज में अनुमति देने में क्या तकलीफ है? अभी मंत्री जी ने कह तो दिया कि इसमें अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान कैसे चलता है और रोका कैसे जाता है, कैसे-कैसे इसको डायवर्ट किया जाता है, यह अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अधिक गम्भीरता दिखायें और कानून में संशोधन लायें।

आपका एक ध्यान और दिलाना चाहता हूं, हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय मंत्री जी विराजमान हैं। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना-2020-21, कितनी स्कूटी वितरित कीं, श्रेणियों में किस प्रकार विभाजन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किया और मेरिटोरियस होने का प्रमाण कोई जिलों से मिलेगा? वह सी बी एस ई और राजस्थान बोर्ड से मिलेगा। उसमें अलग-अलग करके आपने इस तरह से कर दिया, ऐसी रेवड़ियां बांटी हैं। जयपुर की एक बच्ची है, जिसके 94.20 प्रतिशत मार्क्स आये हैं और उसको स्कूटी नहीं मिली है और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर 50 प्रतिशत जिस बच्ची के आये हैं, उसको स्कूटी मिल गई। हमने इस तरह की बन्दरबांट पिछले 40 वर्षों में तो नहीं देखी। आप सुधार करेंगे। इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए योजना में आप संशोधन लायेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।

(समय: 14.00 बजे)

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री मेवाराम जी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज बजट 2023-24 पर चर्चा हो रही है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही अपने-अपने विचार रख रहे हैं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट, ये अभी कह रहे थे, साढ़े तीन घंटे इस विधान सभा के अन्दर बोले। जो घोषणाएं की हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, एस.सी. हो, एस.टी. हो, माइनोरिटी हो, ई डब्ल्यू एस हो, सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, इस बजट का लाभ राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता को किसी न किसी तरह मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस बजट से राजस्थान की 80 परसेंट जनता को लाभ मिल रहा है, 270 घोषणाएं हुई हैं। हम बाहर से चुनकर आये हैं। आजकल इतना नेटवर्क है यू-ट्यूब पर सीधा प्रसारण हो रहा है। सब देख रहे हैं कि हमारे जन प्रतिनिधि अन्दर क्या बोल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है और किस तरह से कार्य हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतना शानदार बजट न तो पहले कभी आया और न ही भविष्य में कभी ऐसा शानदार बजट आयेगा। मैं दावे के साथ आपको कहना चाह रहा हूं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): गहलोतजी भी नहीं लायेंगे?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप सुनें। आप क्या कह रहे हो, कभी कहते हो आपके पास पैसे नहीं हैं, खर्च नहीं कर पाओगे। आप पिछले चार साल का रिकार्ड देखो, कुल 2722 घोषणाएं हुई हैं जिनमें से 85 परसेंट काम हो चुका है। आप बात कर रहे हो कि इनके पास फण्ड नहीं है, कहां से लायेंगे, क्या करेंगे? आप बातों में ही उलझे रहोगे। अभी जो घोषणाएं हुई हैं आपको पता नहीं है, आप यहां बैठे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो घोषणाएं की हैं, अभी से सभी विभागों और अधिकारियों को उनकी तैयारियां फील्ड में जाकर करने को कहा है। आपको पता ही नहीं है, फील्ड में क्या हो रहा है। वहां जाकर पूछें। ये घोषणाएं खाली घोषणाएं नहीं हैं। आपको लग रहा है कि ये घोषणाएं आपके लिए कितनी महंगी पड़ेंगी। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, यह जनता गुमराह नहीं होगी। आपको इस बार सबक सिखा कर रहेगी कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने किस तरह से लोक-कल्याणकारी योजनाएं इस राजस्थान में लागू की हैं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कोरोना काल रहा हो, भीलवाड़ा मॉडल हो, कोई भूखा नहीं सोये, सोशल सिक्योरिटी, अन्तिम छोर पर बैठे हुए आदमी को कैसे हम मुख्य धारा में लायें, इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। आप रेवड़ियों की बात कर रहे हो। आप असत्य वादे करके केन्द्र की सरकार में जरूर आ गये हैं। आपने जो वादे किये थे, उनका क्या हुआ? क्या आपने लोगों को 15 लाख रुपये दे दिये? आपका काला धन वापस आ गया? क्या आपकी महंगाई कम हो गई? दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात का क्या हुआ? ये असत्य घोषणाएं आप कर सकते हैं, हमारे यहां असत्य घोषणाएं नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जिसमें दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मसाले उपलब्ध करायेंगे। ये उस गरीब के लिए कितना लाभकारी होगा? आप इसका विरोध कर सकते हो क्या कि मत दो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा उज्ज्वला योजना में आपने 76 लाख परिवारों को गैस सिलेण्डर पकड़ा दिये, वे खाली पड़े हैं। गरीब उनके ऊपर बिस्तर डालकर बैठे हैं, वापस भरा नहीं पाये, क्योंकि आपने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये रेट कर दी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम गरीब का चूल्हा जले। जो सिलेण्डर आपने दिये, ये बन्द नहीं रहें और घर पर नहीं पड़े रहें इसलिए उन्हें चलाने के लिए सब्सिडी देकर 500 रुपये में सिलेण्डर किया है।

(श्री मेवाराम जैन)

यह बहुत बड़ा कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस बात को मानते हैं और आपके मन में भी चुभ रहा है कि ये कैसे हुआ।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही घोषणा की थी कि मैं 5 साल तक किसी तरह की दरें नहीं बढ़ाऊंगा और न दरें बढ़ाईं। पहले 50 यूनिट फ्री की। अब इस बजट में 100 यूनिट फ्री की। इससे 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का बिल जीरो आयेगा। अब आप बताओ ये रेवड़ी है? इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आम गरीब जनता के बिल फ्री हो रहे हैं। आपके भी कम हो रहे हैं, हमारे भी पैसे कम हो रहे हैं। इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? यह जनता आपको बताएगी कि इस तरह की बातें जो कर रहे हो, आप सही बात बताओ, सही को सही कहने की हिम्मत रखो। आपकी तो एक ही बात है, हमें तो हर स्कीम का विरोध करना ही है। उसका कोई इलाज नहीं है। जनता सब जानती है।

आज किसानों की दो हजार यूनिट बिजली फ्री करना। यह कितनी बड़ी सौगात है? यह आप खुद जानते हो कि किस तरह से किसानों को खुशहाल करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है। आज हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने वहीं आकर विरोध किया। आप सारे विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आपके लिए इतना महंगा पड़ेगा कि आपका पता ही नहीं लगेगा। अभी तो सरकार की बातें कर रहे हो, हम सरकार में आ रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों का आप जितना विरोध करेंगे, ये सरकारी कर्मचारी आपको गंगाजी डालकर छोड़ेंगे। आप विरोध मत करो। आप केन्द्र को ही कहो कि ओ पी एस, पुरानी पेंशन को लागू करें। हमारे तो जो बाकी बचे हुए थे, उन सबको भी इसमें जोड़ दिया है। इसलिए आप इस शानदार योजना का स्वागत करें और विरोध नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, 1 लाख 42 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों दी जा चुकी हैं और 1 लाख 81 हजार प्रक्रियाधीन हैं। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर लगाने का फैसला लिया है। वेद विद्यालय, विवेकानन्द यूथ हॉस्टल, सावित्रीबाई वाचनालय और आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, गत बजट में भी देखा होगा, इतनी स्कूलें क्रमोन्नत करना, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सीनियर की हैं। इस बजट में भी माननीय मुख्य

(श्री मेवाराम जैन)

मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने नई स्कूलें खोलने की घोषणा की है। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने की घोषणा की है और खोली हैं। राजस्थान के अन्दर गरीब परिवार, गरीब बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। उसके लिए ये स्कूलें खोलकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नवाचार किया है जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और यह बहुत बड़ा कार्य है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राइट टू एजुकेशन हमारे क्षेत्र में बिखरी हुई ढाणियां हैं, वहां चार-पांच किलोमीटर का डिस्टेंस भी है। वहां पांचवीं से आठवीं तक नई स्कूलें, कुछ आठवीं से सीनियर स्कूलें और बढ़ायें, लोगों की डिमांड है। वास्तव में आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो सके।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, उसकी भी मजाक उड़ा रहे हैं। 10 से 25 लाख रुपये किया और जो गरीब इलाज नहीं करा सकता था, घर में ही इलाज की वजह से कई जानें गई होंगी, उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की। इस चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का खर्च सरकार उठायेगी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे राजस्थान में देखो एक्सीडेंट्स के कारण कितनी जानें जा रही हैं, उन एक्सीडेंट्स से उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? उसके लिए 5 लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये देने की घोषणा हुई है। यह मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उस परिवार को पता होगा कि उसके दस लाख रुपये घर में आने के बाद उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसके परिवार को किस तरह से लाभ मिलेगा, यह आप विचार करो। इसका भी विरोध है आपका।

सभापति महोदय, इतनी शानदार योजनाएं हैं। मुख्य मंत्री जी, जिस तरह से अब चिकित्सा के क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कालेज खोलना, पी एच सी खोलना, सी एच सी खोलना, डाक्टर नये लेना, मतलब चिकित्सा की किस तरह से शानदार व्यवस्था हो, राजस्थान में सारे अस्पतालों में लोगों को, गरीबों को, सबको मुफ्त मिले, सारे इलाज फ्री हों। यह सारा काम माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, चाहे जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें और जो मैन काम हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से गरीब परिवार, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, एकल महिला हो और

(श्री मेवाराम जैन)

पालनहार योजना हो, जिसके अन्दर इतनी पेन्शन राशि बढ़ायी है, यह उस परिवार या जिसको लाभ मिल रहा है उसको भी पता होगा कि यह पैसे सीधे उसके खाते में जा रहे हैं। पहले वह दर-दर ठोकरें खा रहा था। पहले मजबूर होकर उसको फिरना पड़ रहा था। परिवार में उस बुजुर्ग की कोई सुन नहीं रहा था। चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो उनकी हालत क्या थी, यह दर्द माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोचा और उनके लिए जो यह पेन्शन बढ़ायी है, इससे ज्यादा बढ़िया काम हो नहीं सकता। इसका भी आप विरोध कर रहे हो कि यह क्यों बढ़ायी।

यह आम आदमी आम गरीब के लिए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और गरीबों को और सबको साथ में लेने वाली सारी स्कीमें हैं जितनी भी देखो आप। इसमें शहर में शहरी रोजगार गारन्टी शुरू कर दी। इसमें सौ से सवा सौ दिन का रोजगार देने की योजना चलायी और सफाई कर्मचारियों की तीस हजार की भर्ती, आप कहोगे कि भर्ती ही नहीं होगी। आपको क्या पता होगी या नहीं होगी? इसी कार्यकाल में होगी और आप देखते रह जाओगे, इसलिये आप चिन्ता मत करो।

कोरोना के अन्दर लोगों की जो डैथ हुई उनके परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी देकर उनका पालन-पोषण हो, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच है। कितनी शानदार घोषणा है, इसको तो कम से कम आपको भी कहना चाहिये कि यह शानदार योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है।

चाहे सड़कों की बात हो, 5-5 सड़कें जिले में दी हैं। दस-दस करोड़ की सभी को दी हैं। इसमें आपको भी दी हैं तो यह इतनी शानदार घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। सभापति महोदय, चाहे नगरपालिका क्षेत्र में हो, 20 किलोमीटर नगरपालिका, 35 किलोमीटर नगर परिषद् और 50 किलोमीटर निगमों में की है। यह भी एक बहुत बड़ी शहरों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सौगात दी है। एक लाख वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? जिस तीर्थ में जाना चाहते हैं उनको ले जाकर दर्शन करा रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी इन योजनाओं को चाहे पांच लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए पांच हजार रुपये देने की घोषणा हो,

(श्री मेवाराम जैन)

लघु सीमान्त कृषक को फसलों का प्रमाणित किस्म का बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराना हो, कृषि बजट किस तरह से शानदार लाये हैं। इस बार राजस्व में नयी तहसीलें खोलना, पटवार मण्डल खोलना और सरलीकरण, 'प्रशासन गांवों की ओर' और इसके साथ-साथ क्राइम कम हो, किस तरह से थाने, चौकियां, सी ओ आफिस, एडिशनल एस पी आफिस की नयी घोषणाएं होना, उनके लिए बजट सैंक्शन करना, कई तरह की योजनाओं की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गायों के लिए, पता नहीं इनका ठेका लिया हुआ था कि गौमाता के नाम से कितनी ही बार इन्होंने वोट लिए होंगे पर आपने गौमाता के लिए कुछ किया है तो बताओ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 महीनों की जगह 9 महीनों का अनुदान किया। नन्दीशालाओं के लिए एक साल का अनुदान किया। विकलांग, असहाय जो गाय है उसके लिए एक साल का अनुदान किया। और तो और लम्पी डिजीज के अन्दर भयंकर बीमारी के अन्दर जो दुधारू पशु जिनकी डैथ हुई है किसान उस पर निर्भर था, कृषक उस गाय पर निर्भर था उसके लिए चालीस हजार रुपये देने की घोषणा की है। इस पर तो तालियां बजाओ। इसको तो कहो कि यह स्कीम तो बढ़िया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गायों के लिए भी कितनी घोषणाएं की हैं। आपके मन में गाय की सेवा करने का भाव ही नहीं है अब सरकार ने घोषणा की है कि पंचायत लेवल पर आप नन्दीशाला खोलो। आप पंचायत समिति लेवल पर खोलो, जिला मुख्यालय पर खोलो। उसके खोलने के लिए अनुदान और चलाने के लिए अनुदान, उसके लिए भी आपकी आत्मा नहीं मान रही है। आप यह कार्य नहीं कर रहे हो, आप खुलाओ, कोई फंड की कमी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री चाहते हैं कि जगह-जगह ये जो बेसहारा पशु हैं वो रोड पर नहीं घूमें और इनकी हम सेवा करें। आप भी इसमें पुण्य करो। पैसे सरकार दे रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा 2013 ए एन एम भर्ती का। भर्ती हो गई। बी जे पी सरकार जैसे ही आयी उसमें उन्होंने पद कम कर दिये। जिसका सलेक्शन हो गया था वह आज सड़कों पर घूम रही हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो 2013 की करीबन दो-ढाई हजार से ज्यादा नहीं हैं, इनको आप किसी

(श्री मेवाराम जैन)

तरह से भर्ती में शामिल कराओ, चाहे संविदा पर कराओ। एक सी एच ए भी है उनको भी आप किसी तरह से वापस इसमें लगाओ ताकि उनको रोजगार मिले, बेरोजगार नहीं रहे और बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको कैसे ही करके रोजगार पर लगाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, संविदा भर्ती कर्मचारी थे इनके लिए भी सरकार ने खूब अभी घोषणाएं कीं, जो उनकी मांगें थीं उनके बारे में भी सारी घोषणाएं कीं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र की बातें हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करिये, प्लीज।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दो-तीन मिनट मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने खूब दिया, इसमें कोई कमी नहीं है। बाड़मेर में 7700 करोड़ रुपये की लागत का पावर प्लांट लग रहा है जिसमें कितनों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। संत ईश्वर दास का पेनोरमा, सनावड़ा में चौकी, अभी ढाई सौ से ऊपर के गांव इसमें 42 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र अकेले में जुड़ेंगे और चाहे संस्कृत महाविद्यालय, वेद विद्यालय, बास्केटबाल की अकादमी और पी एच सी रावतसर, तो इस तरह से कई काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं पर दो-तीन ही काम मेरे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक चवा उप तहसील है, माननीय रेवेन्यू मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उस उप तहसील को खोलने के लिए मैंने निवेदन किया वह तहसील खोलें।

बिजली की ज्यादा मेरे यहां ज्यादा प्रोब्लम है इसलिये मैं 132 के वी का असाणी फांटा और एक बाड़मेर शहर में शिव नगर में 33 के वी का जी एस एस खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

चिकित्सा मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक ट्रक यूनियन डिस्पेंसरी थी, पांच करोड़ की जमीन उन यूनियन वालों ने डोनेट की है कि उसमें हमारी डिस्पेंसरी खोलो और हम यह जमीन पांच करोड़ की आपको दे रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस डिस्पेंसरी की आप इस बजट में घोषणा करें। वह पांच करोड़ की जमीन और बिल्डिंग बनी हुई है वह सरकार को देना चाह रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। बिसाला में मैं एक कालेज के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री मेवाराम जैन)

मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के कार्य के लिए माननीय पी एच ई डी मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वह धीमी गति से चल रहा है, इस कार्य को गति दें और ये योजनाएं जल्दी पूरी हों ताकि घर-घर कनेक्शन देने की मुख्य मंत्री जी की जो इच्छा है, वह पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में 100-100 हैंडपम्प देने की घोषणा की थी। अभी भी पानी की समस्या है, इसलिए आप इस बजट में भी 100-100 हैंडपम्प दें और कम से कम 50 ट्यूबवैल दें, ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। सभापति महोदय, जो यह शानदार बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह भूतो न भविष्यति है। ऐसा बजट न तो कभी आने वाला है इसलिए विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि आप ज्यादा विरोध मत करना वरना आपकी हालत और खराब होगी। इसलिए इस बजट को सराहो और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दो, जनता आपको दुआएं देगी। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किये गये बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का मौका दिया। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे भूतो न भविष्यति और खुद ही कह रहे हैं पानी नहीं है, ट्यूबवैल की जरूरत है, बिजली नहीं है और यह भूतो न भविष्यति है। यह असत्य का पुलिंदा पांचवीं बार पेश किया गया है। पहली बार जो बजट पेश किया, उसकी भी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। कोई रोड मैप नहीं है, पैसा आपके पास है नहीं, केन्द्र के ऊपर आप निर्भर करते हो। केन्द्र को कोसने के अलावा आपके पास में कोई काम नहीं है। आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, धरातल पर 40 परसेंट घोषणाएं भी अभी आप उतार नहीं पाये हो। ये हालात राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के हैं और उसके बाद भूतो न भविष्यति। निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति है। ऐसा घोर अन्याय राजस्थान की जनता के साथ कभी नहीं हुआ, यह भूतो न भविष्यति की बात सही है।

पूर्ववर्ती बजट घोषणाओं की बात करें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ बातें जो राजस्थान सरकार की कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में की गई थीं, उन बातों को बार-बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके कान पर

(श्री अभिनेश महर्षि)

जू रेंग नहीं रही है। आप लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया, आप लोगों ने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया और फिर इस बजट में जो बार-बार बात कर रहे थे कि हम युवाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कानून व्यवस्था, इन सब में सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं।

कानून व्यवस्था की क्या बात करें, आपके स्वयं के विधायक, सरकार के पूर्व डी जी और बहुत वरिष्ठ नेता, वह थाने के सामने धरने पर बैठते हैं कि हमारी एफ आई आर दर्ज नहीं हो रही है और वे राजस्थान के इस पवित्र सदन में भी अपनी भावनाओं को उजागर करने से नहीं चूके। कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ी हैं, यह आप सब लोगों को मालूम होना चाहिये।

पिछले बजट में 10 करोड़ रुपये की सड़कों के काम दिये गये थे। राजस्थान की सरकार इस बात का जवाब दे, आंकड़ों के साथ जवाब दे। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की बात करता हूं, पिछले बजट में 10 करोड़ की सड़कों में एक रुपये का भी काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं यह राजस्थान की सरकार का नमूना है।

सभापति महोदय, अभी मैंने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सुना, कमरे कब बना दोगे, केन्द्र सरकार से जब हमको बजट मिल जायेगा, तब बना देंगे। आपने स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, एक आदेश के तहत किया। भारत सरकार की योजना है कि यह देश सम्बल बने और बिना शिक्षा के यह नहीं बन सकता है, इसलिए भारत सरकार ने पैसा भेजा। राजस्थान सरकार उस पैसे पर कुंडली मारकर बैठ गई और लोगों को रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते हैं, आपने स्कूल खोल दीं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दी, इंग्लिश पढ़ाने वाला अध्यापक आपके पास नहीं है। आपके पास विद्यार्थियों को बिठाने के लिए कमरे नहीं हैं और उसके बाद सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार पैसा देगी, तब जाकर कमरे बनेंगे, तो भारत सरकार से पूछ कर खोल देते।

आपने पिछले बजट में जिला अस्पतालों की घोषणाएं कीं। मेरी मांग पर मेरे रतनगढ़ को जिला अस्पताल मिला था। सभापति महोदय, मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी रतनगढ़ के अस्पताल में 60 परसेंट से

(श्री अभिनेश महर्षि)

ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। आपने पी एच सी की घोषणा कर दी, पी एच सी का कहीं अता-पता नहीं है। सी एच सी की घोषणा कर दी, सी एच सी का कहीं अता-पता नहीं है। ऐसे हालात में यदि मैं यह कहूं कि यह असत्य का पुलिंदा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आपने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। आपके नेता जी ने दस तक की गिनती गिनकर वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन धरातल पर क्या हुआ? किसानों ने आपके कारण आत्महत्याएं कीं। किसान आपको लगातार कोसते रहे और मजबूर होकर जब किसान का खेत नीलाम होने लगा, तब जाकर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। आपको यह जनता कैसे माफ करेगी, क्या होगा, मुख्य मंत्री जी जवाब दें इस बात का।

आप बिजली की बात करते हो, सरदारशहर से आने वाले मेरे मित्र बैठे हैं, इनके इलाके में भी सिंचाई की बात होती है। यह सरकार से डरते हुए न कहें तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गया हूं। हमारे चूरू जिले में जहां रात को पाइप में बर्फ जम जाती है, जब बिजली आती है और उसको चालू करते हैं तो बर्फ के टुकड़े निकलते हैं और आप रात को 2 बजे, 3 बजे बिजली देते हो। किसान के प्रति आपके मन में थोड़ी बहुत तो दया आनी चाहिये। किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले आप लोग किसानों के साथ धोखा करने का काम करते हो। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसान को 6 घंटे बिजली देंगे। आप 8 घंटे बिजली देने की बात करने वाले लोग, आज 4-5 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते हो। अभी-अभी कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाईं। जरा पढ़कर आया करो, बिजली की दरें कितनी बार बढ़ा दी हैं? बिजली की दरें बढ़ाकर आप जनता के साध धोखा करते हो। आपने कहा कि हम यह फ्री कर देंगे, यह फ्री कर देंगे, आपके पास पैसा कहां है, क्या कर दोगे? आपने पहले के बजटों की घोषणाओं को तो अभी तक पूरा नहीं किया है।

आपके मन में किसानों के प्रति और गरीब के प्रति कितना दर्द है, इस बात का नमूना मैं बताता हूं। दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत गांवों में, सुदूर ढाणियों में हम कनेक्शन देते थे, रोशनी करने का काम करते थे। राजस्थान की सरकार ने आते ही एक कलम के साथ पहला आदेश किया कि गरीब के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिये और ढाणियों में बिजली देने की योजना को बंद कर दिया। शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार इस पुलिंदे में मुझे बता दे कि कहां आप लोगों ने बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी की बात की है। आप कहते हो हम बिजली में आत्मनिर्भर हो गये। बिजली में आत्मनिर्भर हो गये तो फिर यह कटौती क्यों कर रहे हो? आप मुझे इस बात का जवाब भी देना।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का एक बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी मांग पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की राजलदेसर को तहसील तो बना दिया, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि उस तहसील को तुरंत चालू कर देना। कहीं यह घोषणा, घोषणा नहीं रह जाये, मुझे इस बात का डर है।

इसके साथ-साथ मेरी दूसरी डिमांड है कि रतनगढ़ जिला बनने की स्थिति में है। यह नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे का जंक्शन पाइंट है। सारी सुविधाएं जो एक जिले में होनी चाहिये, वह पूरी करता है। ऐसी स्थिति में लोगों की मांग है कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाना चाहिये। मैं पुरज़ोर शब्दों में रतनगढ़ का प्रथम सेवक होने के नाते रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग करता हूं।

पशुओं के साथ आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा क्रूर व्यवहार आपको माफ नहीं करेगा। लंपी की बीमारी में लोगों ने काम किया। किन लोगों ने काम किया? सामाजिक संगठन के लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन ने काम किया। सामाजिक संगठनों से बात कर, सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाने वाले यदि कोई लोग हैं तो उन लोगों ने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, मैं उन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने घर-घर जाकर गाय की सेवा करने का काम किया। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि लम्पी की बीमारी से जो काल-कवलित हो गये, उनकी गणना किस तरह से करेंगे? कहीं रेवड़ियां वहां भी नहीं बांट देंगे? उनकी सही तरीके से गणना करके उन लोगों को मुआवजा देने का काम करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में गायों की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए कुछ डिमांड हैं। पशु चिकित्सा विभाग से मैं मांग करता हूं कि सिमसिया, बिदावता व जोगलिया में पशु उप केन्द्र स्वीकृत किये जायें। खारिया, कनिराम,

(श्री अभिनेश महर्षि)

गोरीसर में पशु चिकित्सालय खोले जाएं। बीरमसर खारिया स्थित मिरणा की ढाणी में आंगनबाड़ी स्वीकृत की जाये। पशु चिकित्सकों के रिक्त चल रहे पदों को तुरन्त प्रभाव से भरा जाना चाहिए। भोजासर में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की मांग करता हूं।

उसके बाद में विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली की बात करता हूं। पांच करोड़ रुपये दिये, अभी तक उन कामों को पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद 10 करोड़ रुपये दिये, उनके ऊपर तो एक खोरियो भी, मारवाड़ी में कहते हैं कि एक खोरियो भी लगा दे तो मंत्री महोदय, अभी तक तो एक खोरियो भी कोनी लगायो। मेगा हाईवे से छापर बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड बनाने की मांग करता हूं। छह-सात किलोमीटर का चक्कर लगने लग गया है। बीच के अन्दर हिरण अभयारण्य आता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार इसके ऊपर निर्णय करे और वन विभाग से भी बात करे और बात करने के बाद इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाये, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। यह मेरी प्रमुख मांग है।

उसके बाद टीडियासर से गुसाईंसर, लधासर से गोरीसर, रघुनाथपुरा से नेशनल हाईवे 11 और भिंचरी से खोथड़ी, कनवारी से रूखासर, मालासी से धिराणाजोहड़, भोजाणो की ढाणी, कालका माता मन्दिर, खारिया कनिराम से डूंगरी श्यानण, भुकेड़ी से किशनपुरा, कनवारी से डूंगरास, सुलकड़ियां से बिराड़ियां, भरपालसर से इंडस्ट्रियल एरिया तक, नेशनल हाईवे 11 से आबड़सर, आबड़सर से भरपालसर, जेगड़िया बिकान से परसनेऊ, आलसर से रूस्तमधोरा, डाबरिया-डूंगरगढ़ की तरफ जाने वाली। आलसर से जेगड़िया बिकान-परसनेऊ दादोजी मन्दिर तक। मालपुर से गोरीसर, दाउदसर से डेरासर, अणकोन्या से बासी पूर्वी, बासी अगुणी से डूंगरा सगुणा। आबसर से डूंगरास बामनिया, खालिया से बांदीसर, तेजोनसिंह। खालिया से नीमड़ी, छापर से बोथ्यावास होते हुए जैतारण। नीमड़ी चारणान से भैरू जी मंदिर तक और नीमड़ी चुंआ से छापर, छापर चुंआ से मेगा हाईवे, नीमणी बिदावतान से भोजलाई। हाईवे से नीमड़ी बिदावतान, बड़ावर से लालपुरा, बड़ावर से बिलासी छारणान, रामपुर से जिंदरासर और नाम्या से धांधणी तक सड़क निर्माण करवाया जाये। सभापति महोदय, मैं इतनी सड़कों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि क्षेत्र के अन्दर सड़कों की हालत बहुत खराब है और ये सड़कें बनना आवश्यक हैं।

क्षतिग्रस्त सड़कों का तो हाल बेहाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की

(श्री अभिनेश महर्षि)

सुलकड़िया से छाबड़ी, जेगड़िया बिदावतान से राजलदेसर, आलसर से रूस्तमधोरा, आलसर से परसनेऊ, हरासर से राजियासर, बानिसर से तेजभानसिंह, बानिसर से अरावतान, खालिया से आबसर सहित सभी सड़कों की मरम्मत करायी जाये। यह सड़कों के बारे में मेरा निवेदन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का मामला है। मैं बहुत शोर्ट में कह रहा हूं। मेगा हाईवे छापर से नेशनल हाईवे 11, परसनेऊ को जोड़ते हुए यह 5 मीटर चौड़ी सड़क बनायें। आवागमन में बहुत लम्बा चक्कर पड़ता है। यह 22 किलोमीटर का लम्बा चक्कर है, इस चक्कर को खतम किया जाये, इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसकी भी मेरी मांग है कि इसको पूरा किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले समय पांच वर्षों में बहुत अंडरब्रिज बनाये थे। मुझे तकलीफ है और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अंडरब्रिज अब सरकार में आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं बन पाया और हमारे चूरू जिले के अन्दर भी हालात खराब हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मौलीसर छोटा, इसमें 302/1-2 पर आर यू बी निर्माण, भोजासर खंभा नम्बर 335/6, 335/7, प्रेमनगर में मालपुर में खंभा नम्बर 315/316, आबसर पुरानी रेलवे फाटक संख्या, रेलवे स्टेशन ताल छापर, रणधीसर से हरासर जाने वाली कटानी रास्ते पर खसरा नम्बर 473 और 521 पर, भौजलाई से गुलेरिया कटानी रास्ते पर, ये अंडरब्रिज बनाने की मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: प्लीज दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, दो ही मिनट में समाप्त करता हूं। मैं संरक्षण चाहता हूं। चिकित्सा विभाग के अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए प्रेमनगर, छाबड़ी मीठी, ढाकाली, इसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र और गोरीसर' जेगड़िया बिदावतान, परसनेऊ में उप स्वास्थ्य केन्द्र पी एच सी, लाछड़सर और बड़ावर को सी एच सी में क्रमोन्नत करें। राजकीय जिला अस्पताल आदर्श सी एच सी, राजलदेसर, सी एच सी छापर, दाउदसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इनमें चिकित्सा कर्मियों की बहुत कमी चल रही है इनको पूरा करायें। सी एच ए जो कि सड़कों के ऊपर डोल रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा करने का काम किया है, सरकार इनकी तरफ देखे और इनको भी नियुक्ति देकर इनका भी करे। सरकारी अस्पतालों में पद खाली पड़े हैं। मैंने बता दिया कि 40 में से 25 पद खाली पड़े हैं, अन्य चिकित्सा

(श्री अभिनेश महर्षि)

कर्मियों के 50 खाली पड़े हैं। आर जी एच एस में समय पर दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन दुकानों का पेमेंट भी किया जाये।

रतनगढ़ अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर बात है। वहां पर ऑपरेशन थियेटर में निश्चेतन वाला डाक्टर नहीं है और जहां पर आपरेशन थियेटर नहीं है, वहां पर है। इस असमानता को दूर करें।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बस एक मिनट में। सभापति महोदय, बाकी मेरी जो डिमांड हैं, इनको मैं टेबल कर दूंगा, अगर आप अनुमति देंगे तो।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में मेरी बात को खतम करता हूं। जेगड़िया बीकान में जी एस एस का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है इसको पूरा कराया जाये। नई ट्यूबवैल 15 के करीब हैं, मैं नाम टेबल कर दूंगा। ये 15 के करीब मेरी डिमांड हैं, उनको भी पूरा कराया जाये। बाकी, मैटर तो बहुत था। व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं है। राजलदेसर के अन्दर के पद खाली पड़े हुए हैं। हायर एजुकेशन की यदि बात करूं तो महाविद्यालय एक लैब असिस्टेंट के बल पर चला है, कन्या पीजी महाविद्यालय था। राजलदेसर को पी जी करवाया जाये। वहां पर परीक्षा सेन्टर करवाया जाये। वहां पर सब्जेक्ट खोले जाएं। ये सारी बातें, कामर्स और साइंस के सेक्शन खोले जाएं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू। श्री खुशवीरसिंह जी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, और बहुत-सी चीजें हैं, आपकी इजाजत से मैं टेबल कर देता हूं। धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, धन्यवाद। जय सियाराम, जय सियाराम।

श्री सभापति: शुरू करिये प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय खुशवीरसिंह जी साहब, वह गमछा या दुपट्टा लगाओ, भगवा वाला।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आज शहीद दिवस पर मैं उन शहीदों को नमन करते हुए याद करता हूं। आज कारगिल का शहीद दिवस है और उनको मैं याद करता हूं, क्योंकि कुछ लोग इसको और रूप से मनाते हैं। सभापति महोदय, हमारे विद्वान ज्ञानी साथियों ने वास्तव में अंकगणित के साथ में, आंकड़ों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो

(श्री खुशवीरसिंह)

बजट था, उसका विश्लेषण किया है। मैं इतना विद्वान, ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो एक लाइन में ही मेरी बात कहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने Financial Responsibility and Budget Management Act, 2003 के दायरे में बजट को प्रस्तुत किया है। इस बजट में भारत सरकार का कुल कर्जा है, सकल घरेलू उत्पाद का 57.7 प्रतिशत है और राजस्थान सरकार का 40 प्रतिशत के अन्दर रहा है। बाकी तो बहुत सारों ने सभी बातें कही हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट की चर्चा पर हम सभी ने और विपक्ष के साथियों ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी बात रखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका कैलेण्डर भी जारी हो चुका है। इस बजट का कार्य कब प्रारम्भ होगा, कब शुरुआत होगी और कब टेण्डर होंगे, उसका कैलेण्डर जारी हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र की मांग रखता हूं। समय का अभाव है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं हमारे सभी साथियों को आमंत्रित करूंगा। एक मॉडल विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन बनने जा रहा है। जो मैं आपको कह रहा हूं सड़कों की दृष्टि से, चार से पांच किलोमीटर दूर हाईवे या मेगा हाईवे, जिस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर, चार से पांच किलोमीटर दूर कोई ढाणी या गांव नहीं बचा, अब वहां पहुंचने के लिए, आप आकर देख लेना, मैं यह आपको हकीकत बता, रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको। मॉडल विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का मैं कह रहा हूं दावे के साथ में, ये मुख्य मंत्री जी का करिश्मा है। मैं जितना धन्यवाद दूं मुख्य मंत्री जी को, उतना ही कम है। टेबल तो थपथपा दीजिए साथियों।

मैं जे जे एम की अगर बात करता हूं, हमारे मंत्री महोदय भी विराजमान हैं यहां, जे जे एम में हालांकि राजस्थान सरकार को जो राज्यांश 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, उसके बावजूद 70 प्रतिशत मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हो चुका है और कुछ जगह सम्पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन कुछ एक क्लस्टर वन अभी-भी पेंडिंग पड़ा है, कुछ टेक्निकल कारण से तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको आप जल्दी से स्वीकृत करवा दीजिए ताकि शत-प्रतिशत ये मटकी वाला पानी घर-घर ले जाकर पिला देगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें और विशेषकर महिला शिक्षा, एक नहीं दो-दो महिला कालेज और पाली

(श्री खुशवीरसिंह)

जिले की प्रथम महिला कालेज जिले से बाहर, मुख्यालय से बाहर मेरे गांव जोजावर में दी। अभी रानी मुख्यालय पर महिला कालेज दी। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जितना करूं उतना कम है। बच्चियों में इतनी खुशी है कि मेरे पास वीडियो आए, हर स्कूल के अंदर बच्चियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और मुख्य मंत्री जी के पक्ष में बात रखी कि वास्तव में महिला शिक्षा के प्रति इनकी जो सोच है, शिक्षा के प्रति इनकी जो सोच है, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो, चाहे विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात हो, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री महोदय को।

मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा में एक रीको भी दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। सड़क भी दी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सड़कें दी हैं, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मुझे गौण मण्डी से कृषि मण्डी भी दी। इस बजट में वीर बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा भी दिया, जो महापुरुष हुए थे हमारे क्षेत्र के। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। उनके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं मुख्य मंत्री महोदय से मेरी मांग रखता हूं कि मारवाड़ जो मुंसिफ कोर्ट है भवन बना हुआ है और सन् 1990 से वह मुंसिफ कोर्ट चल रहा है। मैं चाहूंगा वह ए सी जे एम में क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि पूर्व में मेरी मांग पर मुख्य मंत्री महोदय ने देसूरी और रानी, रानी में नया मुंसिफ कोर्ट खोला और देसूरी का अपग्रेड किया। मैं चाहूंगा कि ये मुख्यालय है विधान सभा का और सबसे बड़ी तहसील है और नगरपालिका भी मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष बजट में दे दी थी। कई लोगों को संशय था, वीडियो भी वायरल हुआ उनका। उसके बावजूद आज नगरपालिका सुचारु रूप से चल रही है। नगरपालिका भी हो गयी है तो मैं चाहूंगा कि वहां मुंसिफ कोर्ट को ए सी जे एम में क्रमोन्नत किया जाए।

अब मेरे पास में बहुत कम बचा है। मैं क्या मांगू ईमानदारी से मैं तीन दिन से सोच रहा हूं कि बजट में क्या मांग रखूंगा। छोटी-छोटी मांगें हैं, बड़े-बड़े तो सब काम हो गये, मिसिंग लिंक हो गये। हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय जब पधारे थे मेरे गांव में 50 बेड सी एच सी के शिलान्यास और पी एच सी के शिलान्यास के वक्त, 700-800 लोग बैठे थे, उस वक्त मैंने हाथ खड़े करवाये थे, अभी बजट में आप आलोचना कर रहे थे, बिजली की बात कह रहा हूं। मैंने कहा किस-किस के बिजली के बिल आ रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए।

(श्री खुशवीरसिंह)

दो हाथ खड़े हुए, ये मंत्री महोदय साक्षी हैं मेरे। मैंने कहा कि ये मुख्य मंत्री जी को आप जाकर संदेश देना, सिर्फ दो हाथ खड़े हुए 700 लोगों में से। उस वक्त तो 50 यूनिट बिल माफ था, अब 100 यूनिक हो गया है। आप और हम भी उसका लाभ उठा रहे हैं, परंतु बोल नहीं रहे हैं, गुटर-गुटर अपन लाभ उठा रहे हैं उसका। आपके भी माफ हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बजट तो घोषणा है, घोषणा क्या, हम बिल नहीं भर रहे हैं। ये अपना दिल जान रहा है और ये हम कह नहीं सकते हैं। मैं कह सकता हूं। मैं कुछ भी कह सकता हूं।

मैं दूसरी बात करूंगा। मेरे दो पुल रह गये हैं। एक तो हिंगोला गांव में पुल है, वहां पर किसी ने पूर्व में रोड बनाई, इतनी ऊपर कर दी उस रोड को कि उसको नीचे करना पड़ेगा। गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों के कच्चे मकान हैं। बारिशि के मौसम में पानी उनमें भरा रहता है। वह रोड नीचे करने के लिए और पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का एस्टिमेट है। एक दामली पुल की मैं मांग कर रहा हूं। वहां नदी आने पर वह रास्ता बंद हो जाता है।

उद्योग मंत्री महोदय, आप यहां विराजमान हैं तो मैं मांग करूंगा इन्क्यूबेशन सेंटर, जो युवाओं के स्टार्ट-अप के लिए सहायता करता है और युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद है। इस बार मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ दिल खोलकर दे दिया है। कोई कल्पना नहीं है, मुख्य मंत्री जी ने इतना दिया है। मॉडल प्रदेश राजस्थान, पूरे देश के अंदर। आप कहीं भी कितनी भी बात कर लीजिए, लेकिन ये जो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लेकर आये, उनको क्रियान्वित कराये और आमजन तक उसका फायदा हम पहुंचाएं। आप रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। आप जब देते हैं तब तो रेवड़ियां नहीं, आपने इतना घाटा खाकर भी कोई फायदा आमजन को नहीं दिया है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, हालांकि ये सपना, सपना ही रहेगा कि परिवर्तन होगा, सत्ता नहीं होगी। अगर एक बात मुख्य मंत्री जी इस विधान सभा के अंदर तय कर लें कि जिले के युवाओं को बोनस अंक दिये जाएं जो एग्जाम देते हैं। मात्र चार जिलों के लोग सब जगह आकर उनका हक छीन लेते हैं। हम दूसरे जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो उनको बोनस अंक या 80 प्रतिशत आरक्षण उनको उस जिले में दिया जाए। ये अगर कदम उठा दें तो कोई ताकत नहीं कि आपको वापस सत्ता में आने से रोक सके। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि एक मिनी फूड पार्क मेरे विधान सभा

(श्री खुशवीरसिंह)

क्षेत्र में, वेल्यू एडिशन हम कृषि उपज का कैसे कर सकें और उसमें बहुत गुंजाइश है मेरे विधान सभा क्षेत्र में। मेरा विधान सभा क्षेत्र दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक पहाड़ी तलहटी के अंदर है, अरावली की तलहटी है। मैं इतना कह सकता हूं कि वहां पर मैंने सर्वे करवाया था तो उसमें अफीम की खेती भी हो सकती है। वहां पर पट्टे जारी करने के लिए भी मैं मांग कर सकता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अगर उनको अफीम के पट्टे जारी कर दिए जाएं अरावली की तलहटी के अंदर।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ई टी सेंटर तो आपने जोजावर में दे दिया। बहुत बड़ी सौगात, एक करिश्मा और यह क्रांति हो गयी है, लेकिन उसका भवन और इसके साथ मैं पॉली क्लिनिक सेंटर भी मांगना चाह रहा हूं, पशु पॉली क्लिनिक। अब जोजावर में ये हब बन गया और पूरा पहाड़ी मगरा क्षेत्र लगता है। वहां पर चार स्टेट हाईवे हैं।

मैं इस अवसर पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे सकता हूं और दे रहा हूं। उन्होंने जब पिछले कार्यकाल में मैं विधायक था, मैंने मांग की थी और उस वक्त उन्होंने मेरी दो एम डी आर सड़कों को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत किया था। स्टेट हाईवे 61 और स्टेट हाईवे 62, दोनों ही मेरे गांव में से गुजर रहे हैं। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उसके बाद में जब गहलोत साहब की सरकार बनी और भरत सिंह जी जब पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी और आज वह बनकर तैयार भी हो गया है। मैं वसुन्धरा जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे फाइनेंस कमीशन का सदस्य भी बनाया था। हमारे कई साथियों को अटपटा-सा लगा कि इसको कैसे बना दिया। लेकिन उनकी सोच है। वे बेधड़क, बेडर होकर, जो भी काम करती हैं बिना डरे वह काम करती हैं। ऐसे दबंग नेता की जरूरत है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था अपने बजट भाषण में और अख़बार में खबर छपी थी कि हमारे प्रधान मंत्री जी तीन बार, एक-दो महीने में, राजस्थान का दौरा कर दिया है। यह भी मायना रखता है। मुख्य मंत्री जी की बात का भी मायना होता है। वह कोई बात हवा में नहीं करते। उन्होंने कहा यह बजट मैं 2028 का रख रहा हूं। यह भी एक मायना है। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को भी बधाई देना चाहूंगा कि वह हमारे इस सत्र के दौरान राज्यपाल के पद पर आसीन होने जा रहे हैं। हम उनको मिस जरूर

(श्री खुशवीरसिंह)

करेंगे। वे जिस बेबाक तरीके से अपनी बात को कहते हैं और सत्य को सत्य कहते हैं। कोई जाकर गलत भी आंकड़े देते हैं तो मना कर देते कि मैं यह गलत तथ्य नहीं रख सकता हूं। ऐसे नेता को हम भी मिस करेंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय ने सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल की जो बात की है, वह मारवाड़ जंक्शन को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र में 132 के वी की वापारी में जरूरत है, बिजली के सब-स्टेशन की तो वह दिया जाए और अंत में दो मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैंने इस लोकतंत्र को बहुत नजदीक से देखा है। जन्म से ही देखा है। मेरे पिताश्री 1952 से विधायक रहे हैं। सन् 1967 तक विधायक रहे हैं। मैंने पंचायती राज में प्रधान से मेरी राजनीति शुरू की, जिला प्रमुख भी रहा और इस लोकतंत्र को बहुत करीब से देखा है। इस लोकतंत्र के अन्दर हम क्या शपथ लेते हैं, हम क्या बातें करते हैं, संविधान में क्या लिखा हुआ है और संविधान के नीचे हम क्या करते हैं, यह कोई नहीं कह सकता है।

सभापति महोदय, मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं, मैंने इस 15वीं विधान सभा के अन्दर जो अनुभव प्राप्त किया था, हो सकता है कि कुछ अनहोनी नहीं हो, मैं दिल खोलकर बात कहूंगा और सत्य बात कहूंगा। सभापति महोदय, इस 15वीं विधान सभा के अन्दर, जो कुछ घटनाएं पिछले 3-4 वर्षों में घटीं, इस लोकतंत्र में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर यह घटनाएं ऐसे ही घटती रहीं तो यह देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है। मैंने एक किताब लिखी है। मेरे उन दिनों की यादें "My Memories of Those Days" उसका विमोचन किससे कराऊं? मुझे न तो कोई यहां नजर आ रहा है, न यहां नजर आ रहा है। मेरी तो वह हालत हो गई है, मुझे शायरी याद आ रही है।

"किधर ले जाऊं यह दिल,
एक तरफ हूरों की जन्नत
तो एक तरफ परियों की महफिल।
किधर ले जाऊं यह दिल।"

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मैं यह किताब लेकर आया हूं। भारत के लोकतंत्र के अन्दर भूचाल आ जाएगा। यह बुक है, इसका विमोचन किससे कराऊं, यह निर्णय मैं अभी तक नहीं ले पाया हूं। मैंने यह किताब लिख ली है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): लेकिन उचित समय आने पर, जिला स्तर की ट्रेजरी के अन्दर इस बुक को रखवाऊंगा। उचित समय आने पर, उचित व्यक्ति के हाथ से, मैं इसका विमोचन करवाऊंगा।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, जिस दिन इसका विमोचन होगा, भारत के लोकतंत्र के अन्दर भूचाल आ जाएगा। उसमें मैं भी गवाह हूं, मैं भी गुनहगार हूं, उसमें मैं भी साक्षी हूं। इस किताब के अन्दर जो मैंने लिखा है, सच्चाई को लिखा है। मैंने तय कर लिया था, मेरे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया था। पिछले चुनाव के वक्त...

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदन दिलावर।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): गीता के 37वें श्लोक को मुझे याद दिलाया।

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं शहीद दिवस पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुलवामा आतंकवादी हमले में श्री हेमराज जी मीना शहीद हो गये थे। उनकी वीरांगना श्रीमती मधुबाला धरने पर बैठने की धमकी दे रही हैं। सरकार ने उनसे वादा किया था कि शहीद हेमराज जी मीना की प्रतिमा सांगोद में चौराहे पर लगाई जाएगी। इतने साल बीतने के बावजूद भी, इस सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया है। यानी, यह सरकार शहीदों का सम्मान नहीं करती है, यह सरकार शहीदों का अपमान करती है। बहन मधुबाला जी अगर धरने पर बैठेंगी तो मैं भी उनके साथ धरने पर बैठूंगा। सरकार को सावचेत कर रहा हूं कि मधुबाला वीरांगना को धरने पर नहीं बैठना पड़े। आपको यह सावचेत कर रहा हूं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद आता है, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन उपलब्ध कराएंगे। कहां है मोबाइल फोन? हम जब गांवों में जाते हैं तो बहनें कहती हैं दिलावर जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा था न कि मोबाइल फोन देंगे, वह कहां है? मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि वह फोन कहां है? महिलाओं के मोबाइल फोन कहां हैं? हम जाकर उनको क्या जवाब दें, कि उनके साथ धोखा किया। यह तो बजट की घोषणा थी। फिर कह रहे हैं कि हमने अभी जो बजट प्रस्तुत किया, उसकी सारी घोषणाएं पूरी करेंगे तो पहले क्या हो गया, सांप सूंघ गया कि पहले वाले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं कीं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में घोषणा करके भी इन लोगों ने किसानों को, बेरोजगारों को ठगा है। आज सारे किसान व बेरोजगार अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने किसानों, बेरोज़गारों को ही नहीं ठगा, महिलाओं को फोन के नाम पर ठगा। इन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए बजट में कहा था। अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए हम 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये स्टेट कम्पोनेंट प्लान में रखेंगे और उससे अनुसूचित जाति-जनजाति का विकास करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। कहां है विकास? कहां दिखाई दे रहा है? अभी तो गाइड लाइन भी जारी नहीं की, आदेश भी जारी नहीं किया। फिर हमको ठगने की कोशिश की गई। इस बजट में कहा गया है कि हम 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर रहे हैं। आप तो एक लाख करोड़ कर दो, आपको तो करना ही नहीं। कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। राजस्थान की 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति की संख्या है, उसको ठगने की आपने कोशिश की है। यह ठगगीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब के नेतृत्व में मुझे मंत्रिमण्डल में रहने का मौका मिला है। तब अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए, यह डाक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान थे, उसमें जितनी फीस उनकी लगती थी, सारी की सारी फीस सरकार के खजाने से भरी जाती थी लेकिन इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने उसको बंद कर दिया। हज़ारों लोग डाक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे थे, वे रूक गये। अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को डाक्टर, इंजीनियर बनने से क्यों रोका?

(श्री मदन दिलावर)

आपके पेट में क्यों ऐसी मरोड़ हुई कि इस योजना को बंद करो? आज भी उसको चालू नहीं किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति की विरोधी है। यह बजट अनुसूचित जाति-जनजाति को कुचलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि हमने किसानों को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? यह कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी। आपको बिजली देनी ही नहीं है, तो फ्री क्या करेंगे? आपने कहा था कि हम किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे, वह भी दिन में देंगे। गांव में घरेलू बिजली भी 15-15, 20-20 घंटे नहीं मिली। कई दिनों तक पूरा का पूरा इलाका अंधेरे में रहा। किसानों को छह घंटे बिजली देने के नाम पर, आपने दो-दो, तीन-तीन घंटे भी बिजली नहीं दी। आखिर आपको क्या हो गया? अब कहते हैं आपको दो हजार यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। आपको बिजली देनी ही नहीं है, तो कुछ भी कर दो। कुछ भी कह दो, आपको तो ठगना है। ठग विद्या ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। मैंने खेत में काम किया है। ठिठुरती सर्दी में रात को 12 बजे किसान कैसे खेत में खड़ा रहता है, कितनी ठण्ड लगती है। सांप, बिच्छू का डर होता है। कई किसान मौत के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार को दया नहीं आती है। यह रात को ही बिजली दे रही है और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। मेरे पास यह पिछले बजट की कापी है। इसमें घोषणा है कि हम सभी किसानों को दिन में ही बिजली देंगे। जब आपने पिछले बजट की घोषणा ही पूरी नहीं की तो हम कैसे मान लें कि आपने अभी किसानों के लिए घोषणाएं की हैं वह पूरी करोगे? आप किसी भी कीमत पर वह पूरी नहीं करोगे। आपने तो यह भी कहा था कि ट्रांसमिशन लोसेज हो रहे हैं बिजली में, उसको हम रोकेंगे, कम करेंगे, इसलिए हम 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। आपने यह बजट में घोषणा की। आप बताइये, 48 लाख में से आपने 48 उपभोक्ताओं के भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये क्या? लगाये तो कहां-कहां लगाये? माननीय मुख्य मंत्री जवाब देते समय बताना। जनता को तो बताना पड़ेगा न। केवल तालियां पिटवाने से काम चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, और तो और, दिव्यांगों तक को आप लोगों ने ठग लिया। आपने दिव्यांगों के बारे में घोषणा की कि इनको पेंशन देते हैं, उस

(श्री मदन दिलावर)

पेंशन के अतिरिक्त इन सबको हम एक हजार रुपये प्रतिमाह देंगे। कहां दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हो? कितने दिव्यांगों को दिया है? दिव्यांगों को तो कोई भी नहीं ठगता। उनके साथ तो कोई भी धोखा नहीं करता है, पर यह राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान की सरकार, इन दिव्यांगों के साथ भी धोखाधड़ी से नहीं चूकी है।

सभापति महोदय, दिव्यांगों के लिए यह भी कहा था कि जिस परिवार में दिव्यांग है, उस परिवार को बी पी एल मान लेंगे। बी पी एल मानकर, उनको सब प्रकार की सुविधाएं देंगे। क्यों नहीं दी? इस बजट में चर्चा क्यों नहीं की कि हमने नहीं दी? आपको बताना चाहिए था न कि यह-यह योजनाएं हमने पूरी नहीं की हैं, इनके साथ हमने धोखाधड़ी की है, आइंदा इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आपने लेकिन यह भी स्वीकार नहीं किया।

आपने तो यह कहा कि हम दिव्यांगों को उच्च शिक्षा देंगे और इसलिए हम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलेंगे, कहां है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय? कहां है? आपको बताना पड़ेगा, हम तो लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं पर वह दिव्यांगों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय हमको नहीं मिल रहा है।

(समय: 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि हम दिव्यांग छात्र-छात्राओं को स्कूटी देंगे, स्कूटी योजनान्तर्गत देंगे। कहां दिया आपने? काली बाई भील और देवनारायण योजना के लिए भी आपने कहा था कि स्कूटी देंगे, आपने वह नहीं दी है। यानी, मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं यह मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। कितनी सारी घोषणाएं करके अधिकांश घोषणाओं के पलीता लगा दिया आपने और लोगों को ठगा।

और तो और, वे घुमक्कड़ लोग, आसमान तो जिनकी छत है और धरती पर रहते हैं, जिनका न कोई मकान है, न दुकान है, उन लोगों के लिए आप यह घोषणा करते हैं बजट में कि ऐसे सभी घुमक्कड़ लोगों को हम नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड देंगे। आपने इतना बड़ा अभियान चलाया। प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर, लेकिन उसका क्या हुआ? एक भी आपने घुमक्कड़ व्यक्ति को जिसके भूखण्ड नहीं है, जिसका कहीं पर मकान

(श्री मदन दिलावर)

नहीं है, जिसका कोई स्थायी काम नहीं है, ऐसे लोगों को दिया क्या? नहीं दिया। आज भी गाड़िया लोहार, सांसी, कंजर, बावरी, बागरी, मोगया, भोपा, रेबारी, कालबेलिया, जोगी, जागा, राइका, देवासी आप सब लोगों को गालियां दे रहे हैं। वे हमसे यह पूछते हैं कि, दिलावरजी, आप तो विधान सभा में जाते हो, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछकर आना कि हमारी जो घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। कहां है हमारे भूखण्ड। यह थोथी घोषणा करके जिस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय किया है, यह ठीक नहीं है।

आपने यह कहा था कि हम बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लायेंगे और वह नीति लाकर सबका पुनर्वास करेंगे और सबको रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से जोड़ेंगे। कहां है वह नीति? नीति में कहां पर प्रावधान किया है? उस नीति को कभी आपने विधान सभा में रखा है क्या? यह घोषणा थी आपकी, लेकिन बेघर लोगों के लिए जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनका रहने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए आपने घोषणा करके भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब इनको आप भारत का नागरिक नहीं मानते हो, आप राजस्थान का नागरिक नहीं मानते हो और इन लोगों के साथ आप ज्यादती करते हो।

यहां पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी विराजमान हैं। चिकित्सा मंत्री बनते ही इन्होंने एक जोरदार भाषण दिया और यह कहा कि प्रतिनियुक्ति पर कोई भी डाक्टर नहीं रहेगा, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा, सबको मैं वहां पर ही भेजूंगा। क्या हुआ, माननीय मंत्री महोदय? कितने आज भी डेपुटेशन पर हैं। कहां के डाक्टर कहां पर लगे हुए हैं, क्या हुआ? मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आज भी हास्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं। मेरे 70 बेड का हास्पिटल है रामगंज मण्डी में, ट्रोमा हास्पिटल है, वहां पर 36 डाक्टर्स होने चाहिए, केवल 14 डाक्टर्स हैं और 14 डाक्टर्स में भी विशेषज्ञों की जगह पर एम.बी.बी.एस. लगा रखे हैं और जो जवाब देते हैं विधान सभा में तो ये कहते हैं कि हमने 14 डाक्टर्स लगा रखे हैं। एनेस्थिसिया डाक्टर की जगह एम.बी.बी.एस. डाक्टर का क्या करूंगा मैं? ई.एन.टी. वाले की जगह यह एनेस्थिसिया वाले का क्या करूंगा मैं? क्या होगा उनसे? यानी, इनको यह भी

(श्री मदन दिलावर)

पता नहीं है कि कौनसा डाक्टर कहां पर होना चाहिए और पता करो, माननीय मंत्री महोदय, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने जितने कहा, सारे लगा दिये मैंने। इनकी पूरी लिस्ट लगा दी।

श्री सभापति: प्लीज, सुनिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं कि गौ-माता के साथ हमने न्याय किया है।

श्री सभापति: तीन मिनट में आप समाप्त कर दीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौ-माता के साथ न्याय किया बताया इन्होंने। इन्होंने यह कहा था कि गौ-माता और उसके वंश को बचाने के लिए हम नन्दीशालाएं खोलेंगे। कहां हैं नन्दीशालाएं? नन्दीशालाएं नहीं खोलीं इन्होंने क्योंकि इनका बूचड़खाना वालों से समझौता हो गया था। वे नन्दी खुले घूमते रहे और इन्होंने नन्दीशालाएं नहीं खोलकर राजस्थान का विकास, नन्दियों को बूचड़खाना काटने के लिए भेज दिया, यह मेरा आरोप है। यदि वह नहीं होता तो शायद ये नन्दीशाला खोलकर गौ-वंश को बचाने का काम करते। (व्यवधान)

आज भी लगातार मेरे क्षेत्र में जा रहा है गौ-वंश, वहां पर काटा जा रहा है और गाय काटने, गौ-वंश वालों को पकड़ा नहीं जाता है। कांग्रेस के लोग उनकी तरफदारी करते हैं। ये गौ-माता के भी दुश्मन हैं। यानी, ये गौ-माता के दुश्मन, एस.सी., एस.टी. के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, भिखारियों के दुश्मन, तो आखिर ये हैं किसके?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बजट घोषणा में यह कहा था कि जिस भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में एक हजार बच्चियां पढ़ रही होंगी तो उसको हम महाविद्यालय घोषित कर देंगे, महाविद्यालय बना देंगे। कहां है? नहीं, हां पांच सौ। मेरे रामगंज मण्डी में सीनियर सैकण्डरी स्कूल में, इन्होंने तो पांच सौ की घोषणा की थी लेकिन मेरे यहां तो एक हजार बालिकाएं पढ़ रही हैं। सीनियर सैकण्डरी स्कूल में वे पढ़ रही हैं लेकिन वहां पर महाविद्यालय नहीं खोला है, यह क्या तमाशा है? यह बजट घोषणाएं क्यों करते हो? यही हश्र होने वाला है यह।

श्री सभापति: आप आपस में बात न करें, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इन्होंने यह भी कहा था कि हम अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल तो खोले नहीं पर हिन्दी मीडियम स्कूलों के ऊपर ही जाकर लिख दिया कि यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गये। कैसे हो गये? बिना टीचर लगाये ही हो गये? बिना बिल्डिंग के ही हो गये? वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं। फिर यह कहते हैं कि उसी स्कूल में ये पढ़ेंगे। अंग्रेजी वाले भी हिन्दी में पढ़ेंगे और हिन्दी वाले भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो ये कैसे पढ़ेंगे? यानी, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय है और हिन्दी पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय है। राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकारमय कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, ये यह कह रहे हैं कि हम सब बच्चों को दूध पिलायेंगे। दूध की योजना जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, उसको बंद किया और जो आपने दो-तीन साल तक उनका दूध बंद किया, उसका हर्जाना कौन देगा? कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हो गये, यह आपको पता होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय सदस्य, थैंक यू। प्लीज, आपका हो गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उन दूध पीने वाले बच्चों का भी कई सालों तक इन्होंने दूध छीनकर रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आपका समय हो गया। माननीय सदस्य, समय हो गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कालेज खोले, कृषि महाविद्यालय खोले, लेकिन महाविद्यालय में बिल्डिंग नहीं, टीचर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, कुछ भी नहीं है। यह धोखाधड़ी की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनिये। प्लीज, बैठिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): दो मिनट और।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। अब रिकार्ड नहीं होगा, टाइम हो गया आपका। रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप बोलिये। श्री गिर्राज सिंह। आप बोलिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। प्लीज, बैठिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे तो ये बड़े आरोप लगा रहे थे कि हमने यह किया, हमने यह किया।

श्री सभापति: मैं बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोनों पक्ष हैं, उनके माननीय सचेतकगण द्वारा जो समय का विभाजन हुआ है, अब आगे जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे उनका बोलने का समय दस-दस मिनट का निर्धारित किया गया है और मैं आठ मिनट पर बोलूंगा कि दो मिनट में समाप्त करिये, तो कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इनकी बात सुनने वाले नहीं हैं कोई भी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं, आपको ही सुनानी है मुझे।

श्री सभापति: आप चालू करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पायलट साहब के आदमी बैठे हैं, सत्ता पक्ष का एक आदमी नहीं बैठा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): एक भी आदमी नहीं है, देखो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक आदमी नहीं सत्ता पक्ष का, सारे पायलट साहब के आदमी बैठे हैं।

श्री सभापति: पायलट साहब भी सत्ता पक्ष के ही हैं। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, पायलट साहब भी सत्ता पक्ष के ही हैं। आप बोलिये। बोलिये, कंटीन्यू करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड पर जा रही है यह बात कि पायलट साहब सत्ता पक्ष के हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो समय इन्होंने बर्बाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, यह रिकार्ड पर जा रही है बात, इसको डिलीट करवाओ।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ये मेरे समय को बर्बाद कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यह कह रहा हूं कि आप इसको एक्सपंज करवाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये। चालू करिये अपना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, यह रिकार्ड पर गयी बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप चालू करिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, पहले आप इसको तो कंट्रोल करें।

श्री सभापति: आप प्लीज, चालू करिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी बजट पेश हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने किया है। बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है शानदार रहा है और सबको कुछ न कुछ मिला है। चाहे वे बी.जे.पी. वाले हों या कांग्रेस वाले हों या किसी भी दल के लोग हों, सबको फायदा मिला है। अभी पांच सौ रुपये में सिलेंडर की घोषणा की है। उसमें उज्ज्वला वाले हैं। क्या वे बी.जे.पी. वाले नहीं हैं या सब ही कांग्रेस वाले हैं? इनको तो सिर्फ बोलने की आदत है, हल्ला मचाने का काम है और आरोप लगाने का काम है। वही लोग ज्यादा बोलते हैं जिनको ज्यादा फायदा मिलता है। क्या वह फायदा हम सभी कांग्रेस के लोगों को ही होगा? उनमें बी जे पी के लोग नहीं होंगे? ऐसे आरोप लगाने से पहले अच्छी चीजों के लिए तो कम से आप ताली बजा दिया करो। बुराई करने का तो आपका अधिकार है, आपका काम है, आप करते रहो।

श्री सभापति: सुनिए, प्लीज। बोलिए आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, 500 रुपये का सिलेण्डर हो गया। लोगों को खाने के लिए फ्री अनाज मिल रहा है। लोगों को तेल, राशन और चाय की व्यवस्था की है सरकार ने अभी। इनको मालूम नहीं

(श्री गिर्राज सिंह)

है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलना किसे कहते हैं। गरीब आदमी के घर में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च नहीं होती है। इनको सबको पता है। इन सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इनकी विरोध करने की मजबूरी है। विरोध करना इनका धर्म है, इनको करना है, लेकिन ईमानदारी से अगर इनसे पूछा जाए कि सरकार ने कैसा काम किया है तो ये भी तारीफ ही करेंगे। विरोध नहीं कर सकते। यहीं पर विरोध कर सकते हैं। ये चुनाव की वजह से ही डर रहे हैं। सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने इतने अच्छे काम किये हैं इसलिए उसके लिए ये खुद घबरा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चुनाव में हमारा क्या होगा। इनके यहां मुख्य मंत्रियों की लाइन लगी हुई है। इनके यहां करीब दो दर्जन मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। जिसको भी देखो, हर कोने पर मुख्य मंत्री बन रहा है। राठौड़ साहब अलग मुख्य मंत्री बन रहे हैं। राठौड़ साहब को यह दिखता है कि मेरा नम्बर आने वाला है तो वह मैडम के पास भी आ जाते हैं। सबको अपनी-अपनी लगी है। इनको जनता की कोई चिन्ता नहीं है।

अभी दिलावरजी दहाड़ मार रहे थे। इनको पूछो आप। इस सरकार के ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिये। आप एक बार केन्द्र सरकार की तरफ तो देखो, उन्होंने क्या किया है? बताओ। आपने 15 लाख रुपये की घोषणा की थी। लोगों को दे दिया क्या 15 पैसे भी? कभी दिया क्या एक पैसा? आपने अच्छे दिन का वादा किया था, आपने अच्छे दिन ला दिये क्या? कौनसे अच्छे दिन हैं? यही अच्छे दिन हैं? डीजल 63 रुपये से लेकर 105 रुपये पहुंचा दिया और पेट्रोल 120 पहुंचा दिया। इसे ही कहते हैं अच्छे दिन? हमारे तो पुराने दिन ही ला दो, पुराने दिन ही ठीक हैं। हमें आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। जनता यह मांग कर रही है कि आप पुराने दिन लाकर दे दो, हमें आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है, हम अच्छे दिन नहीं चाहते हैं। हमारे तो खराब दिन ही आप वापस कर दो। आप बात करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं।

अभी कह रहे थे कि आपने जनता को ठग लिया। आपने क्या काम किया है? आपने ठगाई नहीं की है? आपने लोगों के साथ में धोखा नहीं किया है? आपने एक पैसे की भी राज्य के लिए कोई योजना दी है क्या? आपके लोक सभा के 25 सांसद बैठे हैं, वे प्रदेश के लिए कोई आवाज उठाते हैं क्या? 13 जिलों की पानी की कितनी गम्भीर समस्या है। हनुमान बेनीवालजी को

(श्री गिर्राज सिंह)

छोड़कर कोई आवाज नहीं उठाता है। आपके एम पी कभी कोई आवाज उठाते हैं क्या? 13 जिलों में पानी की समस्या है। ई आर सी पी योजना वाली बात कर रहा हूं। आपने जाकर कभी मांग की है? आप यहां तो बहुत जोर-जोर से हल्ला मचाते हो।

अभी माननीय प्रधान मंत्रीजी आये थे दौसा के अन्दर, वह क्या कह कर गये? दो प्रदेशों का मामला है। कौनसा मामला है दो प्रदेशों का? हमारे बगल से चम्बल निकल रही है। हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रही है चम्बल? बार-बार किस बात का अड़ंगा लगा रहे हैं? आपका क्या लेना-देना है? पानी समुद्र में जा रहा है। कौनसा समझौता लागू होता है? जनता को पानी पीने के लिए नहीं देंगे। राजनीति करने का काम आपका है, आप राजनीति करते रहेंगे। राजनीति करो, लेकिन पानी जैसी छोटी चीजों पर राजनीति मत करो। यह तो आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ एरिया है, वहां पर पानी की समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन लोगों से मांग करता हूं कि इनके लोक सभा के 25 सांसद हैं, इनके प्रदेश अध्यक्षजी अभी नहीं हैं, नेता, प्रतिपक्ष बैठे हैं। आप अपने सभी सांसदों को लेकर जाएं, जाकर माननीय प्रधान मंत्रीजी से मिलें और कहें कि इस गरीब की योजना को नहीं अटकायें। यह गरीबों से जुड़ी हुई पानी की योजना है। लोगों को इस समय पानी की समस्या बहुत है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप लोग प्रधान मंत्रीजी से समय मांगें और दो-चार दिन पहले हम लोगों को भी बतायें। हम लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। राजनीति मत करो। आप सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति करते हो। आप लोगों ने जनता को ठग लिया। ठगा तो आपने है। आपने जनता को दिया क्या है? आप एक भी बता दो कि जनता के हित के लिए यह काम किया है। आप बताओ कि हमारी सरकार ने जनता के लिए कितना काम कर दिया। 25 लाख रुपये का बीमा आज तक केन्द्र की सरकार ने किया है? किसी प्रदेश की सरकार ने, आपकी सरकार ने 25 लाख रुपये का फ्री इलाज किया है क्या? आपने तो 5 लाख रुपये का भी नहीं किया है। आपने किया हो तो बताओ। 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा किया है जनता के लिए। आपने कहीं 10 पैसे का किया हो तो बताओ। आप तो सिर्फ आरोप लगाते हो, जनता को ठगने का काम करते हो। आप ऐसे आरोप लगा रहे हो। जनता को आपने नहीं ठग लिया? आपने ठग लिया। आपने दो बार केन्द्र में सरकार बनायी, आपने भी

(श्री गिर्राज सिंह)

जनता को ठगा होगा। ऐसे आरोप लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। कुछ काम करके दिखाओ।

अगर आपमें हिम्मत है तो आप डीजल-पेट्रोल के दाम कम करो। आप क्यों नहीं करते हो? हम लोगों ने गैस के सिलेण्डर पर पैसे कम किये हैं, 500 रुपये का सिलेण्डर किया है। आप लोग करके दिखाओ। 500 रुपये आप कर दो। जनता को फ्री हो जायेगा। आप करो तो सही। आप फ्री कर दो। आप क्यों नहीं करते हो? आपको किसी ने रोका है क्या? सरकार जो काम अच्छे करे वह तो आपको बुरी बात लगती है और आप लोग कुछ करते नहीं हैं।

एक वह पौने दो आंख का बाबा। जानते हो कौन है पौने दो आंख का बाबा? वह डीजल-पेट्रोल कितने पैसे में बेच रहा है? 30 रुपये में। उस पौने दो आंख के बाबा का पता नहीं है? किधर गया? खुद की आंख तो उस पर इलाज नहीं हुआ, उसको तो उसने ठीक नहीं किया। पूरी जनता को बेवकूफ बना रहा है। आप ऐसे योगा करो, आप पेट फुलाओ।

श्री सभापति: प्लीज दो मिनट में समाप्त करो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप यह करो, तो ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। इनका पूरा जाल बिछाया हुआ है। कोई बाबा को ले आयेंगे, कोई ड्रामा ले आयेंगे। कोई गऊ के नाम पर राजनीति करता है, कोई भगवान के नाम पर करता है। आप ही भगवान के भक्त हैं? और कोई नहीं है? आपने कोई भगवान को खरीद रखा है? आप ही पूजा पाठ करते हो? आपके दल में रहेगा वह तो हिन्दू है और किसी दूसरे दल में रहेगा वह मोहम्मडन हो जायेगा? वह हिन्दू नहीं है? बीजेपी ने ठेका ले रखा है? आपने कोई टेण्डर लिया है कहीं से? अगर बी जे पी में रहेगा वही हिन्दू है, दूसरे दल में रहने वाला हिन्दू नहीं है। यह आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या?

माननीय सभापति महोदय, इनका तो आरोप लगाने का ही काम है। असत्य ढकोसले करते हैं। काम करते नहीं हैं, वादा खूब करते हैं। घोषणाओं की लाइन लगा देते हैं ये। दिल्ली से मुम्बई तक एक रोड बन रही है। पता नहीं, उसका कितनी बार उद्घाटन कर देंगे। ऐसे उद्घाटन मैंने पहली बार ही देखे हैं जो प्रधान मंत्रीजी कर रहे हैं। शिलान्यास एक जगह होता है। ये हर जगह शिलान्यास कर देते हैं। एक-एक किलोमीटर के टुकड़े पर कर देते हैं। उद्घाटन भी एक-एक टुकड़े पर जाकर करते हैं। यह इनकी योजना है, इनके यह काम हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि जिन्होंने

(श्री गिर्राज सिंह)

बेईमानी, घोटाला और लोगों के साथ धोखा किया है, उन अडानीजी को साथ लेकर अडानीजी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इनको बेईमानी करनी है। इनको प्रदेश के अन्दर सरकार गिरानी है। ईमानदारी की दुहाई देते हैं। कालाधन लेकर नहीं आयेंगे ये। अच्छे दिन लेकर नहीं आयेंगे ये। वह बेईमानी का पैसा कहां गया? जो अडानीजी से पैसे लिए हैं वह इन्होंने एम एल एज की खरीद-फरोख्त में लगा दिये तो वह घोटाला तो करेगा ही। वह कहां से निकालेगा? मध्य प्रदेश के अन्दर जिन्होंने सरकार गिरायी, कर्नाटक के अन्दर सरकार गिरायी, गोवा में आयी हुई सरकार को लेकर ये चले गये, महाराष्ट्र में पटक दी। हर जगह जहां इनको मौका मिलता है वहां पर सिर्फ पैसे के दम पर खरीदे हैं। आपकी ई डी ने कभी इस बात की जांच की क्या कि यह पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी यह मांग उठाई क्या? लोक सभा में कभी उठाई क्या? आपके एम पी या एम एल ए ने कभी उठाई क्या यह मांग? यह पैसा कहां से आ रहा है? आप 35-35 करोड़ रुपये देकर लोगों को खरीद रहे हो और आप कहते हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हो या भ्रष्टाचार फैला रहे हो? इतनी बड़ी रकम आप दे रहे हैं। हर लोगों का ईमान खरीद रहे है, बेईमानी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इनसे यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये राजनीति में आकर भ्रष्टाचार करते हैं और चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। दूसरी तरफ एक हमारी सरकार है आज प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे शानदार काम किये हैं। माननीय सभापति महोदय, आप देखना यह सिर्फ बजट की वजह से घबरा रहे हैं। इनको और कोई डर नहीं है, इनको यह डर है। इनका कहना है कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, आपको क्या टेंशन है? आप पैसा कहां से लायेंगे, आपके पास फाइनेंस की क्या व्यवस्था है? आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता तो हमें करनी है, मुख्य मंत्रीजी को करनी है कि उन्होंने जो बजट पढ़ा है, उन्होंने जो घोषणा की है, यह तो उनका काम है कि उनको पैसा कहां से लाना है, कैसे करना है, क्या व्यवस्था करनी है। आप पहले भी कहते थे कि धरातल पर योजना नहीं आयी। मेरे क्षेत्र में वहां जाकर देख लो। आप देख लो 100 करोड़ से कोई भी योजना नीचे नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सारी योजनाओं का काम चल रहा है और कुछ तो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ मांगें हैं, आपके दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मांग कहां से आ गयी काम पूरे हो गये तो?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जितना ज्यादा लोगों को देंगे, उतनी ज्यादा मांग बढ़ती है। आपने तो कुछ किया नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बसई नवाब जगह है, वहां पर 10 करोड़ रुपये बजट से पूर्व ही स्वीकृत कर दिये थे, उसमें करीब 26 करोड़ की लागत है। मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उसको बजट में शामिल करके उस कार्य को थोड़ा जल्दी करवाया जाये। रिंग रोड का काम है, माननीय सभापति महोदय, 26 करोड़ की लागत है, 10 करोड़ तो पूर्व में ही स्वीकृत हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में गलती से कोई चीज छप गयी है, बसई नवाब उप तहसील चालू करा दी पहले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने, वह चालू है। वह दुबारा उस बजट में फिर दे दी। मैंने मांग तहसील के लिए की है, उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी अभी बैठे हैं, मैं पर्सनली मंत्रीजी से मिला हूं। हमारे यहां बाड़ी में चिकित्सालय की बहुत बड़ी जरूरत है। वहां पर स्थिति बहुत खराब है, वह 200 बेड का अस्पताल है, उसको 300 बेड किया जाये। कृषि उपज मंडी में उसको जगह दें, क्योंकि बाड़ी बीच बाजार में है, वह सिटी के अंदर आती है, इससे सभी को उसका फायदा मिलेगा। कृषि उपज मंडी में इसको कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां 33 किलोमीटर की मंत्रीजी से मैंने पहले मांग की थी, उनको हमने लैटर भिजवाया है, मुख्य मंत्रीजी को भी भिजवाया है। 33 किलोमीटर के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वे गांव भी जुड़ जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक मैंने बाड़ी में तुलसीवर रोड पर नहर की पुलिया के पास पुलिस चौकी की मांग की है। माननीय सभापति महोदय, एक पुल है जो बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र और बाड़ी विधान सभा क्षेत्र, दोनों को जोड़ता है, वह भी जोड़ा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, मेरे यहां कुछ नये हास्पिटल खोले जायें। इनमें डांगबसई है, टोडपुरा है। इसके साथ ही, मेरे यहां कुछ एनिकटों की मांग है, डांग का क्षेत्र मेरे क्षेत्र में है। टोडपुरा गांव है,

(श्री गिर्राज सिंह)

हाजीपुर है, सेवरपाली है, संतनगर के पास में है, गठिया नाले के पीछे। बाड़ी में 220 का मेरे यहां पहले स्वीकृत किया गया पर जहां स्वीकृत किया, वहां गोचर जमीन आ गयी, तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो गयी। पहले बजट में 220 स्वीकृत हुई पर आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और पता ही नहीं वह योजना कहां चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि 220 को तत्काल प्रभाव से चालू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, बाड़ी में बस स्टैण्ड की समस्या है। एक ट्रोमा सेंटर की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारी नगरपालिका क्रमोन्नत नहीं हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाड़ी नगरपालिका को क्रमोन्नत किया जाये। यह जब से बनी है, आज तक उसी स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार। माननीय सदन के नेता ने 2023-24 का बजट पेश किया, वह कितना हवा-हवाई है, यह बात स्वयं मुख्य मंत्रीजी द्वारा कही गयी अंतिम पंक्तियों में झलकती है। मैं उनमें से दो पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा -

'खोल दे पंख मेरे,
कहता है परिंदा,
अभी उड़ान बाकी है,
जमीन नहीं है मंजिल मेरी,
अभी पूरा आसमान बाकी है।'

मैं सम्मान के साथ, सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा -

'परिंदों की माने, खूब उड़ लिए जनाब,
और कितनी उड़ान बाकी है,
कहां पहुंचे इसका पता नहीं हुजूर,
सिर्फ छह महीने का सामान बाकी है।'

आपकी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में हवा में ही रही, धरातल पर आती तो हकीकत पता चलती। खैर, कोई बात नहीं, जल्दी ही आपको जनता धरातल पर ले आयेगी।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेवाड़ की धरा पर सागवाड़ा में आपके नेता आये थे और एक से दस गिनती बोल कर किसानों के दो लाख रुपयों के कर्जे माफ कर देंगे, यह बोल कर गये थे। आज भी किसान उनका इंतजार कर रहा है। अभी बिजली पर घरेलू उपयोग पर 100 यूनिट, कृषि कनेक्शन पर 2 हजार यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। अच्छी बात है, मैं सदन के नेता को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब आप अपना जवाब दें तो सदन के नेता यह बतायें कि जब हमारी सरकार थी और वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्रीजी थीं, 10 हजार तक के अनुदान की किसानों के लिए घोषणा की थी और वह देना प्रारम्भ भी हो गया था, लेकिन जब आपकी सरकार आ गयी तो तीन साल तक वह 10 हजार का अनुदान आपने नहीं दिया। अब किसान वह 30 हजार रुपया लेने के लिए इंतजार कर रहा है। आपका जब चौथा बजट आया तब आपने कहा कि हम 10 हजार की जगह 12 हजार करके किसानों को अनुदान देंगे। यह 25 साल पहले वाली जनता अब नहीं रही है, अब जनता बहुत समझदार है। आपने यह जो 30 हजार नहीं दिये न, इसका खामियाजा आपको 2023 के चुनाव में जनता बतायेगी। माननीय सभापति महोदय, किसानों को बिजली मिल नहीं रही और बड़ी-बड़ी बातें आप कर रहे हो।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आमेट में आप ही के नेता थे, हीरालाल जी देवपुरा राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए पिछले चार साल से मैं लगातार आपको पत्र लिख रहा हूं, लेकिन आपने उसको क्रमोन्नत नहीं किया। पिछले दस दिन से छात्र-छात्राएं वहां आन्दोलन कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे फोन किया कि आप जाकर यह अनशन तुड़वा दो, प्रस्ताव गये हुए हैं। इस बार शायद बजट में कालेज का नाम आ जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उप सचेतक महोदय, हीरालाल जी देवपुरा आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, इस सदन के नेता भी वह रहे हैं, उनके नाम से यह कालेज है। यदि आप पी.जी. में क्रमोन्नत करोगे तो थोड़ा बहुत क्षेत्र में आने के लिए बोलने को रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आमेट में गर्ल्स कालेज की मांग थी। यही नहीं, चारभुजा में 30 सितम्बर, 2018 को आपने विशाल किसान सम्मेलन किया था और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि चारभुजा में वसुन्धरा जी आती हैं और दो-दो बार उनकी सरकार बन गयी, इस बार हमें आशीर्वाद दो, हम आयेंगे तो चारभुजा का विकास करेंगे। चारभुजा क्षेत्र के लिए कालेज

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

की मांग चल रही है, वहां पर पेयजल योजना के लिए, बेड़च नाका योजना की मैंने गत बजट में भी बात रखी, मैं आज भी आपके सामने रख रहा हूं, 2018 में बेड़च नाका को स्वीकृत कर दिया गया था, सरकार बदलने के बाद 2019 में आकर उसको निरस्त कर दिया था। मैं आपसे विशेष तौर से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस पर ध्यान दें। उस समय स्वयं मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद थे, पूर्व उप मुख्य मंत्री पायलट साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे और आपके नेता राहुल जी भी थे। उस चारभुजा की धरा पर यह संकल्प लिया था कि यदि हमारी सरकार आ जायेगी तो इतना विकास इस क्षेत्र में करके बतायेंगे। आज वह जनता याद कर रही है। समय जा रहा है, 6 महीने बाद जब आओगे तो क्षेत्र की जनता वहां जवाब मांगेगी।

गत 4 साल के बजट में मैंने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार शायद यह भूल चुकी है कि राजसमंद जिले में 4 विधान सभा क्षेत्र हैं। उन्हें केवल नाथद्वारा और भीम दिख रहा है, कुम्भलगढ़ और राजसमंद विधान सभा क्षेत्र पर इनकी कोई नजर नहीं है। यह झलक निश्चित तौर पर जनता देख रही है।

उसी तर्ज पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी केन्द्र सरकार का बजट आया था। केन्द्र सरकार के बजट में कुंभलगढ़ से कड़िया आंतरी प्रधानमंत्री सड़क योजना में 14 किलोमीटर सड़क 11 करोड़ 56 लाख की जो स्वीकृत हुई है चिकित्सा मंत्री जी, वह सड़क मेरे से जो चुनाव लड़ते हैं, आपके पूर्व विधायक गणेश सिंह जी परमार के गांव में से होकर जाती है। इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। 11 किलोमीटर में 14 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। यह निश्चित रुप से दिखता है कि एक जैसा विकास कौन कर रहा है। केन्द्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है? यही नहीं चारभुजा से ऊपरी ओढण, नाथद्वारा तक 838 करोड़ रुपये मेगा हाई-वे पर स्वीकृत हुए हैं। वह स्पीकर साहब की विधान सभा और मेरी विधान सभा में से होकर गुजरेगी।

केन्द्र सरकार ने इस बजट में मावली और मारवाड़ जंक्शन, जिस ब्रॉडगेज का पिछले 90 साल से लोगों को इंतजार था, उस ब्रॉडगेज पर 970 करोड़ रुपये पहले चरण में मावली से खाम्बली घाट तक स्वीकृत किये हैं। अतिशीघ्र वह कार्य प्रारम्भ होगा। मैं इसके लिए नरेन्द्र भाई जी मोदी को, रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी को और हमारी लोकप्रिय सांसद दीया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): इसे कहते हैं कि वास्तव में विकास का कार्य हो रहा है।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भेदभाव बरत रहे हैं। केन्द्र सरकार से 70 परसेंट पैसा आपको हर बजट में मिल रहा है। आज जल जीवन मिशन में 50 परसेंट केन्द्र सरकार का पैसा है, लेकिन हर विभाग में जाकर के देखो गहलोत साहब का फोटो लग रहा है। कहीं भी आपने जल जीवन मिशन में जल शक्ति मंत्री का फोटो ही नहीं लगा रखा है। केवल फोटो लगाने से काम नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मेरी नेचर में नहीं है कि आप और आगे टोकें। लेकिन यह आम जनता में, आम चौपाल पर यह चर्चा है।

श्री सभापति: सुनिये, सुनिये, प्लीज। माननीय सदस्य, सुनें इनको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): केन्द्र सरकार जो काम कर रही है, जो पैसा दे रही है, चाहे कोविड हो, आप स्वयं जानते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव में यदि किसी के घर में विवाह होता है, 25 साल पहले तो यह परम्परा थी कि गांव के लोग, समाज के लोग सब मिलकर शादी-समारोह में आते थे और भोजन बनता था तो स्वयं गांव के लोग खड़े होकर परोसगारी करते थे, अब समय बदल गया है, आजकल अपने को परोसगारी के लिए बाहर से वेटर लाने पड़ते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज गांव की चौपाल में चाहे महिला हो, कोई व्यक्ति हो, किसान हो, सब यह कह रहे हैं कि माल नरेन्द्र मोदी भेज रहा है और अशोक गहलोत केवल राजस्थान में परोसगारिया है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सारा पैसा जो आ रहा है, उसमें केवल केन्द्र सरकार के पैसे का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आशा करता हूं कि इस बार राजसमंद जिले में आप कुम्भलगढ़ विधान सभा में भी कुछ देकर चारभुजा में आने जैसे रहो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

सभापति महोदय, 10 फरवरी को आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह बजट राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है, नये विकास की ओर ले जाने वाला बजट है, जनता के लिए नये आयाम पैदा करने वाला बजट है।

इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को साधा है। हर वर्ग से यह बजट जुड़ा हुआ है। चाहे हम युवा की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, दूर बैठे, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाने की बात करें तो इस बजट में आपको हर वर्ग, हर समाज हर तरफ से जुड़ा हुआ नजर आयेगा।

मुख्य मंत्री जी न केवल मन की बात करते हैं बल्कि मुख्य मंत्री जी लोगों के मन की बात सुनते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है, वह क्या चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से क्या चाहते हैं। इन्हीं बातों को, मन की बातों को सुन-सुन करके आम आदमी के लिए बजट पेश किया गया है। हर वर्ग को इससे जोड़ा गया है।

हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री जी ने पहले से ही चिरंजीवी के माध्यम से हर घर में स्वास्थ्य का इतना बड़ा तोहफा दिया है। उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी ने आम जनता की बात को समझा कि किस तरीके से हम चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी की बात करें या बड़े-बड़े आपरेशंस के माध्यम से 10 लाख से भी ज्यादा पैसा आम आदमी का लगता है, इस बात को उन्होंने सोचा और इस राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। इसके साथ-साथ दुर्घटना बीमा में भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया। मैं राजस्थान की जनता की तरफ से मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि एक अभिभावक के रूप में मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ हमारे जोधपुर में हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, बर्न यूनिट लगाने जा रहे हैं। हम एक मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ यूनानी महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी। वह जोधपुर के लिए और उन सब बच्चों के लिए लाभदायक होगी जो मेडिकल में पढ़ना चाहते हैं।

स्वास्थ्य का तो ध्यान उन्होंने रखा ही रखा, चाहे वह मुफ्त दवा

(श्रीमती मनीषा पंवार)

योजना हो, चाहे मुफ्त जांच योजना हो। यहां तक कि उन्होंने पशुओं को भी पीछे नहीं रखा। पशु कौनसा वोट देते हैं? चलो सोचें कि आम आदमी तो वोट देता है, लेकिन पशु कहीं वोट नहीं देता। उसके बाद में भी मुख्य मंत्री जी ने जब वह दूसरी बार मुख्य मंत्री थे, तब सोचा। पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा योजना लेकर आये जो आज बहुत कारगर साबित हो रही है। आप देखिये, जब गायों में लम्पी जैसी बीमारी आयी तो यह योजना बहुत कारगर साबित हुई। उन पशुओं के लिए, गाय के लिए जो हमारी माता है, जिसका मां के बाद हम दूध पीकर बड़े होते हैं, उसके लिए बहुत कारगर साबित हुई। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा पर भी जिस तरह ध्यान दिया, कक्षाओं को क्रमोन्नत करना, आठवीं से दसवीं करना, दसवीं से बारहवीं करना और इसके साथ ही सीनियर कक्षा में बच्चियां 500 पूरी हो जाती हैं उस विद्यालय में तो उसको महाविद्यालय बनाने की घोषणा भी मुख्य मंत्री जी ने की है। हमारी जो बच्चियां हैं, दूरदराज क्षेत्रों में रहती हैं, दूरदराज गांवों में आने-जाने की व्यवस्था नहीं होती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। आज हम देखते हैं कि जगह-जगह ऐसे कई महाविद्यालय खुले हैं जिससे बच्चियां पढ़कर अपने विकास को आगे बढ़ा रही हैं।

यहां तक कि आर टी आई में जो बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा छात्राओं के लिए थी, अब छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। बजट घोषणा से दो दिन पहले जब हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोग मेरे पास इसी बात को लेकर आये थे कि, मैडम, हमारी बच्चियां तो पढ़ रही हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको मैंने आश्वस्त किया था कि मैं, मुख्य मंत्री जी से बात करूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि न जाने कैसे मुख्य मंत्री जी मन की बात जान लेते हैं, उन्होंने पहले से ही अपने बजट भाषण में छात्रों को यह लाभ दिया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। चाहे हम फ्री ड्रेस की बात करें, चाहे हम मिड-डे-मील की बात करें, इसके साथ-साथ 2 दिन से ज्यादा 7 दिन दूध पिलाने की जो बात कही है, वह मुख्य मंत्री जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता।

कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 20 हजार स्कूटी की जगह 30 हजार की घोषणा और 10 हजार मेधावी विद्यार्थियों को स्कालरशिप प्रदान करने की घोषणा की गयी है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

इसके साथ-साथ खेलों के माध्यम से भी मुख्य मंत्री जी हर खिलाड़ी से जुड़ रहे हैं। हम देखें कि आउट आफ टर्म नौकरियां भी प्रदान कीं। दो परसेंट नौकरियां भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखीं। इसके साथ ही गांवों में ओलम्पिक हुए। आप देखिये कि कोरोना काल के बाद किस तरह से लोग घरों में ही बैठे रहे। आप देखिये कोरोना काल के बाद लोगों को जिस तरह से खेल की तरफ प्रोत्साहित किया, लोगों ने गार्डन में वापस जाना शुरू किया। लोगों ने बगीचे लगाने शुरू किये। वापस सुबह की वॉक शुरू हुई और खेल के प्रति उनका प्रोत्साहन बढ़ा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण ओलम्पिक की शुरुआत तो की ही, आप देखिये किस तरह से ग्रामीण ओलम्पिक में सभी ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। दादा, पोता, दादी, बहू, बहन सभी ने मिलकर उसमें एक साथ भाग लिया। बहुत सुंदर वातावरण बना। सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया।

मुख्य मंत्री जी ने जब इसका इतना अच्छा प्रदर्शन देखा, लोगों का उत्साह देखा, 30 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे, तो शहरी ओलम्पिक की भी शुरुआत की। आने वाले समय में हम शहरी ओलम्पिक भी करेंगे, जिससे शहर का आम आदमी आपस में जुड़ सके, प्रेम-स्नेह उसमें मिल सके।

इसके साथ-साथ जोधपुर में वेद विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात की, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। जोधपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आम बच्चों को इंग्लिश से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भी स्थापना की। आप देखिये लाटरी के माध्यम से बहुत पारदर्शिता से इसमें बच्चों का एडमिशन होता है और लाइनें लगती हैं। इसमें आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा हमारी उस स्कूल में पढ़े ताकि उसको भी सभी के बराबर एक सम्मान मिल सके, वो भी अपने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से सब छात्रों के साथ बराबर खड़ा हो सके। अमीर आदमी अपने बच्चों को बड़ी-बड़ी फीस

(श्रीमती मनीषा पंवार)

देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं पर यह केवल और केवल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के दिल में आ सकता है और यह उन्होंने करके दिखाया है। आज देखिये हमारे ब्लाक स्तर पर, वार्ड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से हजारों गरीब बच्चे पढ़कर अपनी शिक्षा पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के लिए मुख्य मंत्रीजी ने 500 करोड़ रुपये का विकास कोष बनाया है। सभी भर्ती परीक्षाएं नि:शुल्क कर दी गई हैं। स्काउट-गाइड और एन सी सी कैडेट्स को रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा मिलेगी। चाहे हमारा कोई भी त्योहार हो, उसमें महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा थी। इसके अलावा आगे जाकर इस योजना में बढ़ोतरी हुई है। 75 करोड़ रुपये से जिला स्तरीय युवा महोत्सव भी मनाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक में 150 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सिंथेटिक, एथेलेटिक्स ट्रेक्स का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर के अशोक उद्यान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जोधपुर में आल वेदर स्वीमिंग पूल भी बनाया जाएगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, देखिये, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, स्मृति ईरानीजी जब हमारा गैस सिलेंडर तीन सौ से साढ़े तीन सौ हुआ तो सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर आ गई थीं, लेकिन आज एक हजार रुपये से भी अधिक का गैस सिलेंडर हो गया है लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है महिलाओं की बात करती हुई। आज मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को समझा कि महिला किस तरह बचत कर अपना घर चला रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिलेंडर पांच सौ रुपये किया, मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप एक अभिभावक की तरह, एक बेटे की तरह हर तरीके से उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जो महिला उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है ऐसे 36 लाख परिवारों को पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।

मुख्य मंत्री फ्री बिजली योजना में 100 यूनिट फ्री, इसमें भी आप देखिए कि किसानों को तो फ्री बिजली यूनिट मिल ही रहे हैं क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, इसके साथ-साथ आम लोगों को भी बिजली के बिल में राहत प्रदान करने के लिए 100 यूनिट फ्री किया। माननीय सभापति महोदय, खाद्य

(श्रीमती मनीषा पंवार)

सुरक्षा योजना के माध्यम से अन्नपूर्णा फूड पैकेट के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा तोहफा कर्मचारियों को मुख्य मंत्रीजी ने दिया। जो कर्मचारी सरकार में लगातार काम करते हैं तो उनके लिए भी एक बुजुर्ग की लाठी बनने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इस स्कीम में सभी कर्मचारियों को, हंडरेड परसेंट कर्मचारियों को जोड़ा। आज वे सभी कर्मचारी उनको बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि ऐसा मुख्य मंत्री हमने नहीं देखा जो बिना कहे, बिना कुछ सोचे-समझे जिस तरीके से आम आदमी का काम करते हैं, वे केवल यह सोचते हैं कि मैं आम आदमी को कैसे राहत प्रदान करूं, मेरे जो कर्मचारी हैं, जो दिन-रात सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं किस तरीके से काम करूं।

माननीय सभापति महोदय, ठेका प्रथा को खतम किया। इसके साथ-साथ सफाई व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की और इस साल उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि जयंती पर एक अवकाश भी घोषित किया जाए क्योंकि ये सफाई कर्मचारी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था का बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी प्रकार की परेशानी हो, सफाई कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलती, तो इस दिन का इनको अवकाश दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे, जिनके मां-बाप जीवन में नहीं रहे, उनका हाथ कौन थामे, उनका हाथ थामा है तो हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने थामा है, उनको सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये देकर सुदृढ़ करने का काम किया है। शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए चाहे हमारा गुलाब सागर हो, चाहे हमारा रानी सागर हो, पदम सागर हो, बजट प्रदान किया गया है। एक हजार नई इंदिरा रसोई का निर्माण करके मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से कहा कोरोना काल में कि कोई भूखा नहीं सोयेगा, उस तर्ज पर उन्होंने आम आदमी को 8 रुपये में सम्मानपूर्वक भोजन कराने का जो तोहफा दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे जोधपुर शहर के लिए बहुत ज्यादा घोषणाएं की हैं। मैं दो-तीन बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा को सभी ब्लाकों पर उपलब्ध कराया गया है, उसी तरह से यूनानी चिकित्सा को भी हर ब्लॉक पर उपलब्ध कराया जाए। जोधपुर भी राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है इसलिए जयपुर की तर्ज पर आतिश मार्केट बनाया जाए। भीतरी शहर में एक कन्या राजकीय महाविद्यालय खोलकर हमारी आम बच्चियां जो शहर में रहती हैं, उनको तोहफा प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए दो लाइनें बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने एक अभिभावक बन राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को राहत पहुंचाई है जिसे इन शब्दों में कह सकते हैं-

"महंगाई से संभाला है, स्वास्थ्य को सुधारा है,
शिक्षा को बढ़ाया है, विकास के पहियों को एक बार फिर घुमाया है,
जब हम हमारी मांगों और क्षेत्र की जरूरतों पर नजर दौड़ाते हैं,
तो यह शब्द कहने को प्रेरित होते हैं,
जो मांगा है, वो मिला है, नहीं मांगा, वो भी मिला है,
जुमला नहीं, विश्वास मिला है, निर्बल को एक संबल मिला है,
राजस्थान को एक नया प्रगति पथ मिला है, एक नया प्रगति पथ मिला है।"

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापतिजी, थोड़ी रहम करना।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2023-24 का जो बजट पेश किया है, राजस्थान का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ है उस दिन से लेकर आज दिन तक कांग्रेस सरकार बराबर गरीबों की मसीहा अपने आपको सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अरबों रुपये खर्च कर दिए राजस्थान में सौ

(श्री रामप्रताप कासनियां)

परिवारों का नाम आप गिना दो जिनकी आपने गरीबी दूर की है। गरीबी दूर इस तरह से नहीं होती है। यदि गरीबी दूर करनी है, गरीब की सहायता करनी है, उसको पढ़ाओ-लिखाओ, उसके लिए कोई लघु उद्योग लगाओ, उसको पैरों पर खड़ा करने का काम करो ताकि इस प्रांत को गति मिले, इस प्रांत के लोगों की गरीबी दूर हो। पता नहीं, मैं सोचता हूं, मेरा ख्याल है सब आप मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी हो पर इतना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद आज भी एक भी गरीब की गरीबी हम दूर नहीं कर पाए। किसी भी व्यक्ति को पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। इस तरह से रेवड़ियां बांटने से अच्छा है उसको स्थायी रोजगार दो, स्थायी धंधा दो। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कितना ही जोर लगा लो, जब तक आप जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक आप इस राजस्थान का और देश का भला नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सौ व्यक्तियों का कोई इंतजाम करते हैं और दो सौ और पैदा हो जाते हैं तो वो कमी पड़ जाती है। मैं इस सदन से यह मांग करता हूं कि सदन एक मत होकर जनसंख्या पर रोक लगाने की तरफ ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग, मैं जब भी इस विधान सभा में आया हूं, पहले बजट के अंदर इस सरकार ने किसानों के लिए तकलीफ कम करने के लिए नन्दीशालाएं खोलने की घोषणा की। यह पांचवां बजट है। हर बजट के अन्दर नन्दीशालाएं/गोशालाएं खोलने की बात हुई है। थोड़ा समय का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बजट में 2019-20 में पेज संख्या 8-9, पैरा संख्या 30-31, इस वर्ष हमने गोपालन विभाग के बजट में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। फिर भी गोवंश संरक्षण हेतु गोशालाओं को दी जाने वाली राजकीय सहायता के अलावा और वित्तीय सम्बल प्रदान करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार ने जन सहभागिता एवं सी एस आर फंड के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं। बहुत बड़े कदम उठाये हैं आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में आवारा पशुओं के कारण खेती की बरबादी के साथ-साथ दुर्घटनाएं, जन-धन एवं गोवंश की भी हानि होती है। हम चाहते हैं कि कोई आवारा पशु सड़क पर नहीं घूमे।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(समय: 15.51 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 2020-21 के बजट में पेज संख्या 13 और पैरा संख्या 47 में लिखा है कि प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सार्टेड सीमन उपयोग की योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस तकनीक के उपयोग से बछड़ों की बजाय बछड़ियां पैदा होंगी। सभापति महोदय, मैंने अभी तक किसी भी गोशाला में बछड़ी पैदा होते नहीं देखी, न गांवों में देखी। इस योजना को अगर सही तरीके से लागू किया जाये तो इसके परिणाम आ सकते हैं। ये आवारा नन्दी जो घूमते हैं, इनकी संख्या में कमी आ सकती है अगर सरकार सही ढंग से इसका उपयोग करे तो।

सभापति महोदय, 2021-22 में पेज संख्या 33-34, पैरा संख्या 87 और 97, प्रदेश की गोशालाओं व पशुपालकों को उनके घर के ही पास आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज की 102 मोबाइल वैटरिनरी सेवा शुरू करने की बात कही गयी है। यानी घोषणाएं बहुत की हैं। लम्पी के अन्दर कोई सुई लगाने वाला डाक्टर कम्पाउंडर कहीं गांव के अन्दर दिखाई नहीं दिया।

बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। हमने प्रत्येक ब्लॉक में नन्दीशाला बनवाने की घोषणा की थी। इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से इन नन्दीशालाओं को 1 करोड़ 50 लाख रुपये मण्डल के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 111 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। कहां खर्च हुई है? अभी तक तो राजस्थान में कहीं नजर आयी नहीं। 2022-23 में पेज संख्या 86 और 88, पैरा संख्या 156 और 159, फिर आपने कहा है, हमने ग्रामीण कृषकों, साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की दृष्टि से ब्लाक स्तर पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये प्रति नन्दीशाला को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, ज्यादा लम्बा पढ़ूंगा तो फिर आप टोकेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि वे इसमें तो पूर्ण पुनीत कार्य के लिए आगे आएं। आगामी वर्षों में जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल संचालित करने के लिए सक्षम एन जी ओ उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 01 करोड़ रुपये की राशि गोशाला स्थापित करने के लिए दी जायेगी। यानी मेरे कहने का भावार्थ है कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया, कोई भी बजट ऐसा नहीं गया, जहां आप नन्दीशालाओं की घोषणा किये बिना रहे हों।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस सदन के अन्दर सर्वप्रथम मैंने मांग की थी और शपथ ली थी कि जब तक बेसहारा पशुओं का सरकार इन्तजाम नहीं करेगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। सदन के काफी सदस्यों ने मेरा साथ दिया, काफी मेरे पक्ष में बोले। मैंने सरकार से कहा कि पैसे का अभाव है तो आप शराब पर टैक्स लगाएं, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाएं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने शराब पर टैक्स लगा दिया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। वह रकम इतनी हो गयी कि आज तक उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। अगर नन्दीशालाएं खोलते तो बहुत्सी नन्दीशालाएं खुल सकती थीं उस पैसे से।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुओं के मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन हैं। उनमें इतनी राशि पड़ी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप इन नन्दीशालाओं पर वह पैसा खर्च करें तो कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने बोला था, तब विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने समर्थन करके कहा था कि आप चाहे किसान की जो एक लाख रुपये की फसल बिकती है, उस पर 5 रुपये, 10 रुपये लगाएं तो वह भी सहन करने के लिए तैयार हैं। दिन-रात खेत की रखवाली करने से यह उचित है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की मांगों की ओर आना चाहता हूं, और तो आप बोलने ही नहीं देंगे। मैं मांग करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ को नया जिला बनाया जाये। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं सूरतगढ़ सी एच सी को क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बरसों पुरानी मांग है एटा सिंगरासर माइनर। पूर्ववर्ती सरकार ने आन्दोलन में किसानों के बीच जाकर यह कमिटमेंट किया था कि नहर पक्की होने के बाद में जो पानी बचेगा, उसके ऊपर पहला अधिकार सिंगरासर माइनर का होगा। सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी क्षेत्र के अन्दर 2008 में जब सरकार आयी थी, उसके लास्ट वर्ष में घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद में 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री मुकेश भाकर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं सरकार से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मांग करना चाहता हूं कि नहर का बढ़ा हुआ पानी सिंगरासर माइनर को मिले। उप-तहसील राजियासर को तहसील का दर्जा दिया जाये। राजियासर में कालेज खोला जाये। जैतसर उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाये और जैतसर के अन्दर कालेज खोला जाये। जैतसर के हास्पिटल को क्रमोन्न्त किया जाये।

सभापति महोदय, खातेदारी। मैं रेवेन्यू मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्षों से लम्बित समस्या पर इस सदन के अन्दर पूर्व राजस्व मंत्री ने दो बार आश्वासन दिया था कि मौके पर जाकर कैम्प लगाकर काश्तकारों को खातेदारी दी जायेगी और जो आबंटन के प्रकरण बाकी हैं...

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिये। विराजिये। श्री मुकेश भाकर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं इतना विद्‌वान नहीं हूं, भटक जाता हूं। सभापति महोदय..

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज सहयोग करें।

(समय: 16.00 बजे)

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट 2023-24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सरकार 2023-24 का जो बजट लेकर आयी है वह इस राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक है। इस बजट को प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखकर तैयार किया गया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर वर्ग को, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सभी वर्गों को इस बजट का फायदा मिलेगा।

इस बजट में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं मुख्य मंत्री लेकर आये हैं, उनमें मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी अगर कोई योजना या बजट लाना है तो वे योजनाएं होंगी। जिनमें चाहे सिलेण्डर 500 रुपये का हो, चाहे मुफ्त की बिजली देना हो, चाहे चिरंजीवी योजना को 10 लाख से 25 लाख करना हो, चाहे ओ पी एस में सभी कर्मचारियों को शामिल करना हो। इसके अलावा जो 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती इस बजट में लायी गयी है उससे मैं समझता हूं इस राजस्थान में एक सामाजिक सुरक्षा का माहौल प्रत्येक वर्ग के लिए बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में लाडनूं को जो सौगात मिली है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे दीनदारपुरा को उप

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

तहसील बनाना हो, चाहे निम्बी जोधा में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करना हो, लाडनूं में स्टेडियम की घोषणा हो और चाहे 24 किलोमीटर सांवराद से लेकर बल्दू गेनाना सड़क की घोषणा हो, मैं समझता हूं कि लाडनूं के इतिहास में लाडनूं के सर्वांगीण विकास के लिए इन घोषणाओं से लाडनूंवासियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मीठड़ी कस्बा लाडनूं से 50 किलोमीटर दूर है और वहां के निवासियों के लिए उप तहसील की मांग मैंने पहले बजट से लेकर हर बजट में की है, तो मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी वापस रिवाइज्ड भाषण पढ़ें तो कम से कम इस मांग को वे ध्यान में रखें।

इसके अलावा बड़वा को पुलिस थाना बनाने की मांग पहले बजट से लेकर अब तक मैंने की है क्योंकि दो तहसीलों के जो गांव हैं, कहीं मोलासर थाना, कहीं डीडवाना थाना है और वहां के निवासियों को न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था मिल पाये, इसके लिए वहां थाने की सख्त जरूरत है।

इसके अलावा लाडनूं में उप जिला से जिला अस्पताल की घोषणा हो। चिकित्सा मंत्री जी यहां बैठे हैं, वहां खारिया, ध्यावा, कसुम्बी, सूपका, गिड़ौदा गांवों में पी एच सी खोलने की मांग मैंने पहले भी उठायी है और मैं चाहूंगा कि इन गांवों को चिकित्सा के तौर पर ये सौगातें मिलें। वहां चाहे दयालपुरा हो, जसवन्तगढ़ हो, बल्दू हो, रताऊ हो, सभापति महोदय, ये बड़े गांव हैं और इनमें चिकित्सा के लिए पी एच सी से क्रमोन्नत होकर सी एच सी इन गांवों में खुले।

सभापति महोदय, इसके अलावा जी एस एस की मांग मैंने बजट में उठायी थी, उनमें लोढ़सर, गेनाना, मणूं, ये गांव हैं, जहां बिजली की व्यवस्था प्रोपर नहीं हो पा रही है जिसके कारण से इन गांवों में मैंने नये जी एस एस की मांग की थी तो इन गांवों की उस मांग को पूरा किया जाए।

इसके अलावा मुख्य तौर पर पहले बजट में लाडनूं में जो रीको की घोषणा हुई थी उसका काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अलावा ट्रोमा सेंटर की बजट में घोषणा हुई थी, उसका स्टाफ लाडनूं अस्पताल में लगा दिया गया है और दूरी की वजह से जो परेशानी आ रही थी उसको पूरा कर दिया गया है, परन्तु अभी भी ट्रोमा सेंटर का काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम उस ट्रोमा सेंटर का काम शुरू किया जाए।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

सभापति महोदय, जो मांगें पूरी की हैं उनके अलावा जो परेशानियां आम जनता को आ रही हैं और अगर उन मुद्दों को इस सदन में नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी जनता ने हम लोगों को देकर भेजा है वह निभाने में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जब रबी की फसल चल रही थी, उसमें बिजली की कटौती बार-बार हुई और पूरे नागौर में किसानों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा। सभापति महोदय, जिस तरह से वी सी आर के नाम पर वहां के अधिकारी और दूसरे जिलों से जो टीमें जाती हैं, वे किसानों को परेशान कर रही हैं इसलिए उस समस्या से किसानों को राहत देने की कोशिश हम लोगों को करनी होगी।

सभापति महोदय, लाडनूं चूंकि सूखा क्षेत्र है, इसलिए पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसमें जो पानी के नये नलकूप और हैण्डपम्प की मांग मैंने की है, मैं चाहूंगा कि उन मांग को यह सदन पूरा करे। इसके अलावा पी एच ई डी का एक्स.ईएन. आफिस जो मैंने लाडनूं में मांगा है, उसको दिया जाए, क्योंकि सूखा एरिया है और डीडवाना में एक्स.ईएन. आफिस होने से हमारे निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक पी एच ई डी के एक्स.ईएन. आफिस की लाडनूं में जरूरत है।

सभापति महोदय, जो बजट सरकार लेकर आयी है और जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है तथा जिस तरह से राजस्थान में एक सामाजिक सुरक्षा का माहौल आम जनता में बना है कि चाहे राम रूठे, लेकिन राज कम से कम उन लोगों का ध्यान रखेगा। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी और सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 170 पेज और 270 बिन्दुओं का बजट भाषण दिया। बजट से पहले जयपुर की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर जिस बचत, राहत और बढ़त की बात की, उसमें बजट को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे सारी की सारी बातें इस बजट में साकार हुईं। बहुत सारी घोषणाएं की हैं लेकिन देखते आये हैं कि अन्तिम वर्ष के बजट की घोषणा धरातल पर प्रभावी

(श्री नारायण बेनीवाल)

तरीके से क्रियान्वित नहीं होती। ऊपर से माननीय मुख्य मंत्री जी के गलत भाषण को सदन तक पहुंचाने वाले ब्यूरोक्रेट्स की मनमर्जी है। हम तो जब से सरकार बनी है तभी से बोल रहे हैं कि सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाने के ढुलमुल रवैये से 10 फरवरी को हमारे स्वाभिमानी प्रदेश की किरकिरी पूरे देश में हुई। दो दिन पहले ही केन्द्रीय वित्त मंत्री संसद में राजस्थान का नाम लेने से मना करते हुए सरकार का मजाक उड़ा रहे थे तो कल प्रधान मंत्री जी ने क्या बोला, वह सबने सुना होगा। एक तो केन्द्रीय बजट में प्रदेश को कुछ दिया नहीं और ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे हैं। सत्ता पक्ष के 24 सांसद, बार-बार मैं एक बात कहता हूं कि इस पक्ष के जो लोग हैं, आप यह कहते हैं, आप शायद अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि 25वें जो सांसद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, वे हमेशा चाहे ई आर सी पी की बात हो, चाहे युवाओं को दो करोड़ के रोजगार की बात हो, वे करते हैं। किसानों का जो बिल था और यहां जो मिलाजुली का खेल इस प्रदेश में चला उस बात को भी हम स्वीकार करेंगे। एथिक्स, क्योंकि माननीय सभापति जी बैठे हैं और सभापति जी हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, हमारे आइडल हैं तो हमें भी एथिक्स की बात कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। नैतिक रूप से जो मिलाजुली का खेल इस प्रदेश में चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार जब किसानों पर तीन काले कानून लेकर आयी, उसमें कांग्रेस के विधायकों को जितना विरोध करना चाहिए था, वह आप लोग नहीं कर पाये। अभी जो बजरी माफिया इस प्रदेश में हावी है, वही बजरी माफिया पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इन नेताओं के साथ फाइव स्टार, सेवन स्टार होटलों में डिनर करते थे पर उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने आज तक नहीं किया और यह हम सबके लिए शर्म की बात है। हमें नैतिक बात इस सदन के अन्दर रखनी होगी तब जाकर हम इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बना पाएंगे। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि-

"राजनीतिक संघर्ष चुनाव तक रह गया,
विकास का मुद्दा बहाव में बह गया।
हर बार सियासत ने जुल्म किये,
गरीब हर जुल्म दबाव में सह गया।

(श्री नारायण बेनीवाल)

खदर के लिए खाकी लाल हो जाती है,
खबर सियासत की दलाल हो जाती है।
जुल्म ढहाये जाते हैं आम जनता पर,
और राजनीति बैठे-बिठाये मालामाल हो जाती है।।"

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर युवाओं को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं और बजट भाषण की शुरुआत में मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पूरे देश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या है। जब पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है तो यह प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से कैसे अछूता रह सकता है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि इस संवेदनशील मुद्दे को, क्योंकि आने वाला जो भारत है उसमें युवाओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होगी, तो कोई अच्छा विजन लेकर, अच्छा रोडमैप युवाओं के विकास के लिए बनाकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं को बहुत-बड़ा सन्देश जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए लोकलुभावन बजट पेश किया, परन्तु इसमें वित्तीय प्रबन्धन, कौशल एवं दूरगामी सोच की पूर्ण कमी नजर आ रही है। युवा बजट अलग से पेश करना प्रदेश के युवाओं के साथ मात्र छलावा है। रीट भर्ती-2016 के लम्बित प्रकरणों को पूरा किया जाये। व्याख्याता भर्ती-2022 का रिजल्ट, कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 5 अंकों की छूट देकर युवाओं को राहत दी जाए। वनपाल, वन रक्षक भर्ती-2020, कालेज लेक्चरर भर्ती-2020, बी डी ओ भर्ती-2021, एस आई भर्ती-2021, सहायक फायर आफिसर भर्ती-2021, आर ए एस भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज विभाग में जे.ईएन. के 2100 पदों पर भर्ती करने की 2019 के बजट में घोषणा की थी परन्तु उसके बाद भी भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट से युवाओं को दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो करेंट अफेयर और दूसरा आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा युवाओं को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आर पी एस सी और आर एस एस बी के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृति किये हैं। सरकार पहले पेपर लीक प्रकरण रोके। उसके बाद समय पर भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी हों। आर पी एस सी जैसी संवैधानिक संस्थाएं

(श्री नारायण बेनीवाल)

हैं जिन पर आम आदमी को पूरा भरोसा था। राजस्थान की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आर पी एस सी हो, लोगों के दिल में बहुत सम्मान था, लेकिन 2013 के बाद हर भर्ती के अन्दर पेपर लीक हुए हैं। उससे इन समस्त संस्थाओं का कद आम आदमी की नजरों में गिरा है। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि यदि हम ऑनलाइन परीक्षाओं की बात करते हैं, जब हमारे बड़े नेता आते हैं, तब तो हम 10-10 लाख लोगों के बैठने की, उनकी सुरक्षा सहित सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं तो ऐसे ऑनलाइन सेन्टर बनाये जाएं, जहां कम से कम हम ईमानदारी से परीक्षा का आयोजन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात करें तो कहीं कालेज नहीं है, कालेज हैं तो फैकल्टी नहीं है। स्कूल और कालेज में खेल मैदान, लाइब्रेरी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, हालांकि चार नये महाविद्यालय पिछले 6 साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र को मिले हैं जिनमें दो कन्या महाविद्यालय हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि अधिकतर पद खाली पड़े हैं, लाइब्रेरियन का पद नहीं है। आज माननीय मंत्री जी ने सुबह जवाब दिया कि हम धर्मशालाओं के अन्दर ही कालेज चला देंगे। हमारे लिए इससे बड़ी विडम्बना की बात क्या हो सकती है? मोदीजी अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। आज सुबह फाइटर प्लेनों के साथ जब मैं मोदीजी की फोटो देख रहा था, फोटो में बिलकुल ऐसा लगता है, सब कुछ बदल दिया है। दैनिक भास्कर के अन्दर बहुत बड़ी खबर छिपी थी, भर्ती की परीक्षा, जिसमें हजारों बच्चों का एक लम्बा फोटो आया संघर्ष करते हुए तो कहीं न कहीं इन सब चीजों के लिए हमें बजट में कोई ठोस प्रावधान करने पड़ेंगे।

यह स्वाभाविक बात है कि जब मुख्य मंत्री जी बजट पेश करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों को ताली बजानी ही पड़ेगी, कोई कितना ही अच्छा काम कर दे तो विपक्ष अपना धर्म निभाकर ताली बजाने वालों का विरोध भी करे, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।

यदि आज हम प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो यह बहुत बड़ी खबर है कि चार साल में दस हजार युवाओं की मौत हुई है, इनमें 2042 विद्यार्थी हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा? यह बात सही है कि आज माननीय

(श्री नारायण बेनीवाल)

अशोक गहलोत जी की सरकार में, जो मंत्री अग्रिम लाइन में बैठे हैं और जिन लोगों ने सरकारें गिराने का प्रयास किया, उन लोगों के चेहरों पर मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स जरूर नजर आ रहा है। बाकी प्रदेश का आम आदमी हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहा है। यदि इस पर हमने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की तो आने वाला समय इस प्रदेश के लिए अच्छा साबित नहीं होगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कृषि और पशुपालन की यदि हम बात करें तो कृषि के लिए जी डी पी का 14 परसेंट है। कृषि का बहुत बड़ा योगदान जी डी पी में है और कृषि से अधिकतम रोजगार मिल रहा है, लेकिन कृषि के बारे में कोई नहीं सोचता। आपने कृषि पर पिछली बार अलग से बजट पेश किया पर लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। यदि हम कृषि और पशुपालन जैसी बातों को, आज हम कैंसर जैसी बीमारियों की बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि रासायनिक खाद का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, पेस्टिसाइड्स का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, कैंसर के लोग उतने ज्यादा बढ़ेंगे। हम जैविक खेती की बात करते हैं। लोगों ने पशुपालन बन्द कर दिया। जब पशु ही नहीं रहेंगे तो हम जैविक खेती की बात कहां से करेंगे?

आज आप देखें, ऊंटों पर रोक लगा दी। इस बार पुष्कर मेले में घोड़ों पर भी रोक लगा दी। सारे मेले बन्द हो गये हैं। नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अन्दर, जो छोटी जोत के किसान थे, उनके लिए वरदान साबित होते थे, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी रहीं कि तीन साल से कम उम्र के बछड़ों पर रोक लगा दी। सारे मेले बन्द हो गये, किसानों की आजीविका बन्द हो गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को ऐसे निर्देश दें कि तीन साल से कम उम्र के बछड़ों पर रोक हटाये। यहां रोक हटाने के लिए कमेटी बनाने की भी घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस कमेटी ने कोई लम्बा-चौड़ा काम नहीं किया तो कहीं न कहीं हम इस दिशा में भी काम करें। माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट के अन्दर गुड गवर्नेंस की बात...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, अभी तो चार मिनट ही हुए हैं।

गुड गवर्नेंस का मतलब होता है किसी भी सामाजिक, राजनैतिक इकाई को इस तरह से चलाना कि वह वांछित परिणाम दे, लेकिन यदि हम

(श्री नारायण बेनीवाल)

यहां गुड गवर्नेंस की बात करें तो वह बेमानी होगी, क्योंकि नागौर की बहुत बड़ी खबर है, प्रत्येक ब्लाक को दो आधार किट मशीनें, एक मशीन की लागत है तीन लाख रुपये। नागौर जिले में पौने चार लाख छात्र, एक साल से कार्टूनों में बन्द थी आधार कार्ड बनाने वाली मशीनें। अब ऐसी खबरें यदि अख़बार में छपेंगी। जब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष नागौर आये थे तो खबर छपी थी कि बैठक में नहीं आये 6 ई.ओ. व एक आयुक्त, कलेक्टर से चार्जशीट देने को कहा। हम कैसे गुड गवर्नेंस की बात करें जब ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है? जनप्रतिनिधियों की कोई मान ही नहीं रहा है तो गुड गवर्नेंस हम कहां से लायेंगे?

माननीय सभापति महोदय, यदि हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आज प्रदेश में बजरी माफिया हावी है। एस ओ जी की एडिशनल एस.पी. दिव्या मित्तल, जो पौने दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेते पकड़ी गई है। वही एस ओ जी जिस पर हम पेपर लीक मामले की जांच कराने का सारा दारोमदार डाल रहे हैं। हम सी बी आई जांच का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे स्टेट की एजेंसी है, मजबूत है। अब यदि उसका एडिशनल एस.पी. पौने दो करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है।

यदि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं। मंत्रीजी, पिछली सरकार के अन्दर जो चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों के कारनामों के कारण इन लोगों को इधर बैठना पड़ा तो भगवान के लिए आप ऐसा कोई काम मत करें कि इन लोगों की जगह आप लोगों को बैठना पड़े।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी फाइल लाया हूं। आपको अलग से दे दूंगा। सारे पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी कई स्कूलें हैं, जहां नामांकन बहुत है, लेकिन शिक्षक विहीन स्कूलें हैं। अखबारों में बहुत बड़ी खबर छपी है। मैं सिर्फ आपके जिले की बताऊंगा। बीकानेर जिले में प्रधानाचार्य के 233 पद, व्याख्याता के 393 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 1320 पद, अध्यापक लेवल II के 1335 पद, अध्यापक लेवल I के 1407 सहित कुल 5 हजार 439 पद खाली पड़े हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, मैं चिकित्सा के अन्दर मांग करूंगा कि 2013 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांचला सिद्धा को सी एच सी घोषित किया था।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2013 में सी एच सी पांचला का...।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हर आदमी यही कहेगा, दो मिनट। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। एक बार आप विराजिए। इतने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपकी पार्टी के व्हिप ने मुझे 10-10 मिनट का समय दिया है। आपको 10 मिनट में समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग बोल नहीं पायेंगे। मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, विराजिए। प्लीज, समय खराब नहीं करें। आप गम्भीरता बरतें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपकी मेहरबानी मुझ पर बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 10 फरवरी को बजट पेश किया। पूरे राजस्थान में 15 हजार टी.वी. लगाई, कालेज में, स्कूल में, होर्डिंग लगाये। सभी नगरपालिकाओं में, यू आई टी में और अख़बार में पेज इतने भरे हुए आये। हमको भी खुशी हुई कि इस बजट में वास्तव में सरकार बहुत देगी, अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा डवलपमेंट होगा।

सभापति महोदय, आप यहां विराज रहे थे। जो सदन के मुखिया हैं, वे

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

तीन घन्टे तक उस पहले वाले बजट को पढ़ लेते तो उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन-सा बजट पढ़ रहा हूं, कौन-सा बजट नहीं पढ़ रहा हूं। जो अधिकारियों ने दिया, वह पढ़ लिया और आठ-दस मिनट तक उस बजट को पढ़ा। फिर पीछे से महेशजी, मुख्य सचेतक साहब आये और उनको रोका, रोका तो भी वे नहीं रुके, उसी को पढ़ रहे थे, पर रुक गये तो ठीक रहा, वरना पिछला बजट ही इस साल पेश हो जाता। इस साल छोटा-मोटा कुछ मिला, वह मिलता भी नहीं। इसलिए सभापति महोदय, इस प्रकार से नहीं हो। होर्डिंग भी इसलिए लगाये कि मैं पहला बजट पढ़ रहा हूं, इस प्रकार की बातें नहीं हों, मुख्य मंत्री जी ध्यान रखें। मुख्य मंत्री जी ने बजट के लिए माफी मांग ली है तो इस पर आगे बोलना अच्छी बात नहीं है। मांफी मांगने के बाद सब लोग माफ करते हैं, इसलिए कोई आगे बात करनी अच्छी बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सत्ता पक्ष के लोगों ने खूब तालियां बजाईं, खूब गड़गड़ाहट की, खूब बातें कीं। इनका फर्ज भी बनता है, सदन में इनका नेता बोल रहा है तो इस प्रकार की तालियां बजाना, इस प्रकार की बातें करना पर वास्तव में, सभापति महोदय, चार साल के जो बजट थे उनकी एक परसेंट भी पालना नहीं हुई। एक चीज भी धरातल पर कुछ नहीं आयी। ऐसा कोई काम नहीं था। इन लोगों ने सबसे बड़ी बात की गायों की बात की, गायों की इन्होंने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की कि हर ग्राम पंचायत पर नन्दीशाला खोलेंगे, एक भी नन्दीशाला या एक भी गोशाला मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो नहीं खोली है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष के मेरे भाई बैठे हैं, इनके कहीं खोल दी हो तो बात अलग है। एक भी नन्दीशाला नहीं खोली और गायों की इतनी बद्दुआ लगेगी इनको। हकीकत में पहले तो 21 आये थे सभापति महोदय, आप तो जीत जाएंगे, मेरे को लगता है आपका तो बहुत अच्छा काम है, पर ये सामने वाले दस भी नहीं जीतेंगे, मेरी गारन्टी है। इस प्रकार का होगा, क्योंकि गायों का श्राप बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की दिक्कतें हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में अच्छी घोषणाएं करते, सड़कों की घोषणाएं इन्होंने खूब कर दीं कि इस प्रकार की हम रोड बनायेंगे। एक-एक किलोमीटर रोड देंगे। इस प्रकार की की थी, पर मेरे वहां एक भी बजट की रोड नहीं बन पाई। फर्स्ट बजट में, जब 2018 का बजट था उसमें इन्होंने कण्डेरा, आम्बा, बस्सी एक रोड की घोषणा की थी, ये अधिकारी भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बैठें हैं, उसकी जांच करा लें। उस बजट में इन्होंने घोषणा करने के बाद भी बजट का पैसा नहीं दिया और माइनिंग फंड से वहां बात करके वह काम चला, लेकिन आज भी वह काम पूरा नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं शहर की बात करूं, चित्तौड़गढ़ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की कि हम स्मार्ट सिटी के रूप में डवलप करने के लिए पैसा देंगे और उसका डवलपमेंट करेंगे, पर एक भी पैसा वहां स्मार्ट सिटी का नहीं आया। जो यू आई टी का पैसा लग रहा है उसकी घोषणा कर दी कि हम इसमें इस पैसे को दे रहे हैं। इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करें। थोथी घोषणाएं नहीं करें और इस प्रकार की घोषणाएं करने से पहले यह जरूर सोचें कि बजट धरातल पर आ जाये इस प्रकार के काम हो जायें।

इन्होंने एक घोषणा बहुत बुरी की साहब, कि हम सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वह कर्जा हम लोगों का माफ नहीं हुआ कि दस दिन में कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ नहीं हुआ। जो भी बैंक हैं, एस बी आई है, बड़ौदा बैंक है उनसे आज भी सर्वे करवा लें और उनका कर्जा माफ कर दें। किसानों से बहुत छलावा हुआ। बहुत तरह की बातें कीं किसानों से कि हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं के साथ इतना छलावा हुआ कि हम युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे पर वह आज दिन तक भत्ता नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को हर मीटिंग में बुला लेते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी चित्तौड़ भी आये। सभी महिलाओं को मोबाइल फोन दे रहे हैं, पर एक भी मोबाइल फोन नहीं मिला। इनकी बजट की घोषणा है। इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करें और घोषणाएं करें तो उन घोषणाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट का काम नहीं हुआ। एक पेपरलीक का मामला बताता हूं। पेपरलीक से युवा बेरोजगार खूब दुःखी हैं क्योंकि बजट लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। यह सरकार लीक है। इस लीक को रोकने के लिए 5-6 महीने का समय है। इस लीक को रोकने की कोशिश करें, वरना यह सरकार 25-30 साल नहीं आयेगी और वास्तव में ऐसी दशा होगी जैसे अभी नारायण जी कह रहे थे न, इस प्रकार का माहौल खराब होगा।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की समस्या के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। आठ घंटे की बिजली देने की घोषणा की। 24 घंटे हम सिंगल फेज बिजली देंगे। आज बिजली आ नहीं पा रही है। तारों में करन्ट आ रहा है और

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

इतनी वी सी आर भर दी। यह बिजली के बिल क्या माफ करे, लाखों लोग, किसान आज कर्जा लेकर उनकी रकम गिरवी रख कर वी सी आर चुका रहे हैं।

सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी इसका रिप्लाई करें तो ऐसा करें कि जितनी भी वी सी आर हैं पूरी माफ करूंगा और जिन वी सी आर के पैसा जमा करा दिये हैं, उन किसानों को मैं पैसा वापस करूंगा, इस प्रकार की घोषणा करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की तो सभी हदें पार हो गई। मैं आर टी ओ विभाग की बात करूं। हमारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान और एम पी बोर्डर पर है। सरकार ने वहां एम पी बोर्डर खतम कर दिया, वहां भी आज की तारीख में अधिकारी बैठे हैं इस बात को नोट करें। वहां के आरटीओ के अधिकारी बैठे हैं और वहां बैठ कर लाखों रुपये, करोड़ों रुपये एक दिन के इकट्ठे करके वो बांट रहे हैं और वे कह रहे हैं कि +++ हमको करना पड़ता है। इस प्रकार का आरोप, अगर नहीं हो तो आप वहां जाकर देखिये कि बोर्डर पर हमारे किसान इस प्रकार से दुःखी हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, +++ क्या मतलब है यह एक्सपंज करो।

श्री सभापति: रिलेटेड हो तो एक्सपंज कर दो।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का आप जरूर देखें और आर टी ओ से लूट-खसोट इस प्रकार की हो रही है। सभी एम एल ए वहां उस रोड से आते होंगे आर टी ओ के इंस्पेक्टर वहां खड़े रहते हैं, इस प्रकार की लूट-खसोट करते हैं। इस आर टी ओ की लूट-खसोट को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं इतनी डैथ्स हो जाती हैं। आठ-दस लोग मिलकर उन गाड़ियों को रुकवाते हैं। आज ऑनलाइन सभी टैक्सेज जमा होने लग गये हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर इस प्रकार की लूट-खसोट हो रही है उसके बारे में देखें।

सभापति महोदय, अंग्रेजी स्कूल आप लोगों ने खोल दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, पर उन अंग्रेजी स्कूलों को वहीं जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है उन पर आपने अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगा दिया। वहां हमने टीचर नहीं लगाया और हिन्दी स्कूल वाले बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं। वहां टीचर भी लगायें, उनकी बिल्डिंग भी बनवायें। आपने कालेज की घोषणा कर दी पर कालेज की बिल्डिंग्स नहीं हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं हैं। इस प्रकार टीचर भी आप लगायें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में हमारे वहां एक एन डी पी एस की धारा 29 होती है और उस धारा 29 के नाम से करोड़ों रुपये ऐंठे जाते हैं। इस प्रकार की लूट हो रही है। धारा 29 के नाम से एक जना कोई अफीम में, डोडे चूरे में गलती कर लेता है कोई किसान तो उसके आठ-दस लोगों को पकड़कर किसी से पांच लाख, किसी से चार लाख, किसी से तीन लाख की वसूली करते हैं। इस प्रकार का सदन में आज प्रस्ताव लें कि धारा 29 को खतम करें और यहां से नहीं हो सकता है अगर केन्द्र से भी हो सकता है तो सर्वसम्मति से इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर उस धारा 29 को खतम करें क्योंकि एन डी पी एस में धारा 29 के कारण लोग काफी दुःखी हैं।

सभापति महोदय, हमारे वहां डोडे-चूरे के हर साल आते हैं और इस प्रकार से डोडे-चूरे को तोलने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं। दो-तीन महीने में डोडा-चूरा खतम हो जाता है, खराब हो जाता है और लोगों के खेतों में डालने के कारण उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इस कारण ऐसा प्रस्ताव लें और ऐसा सरकार आदेश करे कि जितना भी डोडा-चूरा हो रहा है उसको दो-तीन महीने में उस खेत में जला दें। इस प्रकार की घोषणा करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी मांगें रख दूं। सभापति महोदय की खूब मेहरबानी है मेरे पर तो।

सभापति महोदय, एक तो किसानों को आठ घंटे बिजली आप दे दें तो अच्छा रहेगा। बड़ी मेहरबानी रहेगी, क्योंकि पांच-सात महीने आप व्यवस्था करवा दें, उसके बाद तो ये आने वाली सरकार है, राठौड़ साहब, सब बैठे हैं सीनियर मैंबर, हण्ड्रेड परसेंट उसको आठ घंटे करवा ही देंगे। कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय, विद्यालयों में रिक्त पद हैं उन पदों को भरवा दें। सभापति महोदय, थोड़ी मेहरबानी रखें। इधर मेरी तरफ देख लें। इतनी मेहरबानी जरूर रखें। एक विद्यालय में खाली पद हैं उन पदों को भरवा दें। व्याख्याताओं को, स्कूल के प्रिंसिपल, कालेज के प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं, उनको भरवा दें। पी एच सी, सी एच सी आयुर्वेदिक के रिक्त पद हैं उनको भरवा दें। डाक्टर्स के रिक्त पद हैं उनको भरवा दें। कम्पाउंडर्स के रिक्त पद हैं उनको भरवा दें।

सभापति महोदय, कृषक मित्र योजना में लगे कृषक मित्रों को स्थायी किया जाये। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिये हैं। सी एच सी पर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

संविदाकर्मी, प्लेसमेंटकर्मी, विद्युत ठेकाकर्मी को स्थायी किया जाये। आई सी डी एस परियोजना में कार्यरत पदों पर विलोपित किये गये इन कर्मचारियों को वापस आप लगाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, मेरे बस्सी बहुत बड़ा इलाका है और वहां मेरी पंचायत समिति में चालीस पंचायतें हैं। एक नयी पंचायत समिति बस्सी खोलने का प्रस्ताव करें और वहां उप खण्ड कार्यालय भी खोलें। मेरे वहां जितनी भी पी एच सी हैं उनको आप सी एच सी करने की कोशिश करें और जो-जो भी कर्मचारियों की वहां पोस्टें खाली हैं, उनको आप भरवाने की कोशिश करेंगे। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस सरकार ने चार साल में मेरे वहां कोई नये कर्मचारी, नया डाक्टर, नया कम्पाउंडर नहीं लगाया। ये चिकित्सा मंत्री अभी बैठे थे। कल्ला साहब बैठे हैं। कल्ला साहब, आप थोड़ा नोट जरूर करें। मेरे वहां हास्पिटल्स में सभी डाक्टर्स, सभी कम्पाउंडर्स की पोस्टें खाली हैं, नर्सिंग कर्मचारियों की पोस्टें खाली हैं उनको आप भरवा देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों की होगी और चूंकि इस प्रकार की अराजकता पूरे राजस्थान में फैली हुई है....

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 2023-24 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। राजस्थान के जननायक मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने किसान वर्ग, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों, 36 कौम को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसके लिए मैं और मेरे पूरे समाज की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया, इसके लिए पूरा प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी, इससे राजस्थान की आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती मीना कंवर)

माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा पिछले बजट में कर दी गई थी, लेकिन बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारीगण की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करना कर्मचारियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसकी जितनी सराहना की जाये, उतनी ही कम है। इससे कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोगों में भी एक खुशी की लहर छा गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में किसानों के हित को देखते हुए उन्हें 2000 यूनिट तक बिजली में छूट प्रदान की है। रोडवेज में महिलाओं के लिए किराये में 50 प्रतिशत की छूट देकर बहुत बड़ी एक सौगात हमें दी है। साथ ही उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा करने से पूरे प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर छा गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि पूर्व मंत्री दाताहुकुम स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ की आत्मा आपको आशीष दे रही होगी। साथ ही शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र, जो कि शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसको आपने नगरपालिका घोषित किया, जिसके लिए मैं एवं मेरे क्षेत्र की जनता आपको कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कुछ कमियां रह गई हैं, उनको भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा किया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की जनता को ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिसमें दादोसा वीर शिरोमणि देवराज जी का पैनोरमा सेतरावा में बनाने की घोषणा की है। इससे देवराज समाज के 24 गांवों में खुशी की लहर छा गई है। साथ ही स्वर्ग में बैठे पूर्व मंत्री दादोसा खेतसिंह जी व पूर्व प्रधान मेरे पिता स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा भी आपको आशीष दे रही होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की चामूं पंचायत समिति से बाड़मेर के सीमावर्ती गांव चाबा तक बजट में डबल डामर सड़क की घोषणा करने पर समस्त विधान सभा क्षेत्र वासी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान जी ने बजट में 8 हजार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की है, इससे प्रदेश की माताओं, बहनों में खुशी की लहर छा गई है। मैं स्वयं महिला जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की खेल

(श्रीमती मीना कंवर)

की भावना को देखते हुए बालेसर नगरपालिका क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। शेरगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र बनाने की भी घोषणा की है, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की जनता को खूब-खूब सौगातें दी हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। साथ ही मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरे क्षेत्र में उप तहसील आगोलाई, ढाढणियां, दुगर, भाटेलाई सहित 12 ग्राम पंचायतों में पानी की भयंकर समस्या है। वहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं होने की वजह से आज भी तालाब से पानी लाया जाता है व अकाल की स्थिति में पानी की समस्या भयंकर हो जाती है। अत: श्रीमान जी, मेरा आपसे निवेदन है कि गगाड़ी फिल्टर प्लांट से ओपन पानी की पाइप लाइन स्वीकृत करावें, ताकि इनके साथ इनकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका गुणगान करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह बजट चुनावी बजट है और रेवड़ियां बांटने वाला बजट है। इस पर मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने प्रतिपक्ष के साथ भेदभाव किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पड़ोस के क्षेत्र में आपने हर प्रकार से दिल खोल कर घोषणा की और प्रतिपक्ष के एम एल ए के साथ आपने अन्याय किया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं, मंत्री महोदय बैठे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि जितने वोट हमें मिले हैं उतने ही आपके उम्मीदवार को मिले हैं, फिर भी आप भेदभाव करते हो, यह हमारे साथ नहीं, जिन्होंने आपको वोट दिये, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हो। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर नन्दीशाला खोलने की बात कही थी, लेकिन आज तक दोनों पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर नहीं खोली है।

आपने किसानों के साथ धोखा किया था। आपने कहा था 10 दिनों में कर्जा माफ होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो-तीन काश्तकारों ने आत्महत्या कर ली और उनकी जमीन कुर्की पर आ गई हैं। आज वह लोग

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वह अपनी किस्मत को कोस रहे हैं।

युवाओं के साथ आपने धोखा किया। युवाओं को आपने कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। उनको न तो नौकरी मिली और न ही रोजगार मिला।

बिजली के बिलों में आपने कहा था कि हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आपने कम से कम 7-8 बार पैसे बढ़ाये और आज कंज्यूमर लुटा हुआ महसूस कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय योजना में जो ढाणियों में लाइट लग रही थी, उसको बंद कर दिया। 100 मीटर की योजना भी आपने बंद कर दी।

गौरव पथ को बंद करके आपने विकास पथ बनाने की बात कही, परंतु पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में एक भी विकास पथ नहीं बनाया। आपने जनता क्लिनिक खोलने की बात कही, पर आज तक नहीं खुला। अब आप कह रहे हो कि एक करोड़ रुपये देकर पंचायतों पर हम गौशाला खोलेंगे। आपने ऐसी थोथी घोषणाएं बहुत कर दी हैं, लोग समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको बता भी देंगे।

आपने सूक्ष्म सिंचाई योजना मिशन की बात कही है, परंतु अभी भी डिग्गियों का अनुदान नहीं मिल रहा है। लोगों ने डिग्गियां बना ली हैं, लेकिन 2018 में बनी डिग्गियों का अनुदान आपकी सरकार ने नहीं दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिग्गियों का अनुदान शुरू करें ताकि काश्तकारों को सरकार पर भरोसा हो।

इसके साथ-साथ आपने चिरंजीवी योजना की बात की, उसमें आपने सर्प काटना, बिच्छू काटना, जहरीले जानवर के काटने का नहीं दर्शाया है, इसको भी इसमें शामिल करें ताकि जनता को लाभ मिल सके।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट में 30 किलोमीटर सूरतगढ़ से जाखड़ावाली सड़क की घोषणा की है, जबकि जाखड़ावाली से रावतसर तक रोड है। यह हमारी डिमांड भी है, इसको आप स्टेट हाईवे घोषित करो और इस रोड का जाखड़ावाली से आगे बढ़ाकर रावतसर तक चौड़ाईकरण करो ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके और सरकार की आधी-अधूरी घोषणा को पूरा किया जाये। यह कुल 57 किलोमीटर सड़क है और आपने 30 किलोमीटर किया है, 27 किलोमीटर और कर दें तो यह अलग से रास्ता जुड़ जायेगा और दिल्ली जाने वालों की कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी घट जायेगी।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला को नगरपालिका बनाने की मैंने पिछली बार भी मांग की थी। मंत्री महोदय ने यहां से घोषणा की थी कि जिला कलेक्टर का पत्र आने के बाद हम गोलूवाला को नगरपालिका बना देंगे। जिला कलेक्टर महोदय का पत्र भी आ गया, नगरपालिका बनाने के जितने मापदण्ड हैं, वे सारे के सारे तय हैं। इस बजट में मुझे उम्मीद थी कि आप गोलूवाला को नगरपालिका बनाओगे, नहीं बनाया, यह वहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार से आपने अन्य नगरपालिकाएं बनायी हैं, उनमें गोलूवाला के मानदंड सबसे ज्यादा हैं, इसलिए गोलूवाला को नगरपालिका बनाया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हनुमानगढ़ जिले में जो उप जिला अस्पताल घोषित किया है, रावतसर सी एच सी है, उसमें 1200 से लेकर 1500 तक की ओ पी डी है और आज वह हर मानदण्ड पूरा करती है। मेरा आपसे निवेदन है कि रावतसर में भी उप जिला अस्पताल घोषित करें, ताकि वहां के लोगों को न्याय मिले सके और अच्छी व्यवस्था हो सके। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये व पीलीबंगा, गोलूवाला और डबली के चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ायी जाये। पीलीबंगा और गोलवाला में ट्रोमा सेंटर भी स्थापित किया जाये। प्रत्येक सी एच सी में आप अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करें, ताकि गर्भवती माता एवं बहनों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा और रावतसर दोनों बड़े शहर हैं और दोनों में आवागमन की बहुत दिक्कत आती है, इसलिए दोनों में बाईपास की मांग करता हूं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस का पूरा नियन्त्रण नहीं है। उन पर नियन्त्रण किया जाये। हाल ही में हनुमानगढ़ के अन्दर समाजसेवी इन्द्र हिसारिया के गोली चली। उसके बाद नामी डाक्टर पारस जैन को धमकी मिली और फिरौती मांगी गयी और डबली के अन्दर भी व्यापारी से फिरौती मांगी गयी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। रावतसर में एक युवा को, जो 307 का गवाह था, उसको बदमाश ने सरेआम गोली मार दी और उसकी हत्या हो गयी। ऐसी घटना को रोकने के

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

लिए पुलिस पर नियन्त्रण करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डबली चौकी को थाना बनाया जाये व गंधेली में नयी चौकी स्थापित करें।

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रावतसर, पीलीबंगा फाटक काफी देर तक बन्द रहता है, वहां पर आर ओ बी की जरूरत है। मैंने पहले भी मांग की है कि वहां पर आर ओ बी बनाया जाये। पीलीबंगा-रावतसर हाईवे फाटक पर आर ओ बी बनाया जाये व रामपुरा रंगमहल में आर यू बी बनाया जाये। पीलीबंगा 29 एस टी जी फाटक, तिरूपति कालेज के पास आर ओ बी बनाया जाये। 35 एस टी जी के पास आर यू बी बनाया जाये, ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ मैं कॉज-वे की भी मांग करता हूं। लूढ़ाणा से अमरपुरा, बड़ोपल से भोजेवाला, खुदासरी से पूनियोंवालाधर तक भैरूसरी पर कॉज-वे की जरूरत है, ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके।

इसी प्रकार से राजस्थान कैनाल, जो कि जर्जर है, आरडी 84 पर जो पुल टूटा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी को बड़ी परेशानी होती है। आरडी 84 पर, आरडी 99 पर, आरडी 108 खोडा पर जो पुल जर्जर हैं, उनको सही कराया जाये या नया बनाया जाये।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डिगाभागसर, प्रेमपुरा, 26 पीबीएम सूरतगढ़ रोड तक, हनुमानगढ़ रोड से कमाणा के सामन डबली रोड नूरपुरा, भाम्यूवाली मलको का पक्का सारणा रोड तक, खरलिया लिखमीसर रोड से सुरेवाली, गोलूवालाढाणी, रोड तक, चाइया से कनवानी, गन्धेली लालपुरा, विकरवाला नोहर तक, धनासर कैंची से हरदासवाली, एटा-सूरतगढ़ रोड तक, रावतसर मुख्य रोड से 51 आरडी, 2 केबीएम, भैरूसरी जाखड़ावाली सड़क को चौड़ा किया जाये, ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर और पीलीबंगा में बहुत बड़े क्षेत्र हैं और आम आदमी को परेशानी होती है तो ए डी जे कोर्ट की मैं मांग करता हूं। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 डीडब्ल्यूएम, 21 STG-, 21 एमओडी प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। नूरपुरा, लवाणा, 17PBN, 21 एमओडी को प्राथमिक से मिडल बनाया जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): नूरपुरा लवाणा, अहमदपुरा, 10 MOD, सरामसर, 16 DWD, 7DWD चक 3 एमओडी, 22 एमओडी, 22 नम्बर वार्ड रावतसर, प्रेम नगर, कुम्हारा वाली ढाणी, मलकोका को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये व जो अंग्रेजी स्कूल खुले हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। बच्चों के साथ कुठाराघात हो रहा है। वहां भवन की व्यवस्था की जाये व स्टाफ की व्यवस्था की जाये। इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग से हमें कोई राहत नहीं दी गयी है। पीलीबंगा में मैं बालिका छात्रावास की मांग करता हूं। गोलूवाला, डबली, गन्धेली जाखड़ावाली में भी पुरुष छात्रावास की मांग करता हूं। गोलूवाला व डबली को तहसील बनाया जाये। निरदड़ी व जाखड़ावाली को उप तहसील बनाया जाये।

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा क्षेत्र सेमग्रस्त है और वहां पर भूमि लवणीय हो गयी है, जिसके कारण से उस भूमि में काश्त नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस सेमग्रस्त भूमि के लिए सरकार काश्तकार की सहायता करे, ताकि वहां पर वह फसल उगा सके। 1977 में वहां पर खाले बने थे और सेम के कारण वे जर्जर और ध्वस्त हो गये हैं, जिसके कारण काश्तकार को सेमग्रस्त भूमि को सुधारने में दिक्कत हो रही है। आपने बजट के माध्यम से भाखड़ा में तो खाले बनाने के आदेश कर दिये हैं, परन्तु इंदिरा गांधी नहर के काश्तकारों के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भी पक्के खालों के निर्माण की व्यवस्था करें और सेमग्रस्त खालों को प्राथमिकता के आधार पर सही करवायें, ताकि काश्तकार अपनी उस बंजर भूमि को सुधार सकें। इसी के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खेल स्टेडियम खोला जाये। रावतसर व गोलूवाला में भी अच्छे स्तर का एक स्टेडियम बनायें, ताकि लोगों की खेल के प्रति भावना बढ़े। सभापति महोदय, आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री देवी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, गरीबों के मसीहा एवं लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया, वह प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से और समाज के सभी वर्गों, किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं, उद्यमियों, व्यापारियों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए भरपूर लाभ और खुशियां बांटने वाला है। आपने मुझे

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

इस बजट का अनुमोदन करने का, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में जो भी घोषणा की है, वे सभी धरातल पर उतरेंगी। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 76 लाख बी पी एल तथा उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को एल पी जी गैस सिलेण्डर 500 रुपये में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट फ्री, 11 लाख से अधिक किसानों को 2 हजार यूनिट तक फ्री बिजली प्रति माह, एक करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ-साथ प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिये जाने की घोषणा कर महंगाई राहत पैकेज के माध्यम से आमजन को राहत प्रदान की है।

प्रदेश की आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में एक बार रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क कर युवाओं को राहत प्रदान की है। युवाओं के लिए 500 करोड़ का विकास कल्याण कोष, स्काउट गाइड और एन सी सी कैडेट को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड, 75 करोड़ रुपये की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव की घोषणा की है, जो कि अभूतपूर्व है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी चाहे वे किसी बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था में कार्यरत हैं, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा कर सरकार ने सभी के भविष्य की चिंता को समाप्त किया। वर्षों से चली आ रही ठेका प्रथा को समाप्त किया है। कर्मचारियों के प्रमोशन में 2 वर्ष की छूट दी है, संविदा कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आम आदमी के स्वस्थ जीवन के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तथा दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है। वहीं ई डब्ल्यू एस परिवारों को भी अब निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिल सकेगा।

आर टी ई में अब छात्रों को भी छात्राओं की तरह 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। बोर्ड फीस माफ कर दी, निःशुल्क स्कूल ड्रेस दी जायेगी। अब मिड-डे-मील योजना में बच्चों को प्रतिदिन दूध मिलेगा। कालीबाई एवं

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

देवनारायण स्कूटी योजना में 20 हजार की जगह 30 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जायेगी। बुजुर्गों की पेंशन अब कम से कम एक हजार रुपये कर राज्य सरकार बुढ़ापे का सहारा बनेगी। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जायेगी। महिला को राजस्थान रोडवेज में किराये में 30 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, जन-जन के लाडले मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है, जिसके लिए मैं राजस्थान की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक जी गहलोत द्वारा भीलवाड़ा जिले और मेरे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं इस बजट में की हैं, उनके लिए मैं सहाड़ा विधान सभा क्षेत्रवासियों की ओर से हृदय से उनका बार-बार आभार व्यक्त करती हूं। इसी संदर्भ में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मान में चंद लाइनें कहना चाहूंगी -

बचत, राहत और बढ़त का बजट पेश कर,
आपने कई अरमान जगाए,
अपने सुनहरे सपने पूरे होते देख,
लाखों चेहरे मुस्कुराये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की रायपुर एवं मोखुन्दा में पुलिस चौकी, ओज्याड़ा में नवीन पंचायत समिति खोली जाए, ताकि आमजन को सहूलियत हो सके। उप स्वास्थ्य केन्द्र नाथडियास, माझावास एवं सांगवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल तथा गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए। मासिंगपुरा (मोखुन्दा), रामपुरिया (अरनिया), तिलोली (सांगवा), झबरकिया (सोनियाणा), कोटडी (दरीबा) खजूरिया श्याम (गोवलिया), भैंसाकुण्डल (देवली), कालीमंगरी (डेलाणा) तथा मोमी (गुरला) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाएं, ताकि आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना सहित चिकित्सा विभाग की चल रही अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

कालीमंगरी (डेलाना), कुम्हारियाखेड़ा (देवली) प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, सरेवडी (भींटा), टूंगच (खाखरमाला), डांगडी (झडोल), भटेवर (भींटा), मियाला (बागड़), आलोली (अरनिया), झबरकियां (सोनियाणा), भैसाकुण्डल (देवली), शिवपुरा (दूडिया), जाग्रदरी (सेथूरिया), कान्याखेडी (बिलिया कलां) को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए।

किसानों को निरंतर विद्युत आपूर्ति हेतु गंगापुर में अधिशासी अभियंता कार्यालय तथा मण्डी, डेलाना और सांगवा में नये जी एस एस खोले जाएं। ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों की सहूलियत हेतु गंगापुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, मोखुन्दा में उप तहसील कार्यालय तथा कारोई में उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाए। बिलिया कलां ग्राम पंचायत में बनास नदी पर एनिकट निर्माण कराया जाए जिससे लगभग 40-50 गांवों को लाभ मिल सकेगा। भरक माता जी के मंदिर पर रोप-वे स्वीकृत किया जावे।

मेवाड़ पेट्रोल पम्प से काला बावजी रोड, देवरिया-हरिपुरा सड़क, मेन रोड से वाया सूरजपुरा-सगरेव सड़क, पनोतिया से चांदरास, मेन रोड से खरडाया (कैलाशनगर) खेमाणा सड़क, तिलोली से महावीर चौराहा तक सड़क, एप्रोच रोड थला, कोट से सिरोडी सड़क, जूणदा से सांगास सड़क, दूडिया से दौलपुरा सड़क, हरिपुरा से कांगणी सड़क, उल्लाई से झड़ोल एप्रोच रोड, माण्डल-बागोर-गंगापुर-सरगांव-राशमी (सरगांव से जिला सीमा तक), कुल लम्बाई 6 किलोमीटर सड़क का तीन से सात मीटर चौड़ाईकरण।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): सांगास कलां (राजसमन्द) से सहाड़ा वाया नेगड़िया खेड़ा-कागणी एम डी आर सड़क कुल लम्बाई 19 किलोमीटर सड़क की सिंगल लेन से 7 मीटर चौड़ाईकरण, ग्राम लाखोला से भरक जाने हेतु लाखोला ग्राम के बाहर बाईपास निर्माण सहित अन्य सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी करावें ताकि ग्रामीणों को आवागमन की दृष्टि से सहूलियत हो सके।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित तीनों पी.जी. कालेज में प्राचार्य सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरा जावे। मेरी विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालय में अध्यापकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों में भी चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ के काफी पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण आमजन को

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जावे, जिससे गरीबों का कल्याण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसी बजट को चन्द लाइनों में प्रस्तुत करना चाहती हूं-

"जादूगर हैं, जादूगरी का परचम इतना फहरा दिया,
आपके इस बजट ने सारा हिन्दुस्तान हिला दिया।
चिरंजीवी योजना का आज दुनिया में नहीं कोई सानी है,
हर पेंशनर को आपने आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है।
ओल्ड पेंशन स्कीम ने तो इतिहास रच दिया,
दिल्ली वाले भी दंग हैं, ये कैसा हिसाब कर दिया।
जब अशोक है तो राजस्थान की जनता को किस बात का शोक है,
आप भी खुलकर बजाओ ताली, किस बात की रोक है।"

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री सुरेश सिंह रावत।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री सुरेश सिंह रावत)

बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 10 फरवरी, 2023 को जो राजस्थान की विधान सभा में बजट पेश किया, वह बजट गफलत से शुरू हुआ और गफलत से शुरू होकर भूलभुलैया के अंदर वह निश्चित रूप से खो जाएगा और धरातल पर नहीं उतर पाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट की शुरूआत युवाओं के विकास के नाम पर की, लेकिन अफसोस है कि जिन युवाओं को गुमराह करके आप सत्ता में आये हैं, उनके 3500 रुपये जो देने का वादा किया था, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। अगर मैं बात करूं पेपर लीक मामले की, आपने पेज नंबर 6 के बिंदु नंबर 10 में इसका उल्लेख किया। आप 2022 के अंदर भी इसकी रोकथाम के लिए अधिनियम लाए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। अभी आपने स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की, जबकि डेढ़ साल में आपके 16 पेपर लीक हुए और बजट के दस्तावेज को मिला लें तो 17वां दस्तावेज लीक हुआ। अब क्या फायदा जब आपकी चिड़िया चुग गई खेत, आप तो जाने वाले हैं।

दूसरी, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की भी आप लोगों ने लम्बी-चौड़ी घोषणा की। पेज नंबर 11 के बिंदु 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, लेकिन घोषणा के साथ अच्छा होता कि सवा चार साल जो स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है, जो स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था के अंदर हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की मौजूदगी नहीं है, वहां आप फर्नीचर की व्यवस्था करवाते, स्कूल में कमरे बनवाते, जो जर्जर भवन हैं, उनकी मरम्मत करवाते, स्कूल के अंदर कोई स्टाफ लगाते। फिर आप कोई घोषणा करते तो आपकी समझ में आती।

आपके सवा चार साल के अंदर शिक्षा के मंदिर को जो आपने कलंकित करने का काम किया है, आपकी पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनको गांव के अंदर तो कोई बुलाते नहीं हैं और जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके अंदर जबरन उनको वार्षिकोत्सव के बहाने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम किया, मैं उसकी निन्दा करता हूं।

(समय: 17.00 बजे)

इसके साथ ही मैं तीर्थराज पुष्कर से विधायक आता हूं। तीर्थराज

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पुष्कर सबकी आस्था का केन्द्र है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, प्रमुख अखबारों की कटिंग है मेरे पास, उसके अंदर हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने 10/12/2022 को राजस्थान के शासन सचिवालय के अंदर एक बैठक रखी। एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। उसमें हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय को, पूरे प्रशासनिक लवाजमे को जयपुर बुलाकर, उसके विकास की चर्चा की, लम्बे-चौड़े प्रस्ताव बनाए। लगभग 500 करोड़ के काम होंगे, यह सब जगह प्रसारित किया। यही नहीं, इसके अन्दर कहा गया कि पुष्कर सरोवर के अन्दर जो गंदा पानी जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए व्यापक योजना बनाएंगे। डेस्टिनेशन मैरिज को बढ़ावा देने के लिए 100 कमरों का एक आलीशान यात्री आवास बनाएंगे। एस डी एम आफिस के पास आधुनिक स्टेडियम और मेला ग्राउण्ड का विकास करेंगे। जयपुर-नागौर रोड पर सप्तऋषि प्रवेश द्वार बनाएंगे, घाटों पर नये चैंजिंग रूम बनाएंगे, टूरिस्ट विलेज के रूप में डवलप करेंगे। सभी वार्डों में सी सी टी वी कैमरे लगाएंगे। इंटर-लॉकिंग सड़कें, नाले-नालियों का निर्माण करेंगे। अनेकों प्रकार के विकास कार्यों की अख़बारों के माध्यम से घोषणा की। जब हम इसकी तह तक गये कि इतने काम होने वाले हैं। तीर्थराज पुष्कर के पुरोहितों को और आमजन के मन में यह उम्मीद जागी कि सरकार पुष्कर के लिए कुछ करेगी। हद तो तब हो गई, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पढ़ा, बजट में पुष्कर के विकास कार्यों का लोगों को जो सपना दिखाया, अख़बारों में ख़बरें छपवाई गईं सत्ता का दुरुपयोग करके, उसमें से एक भी काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले को मुख्य मंत्री जी स्वयं संज्ञान में लें, क्योंकि यह बड़े स्तर पर बैठक हुई, बैठक होने के बाद भी हमारे पुष्करवासियों को असत्य सपने दिखाए। उनके लिए कुछ नहीं बोला गया। अब 16 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी बजट पर रिप्लाई देंगे, तो मेरी मांग है कि वह इन सब चीजों की घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी बहु-उपयोगी टूरिस्ट काम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की, आज तक उसकी एक ईंट भी नहीं लग पाई।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है, वह हम सबके लिए पीड़ा का विषय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब पिछले बजट में इसकी घोषणा की तो मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अजमेर विकास प्राधिकरण इसकी कार्यकारी एजेंसी है और उसके द्वारा वर्तमान में इस कार्य के लिए जो टेंडर लगाया जा रहा है, उस टेंडर के अन्दर, सीवरेज के पानी की रोकथाम के लिए जिक्र तक नहीं है। सिर्फ बरसाती पानी रोकने के लिए है। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे मांग है कि 16 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी रिप्लाई दें तो इसके बारे में अधिकारियों को डायरेक्शन दें और इस पर कार्यवाही करें। सदन के अंदर जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, जिस काम के लिए घोषणा की, उस काम के अलावा कोई दूसरा भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राथमिकता से करना चाहिए। पुष्कर क्षेत्र के लोगों को, आपकी सरकार व कांग्रेस के नेताओं की बदनीयती, चालाकी, जालसाजी, सिर्फ और सिर्फ विकास के असत्य सपने दिखाकर येन-केन-प्रकारेण आने वाले चुनावों में चुनावी फायदा लेने की सोच के साथ ही आप बार-बार विकास के जुमले दिखा रहे हो। उसका समय आने पर हमारी पुष्कर की जनता जवाब देगी।

सभापति महोदय, चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के अंदर भी आप लोगों ने लम्बी-चौड़ी बात की। आज हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अस्पतालों की जर्जर अवस्था है। अस्पतालों में इक्विपमेंट नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर भी ध्यान दें। उसके बारे में भी घोषणा करें।

सभापति महोदय, बार-बार औद्योगिक समिट होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से लोग लाते हो, लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर उद्योगों का आधारभूत ढांचा है, रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं। उनको एक बार प्लानिंग करने के बाद, उद्योग लगने के बाद, उन सड़कों की सुध नहीं ली जाती। वहां की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसके बारे में विचार नहीं किया जाता। मेरी मांग है कि मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी पालरा, गेगल, रूपनगढ़ एरिया इण्डस्ट्रियल एरिया है। यहां पर सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, पीने के पानी की समस्या है, इन दोनों समस्याओं का समाधान करें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

सभापति महोदय, पेज नम्बर 52 के बिन्दु 93 पर सड़कों की भी बढ़-चढ़कर घोषणा की गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। किशनगढ़ से अरडका होते हुए खुंडियास तक 38 किलोमीटर की आपने स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 2013 से 2018 तक वसुन्धरा जी के कार्यकाल में जो सड़कें बनीं, उसकी आप मरम्मत तक नहीं कर पाये, मैं इसकी निन्दा करता हूं। मांग करता हूं कि जर्जर पड़ी सड़कों की कम से कम मरम्मत तो करें।

सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में आपने पैरा नम्बर 5 में कहा कि हम 100 यूनिट तक मुफ्त करेंगे, 200 यूनिट किसानों को प्रतिमाह मुफ्त देंगे। आपके बिजली के तार हैं उसके अंदर करंट ही नहीं आता तो उसके अंदर आप बिजली मुफ्त करके क्या करेंगे?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): आप रोडवेज किराये में छूट की बात करते हो। चार साल में हमारे गांव में एक भी रोडवेज नहीं चल रही तो आप किराये में किस बात की छूट देंगे?

सभापति महोदय, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की बात की गई कि प्रशासनिक ढांचा है उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे। आप देखेंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, माननीय मुख्य मंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, उनके गृह मंत्री रहते हुए पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर घड़साना के वकील ने आत्महत्या कर ली, यह आप सबके सामने है। इसके अलावा, जयपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है, राजधानी में जो थाने हैं उनको एस आई लेवल का अधिकारी चला रहा है, यह आपके सामने है। प्रदेश की जेलों में सुविधा के नाम पर जेल अधीक्षक द्वारा वसूली की जाती है। ए सी बी द्वारा उन पर मुक़दमे दर्ज किये जाते हैं। अभी हाल ही एक मामला आया था, यह चंदवाजी थाने का मामला है। इसमें हत्या में प्रयुक्त चाकू व 14 प्रकार के अन्य आर्टिकल जो सामान थे, वे थाने से गायब हो गये। जब कोर्ट ने पूछा कि कहां गये, तो कहा कि साहब बन्दर ले गये। इस तरह का मजाक माननीय मुख्य मंत्री जी के रहते हुए प्रदेश में हो रहा है। आमजन में पुलिस का विश्वास था, वह भी कम हो रहा है। पुलिस में हमलों की बात करें तो जयपुर पहले नम्बर वन है, माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह जिला जोधपुर नम्बर दो पर है। जयपुर में एक वाकया ऐसा हुआ कि राठौड़ी के अन्दर एक शख्स को थाने में बिठा लिया और थाने में परेशान होकर वह थाने के इंस्पैक्टर की रिवाल्वर लेकर भाग गया।

श्री सभापति: श्री हरीश मीना।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): पुलिस ने उसको घेरा, उसने फायरिंग शुरू की। इस तरह के अपराध दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): महोदय, आपने मुझे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 के पक्ष में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह बजट वह आधारशिला है जिस पर भावी राजस्थान की, जो प्रगतिशील होगा, विकासशील होगा, उसकी नींव रखी गई है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को उनकी सोच के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके द्वारा प्रस्तुत इस क्रांतिकारी बजट के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, मैं कोई कवि नहीं, कवयित्रियों से मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं तो सीधे मेरी बात पर आ जाता हूं। इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांग रखता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं। मैं उच्च शिक्षा से शुरू करूंगा। सरकार ने प्रदेश में पिछले चार वर्षों में 40 नये कृषि कालेज खोले हैं जो कि एक सराहनीय कदम है, किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं खोला गया है पिछले चार वर्ष में। उनियारा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय संचालित है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि उनियारा कस्बे में कृषि महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, नगरफोर्ट, नासरदा, बनेठा, सोंप, धुवां में राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा उप खण्ड में संस्कृत शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अत्यधिक रूचि होने के कारण मैं सरकार से बनेठा क़स्बे में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पीजी कालेज देवली में, वर्तमान में विज्ञान की बी एससी (यू जी) लेवल की क्लासेज हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवली पी जी कालेज है, उसमें साइंस की भी पी जी कक्षाएं भी शुरू की जाएं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिले।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

राजकीय महाविद्यालय, दूनी में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र विषय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़ एवं राजकीय पी जी कालेज, उनियारा में उर्दू विषय प्रारम्भ करने की सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, स्कूली शिक्षा में पिछले चार वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में एक भी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति का छात्रावास नहीं खोला गया है। प्रदेश में अनेक जगह पर खोले गये हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं क्योंकि यह सरकार की नीति का भी हिस्सा है तो सरकार उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक के गरीब छात्रों को लाभान्वित करने के लिए छात्रावास खोले।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय रिजोदा एवं देवीखेड़ा में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है जबकि सरकार की ऐसी नीति है। वही इसी क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा, बिलासपुर, खरोई, गोविन्दपुरा, दलवासा, रामथला, जलेरी, मुगलाना, स्यावता, महाराज कंवरपुरा, रायपुरा (कचरावता) एवं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोंप को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की सरकार से मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सआदतनगर, अल्लापुरा, बंजारात, गांधीग्राम द्वितीय एवं रावता को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की सरकार से मांग करता हूं।

सर, यह एक बड़ी विडम्बना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूनी एक बहुत बड़ा कस्बा है और वहां पर कालेज भी है और हायर सैकण्डरी स्कूल दो हैं, बच्चों की है और बच्चियों की भी है पर जो हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह जब इतना बड़ा कस्बा है, इतने शिक्षण संस्थान हैं तो दूनी, देवली के जो हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें कृपया साइंस विषय अविलंब खोलें।

इसी प्रकार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली (उनियारा), नगरफोर्ट, सोंप, सुरेली, चोरू, ककोड़, कुंडेर एवं खोहल्या के राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला जाये एवं साथ ही ग्राम पंचायत देवड़ावास, गेरोली, मालेड़ा में कृषि संकाय एवं गावंडी व चांदली के विद्यालयों में कला

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

संकाय प्रारम्भ किया जाये। साथ ही बालिका विद्यालय, उनियारा में भूगोल विषय, बालिका विद्यालय, देवली में उर्दू विषय, बालिका विद्यालय, दूनी में राजनीति शास्त्र, घाड में अंग्रेजी विषय व खेलनिया में इतिहास विषय खोलने की सरकार से मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में वर्तमान में एक भी राजकीय आई.टी.आई. नहीं है। सर, यह बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि दो मेरे उपखण्ड हैं देवली एवं उनियारा, तो दोनों में एक-एक राजकीय आई.टी.आई. खोलने की कृपा करें ताकि हमारे युवा बच्चों को रोजगार के मौके मिल सकें।

सर, चिकित्सा के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। चिकित्सा मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2022-23 के बजट में एक भी पी.एच.सी. और एक भी सी.एच.सी. नहीं दी गयी है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं मंत्री महोदय आपके मार्फत कि मेरे तहसील स्तर के पी.एच.सीज. हैं, कम से कम उनको तो सी.एच.सी. करें और ये हैं- नासिरदा, सोप को आप सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की कृपा करें एवं जो बड़े कस्बे हैं, जिनकी पांच हजार से ज्यादा की आबादी है, जैसे- पलाई, चांदली, हैदरीपुरा, पायगा, खातोली, निवारिया, फूलेता, सांवतगढ़, पनवाड़, बड़ोली आदि बड़े कस्बों में पी.एच.सी. खोलने का श्रम करें, ताकि हमारी गरीब जनता को उनके द्वार पर सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके।

सर, इसी क्रम में जो देवली का अस्पताल है, देवली सबसे बड़ा कस्बा है और वहां पर चार-पांच जिलों की सीमा मिलती है। टोंक की, भीलवाड़ा की, अजमेर की, बूंदी की सीमाएं मिलती हैं और वहां से दो-दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो वहां का जो हास्पिटल है उसको अभी राज्य सरकार ने 100 बेड का हास्पिटल घोषित किया है और सरकार की नीति यह है कि जहां पर 100 बेड का हास्पिटल होता है, उसको आप उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर सकते हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि देवली अस्पताल को चूंकि वह मापदंड पूरा करता है तो उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

सर, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली में गत बजट में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गयी थी जिसकी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बावजूद भी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

अभी तक ब्लड बैंक का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इसको अविलम्ब चालू करे और जनता को इसका लाभ मिले।

सर, पिछली बार मैंने प्रश्नकाल में एक सवाल लगाया था और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया था ट्रोमा सेंटर का उनियारा और देवली में तो सरकार को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि देवली एवं उनियारा में चूंकि यह दोनों नेशनल हाईवे पर हैं, एक्सीडेंट के अनेक केसेज होते हैं तो सरकार यहां पर ट्रोमा सेंटर खोले। सर, मैं मंत्री महोदय को अपना मांग पत्र भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अलग से पेश कर दूंगा।

सर, मेरे कुछ सुझाव हैं सड़कों के बारे में। मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के देवली उपखण्ड में दौलता मोड से गांवडी-राजमहल तक की सरकार ने ढाई सौ करोड़ रुपये की रोड दी है 27 किलोमीटर की। 180 करोड़ की 27 किलोमीटर की रोड है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साहब, उसमें आठ ग्राम पंचायतों का इलाका शामिल होगा और यह जनता की बहुत ही पुरानी मांग थी जो पूरी हुई है। उसके लिए मैं सरकार को और मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं।

इसी तरह से सर, कुछ और छोटी-छोटी सड़कें हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि ये छोटी-छोटी सड़कें बनाएंगे तो हमारी जनता को लाभ मिलेगा। जैसे कि- ककोड़ से गुमानगंज, खातोली से अल्लापुरा, ये दोनों रोड पांच किलोमीटर की कुल हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अविलम्ब इनको पास करें। ककोड़ से गुमानगंज सड़क, खातोली से अल्लापुरा सड़क, बनेठा से रघुनाथपुरा-रामनगर सड़क, गांगली से झुण्डवा सड़क, रामगंज मोड़्याली से रामपुरा धाकडान सड़क, दांता की ढाणी से जाल का झोंपड़ा सड़क, सद्दीकनगर से सोंप सड़क, चोरू से मंडावरा सड़क, रहमान नगर से चोरू सड़क, ये छोटी-छोटी रोड्स हैं। सर, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर की ये सड़कें हैं। अगर सरकार यह कर दे तो बहुत सारे हमारे गांव हैं, जो 70-75 साल से रोड से वंचित हैं, उनको लाभ मिलेगा।

सर, बिजली के क्षेत्र में निवेदन है कि मुझे एक भी जी.एस.एस. नहीं मिला है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र सिंचित है, नहरी इलाका है, जगह-जगह ट्यूबवैल है, दो फसली इलाका है और सब समय नहर से पानी नहीं मिलता है तो लोग

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

ट्यूबवैल पर निर्भर रहते हैं। सर, बिजली की आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पूर्व में खोले गये मतलब, घोषित जो जी.एस.एस. थे, स्यावता, पाडली, कोटडी मोड, अनवार नगर का कार्य भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह बजट में घोषित है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि कृपया इनको प्रारम्भ करें। इसी तरह इस बजट, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीतापुरा एवं बीजवाड में नये जी.एस.एस. खोलने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

इसी प्रकार एक प्रस्ताव है जो विभाग में पेंडिंग है कि नगरफोर्ट कस्बे में 132 के.वी. जी.एस.एस. खोलने की मांग है। यह समस्त मापदंड पूरा करता है और वह राज्य सरकार के बिजली विभाग में पेंडिंग है, तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह नया जीएस.एस. 132 के.वी. का खोले ताकि जनता और किसानों को लाभ मिले और बिजली की जो बार-बार ट्रिपिंग होती है, वह नहीं हो।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): जी सर। इसी प्रकार से सर, अलीगढ़ कस्बे में नवीन सहायक अभियंता कार्यालय, आर.एस.ई.बी. खोलने की मांग करता हूं, क्योंकि यह सब मापदंड पूरे करता है। प्रस्ताव आ चुका है और जो प्रभावशाली एम.एल.एज. हैं या मंत्री हैं उनके तो सर, पन्द्रह-पन्द्रह हजार कनेक्शन पर आपने एक-एक वह खोल दिया पर मेरे इसमें 28 हजार कनेक्शन हैं, इसके तो दो कर दें। यह पूरे मापदंड पूरे करता है तो सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि इसमें न्याय करे।

सर, एक और विडम्बना अपने प्रदेश में यह है कि जो कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं, अनुसूचित जाति के कृषकों को आप प्राथमिकता के आधार पर देते हैं, उसकी वेटिंग नहीं होती है। वह आता है, एप्लाई करता है, दिया जाता है, यह अच्छी नीति है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी तरह से जो टी.एस.पी. क्षेत्र है जो जनजाति के लोग हैं उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पर बाकी जो जनजाति के लोग हैं राजस्थान में, एक ही जाति को आप दो मापदंड से नहीं चला सकते तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि टीएस.पी. की भांति, यहां के जनजाति के जो कृषक हैं, उनको भी उसी नीति के तहत प्राथमिकता पर कृषि कनेक्शन दिये जायें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, एक मेरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चूंकि यह बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, एक विधान सभा क्षेत्र को तोड़कर बनाया गया है, पहले टोंक में पांच विधान सभा क्षेत्र होते थे, टोडारायसिंह तोड़ दी और अब चार रह गयीं तो उन क्षेत्रों को मिलाकर हमको दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच तहसील हैं और चार उप तहसील हैं और उपखण्ड दो ही हैं, तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दूनी में एक नया उपखण्ड कार्यालय खोला जाये ताकि हमारे किसानों को, ग्रामीणों को राहत मिलेगी और उनके कार्य स्थानीय लेवल पर ही सम्पादित होते रहेंगे।

सर, इसी तरह से उपखण्ड मुख्यालय, देवली में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में कैम्प कोर्ट को नियमित करने, सर, अभी कैम्प कोर्ट चलता है, वह पन्द्रह दिन में दो दिन ही चलता है तो मैं यह कह रहा हूं कि जब कैम्प कोर्ट चल रहा है तो उसको नियमित रूप से कर दें ताकि हमारे लोगों को वहां पर राहत मिले। इसी तरह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उनियारा को क्रमोन्नत करके अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायिक मजिस्ट्रेट, ADJ कोर्ट स्थापित करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल में बहुत जगह नई नगरपालिकाएं खोली गयीं। जिस आधार पर भी खोली गयीं, पर मुझे ऐसा पता है, काफी गांव ऐसे हैं जहां 10 से 15 हजार की आबादी है, उसमें नगरपालिका खोली गयी, उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरे यहां दूनी एक कस्बा है, जिसकी आबादी 22 हजार है। अगर नगरपालिका खोलने की पात्रता 15 हजार है तो मेरा कस्बा 22 हजार का है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दूनी में नगरपालिका खोली जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, अंत में, मेरी एक पानी की मांग है। आप जानते हैं राजस्थान में पानी की कितनी दिक्कत है और बीसलपुर ऐसा डैम है, जो पूरे जयपुर को पानी पिलाता है, दौसा को पिलाता है, अजमेर-नागौर सब जगह पानी जाता है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मेरे यहां एक पेयजल की योजना है, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, अगर आपके पास समय हो तो कृपया नोट करें। बघेरा से बड़ला, यह पेयजल योजना 18 किलोमीटर की है। यह योजना 2008 में शुरू

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हुई थी। टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। वही ठेकेदार है, वही इंजीनियर है, वही चीफ इंजीनियर है, वह एक्स.ईएन. था, वह ट्रैप हो गया और वह जेल में गया, जब एडिशनल चीफ इंजीनियर था तब ट्रैप हुआ और जेल में गया।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। उसका नाम है मनीष बेनीवाल। महोदय, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह योजना 2008 में चालू हुई थी, आपके कार्यकाल में पूरी हो जाये और आप जनता को पानी पिलायें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक स्पोर्ट्स का बोल दूं, क्योंकि खेल को हमारे यहां बड़ी प्राथमिकता दी गयी है। हमारे खेलों में राजस्थान के तीन खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान के सर्वोच्च रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान का एकमात्र खिलाड़ी है, जिसका नाम है श्री रामसिंह, वह एकमात्र खिलाड़ी है, जिसने 1984 के ओलम्पिक में 800 मीटर रेस में ओलम्पिक रिकार्ड तोड़ा था। लास एंजिल्स, अमेरिका में वह ओलम्पिक हुए थे। मैंने आज तक किसी मंच पर सरकार को या खेल विभाग द्वारा उनसे सलाह लेना, उनको सम्मानित करते हुए नहीं देखा। इसी तरह जो भारत की फुटबाल टीम थी, उसमें किसी राजस्थान के खिलाड़ी का सलेक्शन होना बड़ी बात है।

श्री सभापति: आपके पास लिखा हुआ है, आप टेबल कर दीजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): एक मगन सिंह है हमारे फुटबाल प्लेयर, जो भारतीय फुटबाल टीम के कैप्टेन रहे थे, उनको किसी खेल से नहीं जोड़ा गया। उनको क्यों वंचित रखा गया है? इसी तरह हमारे जयपुर के लाडले गोपाल सैनी, ओलम्पियन, 22 साल तक उनका एशियाई रिकार्ड रहा 300 मीटर स्टीपलचेज में। उनको क्यों दूर रखा जा रहा है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को जोड़ा जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुझे पूरा-पूरा संरक्षण देंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

माननीय सभापति महोदय, यह बजट पेश करने से पहले मुख्य मंत्रीजी ने प्रचार-प्रसार का पूरा इंतजाम किया। राजस्थान के अंदर 15 हजार जगहों पर टी.वी. लगवाये और होर्डिंग और बैनर लगाकर पूरा प्रचार किया। जब सदन के अंदर मुख्य मंत्रीजी बजट लेकर आये तो बजट ही पुराना आ गया। पिछले साल का बजट आ गया। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना कि पिछले साल का पढ़ें, उससे पिछले साल का पढ़ें, पढ़ा ही था उन्होंने। राजस्थान की जनता जरूर शर्मसार हुई है और प्रदेश की सत्ता को जरूर बट्टा लगा है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आनन्फानन में यह तो अच्छा रहा कि मुख्य सचेतक जी ने मुख्य मंत्रीजी के कान में कह दिया कि यह बजट तो पुराना है और नया बजट आ गया, तो इसका मतलब बजट तो पहले ही लीक हो गया। यह चुनावी बजट है और इस बजट में कोई जान नहीं है। वित्तीय प्रावधान नहीं हैं। घोषणाएं धरातल पर आने वाली नहीं हैं। यह हवा-हवाई बजट है और विधान 2023 के चुनावों में इसकी हवा भी निकल जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, बजट को लेकर सत्ता पक्ष के मित्रों ने बहुत बढ़चढ़कर बातें कीं, कहनी भी चाहिये, सत्ता पक्ष का काम ही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर कोई खास बात नहीं है, इस बजट में कोई दम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के अंदर भी जब गहलोत साहब ने 2013-14 का बजट रखा था लास्ट में, उस समय भी केवल घोषणाएं ही घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं का क्या असर रहा? मात्र 21 विधायक जीतकर आये। अब की बार, यह भी घोषणाओं का बजट है, शायद हो सकता है 10-12 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक जीतकर नहीं आएंगे, ऐसी उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में आपकी सरकार बनी और उससे पहले चुनाव हुए। चुनावों के अंदर राहुल जी को बुलाया गया और राहुल जी से कहलाया गया कि हमारी सरकार बना दो, हम 10 दिन में सम्पूर्ण कर्जे माफ कर देंगे, 3500 रुपये बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे, 24 घंटे घरेलू बिजली देंगे। मुख्य मंत्रीजी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बन गयी। 2018-19 में मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया। उस बजट के अंदर एक तंज कसा हमारी सरकार पर-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

'बेवजह फिजूलखर्ची के बहुत किस्से हैं,

लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से में है।'

लेकिन 2023 के चुनावों के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, तो यह तंज आपके ऊपर लागू हो जायेगा। कुछ घोषणाएं मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो आप पहले बजट से लगातार चार बजटों में और इस पांचवें बजट में करते आ रहे हैं, पर लागू एक भी नहीं हुई।

पैरा नंबर-17, मैं 2018-19 के बजट की बात कर रहा हूं। कृषक कल्याण योजना, फाइलों में दफन, पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दीशालाएं, दफन, सड़क तंत्र के लिए आपने कहा कि 35 हजार करोड़ का सड़क तंत्र बनायेंगे, आज सड़कों की हालत खस्ता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 हजार किलोमीटर तक के एक-एक किलोमीटर के वाल टू वाल विकास पथ बनाये जायेंगे। अब मैं देख रहा हूं कि सारे विधायक उस विकास पथ को टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं, पर ग्राम पंचायत में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह विकास पथ पूर्व उप मुख्य मंत्री, सचिन जी पायलट के साथ आये थे और उन्हीं के साथ वापस चले गये। यह विकास पथ की स्थिति है।

पैरा नंबर-41 में आपने कहा था कि हमारी पिछली सरकार ने सरप्लस बिजली पैदा की है। जब सरप्लस बिजली पैदा की है तो वर्तमान में बिजली क्यों खरीदी जा रही है? 18 रुपये यूनिट में बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम कर रहे हैं। यह बिजली तंत्र पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है।

पैरा नंबर-49 में कहा कि किसानों के लिए 'कुसुम योजना' लायेंगे, आपकी वह योजना भी गायब हो गयी।

पैरा नंबर-81 में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान में सैण्ड नीति बनायेंगे। आपने कहा अवैध बजरी का कारोबार प्रदेश में बढ़ा है। आपने यह भी कहा भ्रष्टाचार की इस बहती हुई गंगा में ईमानदार लोग भी भ्रष्ट हुए हैं। यह गंगा किसने बहाई? यह जांच का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार की इस बजरी की बहती गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के भी कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पैरा नंबर-95 में कहा कि 'गली-मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलेंगे।' आपके वह जनता क्लिनिक कहां गये? वह कहीं देखने को नहीं मिल रहे।

पैरा नंबर-100 में कहा है कि 'युवाओं को तंबाकू, पान-गुटखों से दूर रखने की कार्य योजना बनायेंगे', लेकिन मुझे लगता है कि वह योजना तो बनी नहीं गुटखों से दूर रखने की, लेकिन हर गली और मोहल्ले के अंदर अवैध रूप से शराब का कारोबार आपने जरूर खोल दिया।

आपने पैरा नंबर-113 में लिखा-'हम भिक्षावृत्ति अधिनियम, 2012 लाये'। यह आपने ही लागू किया था। क्या शहरों के अंदर भिक्षावृत्ति खतम हो गयी? नहीं हुई।

आपने पैरा नंबर-124 में कहा था कि 'सर्वपल्ली राधाकृष्णन् विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना लायेंगे'। कुछ भी नहीं हुआ।

प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोले जायेंगे, क्या वह खुल गये?

पैरा नंबर-33 में कहा युवा योजना फाइलों में दफन हो गयी। चार वर्ष की घोषणाएं अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं, तो 2023-24 की इस बजट की घोषणाएं कहां से पूरी होंगी? इसमें वित्तीय प्रावधान ही नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांगों के लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा, फिर वापस अपनी बात करूंगा। मेरे क्षेत्र की जो मांग है प्रमुख रूप से, कपासन उपखण्ड मुख्यालय है और इसके आस-पास राशमी व भोपाल सागर उपखण्ड का मुख्यालय है। कपासन के अंदर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का अस्थायी रूप से कैम्प लगता है। मेरा आपसे आग्रह है यहां पर लगभग 830 केस चल रहे हैं और कैम्प के माध्यम से सुना जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ADJ कोर्ट को स्थायी रूप से करने की घोषणा करें और आने वाली 16 तारीख को जब मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, तब कपासन के अंदर ADJ कोर्ट की घोषणा करेंगे, यह मेरी प्रमुख मांग है।

मातृकुण्डिया बांध का पानी कपासन विधान सभा क्षेत्र के किसानों को मिले।

बनास नदी से कपासन बांध, धमाना बांध, भोपाल सागर बांध, डिंडोली बांध को भरने की फीडर को ठीक करवाकर पानी उपलब्ध करवाया जाये। किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाये। विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पद

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

भरे जायें। कालेज में रिक्त पदों को भरा जाये। पी एच सी, सी एच सी और आयुर्वेद चिकित्सालयों में डाक्टरों, कम्पाउंडरों के पदों को भरा जाये। कृषक मित्र योजना में कृषक मित्र को जो सैकड़ों की तादाद में हैं, उनको स्थायी किया जाये। हाई कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दे रखे हैं। संविदा कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी, विद्युत ठेका कर्मियों को स्थायी करें।

आई सी डी एस योजना में, जिस दिन बजट पढ़ा गया, उस दिन ही प्रखण्ड परियोजना सहायकों के पदों को विलोपित कर दिया। मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को वापस रेगुलर किया जाये।

राशमी के अंदर ए ईएन आफिस जलदाय विभाग का खोला जाये। बासोड़ा में विद्युत विभाग का ए ईएन आफिस खोला जाये। महाविद्यालय, सांवलिया जी और कपासन के अंदर रिक्त पदों को भरा जाये।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, अभी तो शायद 3 ही मिनट हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत आकोला, भादसरैड़ा, सांवलिया जी को नगरपालिका बनाया जाये। बनास नदी पर सांखली पुलिया बनायी जाये। हमीरगढ़-राशमी वाया मरमी सड़क को एम डी आर में घोषित करके पुनर्निर्माण कराया जाये। भादसरैड़ा-राशमी-रोलिया सड़क को मेगा हाईवे बनाया जाये।

मिसिंग लिंक सड़कों के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली बार भी आपने कुछ गड़बड़ की थी और इस बार भी करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 10 करोड़ रुपये सड़कें बनाने के लिए विधायकों को देने की बात कही है। मेरा निवेदन है कि इसको 20 करोड़ किया जाये। साथ ही यह विधायकों की अनुशंषा पर ही हो।

जे जे एम योजना के तहत मेरे क्षेत्र के सभी गांवों को पानी दिया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने सिर्फ क्या काम किया है कि योजनाओं का नाम बदला है, या तो हमारी योजना बंद कर दी या योजनाओं का नाम परिवर्तन करके चालू किया है। अन्नपूर्णा रसोई को आपने इंदिरा रसोई कर दिया। बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। 8 रुपये में खाना दे रहे हैं। हम भी 8 में दे रहे थे। आपने 3 साल बंद रखी।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

भामाशाह योजना, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी का नाम दिया। अटल सेवा केन्द्र को राजीव सेवा केन्द्र कर दिया। ग्रामीण गौरव पथ को विकास पथ कर दिया। बाल गोपाल दूध योजना आपने 3 साल तक बंद रखी। अब डिब्बा पैक पाउडर ला रहे हैं। यह पाउडर घटिया किस्म का आ रहा है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बच्चे इस दूध को पी नहीं रहे हैं। पाउडर को पी नहीं रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्टेट का टोल टैक्स हमने बंद किया था, आपने वापस लागू कर दिया।

वर्तमान सरकार के कारनामों की कुछ झलक दिखाना चाहता हूं। आपकी सरकार ने क्या किया? 'धूल चेहरे पर लगी थी, आप आईना साफ करते रहे'। यह आपकी स्थिति है। पेपर लीक माफिया सक्रिय हो गया। 17 बार पेपर लीक हुए। शराब माफिया, गली-गली, मोहल्लों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। बजरी माफिया, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। भू-माफिया सक्रिय हैं। पुलिस प्रशासन की आड़ में खुला खेल हो रहा है। अवैध वसूली के माफिया, नकली दवाओं के माफिया, नकली खाद्य सामग्री के माफिया, इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हालात बड़े खराब हैं।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह प्रदेश विकास के अंदर तो आगे नहीं है, लेकिन किसमें आगे है, वह मैं बताना चाह रहा हूं। दलितों पर अत्याचार में नंबर वन है, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है, महिला दुष्कर्म में नंबर वन है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, एक मिनट। एक मिनट। साइबर क्राइम में नंबर एक है, पेपर लीक में नंबर एक है, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में नंबर एक है, बिजली की कीमतों में नंबर एक है, बिजली कटौती में नंबर एक है, भ्रष्टाचार में नंबर एक है। इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में चोरी, लूट, डकैती, हत्या, गोलीकांड आम बात हो गयी है। पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस से जो काम होना चाहिए, चोरों को, डकैतों को पकड़ना चाहिए, लेकिन इस पुलिस को रोड और चौराहों पर खड़ा करके हेलमेट और सीट बैल्ट के नाम पर, हेलमेट नहीं है, सीट बैल्ट नहीं है, उनसे हजार-हजार रुपये वसूल किया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): खुद की जेबें भरी जाती हैं और सरकार के पास कोई पैसा भी नहीं आता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रकार से खोटा काम पुलिस के द्वारा मत कराओ। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने राज्य का यह पांचवा शानदार बजट पेश किया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं।

काफी समय से पक्ष और विपक्ष के लोग इस बजट के ऊपर अपनी-अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से इस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को यहां पर प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इस बजट से आने वाले समय में सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, सम्बल भी मिलेगा। उससे उनको इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में और राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने में मदद मिलेगी।

मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी इस बजट की आलोचना भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं। वे कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजट की जो घोषणाएं हुईं उनमें कई तो पूरी हो चुकीं और कुछ पाइप लाइन में हैं, काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वे भी पूरी होंगी। उनका भी काम पूरा हो पायेगा।

कालेज की बात कर रहे थे। कालेज का निर्माण कार्य मेरे यहां चल रहा है और अप्रैल के अंदर वह कंपलीट हो जायेगा। सड़कों का काम चल रहा है। पेयजल का काम चल रहा है। मेरे यहां जो पिछली बार सी एच सी खुली, जमीन का अलाटमेंट हो गया। यह काम क्या जनता को दिखते नहीं हैं? सब दिख रहा है।

आज इलाके के अंदर आप कहीं भी चले जाइये। आप पूछ लें विकास

(श्री आलोक बेनीवाल)

का काम, आज आम जनता यह कहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार है। पिछले 15 साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ, वह इस 4 साल के कार्यकाल में हुआ। यह क्षेत्र की जनता मानती है और कहती है, लेकिन आप तो हुए काम को भी नहीं बताते हैं।

आपने तो घी, दूध, दही इन पर टैक्स लगा दिया। उसकी बात ही नहीं करेंगे। आपने जो वादे किये उनकी बात ही नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना का प्रारूप बनाकर के 25 लाख किया, एक्सीडेंटल बीमे में 10 लाख कर दिया। इस बजट के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो मैं बोलूंगा तो लंबा समय लगेगा, मेरे पास समय कम है।

बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों को साथ रखते हुए जो राहत दी है, उनको सम्बल दिया है, वह आप सबके सामने है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को रिक्वैस्ट करूंगा कि जो एक्सीडेंटल बीमा है, उसमें कुछ दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं, उनको भी शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे माइनिंग में कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना में खतम हो जाता है तो उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

मेरे यहां एक दुर्घटना हुई थी। उसके अंदर उस व्यक्ति को इस चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अंदर और भी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनको भी शामिल करें जिससे उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।

साथ ही, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने काम किया है। सरकार ने काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी काम हुआ है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पानी का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, अनेकों काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे कई सारी सौगातें दी हैं। उनके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो 10 करोड़ रुपये पिछली बार सड़कों के लिए दिये थे, इस बार भी दिये हैं।

मैं एक मांग जरूर रखता हूं आप सबकी तरफ से, शायद आप भी सहमत होंगे कि जो हमारी सरकारी क्षेत्र की स्कूलें हैं, उनकी स्थिति खराब है। 10 करोड़ का प्रावधान उन स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भी रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो पायेगा। स्कूलों की हालत बड़ी खराब है।

(श्री आलोक बेनीवाल)

कहीं कमरे चू रहे हैं, कहीं कमरे कम हैं, कहीं चारदीवारी नहीं है। सरकारी स्कूलों की बहुत हालत खराब है। समसा के माध्यम से इतना पैसा नहीं आता है कि स्कूलों का हम पुनर्निर्माण कर सकें।

सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, वे अभाव में पढ़ते हैं। मैंने अपने विधायक कोष से काफी पैसा देकर स्कूलों को ठीक कराया है, लेकिन उनको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। खास तौर से हमारे बच्चों का मामला है। ये स्कूलें अगर अच्छी बनकर तैयार होंगी, मॉडल स्कूल के रूप में तैयार होंगी तो मैं समझता हूं कि स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जायेगा कि राजस्थान की सरकार ने इन स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भी अलग से बजट दिया क्योंकि बहुत समस्याएं सामने आती हैं। जब हम इलाके में स्कूलों में जाते हैं तो ज्यादातर एक ही मांग होती है कि कमरे दे दो, कहीं चारदीवारी का काम दे दो, कहीं कमरों के पुनर्निर्माण के लिए पैसे दे दो, संस्थाएं इतनी हैं कि हम हमारे बजट में से पूरा काम नहीं कर सकते। लेकिन दस करोड़ रुपये यदि मिलेंगे तो काफी संस्थाओं को हम सुधार सकेंगे और अच्छी बना सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पी एच ई डी और पी डब्ल्यू डी में जो टेंडर की प्रक्रियाएं चलती हैं, इनके निस्तारण का और काम की कोई समय सीमा तय करें, ताकि इनका काम जल्दी से शुरू हो और जल्दी से जल्दी खतम हो। कई चीजें बहुत लम्बे समय तक चलती चली जाती हैं और उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का काम करें, जिससे आम जनता को इससे राहत मिले। कोई योजना बनती है और छह महीने तक शुरू भी नहीं होती है, कई जगह ठेकेदार भाग जाते हैं, फिर वह सड़क पड़ी रह जाती है। इसका कोई ऐसा प्रोसीजर बनाएं कि समय सीमा में सड़क तैयार होकर आम जनता को समर्पित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात को रखूंगा। मेरे यहां बहुत समय से रोडवेज का डिपो चल रहा है, लेकिन उसको पूर्ण डिपो का दर्जा नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि उसको डिपो का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत भी है और उसको पूर्ण डिपो का दर्जा मिल भी सकता है। माननीय सभापति

(श्री आलोक बेनीवाल)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि उसको पूर्ण डिपो का दर्जा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा चौमूं साइड में लगता है और मैं मांग करूंगा कि खेजड़ोली जो एक बहुत बड़ी पंचायत है और आसपास में और भी पंचायतें लगती हैं, वहां पर एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए या महाविद्यालय खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां शाहपुरा में बहुत सालों से जो बालिका कालेज चल रहा है वहां काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। पिछली बार में रसायन विज्ञान में वहां पी जी खुली थी, इस बार मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर अंग्रेजी में पी जी खोलें तो हमारी बच्चियों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कुछ पी एच सीज हैं जिनको सी एच सी बनाया जाए। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखकर भी दिया है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बे समय से शाहपुरा जिले की मांग करता आया है। मैं सदन के माध्यम से, जनता की तरफ से, उनका प्रतिनिधि होने के नाते उस मांग को पुन: दोहराऊंगा कि शाहपुरा को भी जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट में करेंगे तो मैं उनका आभार प्रकट करता हुआ धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील (गमेती)।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट वर्ष 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

इस सरकार का यह पांचवां बजट है और बजट को लगभग 270 बिन्दुओं पर केन्द्रित किया है जिसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, युवा, बिजली हो, सबके लिए अलग-अलग घोषणाएं की गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बहुत बड़ेबड़े होर्डिंग भी लगे हैं, प्रचार भी बहुत व्यापक तौर पर किया गया है लेकिन मैं इस योजना की एक बानगी आपको पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां पर सोहन लाल गरासिया, निवासी सांदरिया, पोस्ट बालवा का धोरा, तहसील

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

कोटड़ा घर पर कोई काम करते हुए फिसल गया था और फिसलने से उसके हाथ-पैर और सिर में चोट आई। हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया और परिवार वालों ने उसको हास्पिटल पहुंचाया। हास्पिटल में पहुंचाने के बाद में उसका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद में जब वो कम्प्लीट हो गया, हास्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए, प्राइवेट हास्पिटल था, मेवाड़ हास्पिटल, जो चिरंजीवी योजना में सम्मिलित है और उस हास्पिटल में उस सोहन लाल को तीन लाख रुपये का बिल थमाया। सोहन लाल के पास में पैसा नहीं होने से जमा नहीं करा पाया तो चार दिन तक उसको और हास्पिटल में रखा। उसने उधार लेकर हास्पिटल में पैसा जमा कराया। चिरंजीवी की पूरी फाइल उसके पास में है, बिल भी है। आप बार-बार इसको बता रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपने विद्यालय बहुत खोले, उच्च शिक्षा में भी आपने सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले, लेकिन स्थिति यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर विद्यालय में सैकण्ड ग्रेड का एक भी अध्यापक नहीं है। वहां के जो बालक-बालिकाएं हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिए पर उनके पुराने भवन बने हुए हैं। उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता नहीं है। कक्षा आठ में पढ़ने वाले बालक आज अपना नाम भी अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहे हैं, यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार आपके जो अध्यापक अच्छी पहुंच रखने वाले हैं वो दूर के विद्यालयों से डेपुटेशन करवाकर अन्य विद्यालयों में शिफ्ट हैं। हमारा क्षेत्र टी एस पी क्षेत्र है और नॉन टी एस पी के बहुत से अध्यापक हमारे वहां पर कार्यरत हैं और वे चाहते हैं कि हमको नॉन टी एस पी एरिया में हमारे गांव की तरफ भेज दिया जाए। वहां पर यदि स्थान खाली होगा तो वहां पर टी एस पी क्षेत्र के डिग्रीधारी हैं वो उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहां पर राजकीय कालेज भाजपा सरकार में खुला था और उसमें आज की तारीख में लगभग 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस कालेज में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोल दिया जाए तो हमारे बालक-बालिकाओं को सुविधा होगी। इसी प्रकार से हमारे पास में पर्याप्त जमीन भी है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

खेल होना आवश्यक है तो खेल मैदान के लिए भी मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहां पर खेल मैदान के लिए कुछ राशि आबंटित करे। इस कालेज में बाउण्ड्री क्षतिग्रस्त है तो उसको भी दुबारा बनवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी एच सी भी है और कुछ भवन रहित पी एच सी भी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे कठार में पी एच सी है उस पर भवन निर्माण की राशि स्वीकृत की जाए। हमारे पंचायत समिति मुख्यालय सायरा पर जो पी एच सी है उसको सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सी एच सी हो या पी एच सी, वहां पर एक्सरे, ई सी जी और अन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाये।

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में आपने गत बजट में किसान कल्याण कोष में कुछ राशि की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उस घोषणा को जमीन तक नहीं पहुंचाया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दे। उसके अलावा कर्जमाफी के लिए आपने चुनाव में घोषणा की थी और अंगुलियों पर 1 से 10 तक गिनती करके बताया था कि सरकार बनने के 10 दिन के बाद में हम पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ नहीं किया गया है।

उसके अलावा, हमारे यहां इस वर्ष भयंकर बारिश हुई थी, जिसके कारण सारी फसल नष्ट हो गयी। उसके लिए किसी प्रकार की कोई जिन्सवारी वगैरह नहीं की है। सरकार से मेरी मांग है कि इसके लिए अधिकारियों को भेजे और जिन्सवारी करके मुआवजा दिलाये। इस बार डी ए पी और यूरिया के लिए जो लाइन लगायी गयी थी, वह सरकार की विफलता बताती है।

हमारे यहां कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाये। इसके अलावा, टी एस पी क्षेत्र में कृषि कनेक्शंस जल्दी नहीं दिये जा रहे हैं। नियम यह है कि आवेदन हेतु फाइल जमा कराने के 90 दिन के अन्दर कनेक्शन दिया जाना होता है, लेकिन अधिकारियों से पूछने पर बताया जाता है कि सरकार के द्वारा हमें ट्रांसफार्मर्स की राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। सरकार से मेरी मांग है कि इस ओर भी ध्यान दे।

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

उसके अलावा जो जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, वे समय पर हमारे यहां बदले नहीं जाते हैं और कहा जाता है कि आप कोई साधन लेकर आएं और ले जाएं। इस प्रकार से सरकार इसकी व्यवस्था करे। उसके अलावा एक आपने गत बजट में घोषणा की थी कि टी एस पी क्षेत्र में हम सोलर से कृषि कनेक्शंस देंगे। मैंने विधान सभा में क्वेश्चन भी लगाया, जिसका उत्तर भी आया। मैंने पूछा कि पूरे उदयपुर सम्भाग में आपने कितने सोलर से कनेक्शंस दिये? उत्तर आया कि हमारे जनजाति मंत्री जो हैं, उनके विधान सभा क्षेत्र में भी किसी के कोई कनेक्शंस नहीं हुए सौर ऊर्जा के।

इसी प्रकार थ्री फेज हमारी जो कृषि की बिजली दी जाती है, वह रात को दी जाती है। रात को नहीं देकर दिन में दी जाये। इसके अलावा, पावर हाउस में जो ठेकेदार द्वारा अप्रशिक्षित लोगों को लगाया हुआ है, उन्हें टाइम पर उनका भुगतान भी नहीं दिया जाता है। आम जनता को समय पर लाइट भी नहीं पहुंचायी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा, एक जल जीवन मिशन है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 85 योजनाएं स्वीकृत होने के बाद में टेंडर खुल गये हैं पर टेंडर खुलने के बाद में अभी तक वर्क आर्डर नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि उनका वर्क आर्डर जल्दी से जल्दी दिया जाये।

उसके अलावा, आपने देखा होगा, अभी कई तहसीलें और उप-तहसीलें खोली गयी थीं। मेरे यहां एक उप-तहसील सायरा है और आजादी के समय से वह तहसील थी। पिछली बार वसुन्धरा जी की सरकार में उसे उप-तहसील घोषित किया गया था। वहां भवन निर्माण भी किया गया। तहसील बनने के मापदण्ड पूर्ण हो रहे थे, लेकिन अभी तक उसे तहसील में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि उसे तहसील बनाया जाये।

उसके अलावा, पंचायती राज पुनर्गठन में हमारे देवला क्षेत्र में एक पंचायत समिति के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। उस प्रस्ताव में पंचायत समिति के पुनर्गठन के मापदण्ड पूर्ण हो रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से वह पंचायत समिति नहीं बनी। उस पंचायत समिति को भी बनाया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमित चाचाण।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): एक एकलव्य मॉडल जनजाति आवासीय विद्यालय गोगुन्दा में है, उसमें खेल मैदान की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाकर साढ़े 6 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाकर साढ़े 6 बजे तक कर दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े 6 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक घण्टा बढ़ाया जाये। कई बोलने वाले माननीय सदस्य हैं। मौका कब मिलता है? आसन के पास शक्ति है। आप एक घण्टा बढ़ा दीजिये। आसन सर्वोपरि है। आप बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति: आपके तीन माननीय सदस्यों को बुलवा देंगे।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। चाहे वह राज्य हो या केन्द्र, जब उस प्रदेश अथवा देश का मुखिया बजट सत्र में आकर बजट पढ़ता है तो पूरे देश, पूरे प्रदेश और हर वर्ग के व्यक्ति की उस बजट पर निगाहें होती हैं कि राज्य और देश में आमजन, किसान, मजदूर को क्या मिलने वाला है। जब मुख्य मंत्री जी ने इस राज्य का और इस सरकार का अन्तिम बजट पढ़ा तो पूरे राजस्थान में, चाहे वह किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, सब में एक खुशी का माहौल था कि मुख्य मंत्री जी ने सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए एक शानदार बजट राजस्थान को दिया।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ केन्द्र का हमारा बजट आया। उसमें भी सभी वर्ग चाहते थे कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन पूरे भारत में सभी को निराशा मिली कि केन्द्र में दिया गया बजट, जिसे अमृतकाल कहते हैं, वह अमृतकाल नहीं, बल्कि मित्रकाल बनकर रह गया। चुनिन्दा व्यक्तियों को फायदा देने के लिए केन्द्र में बजट आया।

आज हमारे लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्य मंत्री राजस्थान के गांधी अशोक जी गहलोत ने 19 हजार करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज दिया। यह पैकेज क्यों देना पड़ा, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि केन्द्र में बैठी तानाशाह सरकार, केन्द्र में बैठी मोदी सरकार, जिस तरह से पिछले 9 साल की उसकी रीति-नीति के कारण पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, जो बेरोजगारी बढ़ी, जिससे पूरा हाहाकार मचा, जिससे पूरा देश चिन्तित हुआ, उसके तहत यह पहला राज्य बना, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने आम गरीब, किसान, मजदूर को राहत देने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया।

चाहे हम उसमें अन्नपूर्णा पैकेट की बात करें। उस दर्द को मुख्य मंत्री जी ने समझा कि आज गरीब, किसान मजदूर के उस घर में जहां दो वक्त का आटा नहीं, आज यह अन्नपूर्णा पैकेट उनके लिए एक वरदान साबित होगा, जिसमें मुख्य मंत्री जी के द्वारा एक-एक किलो नमक, दाल, मसाले, तेल दिए जाएंगे। मुख्य मंत्री जी उनके दर्द को समझ सकते हैं।

चाहे हम बात करें सिलेंडर की, मोदी सरकार ने पूरे देश में कहा कि हम उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद सिलेंडर का क्या हुआ? आज वह सिलेंडर 1100 रुपये का है। एक आम गरीब परिवार उसे नहीं ले सकता था। मुख्य मंत्री जी ने उन गरीब महिलाओं की भावनाओं को समझा। उनके दर्द को दूर करने के लिए बी पी एल उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देने की मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है।

हम बात करें बिजली की। माननीय सभापति महोदय, उस परिवार के बारे में सोचिये, जो एकदम गरीब है, जिसका अधिक बिल आ जाये, वह बिल भर नहीं सकता। बिजली विभाग के अधिकारी उसके कनेक्शन को काटने चले जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके आंसू पोंछने

(श्री अमित चाचाण)

के लिए पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया था, इस बार उसे बढ़ाते हुए 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क करने का काम किया, जिसके तहत पूरे राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का बिल शून्य होगा और 15 लाख वंचित उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार अनुदान दिया जायेगा, जो सबके बिलों में आ रहा है।

इसके अलावा, हम बात करें, पूरे देश में जो एक क्रान्तिकारी पहल मुख्य मंत्री जी ने की है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। इसमें पूर्व में 10 लाख रुपये तक कवर किया जाता था और 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर किया जाता था। भगवान न करे किसी की दुर्घटना हो, लेकिन आज हम देखते हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु हो रही है, नहरों में डूबने से मृत्यु हो रही है, हम उस जीव को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसे 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये का जो सराहनीय काम किया, दुर्घटना बीमा कवर किया। उसके तहत हर परिवार को हम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। आज हम देखते हैं, चाहे किसी का भी घर हो, भगवान न करे बीमारी आये, लेकिन जब गरीब परिवार में बीमारी आती है तो हाहाकार मच जाता है। उसका घर, जायदाद सब बिक जाता है। मुख्य मंत्री जी ने उनकी संवदेना को समझते हुए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये का जो काम स्वास्थ्य बीमा का किया है, यह पूरे देश के अन्दर एक नजीर साबित हुआ है।

(समय: 18.00 बजे)

हम पुरानी पेंशन योजना की बात करें। पूरे देश में 2004 के बाद कर्मचारी चाहते थे कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। जिस तरह से हम सबने कुछ दिन पूर्व ही देखा कि किस तरह से अडानी परिवार में, जो हमारा रिलायंस का पैसा, चाहे एस बी आई का पैसा लगाया गया, किस तरह से उनका शेयर गिरा। आज कर्मचारी चिन्तित थे कि हमारा भविष्य कैसा होगा तो मुख्य मंत्री जी ने ओ पी एस लागू करने का काम किया। इस बजट में जो बोर्ड व निगमों के वंचित कर्मचारी थे, उनको भी इसके दायरे में लाने का काम किया। यह मुख्य मंत्री जी की क्रान्तिकारी पहल थी और पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा उदाहरण बना।

कृषकों की बात करें तो पूर्व में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना चलाई गई, जिसके तहत हजार रुपये महीने किसानों के खातों में आ रहे थे, लेकिन

(श्री अमित चाचाण)

इस बार मुख्य मंत्री जी ने दो हजार यूनिट तक उन किसानों के बिलों को माफ करने का काम किया। यह मुख्य मंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है।

सामाजिक सुरक्षा, आज प्रत्येक आदमी भयभीत रहता है। पूरे देश का यह पहला राज्य है, जिसमें एक करोड़ लोगों को चाहे वह वृद्धजन हो, चाहे विधवा हो, चाहे एकल नारी हो, चाहे विशेष योग्यजन हो, एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। इस बार मुख्य मंत्री जी ने 500, 750, जो न्यूनतम पेंशन थी, उसको बढ़ाते हुए एक हजार रुपये की है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी सदैव गरीब आदमी के लिए चिन्तित रहते हैं। उन्होंने गरीब, मजदूर, किसान के आंसू पोंछने का काम किया है। दूसरी तरफ केन्द्र में बैठी सरकार जो घड़ियाली आंसू तो बहाती है, लेकिन उनके मुंह से गरीब, किसान, मजदूर कभी नहीं सुना जाता है। वे सब पूंजीपतियों के घरानों का घर भरने का काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के बजट से इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कृषि बजट को 5 परसेंट कम करने का काम किया है। फसल बीमा बजट को 12 परसेंट कम करने का काम किया। किसान सम्मान निधि को 13 परसेंट कम करने का काम किया है। मनरेगा बजट, कोरोना काल में हम सबने देखा, किस तरह से मनरेगा ने पूरे भारतवर्ष में एक नया जीवनदान दिया था। उसके बजट को 33 परसेंट कम करने का काम इस केन्द्र सरकार ने किया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 31 परसेंट कम करने का काम किया। कैमिकल फर्टिलाइजर को 21 परसेंट कम करने का काम किया। ग्रामीण विकास को 12 परसेंट कम करने का काम किया। केन्द्र सरकार का यह बजट आम लोगों व किसानों के लिए नहीं बल्कि हम दो, हमारे दो चुनिन्दा पूंजीपतियों के लिए रहा है।

मुख्य मंत्री जी ने युवाओं की भावनाओं को देखते हुए मात्र एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तमाम परीक्षाओं में उनको नि:शुल्क करने का काम किया। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने 2014 में दो करोड़ युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर सत्ता तो हथियाई, लेकिन उसके बाद न तो युवाओं को रोजगार दिया, न युवाओं को सम्भाला गया। ये तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने 1 लाख 80 हजार कर्मचारियों को नौकरी दी और 1 लाख 25 हजार प्रक्रियाधीन हैं। वे भी आने वाले समय में दी जायेंगी। मुख्य मंत्री जी के द्वारा तीस हजार सफाईकर्मियों की भर्ती भी निकाली गई। महिलाओं

(श्री अमित चाचाण)

को रोडवेज में 50 परसेंट की छूट दी गई। मनरेगा की तरह इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लाई गई, जिसके तहत 125 दिन तक प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पूर्व में पांच साल भाजपा सरकार रही और केन्द्र में भी इन्हीं की सरकार थी। आज ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इन चार वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया तो मैं अब इनको आईना दिखाना चाहता हूं। आपने पांच वर्ष क्या किया और हमारी सरकार ने इन चार वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आई, केन्द्र सरकार का सौतेला व्यवहार रहा, सरकार पर आर्थिक संकट भी गहरया, उसके बावजूद भी 4 साल पिछले 5 साल पर भारी पड़ रहे हैं। चाहे हम नये कालेज की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 81 कालेज खोले, हमारी सरकार ने चार साल में 210 खोले। एग्रीकल्चर कालेज एक खोला गया, हमारी सरकार में 42 खोले गये। पिछली सरकार में सब-सेंटर से पी एच सी 7 को बनाया गया। हमारी सरकार ने चार साल में 363 को बनाया। पूर्व की सरकार ने पी एच सी से सी एच सी 23 बनाये तो हमारी सरकार ने 206 बनाये। पूर्व की सरकार में 02 नर्सिंग कालेज बने तो हमारी सरकार 25 बनाने जा रही है।

हम सड़क निर्माण पर व्यय की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 19 हजार 472 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि हमारी सरकार ने मात्र चार साल में 25 हजार 285 करोड़ रुपये खर्च किये। हम कृषि बिजली कनेक्शन की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 1 लाख 77 हजार 226 को कनेक्शन दिये जबकि हमारी सरकार ने चार साल में 3 लाख 27 हजार 459 को कनेक्शन दिये हैं।

हम फसल बीमा की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 5 हजार 822 करोड़ रुपये दिये जबकि हमारी सरकार ने 18 हजार 177 करोड़ रुपये दिये। कृषि बिजली अनुदान की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 31 हजार 940 करोड़ रुपये दिये और हमारी सरकार ने 60 हजार 754 करोड़ रुपये दिये। ग्रामीण विकास पर खर्च की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 21 हजार 586 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि हमारी सरकार ने चार वर्ष में 56 हजार 257 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यदि हम मनरेगा की बात करें तो पूर्व की सरकार ने 16 हजार 792 करोड़ रुपये खर्च किये और हमारी सरकार ने 36 हजार 601 करोड़ रुपये 25 दिन अतिरिक्त के खर्च किये।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा, हम पेंशन की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान उदाहरण बना है। पूर्व की सरकार ने 5 हजार 345 करोड़ रुपये खर्च किये तो हमारी सरकार ने 20 हजार 722 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग की बात करें तो पूर्व की सरकार में जीरो किलोमीटर रीलाइनिंग हुई जबकि हमारी सरकार ने 84 किलोमीटर की रीलाइनिंग की है। पूर्व की सरकार ने 17 नई तहसीलें बनाईं, हमारी सरकार ने 61 तहसीलें बनाई हैं। यह आईना दिखाता है कि पूर्व की सरकार ने पांच साल क्या काम किया है और इस सरकार ने चार साल में क्या काम किया।

विपक्ष का काम होता है, बजट को खराब बताना और सत्ता पक्ष का कहना होता है कि बजट बहुत शानदार दिया है, लेकिन इसका फैसला राजस्थान की जनता को करना है जो पिछले उप-चुनाव में किया। भाजपा के शासनकाल में जो भी उप-चुनाव हुए भाजपा हारी, लेकिन इन चार वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के शासनकाल में 9 उप-चुनाव हुए जिनमें से 7 कांग्रेस ने जीते हैं। इससे पता चलता है कि जो पिछले चार बजट दिये, जनता ने उनकी प्रशंसा की है, विपक्ष तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान से 24 सांसद भाजपा के केन्द्र सरकार में गये थे और वहां सदन में जब हम उनकी बात सुनते हैं तो उन्होंने सिर्फ इस राजस्थान की सरकार को कोसने का काम किया है। राजस्थान को कोसने का काम किया है। वे 24 सांसद एक बार भी यह नहीं बोले कि जिस जनता ने हमें क्षेत्र के विकास लिए भेजा था, उस क्षेत्र के विकास की हम बात करें। उस क्षेत्र में विकास की हम योजनाएं लेकर आएं, उस क्षेत्र के विकास की घोषणा करें।

एक तरफ तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने विधायक कोटे का पैसा सवा दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये करने का काम किया, वहीं जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से हाहाकार मचा हुआ था तब हमारे देश के मोदी ने उन सांसदों का पैसा फ्रीज करने का काम किया, जिससे कि क्षेत्र में पैसा नहीं बांटा जाए। मेरे चूरू लोक सभा क्षेत्र की बात करें, मोदीजी जब चूरू लोक सभा चुनाव में आये थे तब उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि चूरू से सिरसा नेशनल हाईवे बनायेंगे, वाया नोहर जायेंगे। हमारे नेताओं ने वाहवाही लूटी कि नोहर का नाम मोदीजी ने पढ़ा है, लेकिन शायद सांसद महोदय ने उनको मना किया होगा, क्योंकि उनकी सोच रही है कि वोट विकास से नहीं मिलते हैं, वोट तो जाति

(श्री अमित चाचाण)

और धर्म से मिलते हैं, वोट तो भाई को भाई से लड़ाने पर मिलते हैं। आज वह नेशनल हाईवे नहीं है। दूसरी तरफ, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा की थी कि चूरू से नोहर मेगा हाईवे बनेगा। उसका काम भी 229 करोड़ रुपये से शुरू हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, चार वर्ष का कार्यकाल पिछले 20 वर्ष पर भारी पड़ रहा है। नोहर को 40 वर्षों में एक राजकीय महाविद्यालय मिला था। इन चार वर्षों में नोहर क्षेत्र की जनता को चार राजकीय महाविद्यालय मिले। चाहे पी एच सी की बात करें...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरी कुछ मांगें बताना चाहता हूं। दो हजार नर्सिंग भर्ती, हमारी 36 हजार बहनें उसका इन्तजार कर रही हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उस भर्ती को पूरा किया जाए। प्रयोगशाला सहायकों की कुछ सूची बाकी है, उसको पूर्ण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, नोहर फीडर में हरियाणा से हमें पानी पूरा नहीं मिलता है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि रीमॉडलिंग के तहत 45 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत किये जाएं, जिनमें 60 परसेंट केन्द्र सरकार देगी और 40 परसेंट की राशि राजस्थान के हिस्से से आयेगी। हमारे खाले 15 वर्ष पूर्व बन चुके हैं, जो जर्जर हो चुके हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि खालों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया जाए। हमारे नोहर क्षेत्र की एक बड़ी मांग है कि रोडवेज बस डिपो का वहां शुभारम्भ किया जाए, जिसके लिए नगरपालिका जमीन देगी और दानदाताओं के द्वारा भवन का निर्माण करवाया जायेगा। खुईया में मुख्य मंत्री जी ने कृषि कनेक्शन तो काफी किये हैं। उन कृषि कनेक्शनों को चलाने के लिए 132 के वी जी एस एस का निर्माण करवाया जाए। 33 के वी जी एस एस घणियासर, उदासर, निमला, थीराना, मलवानी में स्वीकृत किया जाए।

नोहर के उप जिला चिकित्सालय की मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृति दी है। उसमें ब्लड बैंक की सौगात दी जाए। मेघाना में उप तहसील बनाई जाए। मेघाना व बिरकाली में पुलिस चौकी बनाई जाए। नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज की घोषणा की जाए।

एक मात्र घोषणा जो नोहर की बची है, नोहर-भादरा के 28 गांवों को

(श्री अमित चाचाण)

सिंचित करने का काम किया था और 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं मांग करता हूं कि उसका कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। खुईया, धानसिया, मन्दरपुरा, टोपरिया को सी एच सी बनाया जाए। नई पी एच सी मालासर, मोटेर, थालडका, दलपतपुरा, जबरासर में बनाई जाए। हमारे नोहर की सबसे बड़ी मांग है कि नोहर को भी जिला बनाने की घोषणा की जाए।

मैं मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि-

क्या मारेगी मौत उसे, जो औरों के लिए जीता है।

सारे जहां का प्यार मिलता है उसे, जो औरों के आंसू पीता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान सरकार के बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्रीडूंगरगढ़ में सदियों से जो ड्रेनेज सिस्टम था गन्दे पानी की निकासी के लिए, बहुत सारे एम एल ए रहे, बहुत सारी सरकारें रही पर पहला मौका था जब श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र को सौगात मिली पचास करोड़ की। आज लगातार आजादी के बाद श्रीडूंगरगढ़ की जनता महसूस करती है कि निश्चित तौर पर जो घोषणा की गयी है मुख्य मंत्री जी द्वारा, वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है।

सभापति महोदय, लगातार जनता की मांग घूमचक्कर चौराहे पर बस स्टैंड की थी, वह भी पूरी की। मोमासर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी बात की। कई ऐसी घोषणाएं लगातार हुईं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए मेरी मांग पर ही आऊंगा। साथ ही, सदन के माध्यम से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की अन्य मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीदासर रोड पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण पच्चीस रोज से धरने व क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस मांग को भी सरकार शीघ्र ही पूरा करे एवं डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर रेलवे अण्डरब्रिज निर्माण की मांग लम्बे समय से वहां की जनता करती आ रही है।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, सुजानगढ़-डूंगरगढ़ और लूणकरणसर को जोड़ने वाली सड़क लूणकरणसर एस एच 6ए से कानुता मार्ग वाया सहजरासर, सेरुणा सूडसर, सावंतसर, लिखमीसर, राजेड़ू, बापेऊ, सोनियासर, इयारा कैम्प रोड तक घोषित एम डी आर रोड के लिए बजट वर्ष 2023-24 में राशि स्वीकृत की जाये।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ व उसके आस-पास के क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों से मानव जीवन को बचाने के लिए वहां ट्रोमा सेन्टर और सी एच सी को उप जिला चिकित्सालय बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। साथ ही, ग्राम दुलचासर की पी एच सी को सी एच सी में बदलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है।

सभापति महोदय, उसी प्रकार सोनियासर, बापेऊ, बरजांगसर और बाना गांव में पी एच सी खोलने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। सभापति महोदय, जहां अभी उप स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें। रेवाड़ा, केऊ अभी-अभी नया राजस्व ग्राम बना है, जाखासर, मेहरामसर मेरे क्षेत्र में पड़ता है। गजपुरा और राणासर नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

सभापति महोदय, विद्युत के मामले में, बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा कुएं हैं सबसे ज्यादा वहां मूंगफली और अन्य पैदावार होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को कि इस बजट 2023-24 में वी सी आर प्रकरण में जो छूट दी गई है वह किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि यह छूट लगातार जो दी गई है वह दस परसेंटबीस परसेंट और थोड़ा उसमें सुधार किया जाये तो और ठीक रहेगा। कृषकों की अधिकता को देखते हुए बहुत सारे कृषि कुएं हैं श्रीडूंगरगढ़ में और बीकानेर जिले में जिससे लगातार मांग की जा रही है।

सभापति महोदय, सेरुणा गांव में 220 के वी का जी एस एस स्वीकृत करवाया जाये। उसी प्रकार वर्तमान में जाखासर और राजपुरा पुनरासर में 132 के वी स्वीकृत है उसको चार साल हो गये हैं, वह निर्माणाधीन है, उस निर्माणाधीन का त्वरित रूप से कार्य कराया जाये। उसी प्रकार जालबसर, दुसारणा बड़ा द्वितीय, आडसर द्वितीय, लिखमीसर दिखणादा द्वितीय, ठुकरियासर तृतीय, डेलवां प्रथम, कालरा जोहड़ा धर्मास, कुकणिया द्वितीय में 33 के वी का जी एस एस स्वीकृत किया जाये।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में श्रीडूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र चूरू जिले के कृषि कुओं पर जल हौद बीकानेर के अन्दर नहरी तर्ज पर उसी प्रकार चूरू और बीकानेर क्षेत्र में जहां ट्यूबवैल क्षेत्र है वहां...

श्री सभापति: आपका लिखा हुआ है क्या सारा? लिख कर लाये हैं क्या आप सारा?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): हां, लिखा हुआ है।

श्री सभापति: तो आप टेबल कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): हां, एक मिनट साहब, उसी प्रकार जो तीन-तीन लाख सब्सिडी दी जा रही है नहरी क्षेत्र में, उसी प्रकार बीकानेर और चूरू में जो ट्यूबवैल क्षेत्र पड़ते हैं उनमें भी तीन लाख की सब्सिडी दी जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है। उसी प्रकार सिंगल फेज लाइट जहां लम्बे समय से मांग की जा रही है, उसको नीति के तहत एग्रीकल्चर से जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, हमारे पश्चिमी राजस्थान में मोठ और ग्वार पैदा होता है। सबसे ज्यादा बारानी क्षेत्र में गरीब किसान पैदा करता है उसको समर्थन मूल्य में घोषित कराने की मांग केन्द्र सरकार से की जाये। आज तक केन्द्र सरकार ने या कहीं राज्य सरकार ने यह सिफारिश नहीं की।

सभापति महोदय, इसी प्रकार सूडसर में गौण मण्डी है, वहां कृषि मण्डी घोषित की जाये। इसी प्रकार पशुधन वाले बीकानेर जिले में बहुसंख्यक पशु हैं और वहां लम्पी के तहत बहुत सारे पशु मरे हैं। दूध पर निर्भर हैं वहां सारे। आज तक उनका कोई भी सर्वे वगैरह नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है जो दुधारू पशु हैं उनका सर्वे करवाकर लम्पी में जो मरे हैं उस गौवंश के पशुधन का किसान को मुआवजा दिया जाये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार नायकों के मोहल्ले में तोलियासर में पूर्व में बन्द पड़े सरकारी स्कूल खोले जायें। उसी सन्दर्भ में मैं, सभापति महोदय, एक मिनट और लेना चाहूंगा। सूडसर, पुनरासर, सावंतसर, ये सारे मैं बाद में लिख कर दे दूंगा। इसी प्रकार श्रीडूंगरगढ़ मुख्यालय में मुख्य सीनियर स्कूल है वहां खेल मैदान बनाया जाये।

सभापति महोदय, एक मुख्य मांग बीकानेर जिले की है और लम्बे समय से वकील हड़ताल करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं हाईकोर्ट की। मैं मांग करता हूं सरकार से कि बीकानेर सम्भाग स्तर का मुख्यालय है, लोग लगातार बी जे पी के राज से मांग करते आ रहे हैं, अपने राज में

(श्री गिरधारीलाल)

मांग करते आ रहे हैं तो लम्बा क्षेत्र देखते हुए वहां हाईकोर्ट का न्यायालय खोला जाये।

सभापति महोदय, अभी हमारे क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर का लेवल कम है तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 70 ट्यूबवैल्स की मंजूरी दी जाये। यही कहते हुए मैं..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): थोड़ी सी सड़कों की मांग कर लेता हूं। ग्राम बिग्गा से लोक देवता बिग्गा जी महाराज मन्दिर से ग्राम तोलियासर भैरूंजी मन्दिर तक सड़क बनवायी जाये। साघासर से गीवसर सड़क बनायी जाये। सूडसर से आथूणी, सांवतसर से होते हुए नवीनीकरण किया जाये। सभापति महोदय, अगर कुछ बचा है तो मैं टेबल कर दूंगा। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: सारा बोल दिया आपने, अब टेबल क्या कर दोगे? श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: जगसी राम जी, आपका सारा लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है तब तो आप टेबल कर दीजिये।

श्री जगसी राम (रेवदर): नहीं-नहीं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 10 फरवरी, 2023 को बजट की घोषणा की है वह एक प्रकार से चुनावी घोषणा है और थोथी घोषणाएं नजर आ रही हैं। सभापति महोदय, पिछले चार सालों के अन्दर विभिन्न घोषणाओं की क्रियान्विति आज दिनांक तक नहीं नजर आ पायी है। दो-तिहाई से तीन-चौथाई तक आज तक सारी कागजी घोषणाएं ही नजर आ रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार साल की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं की कई बार सरकार तक, मंत्री महोदय तक जानकारी देने के उपरान्त भी और क्षेत्र में कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद में उन धरनों को उठाया है, लेकिन वे काम अभी तक चालू नहीं हुए हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बजट घोषणा के अन्दर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी घोषणा नहीं की थी और जो की है वह अभी पूरी नहीं हो पा रही है।

(श्री जगसी राम)

मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्दर जो कृषि मण्डी की घोषणा की है सरकार ने, वहां पर अभी तक न तो जमीन के लिए कोई सर्वे हुआ है और न बजट का प्रावधान है। नम्बर-दो, आबूरोड और रेवदर के बीच में गोमती और झामुआ नदी पर पुल के निर्माण के लिए पिछले बजट के अन्दर, यह इनका अन्तिम बजट है, उसमें भी सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सर्वे तक नहीं हुआ है।

इसी तरह से सांचोर, रानीवाड़ा और मंडार सड़क का कार्य, सभापति महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री जी सामने विराजमान हैं, उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया था, सांचोर, रानीवाड़ा और मंडार वाली सड़क है, इसके तीन बार टेंडर निरस्त हुए। टेंडर निरस्त होने के बाद उसको ब्लैकलिस्ट किया है। जालोर वाली सीमा में काम पूरा हो गया है और रेवदर वाला काम अभी भी अधूरा पड़ा है। यह आपकी सरकार की घोषणा में था। अनादरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया था। वहां न तो एक भी नया डाक्टर लगा, न उसमें कोई बिल्डिंग का प्रावधान किया और न वहां कोई स्टाफ की सुविधा है। वह घोषणा सिर्फ कागजों में ही है। जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले गये हैं, वहां न कमरों की व्यवस्था है, न व्याख्याताओं की व्यवस्था है। वहां पर पूर्ण रूप से स्टाफ खाली है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों को परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, सरकार ने कहा था कि पंचायत समिति लेवल पर उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे। सभापति महोदय, मैं यह घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं। वहां पर न तो इसके लिए जमीन आबंटित हुई और न ही वहां पर अभी तक इसकी बिल्डिंग चालू हुई है। पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की जो सरकार ने घोषणा की थी। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान चयनित किया था, उसमें विधायक कोष से भी 25 लाख रुपये दिये हैं, उसके उपरांत भी वहां एक ईंट भी आज तक नहीं रखी गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहूंगा, नंदीशाला की सब बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान का किसान देख रहा है, जनता देख रही है कि नंदियों की आज दुर्दशा हो रही है। मैं समझता हूं कि पंचायत स्तर पर पैसे की व्यवस्था ही नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भामाशाहों को जिन्होंने वहां पर उनके चारे की व्यवस्था की है। प्रदेश के युवा, माता-बहनों, गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के बुजुर्ग, पेंशनधारी,

(श्री जगसी राम)

बीमार, किसान, विद्यार्थियों, सभी वर्गों को खुश करने के लिए आपने प्रयास किया है, इसमें सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नजर आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस बजट में सिरोही जिले में अंजीर के लिए सेंटर फार एक्सीलेंस खोलने की घोषणा के बजाय गुजरात राज्य से सटे मेरे कृषि प्रधान रेवदर विधान सभा क्षेत्र की प्रतिवर्ष टमाटर, सब्जियां, अरण्डी, रायड़ा, मूंगफली की बंपर पैदावार, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने की घोषणा करते तो किसान वर्ग और प्रदेश को आर्थिक सम्बल मिलता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि किसानों की ऋण माफी के जो इन्होंने बड़ेबड़े वादे किये थे, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां रोडा एक्ट के माध्यम से किसानों की जमीन बेची जा रही है और वे काफी परेशान हो रहे हैं। सरकार को उस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, माउंट आबू का पानी गुजरात में बह कर जा रहा है। आबू रोड बनास नदी पर सरकार बजट में कोई प्रावधान ले आती, पिछली सरकार में एम आई टैंक के माध्यम से पानी को बचाने का काम कर रहे थे। इस सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं और पांचवें साल के 7-8 महीने रहे हैं, इसमें भी इन्होंने पानी को रोकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के लिए कोई व्यवस्था की जाये तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भीलमगरा एनिकट है, जिससे कम से कम 20-25 गांवों को फायदा हो रहा था। इसके लिए विधान सभा में कई बार बात रखने के उपरान्त भी आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीथापुरा और सुलेवा एनिकट, सभापति महोदय, डी एम एफ टी फंड के बारे में आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, हमारे प्रभारी मंत्री जी यहां विराजमान हैं, हमने आपको बैठक में भी बताया था, भाजपा के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए, उन कामों को सड़कों के नाम से डी एम एफ टी का पैसा रेवदर विधान सभा क्षेत्र, जहां से सबसे ज्यादा खनिज का पैसा आता है, उसके उपरांत भी उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों को यूरिया और डी ए पी की किल्लत की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा था कि हमने इतना यूरिया, डी ए पी खरीदा। मैं हमारे सामने वाले सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सब जब क्षेत्र में जायेंगे, तब आपको वहां के किसान बतायेंगे कि आपने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है, क्या नहीं की है। यह चिंतनीय विषय है।

सभापति महोदय, हमारे रेवदर और आबू रोड के विद्यालयों में सारे रिक्त पद पड़े हैं, उनको भी भरने की आवश्यकता है। बिजली में आपने कहा कि बिजली सस्ती की है। सभापति महोदय, बिजली सस्ती तो की है लेकिन वहां पर ट्रांसफार्मर जलने के बाद उनको बदलने में 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं। अभी बारिश में तो हमारे यहां 15-15 दिनों में ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं। बिजली जाने पर ए ईएन, एक्स ईएन या एस ई साहब को फोन करते हैं तो वे यही कहते हैं कि आगे से लोड शेडिंग है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: सदन का समय 6.40 मिनट तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगसी राम (रेवदर): लोड शेडिंग का बहाना बनाकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): दो मिनट में मैं मेरी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात कही है, अभी राजस्थान में बजरी का काफी मामला चल रहा है। हम सब देख रहे थे कि बजट में बजरी में क्षेत्र की जनता को कोई न कोई राहत मिले, लेकिन बजरी माफियाओं से राहत देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। बजरी में जनता को लूटा जा रहा है तो वह अपना काम कैसे कर पायेगा? रेवदर-मंडार बाईपास के सरकार ने कई बार बड़े-बड़े वादे तो किये, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ। मंडास्रेवदर की घनी आबादी को देखते हुए वहां बाईपास की आवश्यकता है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, मंडार उप तहसील है, उसको तहसील में क्रमोन्नत करने की मैं सरकार से मांग करता हूं। रेवदर, आबू रोड, पूरा ब्लाक टी एस पी क्षेत्र है। वहां पर इस बजट में सरकार ने आदिवासी, वनवासी भाइयों के लिए किसी प्रकार की कोई नई योजना लागू नहीं की है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं आज इस मौके पर सरकार से कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। ऐसे नहीं।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: फिर आपके बाद के माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे। विराजिए आप। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने 2023-24 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। 2019-20 से लगातार बजट में घोषणाएं की जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर-जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी से एक ही विधायक होने के बाद भी सिवाना की उपेक्षा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, मैं इस बजट में कहूंगा कि पूरे जिले में हर विधान सभा में एक रोड की घोषणा की है पर सिवाना को हमेशा नजरंदाज किया गया है। मैं एक-एक बिन्दु गिनकर कहूं तो इन्होंने बजट में घोषणा की है, चाहे नंदीशाला हो, ग्रामीण गौरव पथ की जगह विकास पथ हो, कर्ज माफी हो, परन्तु कोई क्रियान्विति नहीं होना, यह सरकार के लिए भी बड़ी जिम्मेवारी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विराज रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजों से लगाकर, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कालेज की इतनी अपार घोषणाएं कर दी हैं, प्रदेश के लिए घोषणाएं होना अच्छा है, पर जब तक शिक्षा के तंत्र में कालेज में प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं होंगे, हमारे बाड़मेर, जैसलमेर की स्कूलें, कोई शहर के नजदीक नहीं है और जहां स्टाफ 20 का होना चाहिए, वहां 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। बालोतरा और गुढ़ामालानी से लगाकर, सिवाना से लगाकर एक प्रोफेसर द्वारा आठ-आठ कालेज चलायी जा रही हैं, वे बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे? राजस्थान का नाम कैसे रोशन करेंगे या आगे कैसे बढ़ेंगे?

(श्री हमीर सिंह भायल)

चिकित्सा में आपने देखा होगा कि हमने हास्पिटल खोल दिये। इतने ज्यादा खोल दिये, पर एक भी जगह स्टाफ की जो कमी है, उसको हम दूर कैसे करेंगे? जब तक वह नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कर्जा माफी के नाम पर आपने दो तरीके का रोड मैप अपनाया, और कर्जा माफ नहीं हुआ। सोसाइटी में जिस व्यक्ति को लाख-डेढ़ लाख रुपया मिल रहा था, उसको 50 हजार कर दिया। कई व्यक्तियों को वंचित कर दिया कि ओवरड्राफ्ट हो गया है, इस वजह से आपको लोन भी नहीं मिलेगा। हमारे राजस्थान के नंदीशाला चेयरमैन बैठे हैं, ये बता दें कि बाड़मेर जिले में हर पंचायत समिति में कहां-कहां खुल गया है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप बोलें कि हमारी नीयत नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): हमारी नीयत नहीं, यह सरकार की ड्यूटी है। मेरे कहने का कारण यह है। आपने किसानों के साथ में भी छलावा किया है कि हम आवारा पशुओं के लिए तारबन्दी करेंगे। (व्यवधान) ऑनलाइन आवेदन करें। हजारों किसानों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। एक को भी सब्सिडी में एक नया पैसा तारबन्दी के लिए नहीं मिला है। मैं आपको यहां तक कहूंगा कि पैरा 176 में पोकरण-फलसूंड पेयजल योजना, माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ मंत्री विराजे हैं, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विराजे हैं। मैं ईमानदारीपूर्वक कह रहा हूं कि पोकरण-फलसूंड योजना से सिवाना से लगाकर, बालोतरा से लगाकर, सिणधरी से लगाकर सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि सर्दियों में दो-दो महीने तक पानी नहीं मिल रहा है। यह स्थिति हो गयी है। मुख्य मंत्री जी ने पैरा 176 में 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है पर आज दिन तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। रिफाइनरी को पानी, जो कि प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है पर उस रिफानरी को पानी दे रहे हैं। चोरी होकर वह पानी बिना पैसे के जा रहा है और पशुधन एवं मानव जीवन के पीने के लिए पानी नहीं है। सिणधरी से लगाकर, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि इतने गांव पानी से वंचित हैं, उनके लिए आज की तारीख में दो-दो महीने में और 25 से 30 किलोमीटर तक पानी नहीं मिल रहा है। सिणधरी के अन्दर नाकोड़ा, डंडाली, भूंका, कमकाई, धने की ढाणी।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। मेरी डिमांड हैं, वे तो रखने दें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेयजल की व्यवस्था करेंगे। एक रोड, सिणधरी खारा बांटा से लगाकर 325 तक, मिठोड़ा होते हुए वह रोड करायें। सिवाना सामुदायिक अस्पताल को उप जिला

(श्री हमीर सिंह भायल)

अस्पताल में क्रमोन्नत करें। समदड़ी समिति मुख्यालय पर महिला बाल विकास अधिकारी की मांग है तथा सिवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोला जाये। बाखरड़ा बैल्ट में एनिकट से पीने के लिए पानी दिया जाये। सभापति महोदय, हमारा जो सशक्त एरिया था, हर किसान 100 बीघा में, 400 बीघा में खेती करता था, पर आज पानी नहीं है, इसलिए पीने के लिए तरस रहे हैं।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, यह लिखा हुआ है, इसको टेबल कर दूं? सभापति महोदय, धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सीनियर सदस्य हैं, 10 मिनट और बढ़ा दें। इनके बोलने तक बढ़ा दें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का अन्तिम अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। अब बजट के विरोध पर बोलने का हमको आगे मौका नहीं मिलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है।

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की बात बोल दें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): बजट में दो तरह की बात होती है। पहली होती है बजट की घोषणा और उसका दूसरा भाग होता है, उसकी क्रियान्विति। मैं जब 2003 में विधायक बना था, तब भी अशोक जी गहलोत की सरकार थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी सलाह है कि ये आकाश-पाताल मत बांधो। सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की बातों पर आ जाएं, ताकि आपकी पूरी बात हो जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 10 मिनट बढ़ा दें।

श्री सभापति: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो मुझे सुबह तक बैठायें। मैं तो बैठने के लिए तैयार हूं। यह आप लोगों को डिसाइड करना है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज जो राजस्थान के हालात हैं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। सर्कल में पटवारी नहीं हैं, गांवों में कृषि पर्यवेक्षक नहीं हैं। बजट की क्रियान्विति किस प्रकार से होगी, यह एक चिन्ता का विषय है। यह बजट केवल चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, विकास की इसमें बिल्कुल अनदेखी की गयी है। मेरे भीलवाड़ा शहर की जब मैं बात करता हूं तो पिछले चार सालों के बजट में एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जोधड़ास ओवरब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। इस सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद कोठारी नदी पर पुल का निर्माण होना था, वह पुल का निर्माण हुआ। अधूरे निर्माण में वह पुल ध्वस्त हो गया, उसकी अभी सरकार के द्वारा जांच चलायी जा रही है।

मेरे शहर में स्मार्ट सिटी की घोषणा पिछले बजट में की गयी थी। एक भी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आज तक भीलवाड़ा शहर में नहीं लगा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: सदन का समय 06.50 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अगर इस तरह की घोषणाएं करनी हैं और आपको वाहवाही लेनी है तो निश्चित रूप से आप लीजिये, जनता आपको जवाब देगी। इस बजट की क्रियान्विति के लिए अप्रैल से लेकर केवल सितम्बर माह तक का समय आपके पास है। अक्टूबर में आचार संहिता लग जायेगी और नवम्बर के एंड में चुनाव आ जायेंगे। किस तरह से यह बजट पूरा होगा और किस तरह से इस बजट में राशि का प्रावधान करेंगे?

आज हमारा भीलवाड़ा जिला इस बजट में उपेक्षित हुआ है। भीलवाड़ा जिले में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई है और इसे आप शानदार बजट बता रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है और जिससे हम आपके लिए मेज बजायें। आज की स्थिति में भीलवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरा मेवाड़ क्षेत्र इस बजट में उपेक्षित क्षेत्र है। इस बजट के हालात ये हैं।

आपके इस बजट में एक घोषणा है। बजट के बिन्दु संख्या 102 में एक घोषणा है। पेज संख्या 73 पर-प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात का दबाव कम करने एवं सुनियोजित विकास एवं पूरे प्रदेश को सौंदर्यीकरण करने एवं सीवरेज हेतु 1 हजार 8 सौ करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।' इसमें 25 कार्यों की लिस्ट दी गयी है। इसमें से 11 कार्य केवल जोधपुर के हैं। जिस तरह का क्षेत्रीय असन्तुलन आपने इस राजस्थान में किया है। मैं इस बजट से बोल रहा हूं कि 25 में से 11 काम

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

केवल जोधपुर शहर के हैं और पूरे राजस्थान के शहरों के लिए 14 कार्य हैं। इस तरह का क्षेत्रीय असंतुलन आपने इस राजस्थान में किया है। मैं इस बजट से बोल रहा हूं। 25 में से 11 काम केवल जोधपुर शहर के हैं और पूरे राजस्थान के शहरों के लिए 14 कार्य हैं। इस तरह से विकास हम कर पाएंगे? जिस तरह से आज बीकानेर जिला और पूरा मारवाड़, केवल जोधपुर को आपने मारवाड़ समझ लिया है। पूरा मारवाड़ और पूरा मेवाड़ इस बजट से उपेक्षित चल रहा है। जनता यह पूछ रही है कि हमारे लिए क्या हुआ। अभी-भी समय है। जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तब इन उपेक्षित और वंचित एरिया को जो इस बजट से और पिछले कई बजट से उपेक्षित रहे हैं, जवाब में इनको जोड़कर अगर उनके विकास के लिए घोषणा करेंगे तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से वहां की जनता को कुछ न कुछ राहत मिलेगी।

मेरे भीलवाड़ा नगर में आज की तारीख में यातायात का इतना दबाव है। मैं अपने क्षेत्र की मांग कर रहा हूं। मेरे भीलवाड़ा में, मंत्री साहब विराजमान हैं। ये भी जब गाड़ी से वहां से निकलते हैं तो इनकी गाड़ी को निकलने में भी बड़ी तकलीफ आने लगी है तो आम जनता की क्या हालत होगी? भीलवाड़ा में इतने साधन हैं, इतने व्हीकल हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में कहते हैं कि भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। उस एरिया में हमारे एक रेलवे फाटक है, उस रेलवे ओवरब्रिज को बनाने की पिछले दस सालों से लगातार विधान सभा के माध्यम से मांग की जा रही है। पहले जिंदल के द्वारा उसको बनाया जाना था, लेकिन एन जी टी के द्वारा उसका फैसला दे दिए जाने के बाद मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर हमारे शहर में यातायात के दबाव को कम करना है और जनता को राहत देनी है, 24 घंटे में 60 ट्रेनें निकलती हैं और 60 बार वह फाटक बंद होता है तथा शहर को जोड़ने का एकमात्र वही है। रेलवे पटरी के इस पार और इस पार आधा-आधा शहर है। उस रेलवे पटरी के ऊपर अगर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो जनता को बहुत राहत मिलेगी।

इसके अलावा मेरे शहर में जो हालात हैं, हर जगह जाम लगता है। अगर एक क्रॉस फ्लाई-ओवर बन जाता है तो निश्चित रूप से यातायात के दबाव को हम कम कर पाएंगे और जनता को राहत मिलेगी। भीलवाड़ा जिले का जो बदनौर उपखण्ड है, जिसमें एस डी एम हैडक्वार्टर है, वहां एक कालेज की सख्त आवश्यकता है। आपकी नीति भी है कि एस डी एम हैडक्वार्टर पर कालेज का निर्माण कराया जायेगा, तो कृपा करके इस बजट में आप बदनौर उपखण्ड में कालेज की घोषणा करें।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

वन मंत्री जी से एक मेरी प्रमुख मांग है कि मेरे बदनौर में बैराठ माता क्षेत्र है, उस बैराठ माता क्षेत्र का बहुत बड़ा जंगल का इलाका है जहां कई जंगली जानवर, पैंथर वगैरह हैं। वहां 10-10, 15-15 पैंथर हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): रावली अभयारण्य उसके अटैच है। वह बदनौर-बैराठ का जंगल, रावली अभयारण्य एकदम लगा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र बैराठ मगरे को, बैराठ माता जंगल को भी अभयारण्य घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से वन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और अभयारण्य में भी सुंदरता आएगी। बहुत घना जंगल है। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष बावरी। माननीय सदस्या, आपका समय पर जितना हो जाए, उतना हो जाए, बाकी आप टेबल कर देना। श्री हमीर सिंह भायल का जो बचा हुआ है, उसको टेबल कर देना।

(माननीय सदस्य श्री हमीर सिंह भायल द्वारा सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो वित्तीय बजट 2023-24 पेश किया गया है, ऐसा लगता है कि जनता को लोक-लुभावना बजट दिया गया है और ये बजट देकर खाली मतदाताओं की और किसानों की सहानुभूति बटोरने का एक प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है। असत्य घोषणाओं के अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी सरकार युवाओं पर केन्द्रित बजट लेकर आयी है, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि आज प्रदेश के अंदर युवाओं की क्या स्थिति है। 176 पृष्ठों का यह बजट है। इतना लम्बा बजट भाषण पढ़ा गया है पर इसके अंदर राजस्थान के विकास की बात कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यह पांचवां बजट जो सरकार लेकर आयी है, लोक-लुभावनी घोषणाएं करके बिना विजन का बजट लाया गया है। सरकार ने राजस्थान के ऊपर जो कर्ज का एक भार इन असत्य घोषणाओं के आधार पर बढ़ाया है, वह राजस्थान के सामने है, जनता के सामने है।

मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो ये पांचवां67 बजट है और इन पांच बजट के अंदर कहीं भी मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी उपेक्षा इसमें की गयी है। बोर्डर एरिया पर, सीमा क्षेत्र पर स्थित मेरा विधान सभा क्षेत्र सुविधाओं से वंचित है। जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद इस बजट में हमें कुछ

(श्रीमती संतोष)

दिया जायेगा, लेकिन इस बजट में भी उनको निराशा ही हाथ लगी है। ये बजट सिर्फ जयपुर और जोधपुर तक ही सीमित रहा है। मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जयपुर और जोधपुर से बाहर भी राजस्थान है। केवल कुछ विधान सभाओं को लाभ देने के लिए ये बजट पेश किया गया है।

प्रदेश की जनता, किसान इंतजार कर रहे थे कि पाले की वजह से जो फसल खराबा हुआ है तो कुछ राहत उनको दी जायेगी, मुआवजे की घोषणा की जायेगी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और किसानों के निराशा ही हाथ लगी है। इससे पूर्व जो बजट पेश किया गया था, उसके अंदर किसानों के हित की बात कही गयी थी, किसानों के लिए बजट कहा गया था, लेकिन हम सबको पता है कि राजस्थान के अंदर किसानों के साथ धोखा इस सरकार ने किया है। किस प्रकार से कर्जमाफी का वादा किया, लेकिन आज किसान परेशान है।

फ्री बिजली देने की बात इस बजट में की गयी है। हम सबको पता है डिमांड राशि भरवाने के बावजूद भी आज किसान अपनी पर्ची लेकर बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उनको सामान नहीं दिया जा रहा है, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और कट इतने लग रहे हैं जो समझ से बाहर है। वोल्टेज इतना कम है कि आये दिन किसानों की मोटरें जल जाती हैं और उलटा किसान पर इसका भार पड़ रहा है। जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वे भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। सिंचाई की समस्या हमारे सामने मुख्य रूप से रहती है। सिंचाई के बारे में इस बजट के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, वे अपनी मनमानी करके किसानों के हिस्से का पानी काट लेते हैं। दो-दो दिन लेट पानी छोड़ा जाता है, 6-6 घंटे लेट पानी छोड़ा जाता है। इस दरमियान जिस किसान की बारी होती है, वह पिट जाती है। उसकी भरपाई का कोई भी जिम्मेदार राजस्थान के अंदर नहीं है। यह बजट युवाओं पर केन्द्रित बजट बताया गया है, लेकिन हम सबको पता है कि 65 लाख युवा आज राजस्थान के अंदर बेरोजगार हैं और एक लाख से ऊपर भर्तियां अटकी हुई हैं। ये सब राजस्थान के युवाओं पर आधारित इस बजट की पोल खोलती हैं कि किस प्रकार से हमारा युवा बेरोजगार है, लेकिन राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है?

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि असत्य को जोर से बोलने पर वह असत्य सच नहीं हो जाता है, लेकिन आज हमारे माननीय सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं, वे बार-बार वाहवाही के लिए असत्य बोलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, ...शब्द असंसदीय है। असत्य बोला कीजिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): मैं माफी चाहूंगी। इस असत्य शब्द को बार-बार बोलकर, इस बजट को, इन घोषणाओं को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि राजस्थान में आज क्या स्थिति है, किस प्रकार से हमारे युवा परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, किसान परेशान है।

आशा और उम्मीद के साथ अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स हैं, जो मैं यहां रखना चाहूंगी। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक ट्रोमा सेंटर की हम काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं क्योंकि भारतमाला रोड हमारे यहां से होकर गुजरती है और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रोमा सेंटर की मांग पूरी की जाए। अनूपगढ़ जिला बनाने की मांग मैंने पूर्व में भी की थी और अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए। सभी मापदंड वह पूर्ण करता है। डी टी ओ कार्यालय की मांग मेरे क्षेत्र में लम्बे समय से की जा रही है। डीटीओ कार्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र को दिया जाए। इसी के साथ रामसिंहपुर नाहरावाली को उप-तहसील का दर्जा दिया जावे। एक मुख्य मांग मेरी है कि घड़साना को नगरपालिका बनाया जाए। पूर्व में हमारी जो तत्कालीन सरकार थी, उसके द्वारा घोषणा भी की गयी थी, लेकिन आपकी सरकार ने उसको रोक दिया। मैं चाहूंगी कि जो घड़साना है, 40 हजार की आबादी का कस्बा है, उसको नगरपालिका बनाया जावे। अनूपगढ़ में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी खोला जाए और नाहरावाली को पुलिस चौकी और रोजड़ी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाए। पशु चिकित्सा उप-केन्द्र का भवन हमारे यहां जर्जर हालत में है, उसका भी निर्माण करवाया जाए।

श्री सभापति: शेष भाषण आपको टेबल करने की अनुमति देता हूं।

(माननीय सदस्या श्रीमती संतोष द्वारा सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.50 बजे बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहाड़ा) रायपुर ग्राम पंचायत का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

137. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नगरपालिका गठन के लिए क्या मानदण्ड है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत, रायपुर नगरपालिका के लिए उक्त मानदण्ड पूरे करती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.02.2021 के द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने के सन्दर्भ में मानक निर्धारित किये गये हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 10 फरवरी, 2023 में ग्राम पंचायत रायपुर (सहाड़ा) भीलवाड़ा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है।

(3) भाग संख्या 03 का उत्तर भाग संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर में हरमाड़ा से सीतापुरा तक मैट्रो रेल परियोजना

148. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा जयपुर शहर में यात्री भार को देखते हुए सीकर रोड स्थित हरमाड़ा रोड नं. 14 से सीतापुरा तक मैट्रो रेल परियोजना प्रारम्भ करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जे एम आर सी ने जुलाई, 2020 में जयपुर मैट्रो फेज-2 की डी पी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आर तैयार करवाई है, जिसमें रूट सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक ही प्रस्तावित है, आगे हरमाड़ा रोड नं. 14 तक विस्तार वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रानीवाड़ा में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान में वितरित पट्टे

150. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2022 में प्रारम्भ 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के तहत प्रदेश में दस लाख पट्टे वितरित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमन व नियमों में अनेक प्रकार की छूट व शिथिलता प्रदान की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी छूट व शिथिलता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोर्ट स्टे के उपरांत भी विवादित भूमि के पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त पट्टे कानूनन वैध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल कितने पट्टे वितरित किये गये? पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त अभियान की कालावधि के दौरान पुराने गृहों के विनियमितीकरण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत ली जाने वाली राशि (दरों) में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान में कुल 5136 पट्टे वितरित किए गए हैं।

पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**कुल ग्राम पंचायतें**	**जारी किये गये पट्टों की संख्या**
1.	रानीवाड़ा	32	3163
2.	जसवंतपुरा	12	934
3.	सरनाउ	17	1031
4.	भीनमाल	01	8
	कुल	**62**	**5136**

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर के बाखासर रण को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना

151. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बाड़मेर के बाखासर रण को कच्छ के रण की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक कितने स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? उक्त स्थलों को विकसित करने के क्या-क्या आधार बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाखासर रण को कच्छ के रण की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर बजट उपलब्धता एवं पर्यटक स्थल के महत्व के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला कलेक्टरों द्वारा जिले के विभागों का प्रभावी निरीक्षण

152. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जन समस्याओं के समाधान सहित संबंधित जिला स्तर के विभागों के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग, गुणवत्ता व समय सीमा में पूर्ण करने हेतु जिला कलेक्टरों को विभागों के नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रत्येक जिले में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण व निरीक्षण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जन समस्याओं के समाधान सहित संबंधित जिला स्तर के विभागों के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग, गुणवत्ता व समय सीमा में पूर्ण करने के संबंध में जिला कलेक्टरों को नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण हेतु समय-समय पर निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिनकी छायाप्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रत्येक जिले में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण व निरीक्षण बाबत इस विभाग द्वारा समय-समय पर जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सलूम्बर में नजूल सम्पत्तियां

153. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनुपयोगी नजूल सम्पत्तियों की देखरेख हेतु कोई नीति बनायी गई है? यदि हां, तो क्या? विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कौन-कौनसी नजूल सम्पत्तियां कहां-कहां पर स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नजूल सम्पत्तियों को विक्रय करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.7(12)/साप्र-1/90 दिनांक 04.01.1991 के अनुसार प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा की जाती है। (परिशिष्ट-1)

जिला कलेक्टर, उदयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कोई भी नजूल सम्पत्ति अवस्थित नहीं है। (परिशिष्ट-2)

(2) जी हां। अनुपयोगी (रिक्त) नजूल सम्पत्तियों में से आवश्यकता अनुसार राजकीय विभागों के कार्य उपयोग हेतु आबंटन के उपरान्त शेष अनुपयोगी (रिक्त) नजूल सम्पत्तियों को नियमानुसार खुली नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा

154. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र-2018 में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त जन घोषणा पत्र की शब्दावली क्या थी?

(2) क्या वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की जन घोषणा से पूर्व पूर्ववर्ती सरकार कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही थी? वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने हेतु कोई राइडर, नियंत्रण लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या व कब-कब?

(3) क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने हेतु बेरोजगार युवकों को प्रतिदिन चार घंटे किसी कार्यालय, संस्था अथवा स्थान पर सेवा देने हेतु अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त भत्ते के लिए चयनित कितने बेरोजगारों ने उक्त सेवायें दीं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र-2018 में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जिसकी शब्दावली थी "शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500/- रुपये प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।"

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

(2) जी हां। वर्तमान सरकार के बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा राजस्थान बेराजगारी भत्ता योजना-2012 के अन्तर्गत राज्य के स्नातक बेरोजगारों को प्रतिमाह पुरूष आशार्थियों को 650 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन आशार्थियों को 750 रुपये के अनुसार एक समय में 1 लाख की अधिकतम सीमा में बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष हेतु दिया जा रहा था। दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक उक्त योजनान्तर्गत नियमानुसार 156791 पात्र आशार्थियों को राशि 121.60 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

वर्तमान सरकार आने के बाद जन घोषणा पत्र-2018 के बिन्दु संख्या 10.1 की अनुपालना में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत भत्ता राशि को बढ़ाया जाकर पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह करते हुए एक समय में अधिकतम एक लाख की बजाय 1 लाख 60 हजार आशार्थियों को लाभांवित किये जाने की सीमा निर्धारित की गई।

तत्पश्चात् बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 के अनुसार उक्त योजना को रोजगार योग्य बनाते हुए भत्ता राशि को बढ़ाया जाकर पुरुष आशार्थियों को 4000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह करते हुए एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को लाभांवित किये जाने की सीमा निर्धारित की गई।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए ऐसे बेरोजगार युवक जो पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त हैं उन्हें प्रतिदिन 4 घण्टे विभिन्न राजकीय कार्यालयों में इंटर्नशिप किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर तत्पश्चात् 4 घण्टे इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है।

योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक कुल 1,67,937 पात्र आशार्थियों ने विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की है।

बून्दी के कन्या महाविद्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण

155. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बून्दी के पुराने जेल भवन में संचालित कन्या

(श्री अशोक डोगरा)

महाविद्यालय के लिए नवीन भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय कन्या महाविदयालय, बूंदी के लिए रूसा से आबंटित बजट व भामाशाहों के सहयोग से 6 कक्षा-कक्षों का नवीन भवन बना हुआ है तथा 4 कक्षा-कक्ष पुराने भवन में संचालित हैं। तथापि आवश्यकता, गुणावगुणों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथासमय भवन के विस्तार पर यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।

श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं

156. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिकों के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं व उक्त योजनाओं में विगत पांच वर्षों में कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर स्थित कार्यालय में श्रमिकों की योजनाओं को संचालित करने हेतु कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विगत 5 वर्षों में लाभार्थियों द्वारा योजना आवेदनों में स्वीकृत किये गये आवेदनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) मंडल योजनाओं का संचालन करने हेतु श्रम कार्यालय, उदयपुर से प्राप्त विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ओसियां में सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति

101. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा 2021-22 के बजट में अनुसंधान हेतु सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने जिलों में उक्त की पदोन्नति हुई? यदि नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विगत पांच वर्षों में सी.आई.डी. (सी.बी.) में कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर कब-कब पदोन्नति की गई? यदि नहीं, तो क्यों? वर्गवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021-22 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 432 में निम्नानुसार घोषणा की गई :-

''प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6323 पदों को, कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से, बढ़ाकर 10 हजार किया जाना प्रस्तावित है''।

उपरोक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में 3677 कांस्टेबल के पदों को क्रमोन्नयन करते हुए 3677 कांस्टेबल के पद समाप्त कर, उनके स्थान पर 3677 सहायक उप निरीक्षक के नवीन पद सृजित किये गये। सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के संबंध में संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण/वरिष्ठता सूची/पदोन्नति संबंधी कार्य सी आई डी (सी बी) मुख्यालय जयपुर स्तर पर किया जाता है न कि विधान सभा क्षेत्रवार किया जाता है।

सी आई डी (सी बी) में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के रिक्त पदों पर वर्ष 2017-18 में 23 (सामान्य-18, एससी-5) व वर्ष 2018-19 में 16 (सामान्य-11, एससी-2, एसटी-3) पदों पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के वर्ष 2017-18 में 06 (सामान्य

(गृह मंत्री)

-03, एससी-03) व वर्ष 2018-19 में 11 (सामान्य-10, एसटी-01) पदों पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक की कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल व हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की पूर्व में आयोजित योग्यात्मक परीक्षाओं की रिव्यू प्रक्रिया लम्बित होने के कारण आगामी वर्षो की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

विगत 05 वर्षों में कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पदों पर आयोजित की गई योग्यात्मक परीक्षाओं की वर्गवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जूडो खिलाड़ियों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षण

102. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2018 के पश्चात् पुलिस (R.P.) में कांस्टेबल के पद में खिलाड़ी कोटे का दो प्रतिशत आरक्षण होने के पश्चात् भी जूडो के खिलाड़ियों को उक्त कोटे में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भर्ती में जूडो खिलाड़ियों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम-7 (सी) के अनुसरण में विभागाध्यक्ष द्वारा मुख्य खेल अधिकारी की अध्यक्षता में भर्ती हेतु कमेटी गठित कर विभाग के लिए उपयुक्त एवं आवश्यकतानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के खेलवार पद विज्ञापित किये जाते है। पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2018 में जूडो खेल के 05 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी थी। जूडो खेल के खिलाड़ियों की संख्या पर्याप्त होने के कारण वर्ष 2018 के पश्चात जूडो खेल के खिलाड़ियों की भर्ती नहीं की गई। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पुलिस विभाग में वर्ष 2018 के पश्चात् 2 प्रतिशत खिलाडी कोटा से आरक्षित पदों पर जूडो खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि वर्ष 2018 में जूडो खेल के 05 खिलाड़ियों को खेल कोटा से नियुक्ति प्रदान की जा चुकी थी। राजस्थान पुलिस जूडो टीम में खिलाड़ियों की संख्या पर्याप्त

(गृह मंत्री)

होने के कारण वर्ष 2018 के बाद जूडो खेल के खिलाड़ियों की भर्ती नहीं की गई। जूडो खेल से पुलिस विभाग में आवश्यकतानुसार खिलाड़ियों की भर्ती की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत पुलिस कार्मिकों को शहरी भत्ता

103. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि चौमूं, बगरू, चाकसू, बस्सी आदि क़स्बे पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार व जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में पदस्थापित पुलिस कार्मिकों को शहरी भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। चौमूं, बगरू, चाकसू, बस्सी कस्बे पुलिस आयुक्तालय एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उक्त क्षेत्रों में पदस्थापित पुलिस कार्मिकों को शहरी भत्ता मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	मूल वेतन	देय राशि
1.	23100 तक	620 रुपये प्रतिमाह
2.	23100 से अधिक	1000 रुपये प्रतिमाह

मनोहर थाना में अनुकम्पा नियुक्ति

104. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों में से कितनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई एवं कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत तीन वर्षो के मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों के 15 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 10 कनिष्ठ सहायक, 03 प्रयोगशाला सहायक एवं 02 सहायक कर्मचारी के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से कनिष्ठ सहायक के 06, प्रयोगशाला सहायक के 02 तथा सहायक कर्मचारी के 01 अनुमोदन कर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

कनिष्ठ सहायक के 04 प्रकरण व प्रयोगशाला सहायक के 01 प्रकरण आक्षेपों की पूर्ति के पश्चात् निस्तारण किया जा सकेगा।

सहायक कर्मचारी के 01 प्रकरण आवेदक का भाई राज्य सेवा में होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), झालावाड़ द्वारा 12.01.2021 से प्रकरण निरस्त किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त आवेदनों में से 8 आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है एवं 3 प्रकरण शेष हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। आक्षेपों की पूर्ति होकर आने के पश्चात् विभागीय अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खींवसर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना

105. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों एवं कस्बों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के पश्चात् से अब तक विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कितने कस्बों व गांवों में उक्त विद्यालय खोले गये व शेष में नहीं खोलने के क्या कारण रहे? खोले गये विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों व कस्बों में उक्त स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त घोषणा की पालना में विधान सभा क्षेत्र खींवसर के निम्नांकित दो विद्यालयों को महात्मा गांधी विद्यालयों में रूपान्तरित किया जा चुका है:-

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रूण।
2. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शंखवास।

विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ऐसे गांवों/कस्बों जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत यथा आवश्यकता अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा सकेंगे।

(2) जी हां। शेष प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 के खण्ड 3 के अनुसार।

विद्याधर नगर में वर्षा जल निकासी की योजना

106. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर के सीकर रोड पर वर्षा जल निकासी की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त रोड से वर्षा जल निकासी के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जल निकासी के मार्ग में अवैध कब्जे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कब्जों को हटाने के लिए क्या प्रयास किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र के सीकर रोड पर वर्षा जल निकासी हेतु राशि रु. 39.00 करोड़ से पुरानी ड्रेन के अलावा अधिक क्षमता की नई ड्रेन रोड नं. 02 से द्रव्यवती नदी तक सड़क के दोनों तरफ बनाने की योजना बनाई गई है, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त जविप्रा में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाया जा सकेगा।

(2) विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र के सीकर रोड पर वर्षा जल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

भराव की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए वर्षाकाल से पूर्व अभियान चलाकर ड्रेन एवं इनलेट पाइंट की सफाई एवं वर्षा के दौरान लेबर इत्यादि की तात्कालिक व्यवस्था कर समस्या का यथासंभव निस्तारण कर दिया जाता है।

(3) सीकर रोड से वर्षा जल निकासी हेतु बनाये गये इनलेट पाइंट पर जगह-जगह स्थानीय दुकानदारों द्वारा रैम्प/सीढ़ियां इत्यादि द्वारा इनलेट पाइंट बंद कर दिये गये हैं, जिस हेतु समय-समय पर समझाइश द्वारा यथासंभव इनलेट पाइंट को खुलवा दिया जाता है। जल निकासी के मार्ग में अवैध कब्जे को समय-समय पर अभियान के तहत हटाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

आबू रोड नगर सुधार न्यास द्वारा 90ए की कार्यवाही

107. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर सुधार न्यास, आबू रोड़ द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2018 के पश्चात् किस-किस भूमि की कब-कब 90A की कार्यवाही की गई? स्थानवार व खसरा नंबर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्यास क्षेत्र में दिनांक 1 फरवरी, 2018 के पश्चात् जारी की गई भवन निर्माण की स्वीकृतियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2018 के पश्चात् कुल 113 प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत आदेश जारी किये गये हैं, जिनका स्थान, खसरा नम्बर आदि की विस्तृत सूची पताका "क" पर संलग्न है।

(2) नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2018 के पश्चात् कुल 271 भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर यू आई टी के पेरिफेरी क्षेत्र की पंचायतों में पट्टा देने की योजना

108. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री फूल सिंह मीणा)

(1) क्या यू आई टी, उदयपुर ने पेरिफेरी क्षेत्र में बसी हुई आबादी को पट्टा देने के लिए प्रस्ताव दिया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पेरिफेरी क्षेत्र की पंचायतों में वर्षों से बसी हुई आबादी को भू-आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(15)नविवि/नियम/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2022 के अनुसरण में जिला कलेक्टर को न्यास पत्र दिनांक 23.03.2022 से प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिसके तहत जिला कलेक्टर द्वारा आदेश क्रमांक प.12/3()राज./हस्ता./2022/1323 दिनांक 25.04.2022 से विभिन्न गांवों की कुल 214.335 हैक्टेयर भूमि संबंधित ग्राम पंचायतों को आबादी प्रयोजन हेतु आबंटित की गई है। उक्त आबंटित भूमि में पट्टे संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाते है।

जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना में एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रों के क्रम में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की परिधीय क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों की आबादी भूमियों में से हस्तान्तरण योग्य आबादी भूमियों का न्यास स्तर पर परीक्षण कर न्यास पत्र दिनांक 18.11.2022, 20.12.2022, 04.01.2023 से प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रेषित किये गये हैं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

कोटा में बॉटेनिकल पार्क

109. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर कोटा में बॉटेनिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त पार्क किस स्थान पर बनेगा व उक्त पार्क कब तक बन जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)

(वन मंत्री)

जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर मे बॉटेनिकल गार्डन स्थापित किये जाने हेतु घोषणा की गई है। कोटा में यह गार्डन शहर के अभेडा नान्ता, सकतपुरा क्षेत्र में बन रहा है। यह कार्य दिनांक 21.10.2022 को प्रारम्भ हो चुका है। कार्य को वर्ष 2023 24 में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अस्थाई काश्त (टी सी) कृषि रकबे में खातेदारी देने की योजना

110. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार लंबे समय से चल रहे अस्थाई काश्त (टी सी) कृषि रकबे का पुख्ता आबंटन कर खातेदारी देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उपनिवेशन विभाग में टी.सी. से पुख्ता आबंटन करने के 86 प्रकरण लम्बित हैं, जिनका निस्तारण आबंटन सलाहकार समिति में रखकर नियमानुसार आबंटन की प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी व आबंटन उपरान्त नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

श्रीगंगानर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के जिन काश्तकारों के नाम उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई काश्त (टी सी) भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है तथा उन काश्तकारों द्वारा आबंटन नियमों/शर्तों की पूर्ण पालना की जा रही है, ऐसे अस्थाई काश्तकारों द्वारा सक्षम कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आबंटन सलाहकार समिति की राय से (टी.सी.) भूमि का पुख्ता आबंटन किया जाता है। पूर्व में वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की टी.सी. भूमि का पुख्ता आबंटन किया गया था। तहसील सूरतगढ़ के ग्राम रोही पींपासर, चक गौदारान, हिन्दौर में पत्थरगढ़ी कार्य नहीं होने के कारण रिकार्ड व मौका में भिन्नता होने पर 350 टी.सी धारकों को पुख्ता आबंटन नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त टी.सी. काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अन्वेषणाधीन अपराध के तहत कुर्क सम्पत्तियों को सरकारी सम्पत्तियां मानने का प्रावधान

111. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या पंजीयन एवं मुद्रांक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पत्र क्रमांक प. 2(21) वित्त/कर/2014 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार कुर्क की गई सम्पत्ति को राज. पंजीयन नियम, 1955 के नियम 39 (1) के तहत सरकारी सम्पत्ति मानते हुए पंजीयन से इंकार करने का प्रावधान किया गया है?

(2) क्या उक्त प्रावधान केवल अन्वेषणाधीन अपराध के तहत कुर्क की गई सम्पत्ति पर ही लागू है अथवा उक्त प्रावधान प्रत्येक सरकारी बकाया वसूली के कारण कुर्क की गई सम्पत्ति पर भी लागू होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (भाग-1) के नियम 39 के खण्ड (1) के प्रोविजो के तहत उप पंजीयक को राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की भूमियों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन करने से प्रतिबंधित किया गया है (परिशिष्ट-क)।

वित्त (कर) विभाग के पत्रांक प.2(21) वित्त/कर/2014 दिनांक 12.07.2021 (परिशिष्ट-ख) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां सम्पत्ति किसी केन्द्रीय या राज्यीय कानून के अधीन अन्वेषणाधीन अपराध से संबंधित हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कुर्क की गई हो तो उन मामलों में उस कुर्कशुदा सम्पत्ति का स्वामी उसके अन्तरण के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं होता है। अत: ऐसी स्थिति में ऐसी कुर्क की गई सम्पत्ति का हस्तांतरण दस्तावेज उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होने पर वह राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 (भाग-1) के नियम 39 के खण्ड (1) के प्रोविजो के तहत कुर्क की गई सम्पत्ति को सरकार की सम्पत्ति के समकक्ष मानकर पंजीयन से इन्कार कर सकता है।

(2) उक्त प्रावधान उन सभी मामलों में लागू होगा जहां सम्पत्ति किसी केन्द्रीय या राज्यीय कानून के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कुर्क की गई हो।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नजूल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण

112. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या सम्पदा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बजट 2022-23 में नजूल सम्पतियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों को पच्चीस प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा कराने के पश्चात् अब तक कितने लोगों को सम्पतियों के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में वर्ष 2000 से पूर्व की नजूल सम्पत्तियों पर काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों द्वारा पच्चीस प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा कराने के पश्चात् भी अब तक उक्त सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जाना शेष है? यदि हां, तो उक्त को अब कब तक हस्तान्तरण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के किसी भी रिहायशी कब्जेधारी द्वारा अभी तक पच्चीस प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा नहीं करायी गई है और न ही किसी सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया गया है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में वर्ष 2000 से पूर्व के नजूल सम्पत्तियों पर काबिज अल्प आय वर्ग के किसी भी रिहायशी कब्जेधारी द्वारा अभी तक पच्चीस प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा नहीं कराई गई है और न ही किसी सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जाना शेष है।

धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना

113. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनिया)

(3) उक्त योजना में अब तक कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2021-22 के पैरा संख्या 213 के अंतर्गत "राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हिन्दू तीर्थस्थलों जैसे चारभुजा, नाथद्वारा-राजसमंद, गौतम ऋषि मंदिर-सिरोही, पुष्कर-अजमेर, कोलायत-बीकानेर, खाटूश्यामजी-सीकर, मेंहदीपुर बालाजी-दौसा, डिग्गी कल्याणजी-टोंक; प्रमुख जैन तीर्थस्थलों यथा तिजारा-अलवर, श्रीमहावीरजी-करौली, चमत्कारजी-सवाई माधोपुर, बाड़ापदमपुरा, सांगानेर-जयपुर, देलवाड़ा, अचलगढ़, माउण्ट आबू-सिरोही, रणकपुर-पाली व चांदखेड़ी-खानपुर-झालावाड़; प्रमुख सिख तीर्थस्थलों यथा बुड्डा जोहड़ श्रीगंगानगर, नरायना, खालसा हैरिटेज काम्प्लेक्स-जयपुर, पुष्कर-अजमेर, गुरूद्वारा श्री कलगीधर-बागौर साहिब व माण्डल-भीलवाड़ा तथा प्रमुख मुस्लिम तीर्थस्थलों यथा सरवाड़ दरगाह-अजमेर, दरगाह तन्हा पीर मण्डोर-जोधपुर, दरगाह-कपासन-चित्तौड़गढ़, हमीदुद्दीन दरगाह-नागौर, मिट्ठेशाह दरगाह-झालावाड़, नरहड़ की दरगाह-झुन्झुनूं, हकीम साहब की दरगाह-सीकर, दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चारदरवाजा व दरगाह सांभर-जयपुर के धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये जायेंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।" घोषणा की गई है।

(2) जी हां। वर्ष 2021-22 में धार्मिक पर्यटन सर्किट के तहत विभिन्न विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 89.33 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत किये गये विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) धार्मिक पर्यटन सर्किट के तहत स्वीकृत विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर शहर में नव पर्यटन स्थान का चयन

114. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) क्या सरकार द्वारा विगत बजट में पर्यटन के विकास के लिए प्रत्येक जिले में पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने एवं उक्त पर राशि व्यय करने की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बजट घोषणानुसार कितने जिलों में पर्यटन स्थलों का चयन कर लिया गया है? जिलेवार स्थलों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त घोषणानुसार अजमेर शहर में किस नवीन पर्यटन स्थल का चयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में प्रदेश में नव चिन्हित पर्यटन स्थलों पर कितनी लागत से क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? जिलेवार व स्थानवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2022-23 के पैरा संख्या 105 (1) के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु प्रत्येक जिले के 2-2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधी 100 करोड़ के कार्यों की घोषणा की गई है। प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त बजट घोषणा के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किये गये पर्यटन स्थलों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त बजट घोषणा के क्रम में अजमेर शहर में पर्यटन स्थल का चयन नहीं किया गया है।

बजट घोषणा के तहत अजमेर जिले में पर्यटन के विकास के लिए चिन्हित किये गये पर्यटन स्थल निम्नानुसार है:-

1. प्राचीन वराह मंदिर, बघेरा में विकास कार्य।

2. ग्राम सुरसुरा, तहसील- रूपनगढ़ में स्थित तेजाजी धाम में पर्यटन विकास कार्य।

(4) बजट घोषणा के क्रम में पर्यटन के विकास के लिए चिन्हित किये गये पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत विकास कार्यों एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा में फसल खराबे का मुआवजा

115. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2021 व 2022 में बाढ़ एवं बरसात से रबी एवं खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसे वर्ष में किन-किन किसानों का कितना-कितना नुकसान हुआ है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ एवं बरसात से हुए नुकसान की गिरदावरी करवाई गई है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे गांव में किन-किन फसलों में कितने-कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वर्षों में हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कितने किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में वर्ष 2021 में 1,24,120 एवं वर्ष 2022 में 1,33,354 काश्तकारों को खरीफ फसलों में बाढ़ से नुकसान हुआ है।

संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। खरीफ फसलों में बाढ़ से क्षति की गिरदावरी करवाई गई है। गांव व पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(3) खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से प्रभावित 45,332 किसानों को एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार राशि 24.19 करोड़ रुपये कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट"अ" के अनुसार है।

वर्ष 2022 में बाढ़ से प्रभावित 1,33,354 किसानों को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में आगजनी एवं प्राकृतिक आपदा के दर्ज प्रकरण

116. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मीना कंवर)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से हुई हानि का मुआवजा देने संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2021 से अब तक कितने आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त दर्ज प्रकरणों में पीड़ित परिवारों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई? सहायता राशि का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एस डी आर एफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट''अ'' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2021 से अब तक आगजनी के कुल 26 प्रकरणों में अनुमानित राशि 8.81 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार राशि रुपये 1.96 लाख का भुगतान किया गया है।

खरीफ फसल 2021 सम्वत् (2078) में सूखे से फसल खराबा होने पर 44,624 कृषकों को राशि 51.00 करोड़ रुपये कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया गया है।

अन्य प्राक़तिक आपदा से कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगोद में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों की मरम्मत

117. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कृषि उपज मण्डी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

द्वारा कुल कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सांगोद की दिनांक 25.11.2022 की बैठक में भी उक्त मुद्दा उठाया गया था? यदि हां, तो क्या अधिकारियों द्वारा मौके पर सड़कों का अवलोकन किया गया है? यदि नहीं, तो कृषि उपज मण्डी की आय का उपयोग किस प्रकार किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (अनाज व फल-सब्जी) द्वारा गत 4 वर्षों में (वर्ष 2018-19 से दिसम्बर, 2022 तक) कुल राशि 1,447.45 लाख रु. खर्च की गई, जिसमें से कुल 48.80 किमी लम्बाई की 32 सड़कों के निर्माण पर राशि 1,443.97 लाख रुपये खर्च की गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भवन निर्माण के कार्य पर राशि 3.48 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य अनुमत नहीं है। परिपत्र की छाया प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2010 द्वारा मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। (आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।)

(3) जी हां। पंचायत समिति सांगोद की बैठक दिनांक 25.11.2022 में इस संबंध में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मण्डी समिति को प्रेषित करने का निर्णय किया गया था। उक्त बैठक के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर से मण्डी समिति को निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों से मौका निरीक्षण करवाया जायेगा। कृषि उपज मण्डी समितियों की आय के उपयोग के संबंध में विवरण परिशिष्ट "य" पर उपलब्ध है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क व पुलियाओं का निर्माण

118. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषकों की उपज को मंडी में लाने हेतु ग्रामीण सड़कों व पुलियाओं का निर्माण करवाया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत तीन वर्षों में उक्त मानदण्ड के अनुसार कितनी सड़क व पुलियाओं का निर्माण किया गया तथा कितने कार्य लंबित हैं? क्या सरकार उक्त लंबित कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषकों की उपज मण्डी में लाने हेतु सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जाता है। इस संबंध में प्रावधान/ मापदण्ड विभागीय पत्र दिनांक 31.12.2014 एवं दिनांक 18.03.2020 के द्वारा निर्धारित किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर का क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा एवं देवली के अन्तर्गत आता है। उक्त दोनों मण्डी समितियों में विगत 3 वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2021-22) में किसी भी सम्पर्क सड़क की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अत: कोई कार्य लम्बित नहीं है। वर्ष 2022-23 में कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा द्वारा जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए 5 सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से मण्डी समिति की उपलब्ध बचत के अनुसार 3 सम्पर्क सड़कों की राशि 172.25 लाख रु. की स्वीकृति दिनांक 03.02.2023 को जारी की गई। कृषि उपज मण्डी समिति, देवली से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए सड़क निर्माण मद में वर्ष 2022-23 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आसीन्द में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण

119. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका आसीन्द में इण्डोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका गुलाबपुरा व उप खण्ड बदनौर में इण्डोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सी एस आर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जायेगी।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग सी एस आर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जायेगी।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

बीकानेर के आवासीय खेल विद्यालय में सुविधा बढ़ाने की कार्ययोजना

120. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर मुख्यालय पर संचालित आवासीय खेल विद्यालय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में विभिन्न सुविधाएं बढ़ाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में मैस भत्ता, किट मनी, खेल उपकरण, खेल मैदान का रखरखाव व मरम्मत हेतु कितना-कितना बजट आबंटित किया गया है? क्या सरकार उक्त में वृद्धि करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में वाटर कूलर, मैस में स्थाई पांच कुक लगाने व लम्बे समय से बंद पड़ी डिस्पेन्सरी व स्विमिंग पूल को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय में विभिन्न बारह खेलों के लिए पर्याप्त कोच लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल को प्राप्त 1.57 करोड़ की राशि निम्नांकित कार्यों हेतु आबंटित की गई है:-

1. खेलकूद मैदान एवं रख-रखाव - 78.56 लाख
2. विद्यालय बाउण्ड्रीवॉल मरम्म्त - 14.88 लाख
3. भ्रमण पथ का निर्माण - 13.58 लाख
4. हॉस्टल की मरम्मत - 50 लाख

खेल उपकरणों के क्रय हेतु प्रतिवर्ष 02 लाख रुपये का आबंटन किया जाता है।

मैस भत्ता 100/- प्रति छात्र प्रतिदिन निर्धारित है।

किट मनी 1000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष निर्धारित है।

सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल आवासीय विद्यालय में विभिन्न सुविधाएं बढ़ाने

(शिक्षा मंत्री)

हेतु जांच दल का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट/तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

(2) मैस एवं विद्यालय में वाटर कूलर लगे हुए हैं। डिस्पेन्सरी के संबंध में जांच दल की रिपोर्ट/तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन में आवश्यकता प्रतिपादित की है, साथ ही कुक एवं स्विमिंग पूल की व्यवस्था के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित एवं पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की कार्ययोजना

121. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में वर्तमान में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? क्या सरकार उक्त में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में राज्य में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निम्नानुसार हैं-

श्रेणी	**न्यूनतम मजदूरी दर (रुपये प्रतिदिन)**
अकुशल	259/-
अर्द्ध कुशल	271/-
कुशल	283/-
उच्च कुशल	333/-

उक्त बढ़ोतरी दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी है।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर की जाती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -

1. एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000पार्ट/17953
   दिनांक 28.06.2022

(राज्य मंत्री, श्रम)

2. एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/17906 दिनांक 28.06.2022

3. एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/17859 दिनांक 28.06.2022

4. एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/17812 दिनांक 28.06.2022

5. एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/17765 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें पुनरीक्षित की गयी हैं।

उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.labour.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट

माननीय सदस्य श्री हमीर सिंह भायल का आय-व्ययक पर वाद-विवाद के समय सदन पटल पर रखा गया शेष वक्तव्य

राजस्थान सरकार यह बजट जो बिना सोचे समझे, बिना देखे सदन में पेश किया गया जिसका मैं विरोध करता हूं, राज्य का वित्त और मुख्य मंत्री सदन में बिना पढ़े ही प्रदेश को आने वाले समय में दी जानी सुविधाओं को बोल रहे, जिनको पूर्व में इसी सदन में बोल दिया गया था 10 फरवरी, 2023 के दिन को राजस्थान की विधान सभा में हमेशा याद रखा जाएगा। कोई सी एम इस तरह की गलती कर दे तो उस प्रदेश के क्या हाल होंगे, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हो।

कांग्रेस की सरकार ने पिछले चार बजट में भी राजस्थान की आम जनता के साथ धोखा किया और इस बार भी प्रदेश को कंगाली के कगार पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह बजट युवाओं को भ्रमित करने वाला है बजट से एक कहावत चरितार्थ होती दिख रही है- कांच में धन बताया गया है जिसको बस देखते ही रहो।

पिछले बजट में लगभग 1029 घोषणाएं इसी सदन में ही हुई थीं जिनमें से मात्र 350 घोषणाओं को यह सरकार जमीन पर उतार सकी है, प्रदेश के आम नागरिक को अधिक कर्जदार बना दिया है। प्रदेश पर कर्जा लगातार बढ़ाया गया है, 2019 में प्रदेश पर कर्जा तीन लाख करोड़ था जिसको अब बढ़ाकर वर्तमान सरकार ने सात लाख करोड़ कर दिया है। प्रदेश को कर्ज के मुंह में धकेल कर चुनावी वैतरणी पार लगाने को लेकर बजट जारी किया गया जो आमजन के लिए ठीक नहीं है। आमजन को भ्रमित करके आंकड़े पेश किये गये हैं जिनको पूरा करना असम्भव है। पिछले चार बजट की घोषणाएं अभी भी अधूरी ही पड़ी हैं।

वर्तमान सरकार की सोच है कि सितम्बर-अक्टूबर तक समस्त घोषणाओं को अमलीजामा पहना लिया जावेगा लेकिन यह सम्भव नहीं हो सकता, अगली सरकार पर वित्तीय बोझ डालने को लेकर एक गलत प्रयास किया गया है।

इस बजट में कहीं भी युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं रखी गयी है, मात्र विजन बताया गया है। भर्ती प्रक्रिया सभी विभागों की अधूरी पड़ी हैं या फिर सभी पेपर लीक हो गये हैं जिसके कारण प्रदेश का युवा लगातार

दु:खी है। प्रदेश में बेरोजगारी के कारण अनेकों युवाओं ने आत्महत्याएं की हैं। कई परिवार उजड़ गये हैं, फिर भी प्रदेश की सरकार बजट में किसी भी प्रकार की भर्ती को लेकर कोई घोषणा नहीं कर रही है।

पिछले बजट और इस बार के बजट में कृषि बजट अलग पेश किया गया जिससे क्या राहत मिली है, मुझे लगता है यह भी एक कागजों का पुलिंदा ही है। एक भी घोषणा जो किसानों को लाभ प्रदान कर सके, इसमें भी नहीं है और पिछले बजट में भी नहीं थी।

किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए पिछले और वर्तमान बजट में घोषणा की है, मुझे बडे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कनेक्शन पिछले वर्ष जारी किये हैं, उन सभी में किसानों से सरकार ने मांग पत्र की सभी राशि वसूली कर दी है और आज दिन तक बिजली का सामान नहीं मिला है, किसान कर्ज के तले डूब गया है, बोई हुई फसलें बर्बाद हुई हैं नलकूप खुदवा लिए हैं और बिजली का अभी भी कनेक्शन नहीं हुआ है और सरकार है जो अभी भी घोषणा कर रही है।

बिजली संकट वर्तमान सरकार के लिए चार वर्षों से लगातार हो रखा है किसानों को समय पर थ्री फेज बिजली नहीं मिली जिसके कारण किसानों की आधी फसल खराब हो गयी है। बोई हुई फसल को बीच में ही छोड़ना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में घरों में भी कई कनेक्शन अभी भी बाकी हैं जिसको लेकर बजट में कोई प्रबन्धन नहीं किया है। पूर्व में केन्द्र की स्कीम जो कनेक्शन हुए उसके सिवाय वर्तमान सरकार ने घरेलू कनेक्शन नहीं दिये हैं, उलटा बिजली आपूर्ति कम की है। अभी भी बच्चों के बोर्ड एग्जाम होने को हैं और बिजली संकट बोलकर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती की जा रही है।

बजट में घोषणा की गयी है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त में घरेलू और 2000 यूनिट बिजली कृषि क्षेत्र में प्रतिमाह मुफ्त में मिलेगी, लगातार सतर्कता दलों द्वारा किसानों से चौथ वसूली की जा रही है और विजिलेंस करवाकर सरकार लाखों रुपये किसानों से ले रही है। यह राशि मासिक बिल से भी ज्यादा भरवाई जा रही है। किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है और अब बजट में कर प्रस्ताव पेश करके एमनेस्टी योजना लाकर राहत प्रदान करने की बात कर रही है जबकि हर माह में तीन से चार दिन के लिए सरकार आदेश करती है कि किसानों की विजिलेंस करो और किसानों से चौथ वसूली के साथ ही बिजली विभाग में लाखों रुपये की शीट भरी जाती है, किसानों को वर्तमान सरकार ने कंगाल कर दिया है।

राजस्थान सस्कार समय पर बिजली को लेकर प्रबन्धन नहीं कर सकी

जिसके परिणाम से आज प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। सरकार अपने निजी मामलों में उलझने के कारण से आम जनता को परेशान किया जा रहा है।

पेयजल को लेकर वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी पेयजल की राशि का भी सही तरह से उपयोग करने में विफल है। मेरे क्षेत्र की बात करूं तो अभी भी इस सर्दी के मौसम में भी लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, कोई भी प्रबन्धन नहीं है विभाग के पास। भूमिगत जल स्तर बिलकुल नहीं है और योजना का कार्य 2008 से लम्बित है। पिछले चार वर्षों से मुख्य लाइन के मात्र 10 किलोमीटर पाइप भी अभी तक नहीं डाले हैं जिसके कारण से सिवाना विधान सभा क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है और इस बजट में भी सिवाना योजना पोकरण फलसूंड बालोतरा सिवाना के लिए कोई प्रबन्धन नहीं है।

उलटा इस योजना से ही पचपदरा रिफाइनरी को पानी दिया जा रहा है जो योजना बनी उस समय प्रोजेक्ट में समाहित ही नहीं था फिर भी जनता का पानी लूटा जा रहा है और सरकार मूक दर्शक है।

नर्मदा योजना से मेरे क्षेत्र सिणधरी के 13 गांव जोड़ने की योजना पूर्व में बनी थी जिसमें आज दिन तक कभी भी बजट प्रावधान नहीं हुआ है और उन गांवों में आज भी लोग मात्र बरसाती जल पर ही निर्भर हैं लेकिन सरकार का ध्यान कभी भी उस ओर नहीं गया है। कई बार अवगत करवाने पर भी बजट में कोई प्रबन्धन नहीं किया गया है।

सिवाना विधान सभा के सिणधरी और सिवाना के लगभग सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च जलाशय (एस आर) बने हुए लम्बा अरसा हुआ है। उनमें पानी नहीं आने से सरकार का अरबों रुपयों को घाटा हुआ है। यह सब सरकारी तंत्र के कुप्रबंधन के कारण हुआ है जिससे यह सभी टंकियां बेकार हो रही हैं और पानी आने के बाद भी स्टोरेज के लिए यह सभी जलाशय कोई काम के नहीं रहेंगे, यह सब कुप्रबंधन का नतीजा है।

विधान सभा वार अधिशासी अभियंता कार्यालय पेयजल विभाग के किये जाने के लिए राजस्थान सरकार की योजना पर भी सिवाना विधान सभा क्षेत्र का अभी भी कार्यालय बालोतरा में ही है जिसके कारण सिवाना क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार होता है। मेरी मांग है कि सिवाना मुख्यालय पर XEN कार्यालय खोला जावे।

शिक्षा के क्षेत्र को देखा जावे तो बाड़मेर जिले में अभी 12 प्रतिशत पद खाली हैं जिसमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पद बहुत अधिक खाली हैं।

सरकार लगातार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा किये जा रही है और एक भी अध्यापक अंग्रेजी माध्यम का नहीं लिया जा रहा है, उल्टा हिन्दी माध्यम के विद्यालयों से अध्यापकों को उन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति दी जा रही है जिसके कारण दोनों ही विद्यालयों की स्थिति खराब हो रही है। एक तरफ स्टाफ कम हो रहा है और दूसरी तरफ उनको इंग्लिश में पढ़ाना नहीं आता है। शिक्षा विभाग के ढांचे को विफल कर दिया है। लगातार ट्रांसफर होने से पद खाली हो रहे हैं, सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है।

यही स्थिति कालेज शिक्षा की है।

यही स्थिति आई टी आई में है।

यही स्थिति संस्कृत शिक्षा विभाग में है।

चिकित्सा विभाग की स्थिति और भी खराब है। रिक्त पदों के कारण से मरीज परेशान है। कोरोना काल में योद्धा की तरह कार्य करने वाले सी एच ए (कोविड सहायकों) को इस बजट में छोड़ दिया गया है, इनको भी प्रदेश का हिस्सा मानकर रहता देने की आवश्यकता है।

सिवाना अस्पताल लगभग 40 वर्षों से संचालित है जिसको आज जिला उप अस्पताल की आवश्यकता है और जनसंख्या के आधार पर सिवाना क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो नये खोले जाने की मांग है जिसमें धनवा, चाडो की ढाणी और जेठन्तरी मुख्य रूप से है।

सिणधरी क़स्बा मेगा हाईवे से जुड़ा हुआ है जिसके कारण से दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं इसलिए ट्रोमा सेंटर की नितांत आवश्यकता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों से वंचित राजस्व गांवों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए गांवों में सुविधाएं बढ़ाई जायें।

नि:शुल्क इलाज है लेकिन मेन पावर की कमी से सभी सुविधाएं मिल नहीं सकती हैं, चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की जानी चाहिए, जिसका इस बजट में कहीं उल्लेख ही नहीं है।

बजट में सड़क निर्माण को लेकर थोथी घोषणा पिछले पांच वर्षों में मात्र 10 करोड़ की राशि दिया जाना, मात्र एक भी सड़क नहीं बन पा रही है और वो भी इन चार साल में अभी भी कहीं काम शुरू नहीं हुआ है।

बजट घोषणा 10 जुलाई, 2019 के बिन्दु संख्या 39 में लिखा था कि राज्य की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकास पथ बनवाये जायेंगे जो आज दिन तक नहीं बने।

वसुन्धरा राजे जी की सरकार में बने गौरव पथ का विकल्प आपने विकास पथ घोषणा की जो अभी तक पूरी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें चलने लायक नहीं हैं।

अभी भी घोषणा है इंटर लोकिंग सड़कें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक किलोमीटर बनवाई जाएंगी यह भी विकास पथ की ही भांति है या और कोई।

पिछले पांच बजट में हर जिले में सड़क मरम्मत और मेजर रिपेयर के काम देय हैं लेकिन सिवाना विधान सभा में आज दिन तक एक भी सड़क का नहीं दिया जाना प्रश्नवाचक बात है।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र को उलटा तीन कार्यालयों के अधीन कर दिया है बालोतरा बाड़मेर और बायतु तीन कार्यालयों में बांटने का कार्य जरूर किया है।

मेरी मांग है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र का अलग कार्यालय जो सिवाना में ही हो जिसमें सिवाना सिणधरी और समदड़ी सहायक अभियंता कार्यालय को शामिल करके अलग से XEN कार्यालय सिवाना में हो।

जोधपुर को जालौर-सिवाना-आहोर-समदड़ी और सिवाना का पूरा आबादी क्षेत्र को सीधा जोधपुर से जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे-66 जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया लेकिन रेलवे ब्रिज देवड़ा फाटक पर नहीं बना, उसको बनवाया जाना आवश्यक है।

इस सड़क के लिए मैं आदरणीय वसुन्धरा राजे जी और युनुस खान साहब को धन्यवाद देता हूं।

मेरी मांग है कि जयपुर को सीधा जोड़ने के लिए विधान सभा क्षेत्र आहोर-जालौर-रानीवाड़ा-भीनमाल-बाड़मेर-सिवाना-पचपदरा के लिए सिणधरी से सिवाना और सिवाना से खंडप जालौर सरहद भाद्राजून-पाली तक सड़क मार्ग को डबल लेन जिसकी दूरी कुल अनुमानित 165 किलोमीटर है जिसमें से 24 किलोमीटर बन रही है, इस सड़क की स्वीकृति करवाने का श्रम करावें।

वर्तमान सरकार द्वारा झूठी घोषणा जो अब तक भी पूरी नहीं हुई उसका वर्ष वार बिंदु वार विवरण-

1. **बजट घोषणा 2019-20** के बिंदु-24 में ऋण माफी का जिक्र है जो

आज दिन तक पूरी नहीं हुई है आज भी किसान ऋण के बोझ से दबे हैं और जिनकी राशि माफ़ कर दी ग्राम सेवा सहकारी समिति से, उनको आज दिन तक वापस लोन नहीं मिला।

2. बिंदु संख्या-31 में अंकित है हर पंचायत समिति स्तर पर नंदी गो शाला, जो आज दिन तक नहीं।

3. बिदु संख्या-39 विकास पथ अभी भी नहीं बने।

4. बिंदु संख्या-48 में एक लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे। आज भी किसान घूम रहा है जिनसे सरकार ने मांग पत्र की राशि वसूल ली और सामान नहीं मिला।

5. बजट घोषणा पैरा-64 में अंकित है 200 करोड़ रुपये से सौर ऊर्जा चालित नलकूप स्थापित किये जायेंगे एक भी नहीं लगा।

6. पैरा-19 में है पचपदरा में पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स स्थापित होगा आज भी नहीं।

7. बजट पैरा-80 में अंकित है बजरी माफिया पर अंकुश लगाकर कम दर में किसानों को बजरी मिलेगी इसका उल्टा हुआ आज भी बजरी माफिया ही सक्रिय है और अधिक कीमत वसूली जा रही है जिसमें सरकार ही भागीदार है सबसे बड़ी विकट समस्या।

8. इसी बजट में जनता क्लिनिक पैरा-95 में अंकित है यह योजना किस स्थान पर कार्य कर रही है।

9. बिन्दु सं. पैरा-147 गोडावन राज्य पक्षी संरक्षण-जो खाली घोषणा ही है कोई प्रबन्धन नहीं।

10. बिन्दु संख्या-164 सभी दस्तावेज राजस्व ऑनलाइन आज दिन तक एक भी तहसील सही ढंग से कार्य करने में सफल नहीं रही।

11 इसी बजट का बिंदु-174 में घोषणा-100 अग्निशमन वहां दूरदराज के क्षेत्रों को दिये जायेंगे हमारे से दूर कौन है एक भी वाहन नहीं।

बजट घोषणा 2020-21

1. बजट घोषणा बिंदु-45 और 46 झूठगोदाम निर्माण ग्राम सेवा सहकारी समिति और नये ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन।

2. बिंदु संख्या-70 ग्रामीण ओलम्पिक खेल जिसमें विद्यालय खेलों का महत्व कम हुआ और बच्चे खेलों को भूल ही गये।

3. बिंदु संख्या-87 रिफायनरी परियोजना में युवाओं को रोजगार के लिए हाईड्रो कार्बन सेंटर की स्थापना से ट्रेनिंग की बात जो झूठ।
4. बिंदु संख्या-99 में कम्प्यूटर शिक्षक केडर बनाने की घोषणा जो आज दिन तक नहीं हुआ और हो भी गया तो एक भी शिक्षक नहीं लगा।
5. बिदु संख्या-120 फिर एक लाख तीस हजार कृषि कनेक्शन की घोषणा-जो फील्ड में नहीं।
6. बिंदु-182 अग्नि शमन वाहन खरीदने की बात जिसमें 100 वाहन लेने की बात तो यह किस उपखण्ड को दिये।

बजट घोषणा-2021-22

1. बिदु-17 मॉडल सी एच सी विकसित करनी-मेरे क्षेत्र में तीन हैं एक भी मॉडल नहीं बनी, उल्टा स्टाफ कम है।
2. बिंदु संख्या-68 कृषि बजट का हिस्सा ऋण माफी की घोषणा और एक भी किसान का ऋण माफ नहीं और सोसायटी से मिलने वाले ऋण को कम किया है और डिफाल्टर की एक किसानों की और विंग बना दी जो आज भी ऋण के लिए घूम रहे हैं।
3. बिंदु संख्या-87 पशु चिकित्सा की मोबाइल वेटेरिनरी सेवा, जिसको हम सभी ने लम्पी बीमारी में देखा, गाय को देखना वाला कोई नहीं था दानदाताओं के भरोसे ही गाय माता रही है, सरकार का प्रबन्धन शून्य था।
4. बजट का पैरा-176 पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना योजना में वर्ष 2038 की मांग के अनुरूप बजट प्रावधान करके 580 करोड़ की राशि आबंटन का लक्ष्य रखा है।

लेकिन आज दिन तक सिवाना की जनता को लाभ नहीं मिला है आज भी इस योजना का काम अधूरा है तो बजट खर्च क्या हुआ। आज भी पेयजल के 890 दिन धरना चल रहा है।

बजट घोषणा-2022-23

1. बजट बिन्दु-46 भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने की घोषणा और 32 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी, अध्यापकों के पद पर जो आज दिन तक नहीं हुई है और पेपर लीक करवाकर युवाओं को धोखा।
2. बिदु संख्या-62 जिसमें श्रमिकों को लंबित प्रकरण निस्तारण करके सभी मांग के आधार पर राशि देने का वादा लेकिन आज भी इस

योजना वो स्थिति वो ही है श्रमिकों को दी जाने वाली सभी सहायता शर्तें लंबित ही हैं।

3. पैरा-72 सड़क निर्माण के 10 करोड़ के प्रस्ताव आज भी अधूरे पड़े हैं।

4. बिंदु-110 कानून व्यवस्था सुधारने की बात-अपराध उलटे बढ़े हैं सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है, अपराध की श्रेणी में राज्य अव्वल है।

5. कृषि बजट के अधीन तार बंदी योजना में लाखों लोगों से आवेदन लिए हैं एक भी किसान को अभी तक चार साल में अनुदान नहीं मिला है और अभी भी घोषणा और कर रहे हैं।

6. बजट पैरा-136 किसानों को दिन में बिजली देने की बात-बिजली चार साल से किसानों को मिल ही नहीं रही है- झूठ से ही कार्य चला रही है सरकार।

7. बजट बिदु-152 किसानों को समय पर खाद दिया जाने के लिए नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाकर लाभ की बात लेकिन पुरानी में भी चार साल से खाद नहीं आ रही है, किसानों के लिए खाद के लिए इस बजट में भी प्रबन्धन नहीं है।

8. पैरा संख्या-156 एक बार और झूठ का सहारा लिया गया है। आवारा पशुओं के लिए नंदी गोशाला के लिए ब्लाक स्तर पर राशि आबंटन की बात रखी है मेरे किसी भी ब्लाक में नंदी गोशाला को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ है।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र जिला बाड़मेर के लिए बजट घोषणा 2023-24 में कोर्ड विशेष राहत नहीं मिली है विगत पांच वर्षो से सिवाना के लिए बजट सड़क मेजर रिपेयर में एक भी नहीं हुई है और बजट पूर्व भी मेरे द्वारा मांग पत्र दिया गया था लेकिन अभी तक सिवाना क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है।

मेरा विशेष आग्रह है कि बजट रिप्लाई में सिवाना के लिए निम्न सौगात आमजन के हित में दिलवाकर शहर प्रदान करावें-

- सिवाना सामुदायिक अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत की मांग।
- समदड़ी समिति मुख्यालय पर महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय की मांग।

- सिवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता कार्यालय की मांग।
- सिवाना मुख्यालय पर पी एच ई डी विभाग के अधिशाषी अभियंता कार्यालय की मांग।
- सिणधरी मुख्यालय पर सिविल (मुंसिफ) न्यायालय की मांग।
- सिणधरी मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर खुलवाने की मांग।
- सिवाना क्षेत्र में उप तहसील-पादरू और ठोड़ू खोला जावे।
- सिवाना क्षेत्र में विद्युत विभाग से सेला में 132 के वी सब स्टेशन, 33/11 के वी सब स्टेशन-केरली नाड़ी, सिणधरी देवन्दी (सिवाना), जेठन्तरी (समदड़ी), रामपुरा (समदड़ी), डांडाली (सिणधरी)।
- सिवाना मुख्यालय पर पुलिस वृत्त अधिकारी कार्यालय की मांग।
- सिवाना के खंडप में पुलिस चौकी स्थापना की मांग।

मोकलसर अस्पताल को सी. एच. सी. में क्रमोन्नत की मांग, नवीन पी एच सी धनवा, चाडो की ढाणी और जेठन्तरी में खोले जाने की मांग।

भाकरड़ा बेळट में एनीकट तेलवाड़ा, गोर्यणा-घीटा रितड़ा नाला नाल सिणेर काजी गुड़ा धारना भी दे पानी पीने की मांग।

माननीय सदस्या श्रीमती संतोष द्वारा आय-व्ययक पर वाद-विवाद के समय सदन पटल पर रखा गया शेष वक्तव्य

इस बजट को युवाओं पर केन्द्रित बजट बताया गया है, लेकिन युवाओं के हितों के प्रति राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है ये पूरा राजस्थान आज जानता है। राजस्थान में 65 लाख युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार राजस्थान में बेरोजगारी की भारी समस्या है, इसे स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं। जब आप समस्या ही स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान कैसे होगा? 1 लाख पदों की भर्तियां राज्य सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण अटकी हुई है। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगा रखा है।

सभापति महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जो बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 पेश किया है, ऐसे लगता है कि जनता को लोक लुभावना बजट देकर मतदाताओं व किसानों की सहानुभूति बटोरने और प्रदेश की जनता का हितैषी बनने का दिखावा किया जा रहा है। 176 पृष्ठों का लम्बा बजट भाषण पढ़ा गया लेकिन प्रदेश के विकास की बात कहीं भी नजर नहीं आ रही। बजट-बढ़त-राहत का बजट बताया जा रहा है।

कैसी बचत, कैसी बढ़त, कैसी राहत, राजस्थान की जनता को सब समझ में आ रहा है।

लोक-लुभावनी घोषणाएं करके बिना विजन का बजट लाकर आज राजस्थान को कर्ज में डुबाने का कार्य इस सरकार ने किया है।

ये बजट सिर्फ जयपुर और जोधपुर तक ही सीमित रहा है। जयपुर और जोधपुर से बाहर भी राजस्थान है। जो क्षेत्र पहले से ही विकास की दौड़ में आगे हैं, वहां पर नये संस्थानों को खोलने के स्थान पर राज्य सरकार को उन स्थानों पर नये संस्थान खोलने चाहिए जो विकास की दौड़ में पीछे हैं।

मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है।

बोर्डर सीमा पर स्थित मेरा क्षेत्र हर सुविधा से वंचित है। ऐसा पक्षपात।

प्रदेश की जनता व किसान इंतजार कर रहे थे पाले व शीतलहर से खराब हुए फसलों के मुआवजे की घोषणा मुख्य मंत्री जी करेंगे, लेकिन किसानों को निराशा ही हाथ लगी है।

पूर्व में सरकार किसान बजट सरकार लेकर आयी थी, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है हमारे सामने है। यूरिया डीएपी के लिए लाइनें/समय पर सिंचाई पानी नहीं, किसानों को फ्री बिजली, लम्बे कट रात को बिजली, वोल्टेज कम मीटरें जल, डिमाण्ड राशि भरने पर भी कनेक्शन नहीं, ट्रांसफार्मर जलने पर ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है।

मेरे क्षेत्रों में किसानों को समय पर सिंचाई पानी नहीं, 2-2 दिन लेट पानी छोडा जाता है इस दौरान जिस किसान की बार कट गई उसका नुकसान भरपाई।

विधान सभा क्षेत्र में ट्रोमा सेन्टर की मांग, भारतमाला रोड गुजरता है आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं।

अनूपगढ़ को जिला, सभी मापदण्ड पूरा करता है।

डीटीओ कार्यालय की मांग (प्रगति बनती है अनूपगढ़ विधान सभा)।

रामसिंहपुर/नाहरावाली को उपतहसील का दर्जा दिया जाये।

पूर्व में तत्कालीन सरकार द्वारा घड़साना को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था लेकिन आपकी सरकार ने रोक लगा दी।

घड़साना काफी बड़ा कस्बा है। प्रदेश की धान मंडियों में घड़साना मंण्डी का नाम भी आता है। 40 हजार आबादी वाला कस्बा है।

अनूगपढ़ में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाए तथा सदर पुलिस थाने की मांग भी लम्बे समय से।

नाहरावाली में पुलिस चौकी व रोजड़ी पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाये।

अनूपगढ़ का तहसील कार्यालय का भवन बिलकुल खण्डहर हो चुका है।

पशु चिकित्सा उपकेन्द्र

अनूपगढ़ क्षेत्र में काफी ग्राम पंचायतें हैं जहां पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नहीं है।

अनूपगढ़ शहर का पशु चिकित्सालय का भवन बिलकुल जर्जर है। नया भवन बनवाया जाये।

उच्च शिक्षा

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की अति आवश्यकता है। साथ ही में घड़साना/रावला में राजकीय महाविद्यालय खोले जायें।

सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में पीजी की क्लासें शुरू की जाएं।

मेरे क्षेत्र की रावला मण्डी के व्यापारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजफैड को गेहूं 88,000 क्विंटल विक्रय की गई है जिसको राजफैड ने रावला क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से खरीदा है। व्यापारियों की आढत राशि 30 लाख 35000 रुपये का भुगतान अतिशीघ्र करवाया जाये।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

अनूपगढ़ शाखा के पानी को रिजर्व किया जाये ताकि मेरे क्षेत्र में आ रही सिंचाई पानी की समस्या का समाधान हो सके।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर निर्माण व अनूपगढ़ ब्रांच में निर्माण कार्य की आपने बजट में बात कही है लेकिन पूर्व में जो नहर निर्माण हो चुका है वहां नहर के पटड़े अभी भी अधूरे पड़े हैं, सिंचाई विभाग कार्य नहीं कर रहा और ग्राम पंचायतों को एन.ओ.सी. नहीं दी गई।

पुलिस विभाग

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पुलिस के जवान 24 घण्टे ड्यूटी करते हैं। आपातकालीन स्थिति में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका ग्रेड पे 3600 किया जावे और साइकिल भत्ते की जगह वाहन भत्ता दिया जावे जिससे अपराधियों को पकड़ सकें।

होमगार्ड

राज्य में बोर्डर होमगार्ड की चार सशस्त्र बटालियन के 2,664 जवान जो राज्य की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं विभिन्न एजेंसियों के साथ सुरक्षा हेतु सेवाएं दे रहे हैं। इनके प्रस्ताव पर इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक व गंभीरता से विचार कर बजट में शामिल किया जाये।

आंगनबाड़ी

नई खोलने की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन भवन ही नहीं है।

आंगनबांड़ी कार्यकर्ता, साथिन के मानदेय को बढ़ाया जाए क्योंकि नाम मात्र के मानदेय में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रही है और स्थायी किया जाये।

डिग्गी अनुदान

पिछले बजट में घोषणा की गई लेकिन अभी तक।

समाज के हर वर्ग के कल्याण की उत्थान की बात सीएम साहब के द्वारा की गई है। लेकिन यह सरकार एससी/एसटी की कितनी हितेषी है। किस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं हमारे सामने है।

आपकी सरकार के अधिकारी कितने सही तरीके से काम कर रहे है, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी।

टिब्बी हनुमानगढ़ का एक मामला जिसमें एससी/एसटी की जमीन पर जनरल का कब्जा है। हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी एडीएम हनुमानगढ़ फैसला नहीं कर रही है। क्या कारण है समझ से बाहर है। बहस हो चुकी है और जमीन का मालिकाना हक होने के बाद भी पिछले दो वर्षों से फाइल को अटका रखा है। सिर्फ फैसला करना है। निर्णय नहीं दिया जा रहा है। और वर्षों से वह पीड़ित परिवार न्याय का इन्तजार कर रहा है। कितने गम्भीर अधिकारी हैं राजस्थान में।

टैक्सी यूनियन

माननीय सभापति महोदय,

प्रदेश में जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश में जिन-जिन जगह पर टैक्सी स्टैण्ड के नाम से जमीन नहीं है। उन जगह पर टैक्सी स्टैण्ड के नाम से जमीन नि:शुल्क जारी की जावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के टैक्सी स्टैण्ड अनूपगढ़, घड़साना, रावलामंडी, रामसिंहपुर, खानूवाली, 365 हैड (2 केएलडी में राज्य सरकार नि:शुल्क जमीन अलोट करे जिससे टैक्सी ड्राइवर गाड़ी निश्चित जगह पर रोक सके। कोरोना काल में भी इन्होंने नि:स्वार्थ भाव के साथ कार्य किया था। निश्चित जगह नहीं होने के कारण इनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

मेरे विधान क्षेत्र की 4 पंचायतें 3 STR, 24 ASC, 2 MLD (B), 8 PSD (B) मंडी विकास समिति के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

इस मण्डी एडियम की जगह को पंचायतों को हैण्डओवर किया जावे ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

सड़क:

सड़कों की स्थिति खराब है। उन्हें नया बनाया जाये।

27 ए, 2 पीजीएम, सखी रोड, 365 हर ऐसी कई सड़कें जिन्हें डबल रोड सीमा क्षेत्र की बीएसएफ चौकियों के लिए सड़क नहीं बनाया जाये।

शिक्षा

प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष में शिक्षा को लेकर भी बजट में कहा है कि विद्यालय तो क्रमोन्नत कर दिए लेकिन विद्यालय को चलाने के लिए अध्यापकों के पद काफी लंबे समय से रिक्त हैं। जिससे गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिन्हें मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत 5 एमएलडी के ग्राम 4 एमएलडी (बी), ग्राम पंचायत 11/12 एनडी (नाहरावाली) के ग्राम 12 एनडी, ग्राम पंचायत 9 एलएम (बी) के ग्राम 11/12 एलएम, ग्राम पंचायत 65 जीबी के 1 आरटीएम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और ग्राम पंचायत 22 एए, के ग्राम 23 एए, ग्राम पंचायत 72 जीबी के ग्राम 68/2 जीबी, ग्राम पंचायत 9 एलएम (बी) के ग्राम 1 एनडब्ल्यूएम (नाईयावाली) व ग्राम 11 एलएम, ग्राम पंचायत 15 एलएम के ग्राम 3 जेएम, ग्राम पंचायत 4 एलएम के ग्राम 6 एनडी व ग्राम 2 एलएम, ग्राम पंचायत 3 एनडी के ग्राम 4 केएएम (खाल) ग्राम पंचायत 12 केएनडी के ग्राम 16 केएनडी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनको क्रमोन्नत करने के लिए कई बार माननीय शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया है। इन विद्यालयों को अतिशीघ्र क्रमोन्न्त किया जाये जिससे गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र की रावलामंडी में विज्ञान संकाय, कृषि संकाय अन्य संकाय व बीकानेर संभाग को सबसे पुराना विद्यालय रामसिंहपुर में विज्ञान संकाय की स्वीकृति के आदेश दिये जाएं।

17 एमडी राउमा में विद्युत कनेक्शन तक नहीं है। एमएलए मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है।

1 एसटीवाई सताइयां, 10 केपीडी, 10 पी, 2-3 केडी, 5 एमजीएम, 4 केएचएम, 3 पीएम, 3 केपीडी, 14 आरजेओ, 3 आरजेएम, 3 केएचएम, 11 एआरएम, 7 एआरएम, 8 आरजेडी, 17 एमडी आदि।

सड़कें

माननीय सभापति महोदय, पूर्व बजट में अनुशंषा की गई सड़कों का निर्माण आज दिनांक तक नहीं करवाया गया है। गांवों की आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले गत वर्ष 2021 की सड़कें भी लंबित पड़ी हैं।

अनूपगढ़ 27ए चौराहे से 27 ए तक डबल रोड, रामसिंहपुर से वाया कुपली, लुणिया, डब्बर, 6 डीडी, घड़साना तक, अनूपगढ़ रामसिंहपुर मुख्य

सडक के रेलवे अंडर ब्रिज चक 74 जीबी से 5 यूडीएम तक (रिसोल्विंग), चक 20 एएस से 4 केएएम तक, ग्राम 5 यूडीएम से ग्राम 71 जीबी (मोघी) की ओर, अनूपगढ़ रामसिंहपुर मुख्य सड़क के चक 66 जीबी से 5 यूडीएम तक (रिसोल्विंग), ग्राम 69 जीबी से रामसिंहपुर की ओर, ग्राम 3 एनडी से चक 2 एलएम (बी) की ओर, ग्राम 3 एनडी से धांधडा गांव तक, ग्राम 27 ए से 26 ए. 25ए,10 के, पूर्व डामर सड़क रोड 28 ए से लैला मजनूं पोस्ट तक, ग्राम 29 ए से कैलाश पोस्ट तक, ग्राम 14 के से शेरपुरा पोस्ट (भारत-पाक) बोर्डर तक, चक 18 पी से चित्रकूट पोस्ट (भारत-पाक) बोर्डर तक, ग्राम 16 पी से 19 पी तक, चक 15 पी से 17 पी लिंक रोड तक, चक 20 एएस से 19 एएस तक, नाहरांवाली से अनूपगढ़ मुख्य सड़क के चक 2 एनएसएम से 14 एलएम तक, ग्राम 13 ए से नांहरांवाली तक, चक 15 एलएम गांव से चक 3 जेएम तक, चक 18 एलएम से 3 जेएम तक. नाहरांवाली लिंक रोड 5 एलएम से 11 एलएम लिंक रोड तक, चक 10 एलएम (ए) लिंक रोड से 1 एनडब्ल्यूएम (नाईयांवाली) राजकीय विद्यालय तक, चक 22 एए गांव से 4 एमएसआर तक, चक 8 ए से चक 11 ए तक, चक 8 के (बी) से 27 ए रोड तक, ग्राम 4 के से ग्राम 12 एबी तक, चक 6 एच से 13 एमडी तक, चक 6 एच से 12 एच तक, चक 2 पीजीएम (बी) से सूरतगढ़ रोड तक, घड़साना नई मण्डी से सखी, रावलागांव होते हुए रावला-खानुवाली मुख्य सड़क तक, चक 3 जीएम (जनतावाली) से 7 जीएम तक, रोजडी से 9 आरजेडी तक, ग्राम 8 एसकेएम से 23 केडी तक, ग्राम 21 एएस (ए) आबादी से मोमेवाला हैड तक ग्राम 21 एएस (ए), ग्राम 7 जीडी से ग्राम 17 एमडी, चक 4 एसजेएम (सेखडा) से 1 एसजेएम होकर 10 डीओएल तक, सहारनपुरा (रावला) से 4 केपीडी पंचायत मुख्यालय तक, ग्राम 15 केडी नहर की पुलिया से 16 केडी तक, ग्राम 4 पीएसडी से 1 पीएम (प्रथम), खानुवाली से 16 केएनडी तक, ग्राम 20 केएनडी से 22 केएनडी, ग्राम 9 पीएसडी (ए) से 9 पीएसडी (बी) तक इत्यादि।

चिकित्सा

राज्य सरकार ने बजट में चिकित्सा क्षेत्र में वाहवाही लूटी जा रही है हकीकत कुछ और ही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ में चिकित्सकों के 14 पद स्वीकृत हैं। लेकिन 4 चिकित्सक लगे हैं। लोग अपना इलाज कहां से करवाएं। पिछले सत्र के दौरान सदन में भी आश्वस्त किया था कि चिकित्सक लगा देंगे लेकिन नहीं लगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ की बिल्डिंग का मुद्दा भी सदन में कई

बार उठाया गया है। अभी भी बिल्डिंग की स्वीकृति जारी नही हुई है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घड़साना व रावला की हालत बहुत खराब है मौके पर चिकित्सकों के रिक्त पद हैं। मेरे बार-बार सदन में कहने पर अभी तक किसी भी प्रकार का चिकित्सक नहीं लगाया गया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात सदन में बार-बार की जा रही है लेकिन हकीकत में चिरंजीवी योजना की क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है।